चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

www.chauthiduniya.com

1986 से प्रकाशित | दिल्ली, 23 जनवरी–29 जनवरी 2012 | मूल्य 5 रुपये

ममता और नीतीश को आगे आना चाहिए

पेज-3

कांग्रेस-भाजपा का कम्युनल कार्ड

पेज-4

सबके दुलारे दाग़ी, दलबदलू और धन्ना सेठ

पेज-5

अपनी रक्षा अपने हाथ

पेज-7

कांग्रेस और मुलायम सिंह में समझौता हो गया

यह सौदेबाज़ी है सत्ता की. यह लालसा है हिंदुस्तान की सियासत पर क़ब्ज़ा करने और अपनी-अपनी वंश बेल को फलने-फूलने का मौक़ा देने और राज करने की. यह साज़िश है अवाम को छलावे में डालने की. इस मक़सद में कामयाब होने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को हर नुस्खा क़बूल है. लिहाज़ा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जुगलबंदी कर ली है. केंद्र और उत्तर प्रदेश की गद्दी पर काबिज़ होने की ख़ातिर दोनों पार्टियां अब एक राह पर चल पड़ी हैं.

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

रूबी अरुण

कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच यह करार हो चुका है कि उत्तर प्रदेश में वे मिलजुल कर सरकार बनाएंगी. इस समझौते के मुताबिक़ केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव उप मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे. हालांकि अखिलेश ने सूबे का वजीर-ए-आला बनने का सपना पाल रखा है, पर उन्हें अपने पिता का भी ख्याल रखना है और कांग्रेस ने अखिलेश यादव को उनके त्याग का ख़ूब सिला दिया है. कांग्रेस आलाकमान ने यह वायदा किया है कि उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव हिंदुस्तान के उप प्रधानमंत्री होंगे. कयासों के साथ-साथ बहस और आकलनों का दौर भी जारी है. कहा यह भी जा रहा है कि अगर राहुल गांधी की मेहनत रंग लाई तो कांग्रेस विधायकों का आंकड़ा तिहाई तक भी पहुंच सकता है. सुलह-सफ़ाई लालू प्रसाद यादव के साथ भी हुई है. तय यह हुआ है कि उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा, उसमें मुलायम सिंह के साथ लालू प्रसाद यादव को भी जगह दी जाएगी, जिसके बदले कांग्रेस को उनसे बिहार में एक बना बनाया वोट बैंक मिल जाए. चूंकि लालू की स्थिति अभी कमज़ोर है, लिहाज़ा कांग्रेस उनसे अपनी मनमर्जी से बराबरी पर समझौता कर सकती है. वैसे भी कांग्रेस को विपक्षियों के वार से बचने के लिए लालू टाइप के माउथपीस की बेहद ज़रूरत है. कांग्रेस मुलायम-लालू से सौदेबाज़ी करके कई मक़सद हासिल करना चाहती है. उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद उसके सिर पर लोकसभा चुनाव का भूत सवार होगा. अगर यह करिश्मा होता है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में सरकार बना लेती है, तब उसकी निगाह उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर होगी. उत्तर प्रदेश में लोकसभा में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें पाने की ख़ातिर कांग्रेस को कुछ चुग्गे भी डालने होंगे. ज़ाहिर है, वह यह काम मुलायम सिंह को उप प्रधानमंत्री बनाकर पूरा कर लेगी. इस गठजोड़ में मुलायम सिंह के लिए वे नेता कारगर हो सकते हैं, जो कभी उनके साथ थे और बाद में पाला बदल कर कांग्रेस के साथ हो गए. इनमें बेनी प्रसाद वर्मा, राजबब्बर एवं रशीद मसूद जैसे लोग शामिल हैं. इन नेताओं की मुलायम सिंह के साथ कभी कोई रंजिश नहीं रही, लेकिन अभी तक यह साफ़ नहीं हो पाया है कि मुलायम सिंह के साथ हुए कांग्रेस के समझौते को ये नेता किस रूप में लेंगे.

दूसरा भी एक और अहम कारण है मुलायम-लालू से समझौते का. यूपीए को केंद्र में अपनी सरकार भी बचानी है. सहयोगी पार्टी तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के नगर निकाय चुनावों के वक़्त से ही लगातार कांग्रेस को दबाव में लिए हुए हैं. वह बार-बार धमकियां दे रही हैं और अब तो खुलकर कहने लगी हैं कि केंद्र सरकार चाहे तो उनसे अपना नाता तोड़ सकती है. केंद्र में सहयोगी दल होने के बावजूद उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में अलग-थलग होकर चुनाव लड़ रही है. इसलिए कांग्रेस को ममता बनर्जी के विकल्प की तलाश है. मुलायम सिंह के 22 और लालू यादव के 4 सांसद हैं. राष्ट्रीय लोकदल के पांच सांसद केंद्र में शामिल हो ही चुके हैं. अब मुलायम-लालू के यूपीए के घटक दल बनने से केंद्र सरकार की निर्भरता ममता बनर्जी से कम हो जाएगी. हालांकि पार्टी के अंदर लालू के विरोध में भी कुछ स्वर हैं, पर उन्हें कांग्रेस आलाकमान ने नफ़ा-नुकसान का गणित समझा कर शांत करा दिया है और जो लोग मुलायम और लालू से सद्भाव रखते हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश चुनाव तक इंतज़ार करने के लिए कहा गया है. पर हां, संभावना इस बात की भी पूरी है कि अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की रणनीति कामयाब हो जाती है तो कांग्रेस को मुलायम और लालू से दूरी बनाते भी देर नहीं लगेगी. फिर कांग्रेस महासचिव उत्तर प्रदेश का प्रयोग बिहार में दोहराएंगे, लेकिन अगर पार्टी बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में भी चौथे नंबर पर आती है, तब इन 26 सांसदों का सरकार में शामिल होना तय है. हालांकि कांग्रेस ने लालू-मुलायम से सौदेबाजी का यह सिलसिला काफी पहले ही शुरू कर दिया था, लेकिन मुंह मांगा मंत्रालय न मिलने की वज़ह से बात ठंडे बस्ते में डाल दी गई.

पिछली बार इस मुताल्लिक आख़िरी बार 14 मई, 2010 की रात को बात हुई थी, जब राहुल गांधी की तरफ से केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार शिंदे लालू यादव के आवास 25, तुगलक रोड गए थे. तय यह हुआ था कि ममता बनर्जी की रोज़ की किचकिच से निजात पाई जाए और लालू-मुलायम-अजित सिंह सरकार में शामिल हो जाएं. उसी समय रामविलास पासवान को राज्यसभा सदस्य मनोनीत करने की बात भी पक्की हो चुकी थी. चूंकि पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा इल्जामों के घेरे में आ चुके थे, लिहाज़ा कांग्रेस उनकी भी छुट्टी करने के मूड में थी. रक्षा मंत्री ए के एंटोनी के विकल्प पर भी ग़ौर किया जा रहा था, लिहाज़ा अजित सिंह को नागरिक उड्डयन मंत्रालय, लालू यादव को दूरसंचार या रक्षा मंत्रालय और मुलायम सिंह यादव को रेल मंत्रालय का प्रभार देने की योजना बनी थी. सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी लालू यादव ने कन्नी काटनी शुरू कर दी. जबकि पहले वह इस मामले की अगुवाई कर रहे थे. राहुल गांधी ने जब उनसे इस रवैये की वज़ह पूछी तो पता चला कि उन्हें तो सिर्फ़ रेल मंत्रालय ही चाहिए. दलील यह थी कि उन्होंने भारतीय रेल के लिए अपने मंत्रित्वकाल में बहुत काम किया है और इस बार उन्हें फिर से रेल मंत्रालय मिल जाए तो वह भारतीय रेल को दुनिया की नंबर वन रेल बनाने का अपना वायदा और सपना दोनों पूरा कर सकेंगे. साथ ही ममता बनर्जी को मुंह तोड़ जवाब भी दे पाएंगे, क्योंकि ममता बनर्जी ने रेल मंत्रालय संभालते ही अपनी सारी ऊर्जा लालू यादव को घोटालेबाज और झूठा साबित करने में लगा दी थी.

लालू यादव इस बात से भी बड़े दु:खी थे कि ममता ने उनके द्वारा शुरू की गई परियोजना गरीब रथ का नाम दुरंतो एक्सप्रेस कर दिया. इसलिए लालू दोबारा रेल मंत्री बनकर सारी कसर पूरी कर लेना चाहते थे. पर राहुल गांधी की मंशा यह थी कि रेल मंत्रालय जैसा सबसे ज़्यादा जनोपयोगी मंत्रालय उत्तर प्रदेश के हवाले करके वह उसका सियासी फ़ायदा उठा सकें. राहुल ने समझाना भी चाहा, पर लालू अड़ गए तो फिर माने नहीं. बात यहीं बिगड़ गई और राहुल गांधी लालू यादव से इतने नाराज़ हो गए कि उन्होंने उनसे बातचीत भी बंद कर दी. राहुल को लगा कि लालू ने अपनी हरकतों से उनके मिशन 2012 के सपनों के साथ खिलवाड़ किया है. यही वज़ह रही कि राहुल ने बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की कमज़ोर हालत के बारे में जानते हुए भी लालू के साथ गठबंधन नहीं किया. हालांकि रामविलास पासवान ने कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी से अपने अच्छे संबंधों की बदौलत सुलह कराने की कोशिश भी की, लेकिन राहुल नहीं माने. बहरहाल, बिहार विधानसभा चुनाव ने लालू को उनकी औकात बता दी, तब उन्होंने कांग्रेस का हिमायती बनने का मौका तलाशना शुरू कर दिया. जब एफडीआई और लोकपाल के मुद्दे पर कांग्रेस पर चौतरफा वार होने लगे, तब लालू अपने बड़बोलेपन और मसखरेपन से उसकी ढाल बन गए. वह भी तब, जब राहुल गांधी लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे. सोनिया गांधी तो हमेशा से लालू यादव की कायल रही हैं. अब राहुल गांधी को भी लगा कि जिस तरीके से उनकी सरकार आरोपों से घिर रही है, उसमें लालू जैसे व्यक्ति की बेहद ज़रूरत है, चार सांसदों की ताक़त बढ़ेगी, सो अलग.

ख़ैर, फ़िलहाल उत्तर प्रदेश में जो चुनौतियां राहुल गांधी और कांग्रेस के सामने हैं, वे यह हैं कि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी के जो ख़ास सिपहसलार बने हैं बेनी प्रसाद वर्मा और पी एल पुनिया. इन दोनों में बुरी तरह रार ठनी हुई है. बेनी कांग्रेस के लिए पिछड़ों के वोट बैंक का हथियार हैं तो पुनिया दलित वोट बैंक का. वैसे दोनों ही पूरी तरह राहुल के साथ हैं, पर राहुल के लिए इन दोनों को एक साथ साधना दुश्वार हो गया है. एक को मनाओ तो दूजा रूठ जाता है वाली तर्ज़ पर राहुल की रस्साकशी जारी है. बहस इस बात की भी है कि उत्तर प्रदेश में राहुल की जनसभाओं में जो भीड़ इकट्ठा होती है, वह किसकी वज़ह से. कांग्रेस यह मानती है कि यह राहुल गांधी का करिश्मा है, पर बेनी के लोग यह प्रचारित करते हैं कि यह बेनी प्रसाद वर्मा का जोर है. ऐसा नहीं कि बेनी कैंप की इस हरक़त से राहुल गांधी नावाकिफ हैं या कांग्रेसियों में नाराज़गी नहीं, पर बात यहां बेनी समर्थित वोटों की है, जिन्हें राहुल किसी कीमत पर गंवाना नहीं चाहते. खासकर भ्रष्टाचार के मामले में बसपा से निकले गए और सीबीआई जांच के दायरे में आए बाबू सिंह कुशवाहा के भाजपा में शामिल होने के प्रकरण के बाद. दीगर है कि भाजपा दागी कुशवाहा के मामले में अभी तक कोई ठोस फैसला इसीलिए नहीं ले पाई है, क्योंकि उसकी निगाह भी

(शेष पृष्ठ 2 पर)

अगर ऐसा हुआ तो यह समझौता टूट जाएगा

कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच यह तो करार हो गया कि नतीजे आने के बाद बेनी प्रसाद वर्मा को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलेगी और सपा के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव को उप मुख्यमंत्री की, लेकिन यह होगा कैसे, विचार इस पर भी करने की ज़रूरत है. सबसे पहली बात कि यह तभी मुमकिन हो सकेगा, जब कांग्रेस के हक़ में 100 से ज़्यादा सीटें आएंगी. अगर समाजवादी पार्टी को कांग्रेस से ज़्यादा सीटें मिल गईं तो अखिलेश मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनना चाहेंगे और ऐसी स्थिति में क्या कांग्रेस और सपा के बीच का करार कायम रह पाएगा? कांग्रेस ने बेनी प्रसाद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार तो बना दिया, पर बेनी बाबू को वजीर-ए-आला के तौर पर कांग्रेस के पुराने नेता और दूसरे सहयोगी मसलन पी एल पुनिया और रशीद मसूद तभी स्वीकार करेंगे, जब बेनी प्रसाद समर्थित उम्मीदवार सबसे ज़्यादा संख्या में जीतकर आएं. कांग्रेस बेनी प्रसाद को पिछड़ों के दूत के तौर पर प्रचारित कर रही है. दूसरी तरफ पी एल पुनिया कांग्रेस के लिए दलित वोटों के तारणहार बने हैं. मैदान में उनके भी कई उम्मीदवार आजमाइश में लगे हैं. अगर जीत में पुनिया समर्थित उम्मीदवारों की ज़्यादा भागीदारी रही तो क्या वह या उनके समर्थक या फिर उत्तर प्रदेश का दलित तबका यह नहीं चाहेगा कि पुनिया ही सूबे के मुख्यमंत्री बनें. बात यहीं खत्म नहीं होती. उत्तर प्रदेश में रशीद मसूद साहब भी हैं, जिनके उम्मीदवार भी खासी तादाद में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. रशीद मसूद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का मुसलमान चेहरा बनकर उभरे हैं. मान लिया जाए, अगर उनके हिमायती विजयी उम्मीदवारों की संख्या पुनिया और बेनी वर्मा गुट केउम्मीदवारों से ज़्यादा हुई तो फिर क्या रशीद मसूद उत्तर प्रदेश के वजीर-ए-आला नहीं होना चाहेंगे. तब मुसलमानों की ज़बरदस्त हिमायत करने का दावा करने वाली कांग्रेस क्या करेगी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी का क्या रुख़ होगा? चूंकि बेनी वर्मा को भावी मुख्यमंत्री के तौर पर प्रचारित किया जा रहा है, ऐसे में अगर नतीजों के बाद तस्वीर का रुख कुछ और होता है, तब क्या बेनी प्रसाद इतनी आसानी से अपनी दावेदारी छोड़ पाएंगे? ऐसी हालत में कांग्रेस शायद प्रदेश में टूट की कगार पर पहुंच जाए और सपा के साथ हुए करार का कोई मतलब ही न रह जाए. अगर न हुई तो फिर समाजवादी पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशी को मुख्यमंत्री के तौर पर क्यों कबूल करेगी? अगर मुलायम सिंह यादव उप प्रधानमंत्री और बेनी प्रसाद वर्मा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो उन्हें जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि ऐसे हालात पैदा न हों.

महत्वपूर्ण देशों में उच्चायुक्त या राजदूत उन्हें ही बनाया जाता है, जिनका तत्कालीन सरकार से नज़दीकी रिश्ता हो.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

उच्चायुक्तों की कमी

प्रधानमंत्री की व्यस्तता का प्रभाव भारत की विदेश नीति पर भी पड़ रहा है. कई देशों में भारत सरकार अपना राजदूत या उच्चायुक्त नियुक्त नहीं कर पा रही है. इसके पीछे एक कारण तो प्रधानमंत्री की राजनीतिक व्यस्तता बताई जा रही है, क्योंकि वही विदेश मंत्री और विदेश सचिव के साथ मिलकर राजदूत या उच्चायुक्त की नियुक्ति करते हैं. दूसरी वजह यह है कि इसके लिए राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले लोगों की तलाश की जा रही है. महत्वपूर्ण देशों में उच्चायुक्त या राजदूत उन्हें ही बनाया जाता है, जिनका तत्कालीन सरकार से नजदीकी रिश्ता हो. अगस्त 2011 में नलिन सूरी की सेवानिवृत्ति के बाद किसी को ब्रिटेन का उच्चायुक्त नहीं बनाया गया. यही स्थिति बांग्लादेश में है. रंजीत मित्तल गत अक्टूबर में सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन किसी को अभी तक वहां का उच्चायुक्त नहीं बनाया गया है. विदेश मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि विदेश सचिव रंजन मथाई इस बीच कुछ राजदूतों एवं उच्चायुक्तों की नियुक्ति की घोषणा करने वाले हैं. चूंकि 1975 एवं 1976 बैच के कई आईएफएस अधिकारी सेवानिवृत्त होने वाले हैं, इसलिए विदेश मंत्रालय को जल्दी ही दूसरे लोगों को नियुक्त करने की जरूरत पड़ेगी.

वरिष्ठता की अनदेखी

वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की नियुक्तियां एवं स्थानांतरण विवादों से परे नहीं होते हैं. यही स्थिति पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है. राज्य के पुलिस स्थापना बोर्ड, जिसके प्रमुख डीजीपी एन मुखर्जी हैं, में नियुक्ति को लेकर विवाद चल रहा है. 1981 बैच के आईपीएस अधिकारी नजरुल इस्लाम, जो अभी एडीजी रैंक के हैं, ने बोर्ड के पुनर्गठन पर सवाल उठाया है. उनका कहना है कि अभी बोर्ड के कई सदस्य उनसे रैंक में नीचे हैं, इसलिए बोर्ड के पुनर्गठन से पहले इस बात पर विचार किया जाए. सूत्रों के अनुसार, पुलिस स्थापना बोर्ड का गठन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर किया गया है, जिसके अनुसार डीजीपी के अलावा बोर्ड में चार सदस्य होंगे, जो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी होंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार वरिष्ठता का ध्यान नहीं रख रही है.

ईमानदार बाबू की परेशानी

सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता और जिम्मेदारी के लिए शोर मचाया जा रहा है, लेकिन फिर भी आदिवासी क्षेत्रों में होने वाले भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले अधिकारियों के लिए अपना करियर सही तरीके से चलाना मुश्किल होता है. हरियाणा कैडर के वन सेवा के एक अधिकारी संजीव चतुर्वेदी के साथ ऐसा ही होता रहा है. उन्होंने जब वन विभाग के भ्रष्टाचार को उजागर किया तो उन्हें अपने पांच साल के कार्यकाल में बारह बार स्थानांतरण झेलना पड़ा, साथ ही कई आरोपों का भी सामना करना पड़ा. उन्होंने जब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की बात कही तो भी हरियाणा सरकार ने उन्हें जाने नहीं दिया, लेकिन उन्हें खुशी तब हुई, जब हाल में केंद्र में लाए जाने वाले अधिकारियों की सूची में उनका नाम भी शामिल कर लिया गया. यही नहीं, सीबीआई ने यह भी कहा कि वन विभाग की जिन अनियमितताओं का पर्दाफाश संजीव चतुर्वेदी ने किया है, उनकी स्वतंत्र जांच की जानी चाहिए. इसे भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले अधिकारियों के लिए खुशी की बात कही जा सकती है.

dilipcherian@gmail..com

साउथ ब्लॉक

सिब्बल और जोशी संयुक्त सचिव

1986 बैच की आईएएस अधिकारी रजनी शेखरी सिब्बल को पशुपालन विभाग में संयुक्त सचिव बनाया जाएगा. वह डॉ. संजीव रंजन की जगह लेंगी, जो अध्ययन के लिए सिंगापुर गए हैं. इसी तरह 1989 बैच के आईएएस अधिकारी मनोज जोशी को डीओपीटी में संयुक्त सचिव बनाया जाएगा. जोशी वहां राजीव कपूर की जगह लेंगे.

राजकुमार और वी के मीणा निदेशक

1989 बैच के आईडीएसई अधिकारी राजकुमार सिंह को जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन में निदेशक बनाया गया है. इसी तरह 1993 बैच के आईएएस अधिकारी वी के मीणा को शहरी विकास मंत्रालय में निदेशक बनाया गया है. वह मनोज कुमार अग्रवाल की जगह लेंगे.

खेतान डीडीए में सदस्य बने

1987 बैच के आईएएस अधिकारी चितरंजन कुमार खेतान को शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण में सदस्य (वित्त) बनाया गया है. वह नंदलाल की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल दिसंबर 2011 में समाप्त हुआ है.

पुन्हानी और सरिता वित्तीय सलाहकार

1984 बैच की आईए एंड एएस अधिकारी सरोज पुन्हानी को डाक विभाग में संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार बनाया गया है. वह अन्ने मोरेस की जगह लेंगी. इसी तरह सरिता मित्तल को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव एवं और वित्तीय सलाहकार बनाया गया है. वह अजय नारायण की जगह लेंगी, जिन्हें मानव संसाधन विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार बनाया गया है.

किरन कपड़ा मंत्रालय में सचिव

1975 बैच की आईएएस अधिकारी किरन ढींगरा को कपड़ा मंत्रालय में सचिव बनाया गया है. कुछ महीने पहले वह पंचायती राज विभाग में सचिव बनाई गई थीं. कपड़ा मंत्रालय में सचिव का अतिरिक्त प्रभार पी के चौधरी के पास था.

कांग्रेस और मुलायम सिंह में समझौता हो गया

जनता सियासी हवा का रुख भांपने में लगी है कि राजनीतिक पार्टियों के चुनाव पूर्व गठबंधन से क्या जातीय समीकरण बनते हैं. इन जातीय समीकरणों के अलावा विकास और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे भी प्रभावी हो सकते हैं. जुलाहों को पैकेज और क़र्ज़ माफ़ी आदि का दाना डालकर कांग्रेस ने मऊ, आजमगढ़, जौनपुर एवं भदोही वगैरह में फ़ायदा उठाने की कोशिश की है.

पृष्ठ एक का शेष

कुशवाहा के वोट बैंक पर टिकी है. राजनीति में सब कुछ लुटाने के बाद बेनी प्रसाद ने कांग्रेस का हाथ पकड़ा और कांग्रेस ने भी उन्हें सम्मान देते हुए न सिर्फ़ गोंडा से टिकट दिया, बल्कि देवीपाटन की लगभग सात सीटों पर उन्हीं की सलाह से टिकट दिए. बेनी वर्मा खुद तो जीते ही, उन्होंने फैजाबाद, बहराइच, श्रावस्ती, सुल्तानपुर एवं महाराजगंज सीट पर भी कांग्रेस को जीत दिलाई. लाजिमी है कि राहुल गांधी उनके बड़बोलेपन को नज़रअंदाज़ करेंगे और उनका मान-सम्मान भी ऊंचा बनाए रखेंगे. आख़िर सवाल उत्तर प्रदेश की सत्ता हथियाने का है. बेनी वर्मा कांग्रेस के लिए देवरिया, बनारस एवं जौनपुर आदि के कुर्मी बहुल क्षेत्रों की सीटें जीतने में बेहद सहायक साबित होंगे.

वैसे उत्तर प्रदेश में जो सियासी हालात दिख रहे हैं और जो रुझान मिल रहे हैं, उनके मुताबिक, प्रदेश में जिसकी भी सरकार बने, वह बिना भाजपा या कांग्रेस के समर्थन के बनती नहीं दिख रही. अभी तक की चुनावी समीक्षा के मुताबिक़, मायावती सरकार को लेकर आम जनता के बीच न समर्थन का भाव दिख रहा है और न विरोध का. विपक्षी पार्टियां भी मायावती सरकार के ख़िलाफ़ भूमि अधिग्रहण, कानून व्यवस्था एवं भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को सही तरीके से उठाने में नाकाम साबित हुई हैं. अभी तक उत्तर प्रदेश की जनता भी यह तय नहीं कर सकी है कि उसे किस पार्टी को वोट देना है. जनता सियासी हवा का रुख भांपने में लगी है कि राजनीतिक पार्टियों के चुनाव पूर्व गठबंधन से क्या जातीय समीकरण बनते हैं. इन जातीय समीकरणों के अलावा विकास और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे भी प्रभावी हो सकते हैं. जुलाहों को पैकेज और क़र्ज़ माफ़ी आदि का दाना डालकर कांग्रेस ने मऊ, आजमगढ़, जौनपुर एवं भदोही वगैरह में फायदा उठाने की कोशिश की है. इन जिलों में पासी समाज का बाहुल्य है. पिछले लोकसभा चुनाव में मनरेगा कार्ड ने इस इलाके में कांग्रेस को बड़ा वोट बैंक दिया था. इसके अलावा जो रुझान देखने को मिल रहे हैं, उनसे लग रहा है कि इस बार बसपा को ज़बरदस्त नुकसान होने वाला है, जिसका सीधा फायदा दलित वोटों के तौर पर कांग्रेस को होता दिख रहा है. सपा का आंकड़ा 2007 में 97 था, जो इस बार 135 से 140 तक पहुंचने की बात राजनीतिक समीक्षकों द्वारा कही जा रही है. अजित सिंह के साथ का भी फायदा कांग्रेस को मिलेगा. मेरठ, बुलंदशहर, बागपत एवं गाज़ियाबाद आदि इलाकों में कांग्रेस गठबंधन का प्रदर्शन अच्छा हो सकता है.

कांग्रेस ने पहले भी अपने हितों के मुताबिक, विभिन्न दलों से गठबंधन करके भानुमती का कुनबा जोड़ा है. कांग्रेस की सियासी चाल और राजकाज में लगभग डेढ़ दशक से कुछ क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय दल अहम किरदार निभा रहे हैं, जिन्होंने अपनी शर्तों के मुताबिक कांग्रेस से गठजोड़ करके सत्ता का भरपूर लुत्फ़ भी उठाया है, लेकिन जब भी उन्हें लगा कि हम सत्ता संतुलन की धुरी बन गए हैं, तब वे अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए सौदेबाजी और सरकार को डांवाडोल करने से भी बाज नहीं आए. दरअसल उनके सामने यह मसला भी होता है कि उन्हें अपनी प्रासंगिकता बनाए रखनी होती है. लिहाज़ा टकराव शुरू होता है. तब गठबंधन का एक और नया सिलसिला जन्म लेता है. इन्हीं हालात में उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच पनपे इस नए गठजोड़ और सत्ता की सौदेबाजी से क्या युवराज राहुल गांधी को हिंदुस्तान की सल्तनत हासिल हो पाएगी?

लालू यादव इस बात से भी बड़े दुःखी थे कि ममता ने उनके द्वारा शुरू की गई परियोजना ग़रीब रथ का नाम दुरंतो एक्सप्रेस कर दिया. इसलिए लालू दोबारा रेल मंत्री बनकर सारी कसर पूरी कर लेना चाहते थे. पर राहुल गांधी की मंशा यह थी कि रेल मंत्रालय जैसा सबसे ज़्यादा जनोपयोगी मंत्रालय उत्तर प्रदेश के हवाले करके वह उसका सियासी फ़ायदा उठा सकें.

साथ में लखनऊ से अजय कुमार
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 3 अंक 46
दिल्ली, 23 जनवरी–29 जनवरी 2012
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
प्रथम तल, विराट कॉम्प्लेक्स के पीछे, सरदार पटेल पथ, कृष्णा अपार्टमेंट के नज़दीक, बोरिंग रोड, पटना-800013
फोन : 0612 2570092, 9431421901

ब्यूरो चीफ (लखनऊ)
अजय कुमार
जे-3/2 डालीबाग कॉलोनी, हजरतगंज, लखनऊ-226001
फोन : 0522-2204678, 9415005111

प्रबंध संपादक
श्रीनिवास गुप्ता (ठाकुर) (उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड)
सी-20, ट्रांस यमुना, एनएच-2, आगरा
फोन : 0526-4064901, 9837082462

प्रबंध संपादक (महाराष्ट्र)
प्रवीण महाजन
मुरलीधर कॉम्प्लेक्स, बुटीवाडा के सामने होटल गणराज के बाजू में टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर-440012
फोन नं : 0712-2544988, 2549846

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-4783999/011-23418962
0120-6450888, 0120-6452888
0120-6451999
विज्ञापन व प्रसार +91 120-4783999
+91 9266627366
फैक्स न. 0120-2544378

पृष्ठ-16+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड एवं महाराष्ट्र)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

हर बार तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी ने कांग्रेस को पीछे हटने पर मजबूर किया, लेकिन सवाल है कि यह कब तक चलता रहेगा.

संविधान की आत्मा को बचाने के लिए

ममता और नीतीश को आगे आना चाहिए

एक तरफ़ कांग्रेस और भाजपा हैं तो दूसरी तरफ़ ममता एवं नीतीश खड़े हैं. ममता एवं नीतीश जैसे नेता सामाजिक विकास के रास्ते आर्थिक विकास, समानता और बराबरी की राजनीति करते हैं. दूसरी तरफ़ कांग्रेस और भाजपा राजनीति को महज़ सत्ता पाने का ज़रिया समझती हैं. सवाल यह है कि अगर देश में प्रजातंत्र को जीवंत बनाना है तो क्या ममता बनर्जी और नीतीश कुमार जैसे नेता एक साथ मिलकर सामाजिक विकास की राजनीति को मज़बूत करेंगे, संविधान की भावनाओं को सरकारी नीतियों में शामिल करेंगे या फिर कांग्रेस और भाजपा जैसी पार्टियों के साथ मिलकर मूकदर्शक बने रहेंगे?

मनीष कुमार

भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन गडकरी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच थे. अनौपचारिक माहौल था और वह देश और भविष्य पर बातचीत कर रहे थे. अनायास उनके मुंह से एक कड़वा सच निकल गया. उन्होंने कहा कि सरकार किसी की बने, देश की हालत सुधरने वाली नहीं है. जनता को ख़ुद अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा. अगर देश के मुख्य विपक्षी दल के अध्यक्ष ऐसी धारणा रखते हैं तो सचमुच देश का भविष्य ख़तरे में है. यह ख़तरा इसलिए पैदा हुआ है, क्योंकि भारत की राजनीति से विचारधारा का पतन हो गया है. देश की जनता के सामने सिर्फ़ दो विकल्प हैं यूपीए या एनडीए, जिनमें वैचारिक मतभेद न के बराबर हैं. एक की सरकार दूसरे के छोड़े हुए कामों को पूरा करती है. अगर भविष्य में यूपीए की सरकार सत्ता से बाहर जाती है तो एनडीए उन्हीं नीतियों को आगे बढ़ाएगा, जिसे यूपीए ने आधा छोड़ दिया है. यह इसलिए कहा जा सकता है कि क्योंकि भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड हो या फिर एफडीआई का मसला हो, आर्थिक नीति हो या विदेश नीति, लगभग एक जैसी है. सरकार कोई भी होती है, अमेरिका के साथ रिश्ता वैसा ही रहता है. इजरायल से हथियार के सौदे को दोनों ही एक तरह से महत्व देते हैं. इन समानताओं के पीछे की वजह यह है कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही एक–दूसरे की बी टीम बन गई हैं. वैचारिक मतभेद नहीं रह गए हैं, इसलिए लोकसभा और राज्यसभा में बहस नहीं होती, सिर्फ़ हंगामा होता है. इसका सबसे ज़्यादा ख़ामियाजा ऐसी पार्टियों को होता है, जिनकी विचारधारा तो अलग है, लेकिन गठबंधन धर्म का पालन करने की मजबूरी ने उन्हें असरहीन बना दिया है. यही भारत की डेमोक्रेसी के लिए आज सबसे बड़ा ख़तरा है. जबसे देश में नव उदारवाद की नीति लागू की गई, तबसे राजनीति की दशा और दिशा बदल गई. भारत की राजनीति दो धड़ों में बंट गई है. एक तरफ वे खड़े हैं, जो राजनीति को महज़ सत्ता पाने का ज़रिया समझते हैं और दूसरी तरफ वे हैं, जो राजनीति को सामाजिक और आर्थिक विकास का ज़रिया मानते हैं. एक तरफ केंद्र की सरकार है, दूसरी तरफ संविधान की भावना है.

पिछले 20 सालों में केंद्र में जिस किसी गठबंधन की सरकार बनी, उसने संविधान की आत्मा को ही दफना दिया. पता नहीं, देश के कितने मंत्रियों और नेताओं ने संविधान में दिए गए डायरेक्टिव प्रिंसिपल पढ़े होंगे. अगर पढ़े भी होंगे तो भूल गए होंगे. पिछले 20 सालों से देश चलाने वालों के सामने दो रास्ते मौजूद हैं. पहला रास्ता ग़रीबों, पिछड़ों, किसानों और मज़दूरों के विकास के ज़रिए आर्थिक विकास का है और दूसरा रास्ता है देश के उद्योगपतियों और विदेशी कंपनियों को फ़ायदा पहुंचा कर आंकड़ों का मायाजाल बिछाना और विकास का भ्रम फैलाना. अफ़सोस तो इस बात का है कि पिछले 20 सालों से केंद्र की सरकारों ने दूसरा रास्ता अपनाया, विकास का भ्रम ही फैलाया. यही वजह है कि देश में आदिवासियों को उनकी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता है, किसानों के खेत कम क़ीमत में ख़रीद कर बिल्डरों को बेच दिए जाते हैं, कभी एसईजेड तो कभी डैम या न्यूक्लियर पावर प्लांट के नाम पर ग़रीब किसानों को उनकी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता है. सवाल है कि यह विकास का कैसा मॉडल है और इससे किसका विकास होगा? आंकड़े बताते हैं कि पिछले 20 सालों में ग़रीब पहले से ज़्यादा ग़रीब और अमीर पहले से कई गुना ज़्यादा अमीर हो गए हैं. यूपीए और एनडीए की गठबंधन सरकारों ने देश की जनता को यही तोहफ़ा दिया है.

भारत की राजनीति में यह समुद्र मंथन का वक़्त है. एक तरफ इंडस्ट्री को फ़ायदा पहुंचाने वाली केंद्र सरकार है तो दूसरी तरफ किसानों के हक़ के लिए लड़ने वाली बंगाल की दीदी है. एक तरफ जनता के साथ मिलकर ज़मीन पर राजनीति करने और बेदाग़ छवि वाली मास लीडर है तो दूसरी तरफ दिल्ली के मंत्रालयों में मंत्री बने बैठे देश के वकील हैं, जिन्होंने ग़रीबों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, किसानों और मज़दूरों को भुला दिया है. फिर भी वह क्या मजबूरी है कि दोनों साथ–साथ यूपीए गठबंधन में हैं. कांग्रेस गठबंधन की विचारधारा और ममता के तेवरों का अंतर इतना गहरा है कि कभी पेट्रोल के दाम पर, कभी रिटेल में एफडीआई पर, कभी लोकपाल क़ानून या फिर तीस्ता जल बंटवारे के मामले पर, ममता का सामना कांग्रेस पार्टी से हो जाता है. दोनों में इतना मतभेद है कि ममता ने इंदिरा भवन का नाम ही बदल दिया. हर बार तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी ने कांग्रेस को पीछे हटने पर मजबूर किया, लेकिन सवाल है कि यह कब तक चलता रहेगा. अब तो ममता बनर्जी ने उत्तर प्रदेश चुनाव में अकेले उतरने का ऐलान भी कर दिया. तृणमूल और कांग्रेस के बीच खटास यहां तक पहुंच गई है कि दोनों एक–दूसरे को नया सहयोगी तलाशने की नसीहत तक दे रहे हैं. कांग्रेस के प्रदर्शनों और बयानों के जवाब में कोलकाता की सड़क पर तृणमूल समर्थक भी उतर आए. तृणमूल नेताओं ने साफ़ कर दिया कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं है और कांग्रेस चाहे तो गठबंधन से बाहर निकल सकती है. सवाल यह उठता है कि यूपीए गठबंधन में कांग्रेस की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी का ऐसा रुख़ क्यों है?

ममता बनर्जी के सामने कई चुनौतियां हैं. एक तो उन्हें पश्चिम बंगाल का कायाकल्प करना है, लेकिन आज पूरा देश उनकी तरफ देख रहा है. केंद्र सरकार की नीतियां किसी भी मायने में जनता के हक़ में नहीं हैं. लोगों की नज़र में केंद्र सरकार भ्रष्टाचार का केंद्र है. मंत्रियों पर घोटाले करने से लेकर महंगाई बढ़ाने तक के आरोप हैं. जब भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल क़ानून बनाया जाता है तो उसमें ममता बनर्जी से कोई पूछता तक नहीं है और जब वह इसका विरोध करती हैं तो उन्हें कठघरे में खड़ा कर दिया जाता है. जब पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं या जब वह महंगाई को लेकर विरोध करती हैं, तब भी उन्हीं पर यह इल्जाम लगता है कि वह गठबंधन धर्म का पालन नहीं करती हैं. जिन महापुरुषों ने संविधान बनाया, उन्होंने भारत को एक मल्टी पार्टी सिस्टम का रूप दिया. मतलब यह कि अलग–अलग राजनीतिक दलों को जगह दी, ताकि अलग–अलग विचारधाराओं को जगह मिल सके. अब सरकार बजट लाने वाली है. इस बजट की रूपरेखा क्या होगी, यह कौन तय करेगा? मनमोहन सिंह और उनके अर्थशास्त्री मित्रों की टोली, जिनका उद्देश्य उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाना है. अगर सरकार सख्ती के साथ आर्थिक सुधार लागू करती है तो ममता बनर्जी क्या करेंगी? वह गठबंधन धर्म निभाएंगी या फिर जनता के साथ खड़ी होंगी, यह फ़ैसला तो ममता बनर्जी को ही करना है.

हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी वैचारिक एकाधिकार के चंगुल में फंस गई है. कहने मतलब यह कि देश की राजनीति ऐसी राह पर अग्रसर है, जहां सरकार किसी भी पार्टी की बने, लेकिन नीतियां नहीं बदलतीं, सिर्फ़ मंत्रियों के चेहरे बदल जाते हैं. हक़ीक़त यह है कि केंद्र की सत्ता दो ऐसी राजनीतिक धुरियों में सिमट गई है, जिनकी चाल, चरित्र और चेहरे एक जैसे हैं.

हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी वैचारिक एकाधिकार के चंगुल में फंस गई है. कहने मतलब यह कि देश की राजनीति ऐसी राह पर अग्रसर है, जहां सरकार किसी भी पार्टी की बने, लेकिन नीतियां नहीं बदलतीं, सिर्फ़ मंत्रियों के चेहरे बदल जाते हैं. हक़ीक़त यह है कि केंद्र की सत्ता दो ऐसी राजनीतिक धुरियों में सिमट गई है, जिनकी चाल, चरित्र और चेहरे एक जैसे हैं. यही वजह है कि सरकार किसी भी गठबंधन की हो, चाहे वह यूपीए हो या फिर एनडीए, उससे जनता को कोई उम्मीद नहीं है. लेकिन जब हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे नेताओं को देखते हैं तो एक आशा जगती है, एक ईमानदार नेता नज़र आता है, जनता के लिए कुछ करने का जज्बा दिखता है. बिहार में वह परिवर्तन की मिसाल कायम कर रहे हैं, सामाजिक विकास के साथ आर्थिक विकास का नारा बुलंद करते दिखाई देते हैं, हिंदू–मुस्लिम–सिख–ईसाई के बीच भाईचारा बढ़ाने वाले एक नेता नज़र आते हैं. शरद यादव जब संसद में बोलते हैं तो लगता है कि लोकसभा में ऐसा नेता आज भी मौजूद है, जो ग़रीबों की तरफ से बोलता है, जो किसानों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाता है, लेकिन जब केंद्र की सत्ता में उनकी भागीदारी पर नज़र डालते हैं तो मायूसी होती है. दोनों ही नेता जनता दल यूनाइटेड पार्टी के हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन में है. अफसोस इस बात का है कि बिहार के बाहर भारतीय जनता पार्टी के लिए जनता दल यूनाइटेड की कोई अहमियत नहीं है. यही वजह है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में भाजपा–जदयू का बरसों पुराना गठबंधन टूट गया. अजीबोग़रीब स्थिति पैदा हो रही है कि एनडीए के दो बड़े मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी आमने–सामने होंगे. एनडीए गठबंधन भी यूपीए की तरह एक तनाव की स्थिति से गुजर रहा है. वैचारिक मतभेद और एक–दूसरे की पार्टी के नेताओं को नीचा दिखाने का दौर यहां भी जारी है. भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में रहती है तो उसकी आर्थिक नीति कांग्रेस की आर्थिक नीति से अलग नहीं होती. सरकार चलाने का अंदाज कांग्रेस और भाजपा का एक ही जैसा है. सवाल नीतीश कुमार के लिए है कि क्या वह उन नीतियों का समर्थन करेंगे, जिनका विरोध करते रहे हैं.

एक ज़माना था, जब भारतीय जनता पार्टी को हिंदुस्तान की राजनीति में अछूत माना जाता था. ख़ासकर, बाबरी मस्जिद ध्वंस के बाद से तो हर पार्टी उससे दूर ही रही. भारतीय जनता पार्टी के पास आज भी ऐसे नेता नहीं हैं, जो दूसरी पार्टियों से बात करके कोई कारगर गठबंधन बना सकें. वह जब भी केंद्र की सत्ता पर आई, उसने जेडीयू के सहारे गठबंधन तैयार किया और सत्ता पर क़ाबिज़ हुई.

एक ज़माना था, जब भारतीय जनता पार्टी को हिंदुस्तान की राजनीति में अछूत माना जाता था. ख़ासकर, बाबरी मस्जिद ध्वंस के बाद से तो हर पार्टी उससे दूर ही रही. भारतीय जनता पार्टी के पास आज भी ऐसे नेता नहीं हैं, जो दूसरी पार्टियों से बात करके कोई कारगर गठबंधन बना सकें. वह जब भी केंद्र की सत्ता पर आई, उसने जेडीयू के सहारे गठबंधन तैयार किया और सत्ता पर क़ाबिज़ हुई. यही वजह है कि एनडीए गठबंधन के संयोजक हमेशा जनता दल यूनाइटेड के ही नेता रहे. जब पहली बार एनडीए गठबंधन की सरकार बनी थी, तब जार्ज फर्नांडीस साहब ने अहम भूमिका निभाई थी. वह आजकल बीमार हैं, लेकिन उनकी जगह यह भूमिका शरद यादव बखूबी निभा रहे हैं. समस्या यह है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की विचारधारा में ज़मीन–आसमान का फ़र्क़ है. जब सरकार बनती है तो जनता दल यूनाइटेड की विचारधारा कहीं गुम हो जाती है. जिस तरह यूपीए गठबंधन में दूसरी पार्टियों की विचारधारा गौण हो जाती है, वही हाल एनडीए में भी होता है. यूपीए की नीतियों में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दखल नहीं है और एनडीए सरकार में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोई सुनने वाला नहीं है. इसकी वजह साफ़ है कि केंद्र सरकार की सत्ता की चाबी उद्योगपतियों और बड़ी–बड़ी कंपनियों के हाथों में है. जो भी नीतियां बनती हैं, उनमें उनके लाभ को पहले ही सुनिश्चित कर दिया जाता है. बड़ी–बड़ी कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सरकार के नुमाइंदे घोटाला करने से भी नहीं चूकते. अब सवाल यह है कि क्या भविष्य में ऐसी कोई सरकार बन सकती है, जो देश के दलितों, गरीबों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, किसानों एवं मज़दूरों की समस्याओं को प्राथमिकता दे और उसमें ममता बनर्जी और नीतीश कुमार की क्या भूमिका हो सकती है?

ऐसे माहौल में ममता बनर्जी और नीतीश कुमार को देखकर आशा जगती है. दरअसल, इन मास लीडरों का दायित्व बढ़ जाता है. एक तरफ कांग्रेस और भाजपा हैं तो दूसरी तरफ ममता एवं नीतीश खड़े हैं. इनके बीच की लड़ाई आने वाले समय में और भी तेज होगी, क्योंकि ममता एवं नीतीश कुमार जैसे नेता और उनकी राजनीति संविधान में बताए गए मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं. वे सामाजिक विकास के रास्ते आर्थिक विकास, समानता और बराबरी की राजनीति करते हैं. दूसरी तरफ कांग्रेस और भाजपा हैं, जो राजनीति को महज सत्ता पाने का जरिया समझती हैं. सवाल यह है कि अगर देश में प्रजातंत्र को जीवंत बनाना है तो क्या ममता बनर्जी और नीतीश कुमार जैसे नेता एक साथ मिलकर सामाजिक विकास की राजनीति को मज़बूत करेंगे, संविधान की भावनाओं को सरकारी नीतियों में शामिल करेंगे या फिर कांग्रेस और भाजपा जैसी पार्टियों के साथ मिलकर मूकदर्शक बने रहेंगे? ऐसा मौका बार–बार नहीं आता, जब वक़्त आपको इतिहास रचने का मौका देता है. यह वक्त ऐसा है, जो ईमानदार और ज़मीन से जुड़े नेताओं को एक अवसर देता है.

manish@chauthiduniya.com

महज़ साढ़े चार फ़ीसदी अल्पसंख्यक आरक्षण के नाम पर उसने एक ऐसा खेल शुरू किया है, जिसका परिणाम भयानक हो सकता है.

कांग्रेस-भाजपा का कम्युनल कार्ड

इस मुल्क के मुसलमानों के लिए यह वक़्त अब जागने का है. अब दिल नहीं, दिमाग़ से काम करने का वक़्त आ गया है. उन्हें इस सच को स्वीकारना होगा कि वह जमाना गया, जब आस्तीनों में सांप पलते थे. अब ये सांप दोस्त बनकर साथ-साथ चल रहे हैं. उन्हें रहज़नों से तो ख़तरा था ही, अब रहबरों से भी ख़तरा है. आख़िर कौन है उनके दुश्मन और क्या है ख़तरा?

शशि शेखर

उमा भारती कहती हैं कि मुस्लिम आरक्षण इस देश के बंटवारे का रास्ता तय करेगा. मुस्लिम आरक्षण की बात करके कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति कर रही है. ऐसा करके कांग्रेस ने संविधान, क़ानून एवं मर्यादा का उल्लंघन किया है. मुस्लिम आरक्षण इस्लाम के बुनियादी उसूलों के ख़िलाफ़ है, क्योंकि मुस्लिम समाज में जाति प्रथा नहीं है. जाति प्रथा तो हिंदू समाज में है. अब सवाल यह है कि उमा भारती के इस बयान का मतलब क्या है? मतलब बहुत साफ है. अब उत्तर प्रदेश चुनाव को सांप्रदायिकता के हवाले कर दिया गया है. कांग्रेस और भाजपा, दोनों ने अपना-अपना कम्युनल कार्ड खेल दिया है. जो कांग्रेस आरक्षण की बात करके अपनी पीठ थपथपा रही है, वह दरअसल चाहती ही नहीं है कि इस मुल्क के मुसलमानों का भला हो. बार-बार साढ़े चार फ़ीसदी अल्पसंख्यक आरक्षण को मुस्लिम आरक्षण का नाम देकर उसने अपना कम्युनल कार्ड खेला, वहीं इस वजह से भाजपा को भी अपना कम्युनल कार्ड खेलने का मौक़ा दे दिया. अब उत्तर प्रदेश चुनाव में भाजपा जमकर मुसलमानों पर हमला बोलेगी. वह इस बहाने मंदिर, गौ हत्या, रामराज, समान नागरिक संहिता और धारा 370 का अपना पुराना राग भी अलापेगी. अब सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के ज़रिए नफ़रत फैलाने का काम होगा. ज़ाहिर है, इस सबके लिए कांग्रेस भी बराबर की ज़िम्मेदार होगी.

महज़ साढ़े चार फ़ीसदी अल्पसंख्यक आरक्षण के नाम पर उसने एक ऐसा खेल शुरू किया है, जिसका परिणाम भयानक हो सकता है. कांग्रेस को मुसलमानों की वाक़ई फ़िक्र होती तो वह रंगनाथ कमीशन और सच्चर कमेटी की सिफ़ारिशों को ईमानदारी से लागू करती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया. उसने साढ़े चार फ़ीसदी आरक्षण यह कहकर लागू किया कि वह ऐसा रंगनाथ कमीशन की सिफ़ारिश के आधार पर कर रही है. जबकि यह सरासर झूठ है. रंगनाथ कमीशन ने साढ़े चार नहीं, 15 फ़ीसदी या साढ़े 8 फ़ीसदी आरक्षण की सिफारिश की थी. इसके अलावा कमीशन ने मुसलमानों की भलाई के लिए और भी बहुत सारे उपाय बताए थे, जिनमें से शायद ही किसी सिफ़ारिश पर अमल किया गया हो. उल्टे भाजपा को नफ़रत फैलाने का एक मौक़ा दे दिया गया. तभी तो उमा भारती, जिन्होंने शायद ही सच्चर कमेटी एवं रंगनाथ कमीशन की सिफ़ारिशों या संविधान को ईमानदारी से पढ़ा होगा, अल्पसंख्यक आरक्षण को मुल्क के लिए ख़तरा बता रही हैं. उमा भारती को चाहिए था कि वह अपनी पार्टी के अंदर के मुस्लिम साथियों से पूछतीं कि मुस्लिम समाज के धोबी, रंगरेज़, धुनिया, सैफ़ी, अंसारी, नाई एवं मोची की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक हालत क्या है. अगर उमा भारती ने इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश की होती तो शायद ऐसा कुछ बोलने से पहले वह दस बार सोचतीं.

सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि इस पूरे मसले पर मुलायम सिंह एवं मायावती ख़ामोश हैं. मुस्लिम आरक्षण के मसले पर जहां कांग्रेस और भाजपा के बीच तलवारें खिंच गई हैं, वहीं बसपा और सपा ख़ामोश हैं. मुसलमानों को आरक्षण दिए जाने का वायदा उत्तर प्रदेश में सबसे पहले मायावती ने ही किया था और रैलियों में वह दावा कर रही थीं कि उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मुसलमानों को आरक्षण देने की सिफ़ारिश की है, लेकिन अब वह इस मुद्दे पर कुछ बोलने को तैयार नहीं हैं. दूसरी तरफ़ समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव हैं, जो तेज़ी से अपनी तरफ़ आने वाले मुसलमानों को देखकर इस मुद्दे को छेड़ना नहीं चाहते. उन्हें डर है कि उनका कोई बयान मुसलमानों को नाराज़ न कर दे और वे उनसे दूर हो जाएं, लेकिन यह बात भी सही है कि ओबीसी कोटे के अंदर अल्पसंख्यकों के लिए साढ़े चार फ़ीसदी कोटे के ऐलान से मुलायम सिंह ख़ुश नहीं थे, क्योंकि ओबीसी कोटे के अंदर उनकी अपनी यादव बिरादरी भी आती है. फिर भी मुसलमानों को ख़ुश करने के लिए मुलायम सिंह और आज़म ख़ां उत्तर प्रदेश में सत्ता मिलने पर उन्हें 18 फ़ीसदी आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, लेकिन सलमान ख़ुर्शीद ने जब आरक्षण को बढ़ाकर 9 फ़ीसदी करने की बात कही और उस पर बावेला मच गया, तब भी मुलायम सिंह ख़ामोश रहे. यह बात वाक़ई हैरान करती है. उत्तर प्रदेश का मुसलमान इस मसले पर उनकी राय जानना चाहता है, लेकिन वह ख़ामोश हैं. आख़िर क्यों, उनकी इस ख़ामोशी का मतलब क्या है?

shashishekhar@chauthiduniya.com

सोचते नहीं, सिर्फ़ बोलते हैं

कांग्रेस के दिग्विजय सिंह और भारतीय जनता पार्टी की उमा भारती उत्तर प्रदेश के चुनाव में आमने-सामने हैं. दिग्विजय सिंह और उमा भारती के बीच ज़ुबानी जंग जारी है. दोनों के बयानों से चुनाव में सांप्रदायिकता को हवा मिल रही है. उमा भारती मुस्लिम आरक्षण का विरोध करती हैं तो दिग्विजय सिंह बाटला हाउस का मामला उठा रहे हैं. दोनों ऐसे-ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं, जिनसे हिंदू-मुस्लिम भाईचारे को चोट पहुंचती है. सवाल यह है कि दिग्विजय सिंह बाटला हाउस का मामला उठाकर क्या साबित करना चाहते हैं. केंद्र में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस का गृहमंत्री है और उनकी ही पुलिस है, फिर बाटला हाउस मामले के लिए वह किस पर उंगलियां उठा रहे हैं, किसे मुजरिम साबित करना चाहते हैं? दरअसल वह वोट पाने के लिए यह साबित करना चाहते हैं कि कांग्रेस मुसलमानों की हमदर्द है. यही वजह है कि वह आरएसएस, भाजपा या दूसरे विवादास्पद मसलों पर बयान देते हैं. उनसे निपटने का काम भाजपा ने उमा भारती को सौंप दिया है. पार्टी में वापस होते ही उमा भारती ने दिग्विजय सिंह को राहुल गांधी की स्टेपनी बता डाला, आरएसएस के मसले पर दिग्विजय सिंह को यह नसीहत दे डाली कि उन्हें पंडित नेहरू का वह पत्र पढ़ना चाहिए, जिसमें उन्होंने आरएसएस से कश्मीर बचाने की अपील की थी. बहरहाल, इस ज़ुबानी जंग का कुछ नतीजा निकले या न निकले, लेकिन उत्तर प्रदेश चुनाव में सांप्रदायिक तनाव ज़रूर बढ़ रहा है.

बसपा से ग़ायब होते मुस्लिम चेहरे

इन तस्वीरों को ग़ौर से देखिए, यह तस्वीर पांच कालिदास मार्ग लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास की है, जहां कई मौलवी और मौलाना नंगे पैर खड़े हैं, जबकि मायावती ख़ुद चमचमाती क़ीमती सैंडिल पहने हुए हैं. दरअसल कुछ साल पहले बसपा सरकार के कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बुलावे पर ये लोग लखनऊ आए थे, लेकिन मुख्यमंत्री से मिलने के वक़्त इन सभी मौलानाओं को सिक्योरिटी ने अपने जूते-चप्पल उतार कर अंदर जाने को कहा. मायावती का यह बर्ताव इन मौलवियों और मौलानाओं को चुभ गया. मायावती के इस रवैये की मज़म्मत बसपा नेता रहे सिराज मेंहदी ने भी की थी. पिछले विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट हासिल कर मुख्यमंत्री बनीं मायावती ने कई ऐसे काम किए, जो मुसलमानों को बेहद नागवार गुजरे. मसलन, उत्तर प्रदेश में जब सपा या भाजपा की सरकार थी, तब रमजान के दौरान मुख्यमंत्री की ओर से इफ्तार पार्टी दी जाती थी, लेकिन मायावती ने उसे बंद कर दिया. इसके अलावा भाजपा और सपा की सरकारों में जब जनता दरबार लगता था तो उसमें कई मुस्लिम चेहरे नज़र आते थे, लेकिन बसपा सरकार में लगने वाले जनता दरबार में दाढ़ी और टोपी वाले मौलाना-मौलवी नज़र नहीं आते. कुछ लोग अगर आते भी हैं तो उन्हें नसीमुद्दीन सिद्दीकी के पास भेज दिया जाता है. इससे ज़ाहिर होता है कि मुस्लिम वोट हासिल कर उत्तर प्रदेश में हुकूमत करने वाली मायावती ने किस तरह मुसलमानों को नज़रअंदाज़ किया. मायावती ने मुसलमानों से जुड़े सभी मसलों की ज़िम्मेदारी अपने मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी को सौंप दी.

पिछले चुनाव में बसपा के लिए जीने-मरने की कसमें खाने वाले मुस्लिम नेताओं को भी मायावती ने चुन-चुनकर बाहर का रास्ता दिखाया. जहां पहले क़रीब दर्जन भर मुस्लिम नेता थे, वहीं पांच साल में उनकी तादाद महज़ तीन या चार रह गई है. मेरठ से हाज़ी याकूब कुरैशी, बिजनौर से शाहनवाज़ राणा, बाराबंकी से फ़रीद महफूज किदवई, बरेली से सहजिल इस्लाम, मुरादाबाद से अकबर हुसैन, बदायूं से मोहम्मद मुस्लिम ख़ान, रामपुर से नवाब काज़िम अली ख़ान और पीलीभीत से अनीस ख़ान आदि वे विधायक हैं, जो कल तक मायावती और उनकी पार्टी बसपा के ख़ास चेहरे हुआ करते थे. इन मुस्लिम नेताओं ने 2007 के चुनाव में मायावती की सरकार बनाने में अहम किरदार निभाया था. लिहाज़ा बसपा को मुस्लिम मतदाताओं का पूरा साथ मिला. यही वजह थी कि बसपा ने राज्य के कई मुस्लिम बहुल इलाक़ों में कामयाबी हासिल की. उसके 61 मुस्लिम उम्मीदवारों में से 30 ने जीत का परचम लहराया था, लेकिन अगले महीने होने जा रहे विधानसभा चुनाव में राज्य के मुस्लिम मतदाता अगर बसपा को ख़ारिज कर दें तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि उसके दिग्गज मुस्लिम नेताओं ने उसका साथ छोड़ दिया है.

ज़्यादातर नेताओं को मायावती ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया तो कईयों ने अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ दी. जिन लोगों को बसपा से निकाला गया, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं. फ़िलहाल मायावती के दरबार में तीन मुस्लिम चेहरे बचे हैं, जिनमें बांदा से विधायक एवं बसपा सरकार में कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी, राज्यसभा सदस्य मुनकाद अली और हरदोई से विधायक अब्दुल मन्नान शामिल हैं. बसपा से निकाले गए नेताओं का आरोप है कि नसीमुद्दीन पर भ्रष्टाचार के कई मामले चल रहे हैं, लेकिन मायावती सरकार में उन्हें कोई ख़तरा नहीं है. इससे साबित होता है कि मायावती ने किस कदर मुसलमानों के जज़्बातों को चोट पहुंचाई है. अब जबकि अगले महीने विधानसभा चुनाव हैं, सभी पार्टियों की कोशिश है कि वे अधिक से अधिक मुस्लिम वोट अपने पक्ष में कर सकें. सत्तारूढ़ बसपा पांच साल पहले इस मामले में कहीं अच्छी हालत में थी. उसके पास कई मुस्लिम चेहरे थे, लेकिन अब उनकी संख्या महज़ गिनती में रह गई है. ऐसे में इस बार मुसलमानों का वोट बसपा के पक्ष में जाए, इसकी संभावना कम है.

अभिषेक रंजन सिंह
arsingh@chauthiduniya.com

समाजवाद को ठेंगा दिखाकर कांग्रेसी रंग में रंगने वाले नेताओं के आगे जीवन भर कांग्रेस का झंडा उठाने वाले हाशिए पर पहुंचा दिए गए हैं.

सबके दुलारे दाग़ी, दलबदलू और धन्ना सेठ

यह लोकतंत्र की सियासी गाथा का स्याह पक्ष है, जहां दाग को अच्छा माना जाता है. निष्ठा जहां पैसे के आगे दम तोड़ देती है. ईमानदारी जहां बाहुबल के आगे हार जाती है. यह चुनावी समर है. जहां सब कुछ जायज़ है, बशर्ते आप ईमानदार न हों, साफ छवि के न हों. यहां जनता हारती है, जीतता है सिर्फ़ पैसा और पावर. क्या है उत्तर प्रदेश के चुनावी महासमर की हक़ीक़त. पढ़िए इस रिपोर्ट में.

अजय कुमार

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए ताल ठोंक रहे किसी भी दल को दलबदलुओं और दागियों से परहेज नहीं है. इनके सहारे कोई साइकिल पंक्चर करना चाहता है तो कोई पंजा मरोड़ना. कोई हाथी की मदमस्त चाल को मंद करने की फिराक में है तो कोई कीचड़ में खोलने वाले कमल को कीचड़ में ही मिलाने की व्यूह रचना कर रहा है. इस सबके बीच जनता बेचारी तमाशबीन बनी बैठी है. जनता इन सबके दागदार दामन से वाक़िफ़ है, लेकिन वह क्या करे. उसे तो कम दाग या ज़्यादा दाग वालों में से ही किसी एक को चुनना है. यह जनता की मजबूरी है और शायद नासमझी भी. बहरहाल, इस सबके लिए सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार कोई है तो वे हैं राजनीतिक दल. दागियों और दलबदल के खेल में जुटे विभिन्न राजनीतिक दलों में से एक भाजपा ने हाल में बसपा से निकाले गए उसके कुछ दागी दिग्गज नेताओं को अपने यहां शरण देकर एक नई बहस को जन्म दे दिया है. इसके लिए भाजपा की आलोचना भी हो रही है, लेकिन उसे अपनी चाल, चरित्र और चेहरे से अधिक चिंता जिताऊ प्रत्याशियों को लेकर है. भाजपा के इस क़दम का सिर्फ़ पार्टी से बाहर ही विरोध नहीं हो रहा है, बल्कि आरएसएस और पार्टी के कुछ नेताओं को भी यह सब रास नहीं आ रहा है. यह और बात है कि वे फ़िलहाल मुंह खोलने से कतरा रहे हैं. भाजपा ने दागियों को न केवल पार्टी में शामिल किया, बल्कि उनमें से कई को विधानसभा के लिए टिकट भी थमा दिया. ऐसा किसके इशारे पर हुआ, यह एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है. दलबदल के इस खेल में हाथ आजमाने के बाद पार्टी में मंथन का भी दौर शुरू हो गया है.

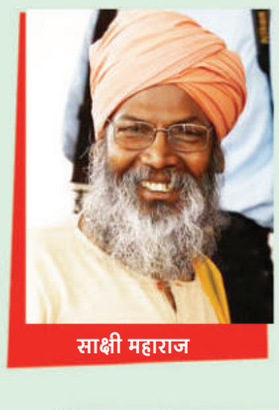

साक्षी महाराज

दद्दन मिश्र

अमरमणि त्रिपाठी

गुड्डू पंडित

बादशाह सिंह

भले ही आज भाजपा दागियों को पार्टी में शामिल करने से कठघरे में खड़ी हो गई हो, लेकिन साफ-सुथरी राजनीति और चुनाव सुधारों से सरोकार रखने वाली स्वयंसेवी संस्था नेशनल इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक़, बीते माह के अंत तक उत्तर प्रदेश में भाजपा ने बीस, कांग्रेस ने छब्बीस और समाजवादी पार्टी ने चौबीस ऐसे लोगों को टिकट दिए हैं, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है. बसपा भले ही अबकी बार दागियों और अपराधियों को टिकट देने से परहेज कर रही हो, लेकिन 2007 के विधानसभा चुनाव में उसने भी दागियों को फलने-फूलने का ख़ूब मौक़ा दिया था. भ्रष्टाचार और राजनीति के अपराधीकरण के मुद्दे पर राजनीतिक दलों की कथनी और करनी में काफी अंतर है. जहां तक बात दलबदलुओं की है, उनकी तो सभी दलों में चांदी है. खासकर चुनाव के समय तो दलबदल का मौसम ही आ जाता है. आज जो नेतागण दलबदल को लेकर भाजपा पर उंगली उठा रहे हैं, उनमें भी कई नेता अनेक बार दलबदल कर चुके हैं. अगर कांग्रेस की बात करें तो दलबदल को लेकर उसने भाजपा पर ज़बरदस्त हमला बोल रखा है, बिना यह परवाह किए कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस में इस समय दलबदलुओं का ही दबदबा है. राहुल के मिशन 2012 को पूरा करने का ज़िम्मा भी यही दलबदलू संभाले हुए हैं. परंपरागत कांग्रेसी हाशिए पर हैं या फिर हाईकमान के रवैये से क्षुब्ध होकर घर बैठ गए हैं. कांग्रेस हाईकमान को भी पुराने कांग्रेसियों से ज़्यादा भरोसा उन नेताओं पर है, जो दूसरे दलों से आए हैं.

नरेश अग्रवाल

प्रदेश कांग्रेस की बागडोर सपा छोड़कर आई डॉ. रीता बहुगुणा जोशी के हाथों में है. सपा से ही आए बेनी प्रसाद वर्मा को इस चुनाव में सबसे ज़्यादा तवज्जो मिल रही है. कहा तो यह भी जा रहा है कि अगर बिल्ली के भाग्य से छीका टूट गया तो बेनी बाबू उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं. बेनी की तरह राजबब्बर भी सपा से आकर कांग्रेस को मज़बूत कर रहे हैं. राजबब्बर भी बेनी की तरह अमर सिंह से खटपट होने के बाद कांग्रेस में शामिल हुए थे. अब वह हाईकमान के सबसे भरोसेमंदों में गिने जाते हैं. वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव अभियान रशीद मसूद की अगुवाई में चलाने के संकेत हैं. हाल में सपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए रशीद मसूद को तो पार्टी की सबसे ताक़तवर कमेटी कांग्रेस कार्यसमिति में ले लिया गया है. राहुल के मिशन 2012 को पूरा करने के लिए जिन नेताओं के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव मैदान में उतरने जा रही है, उनमें परंपरागत कांग्रेसियों के बजाय समाजवादी पार्टी से आए नेताओं की संख्या कहीं अधिक है. कांग्रेस में उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक दलबदलुओं का ही सिक्का चल रहा है. कई सीटों पर पुराने कांग्रेसियों को दरकिनार कर बेनी की सिफारिश पर दूसरे दलों से आए लोगों को टिकट दिए गए. इसी प्रकार बसपा से कांग्रेस में लौटे पूर्व एमएलसी सिराज मेंहदी को मीडिया कोऑर्डिनेटर बनाया गया है. बसपा छोड़कर आए पूर्व सांसद बलिहारी बाबू पर भी कांग्रेस हाईकमान मेहरबान है.

समाजवाद को ठेंगा दिखाकर कांग्रेसी रंग में रंगने वाले नेताओं के आगे जीवन भर कांग्रेस का झंडा उठाने वाले हाशिए पर पहुंचा दिए गए हैं. पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह मुन्ना, कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य रहे हरिकेश बहादुर, पूर्व विधायक भूधर नारायण मिश्र, नेक चंद्र पांडेय, राजेश पति त्रिपाठी, सुबोध श्रीवास्तव, डॉ. संतोष सिंह, रत्नाकर पांडेय, चंद्रभान मणि त्रिपाठी, जयराम गौतम, प्रियदर्शी जेटली एवं अनुसूइया शर्मा जैसे दर्जनों नेता किनारे कर दिए गए हैं. खीरी से कई बार विधायक रहे तेज नारायण त्रिवेदी तो पार्टी छोड़कर चले गए. दागियों, अपराधियों एवं भ्रष्टाचारियों को शामिल करके सत्ता पाने का सपना संजोए भाजपा के बारे में तो जितना भी कहा जाए, कम है. उस पर भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी कहते हैं, भाजपा गंगा है, जिसमें नालों का पानी भी गंगाजल बन जाता है. आम लोगों से लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं तक को यह भरोसा नहीं हो पा रहा था कि बसपा, सपा और कांग्रेस को दागियों की पनाहगाह बताते न थकने वाले नेताओं ने उन्हीं बाबू सिंह कुशवाहा को पार्टी में ले लिया, जिन्हें एनआरएचएम घोटाले में मुख्य भूमिका निभाने वाला बताते हुए मंत्रिमंडल से न केवल बर्खास्त करने की मांग भाजपा ने उठाई थी, बल्कि जेल भेजने की मांग भी की थी. जो कुशवाहा छह महीने से लगातार भाजपा की भ्रष्टाचार विरोधी समिति के अध्यक्ष किरीट सोमैया के निशाने पर थे, वह अब पार्टी में शामिल हैं.

राजनीति के अपराधीकरण के लिए सपा, बसपा एवं कांग्रेस को कोसने वाली भाजपा में इधर शामिल हुए और पद-प्रतिष्ठा से नवाजे गए लोगों पर नज़र डालें तो पता चलता है कि केवल दलबदलुओं को ही प्रत्याशी नहीं बनाया गया, बल्कि उन प्रेम नारायण पांडेय को तरबगंज से उम्मीदवार बना दिया गया, जिन पर भाजपा कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न का आरोप है. भाजपा की तीसरी सूची में साक्षी महाराज का भी नाम है. वह अक्टूबर में जनस्वाभिमान यात्रा के दौरान भाजपा में शामिल हुए थे. साक्षी पर उन्हीं के आश्रम में रहने वाली विद्या भारती ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था. इसी प्रकार दलबदलू पूर्व विधायक शशिबाला पुंडीर, अजय सिंह पोईया, पूर्व विधायक समरपाल एवं अनिल यादव भी भाजपा का टिकट पाने में सफल रहे. बसपा छोड़कर आए बाबू सिंह कुशवाहा, दद्दन मिश्रा, बादशाह सिंह एवं अवधेश वर्मा से भाजपा को क्या फ़ायदा होगा? इस सवाल का जवाब तलाशा गया तो पता चला कि भाजपा दरअसल पिछड़ा कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है. अवधेश वर्मा और दद्दन मिश्रा तो टिकट भी पा गए हैं.

सपा भी इससे अछूती नहीं है. सपा में दागियों और दलबदलुओं की संख्या अच्छी-खासी है. हद तो तब हो गई, जब बलात्कार और अपहरण के एक मामले को लेकर चर्चा में आने के बाद बसपा से निकाले गए विधायक गुड्डू पंडित को सपा में शामिल कर लिया गया. गुड्डू पंडित जब तक बसपा में रहे, तब तक समाजवादी पार्टी उनके नश्तर चुभोती रही. आज की तारीख़ में वह सपा की तरफ़ से चुनावी मैदान में हैं. नरेश अग्रवाल जो वैश्यों का नेता होने का दंभ भरते हैं, वह भी सपा में पाला बदल कर आ गए हैं. नरेश अग्रवाल, उनके विधायक पुत्र नितिन अग्रवाल, कई बार भाजपा के टिकट से चुनाव जीते गोमती यादव (लखनऊ), लोकदल के पूर्व मंत्री कुतबुद्दीन अंसारी (नूरपुर), बसपा के हाजी गुलाम मोहम्मद (सिवालखास), लोकदल के बदरुल हसन (सिकंदराबाद), सुनील सिंह (स्याना), बसपा की राजेश्वरी देवी (सांडी) एवं महेश वर्मा (औरैया) पाला बदल कर आए थे, उन्हें टिकट देने में सपा नेतृत्व को कोई संकोच नहीं हुआ. इसी प्रकार राष्ट्रीय लोकदल में भी दलबदलुओं का सिक्का चल रहा है. करतार सिंह, सपा से आए अशरफ अली ख़ान, पंडित उमेश सैथिंया, अमित यादव, बासित अली एवं हाजी याकूब क़ुरैशी राष्ट्रीय लोकदल की शोभा बढ़ा रहे हैं.

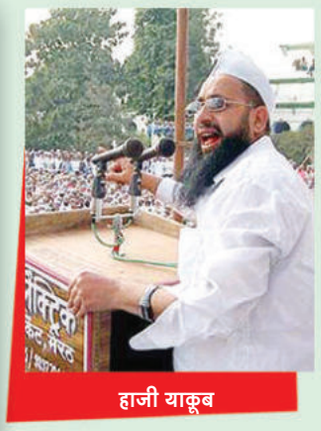

हाजी याकूब

कितने दाग़ी, कितने धन्ना सेठ

एक नज़र 2007 यानी मौजूदा विधानसभा के सदस्यों की चाल, चरित्र और चेहरे पर. 73 विधायकों के ख़िलाफ़ संगीन मामले लंबित हैं. संगीन मामलों से मतलब है हत्या, हत्या की कोशिश या फिरौती के लिए अपहरण. इनमें सबसे ज़्यादा बसपा के 34, सपा के 16, भाजपा के 8, कांग्रेस के 4, आरएलडी के 4 और 7 अन्य शामिल हैं. प्रतिशत के हिसाब से देखें तो सबसे आगे आरएलडी है. उसके दस में से 4 विधायकों के ख़िलाफ़ संगीन मामले हैं. फिर नंबर आता है कांग्रेस, बसपा और सपा का. 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 293 ऐसे निर्वाचन क्षेत्र थे, जहां कम से कम एक दागी उम्मीदवार मैदान में था. 148 क्षेत्रों में एक दागी उम्मीदवार था, वहां जनता ने साफ-सुथरी छवि वाले 94 उम्मीदवारों को चुना यानी 64 फ़ीसदी अच्छे उम्मीदवार चुने गए. 48 ऐसे क्षेत्र थे, जहां 3 दागी उम्मीदवार थे, वहां साफ-सुथरी छवि वाले सिर्फ़ 11 उम्मीदवार ही चुने जा सके, जबकि 37 दागी उम्मीदवार जीतकर आए. 6 ऐसे क्षेत्र थे, जहां 4 दागी उम्मीदवार लड़ रहे थे, वहां सभी दागी चुनाव जीत गए. यानी जिन क्षेत्रों में कम दागी थे, वहां साफ छवि के लोग जीते और जहां दागियों की संख्या ज़्यादा थी, वहां दागी उम्मीदवार चुनाव जीते. ज़ाहिर है, मतदाताओं के पास अच्छे विकल्प हों तो अच्छे उम्मीदवार ही चुनकर आएंगे. वहीं इस बीमारू प्रदेश के विधायकों की आर्थिक स्थिति ज़बरदस्त रूप से सेहतमंद है. 2007 के विधानसभा चुनाव में 125 करोड़पति विधायक चुनकर आए. लगभग 32 फ़ीसदी करोड़पति विधायक. इनमें सबसे ज़्यादा सत्तारूढ़ दल यानी बसपा के 51, सपा के 37, भाजपा के 15, कांग्रेस के 8 और आरएलडी के 5 विधायक शामिल हैं. अगर राज्य के सभी विधायकों की बात की जाए तो प्रत्येक की औसत संपत्ति 1.14 करोड़ रुपये है.

शशि शेखर
shashishekhar@chauthiduniya.com

feedback@chauthiduniya.com

आश्चर्य की बात यह है कि उक्रांद के दोनों प्रत्याशी अपनी पार्टी के निशान पर नहीं, बल्कि भाजपा के निशान पर चुनाव लड़ेंगे.

सिर्फ़ उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहे चुनाव

पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन ताज्जुब की बात है कि मीडिया में सबसे ज़्यादा ख़बरें सिर्फ़ उत्तर प्रदेश से ही आ रही हैं. मानों मणिपुर या गोवा देश के लोगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है. तो आइए जानते हैं कि मणिपुर, गोवा, पंजाब और उत्तराखंड में क्या चल रहा है, यहां के मसले क्या है, यहां के राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं और यहां के चुनाव देश की राजनीति को कैसे प्रभावित करेंगे.

वर्ष 1961 तक गोवा पुर्तगाली शासन के अधीन था. पुर्तगालियों के जाने के बाद यहां के पहले मुख्यमंत्री बने महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के दयानंद बांदोदकर. वर्तमान में दिगंबर कामत यहां के 19वें मुख्यमंत्री हैं. आगामी 3 मार्च को होने वाले चुनाव में यहां की जनता अपना 20वां मुख्यमंत्री चुनेगी. राज्य में क़रीब 10 लाख पंजीकृत मतदाता हैं, जो 40 विधायकों का भाग्य तय करेंगे. यहां एक चरण के चुनाव के लिए 6 फरवरी को अधिसूचना जारी होगी. नामांकन की आख़िरी तारीख़ 13 फरवरी और नाम वापस लेने की आख़िरी तारीख़ 16 फरवरी. वर्तमान विधानसभा में कांग्रेस की 16, भाजपा की 14, एनसीपी की 3, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी की 2, सेव गोवा फ्रंट की 2, यूनाइटेड गोवन्स डेमोक्रेटिक पार्टी की एक और 2 सीटें अन्य के पास हैं. इस चुनाव में अवैध खनन एक अहम सियासी मुद्दा बन सकता है. राज्य सरकार ने भी बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष माना कि सूबे में अवैध खनन हो रहा है. एक आंकड़े के मुताबिक़, गोवा में 6000 करोड़ टन लौह अयस्क का अवैध खनन किया गया. गोवा विधानसभा की लोक लेखा समिति यानी पीएसी ने 3,500 करोड़ रुपये के खनन घोटाले की बात कही है. हालांकि अवैध खनन से जुड़ा एक और अहम मसला है, जिसकी वजह से हज़ारों ग़ैर गोवा वासी गोवा में रह रहे हैं, जो अवैध खनन के काम से जुड़े हुए हैं. उनका कहना है कि अगर खनन रुक गया तो उनकी रोजी-रोटी छिन जाएगी.

अपराधों में बढ़ोत्तरी भी एक अहम मसला है. खासकर, गोवा पर्यटन के लिए चिंता का एक विषय है. ब्रिटिश युवती स्कारलेट का मर्डर, एक जर्मन युवती के साथ बलात्कार जैसी घटनाओं ने गोवा की क़ानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं. स्कारलेट मामले में तो गोवा के गृह मंत्री रवि नाईक के बेटे का भी नाम आया था. बहरहाल, यहां मुख्य मुक़ाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच है, लेकिन कई क्षेत्रीय दल भी हैं, जो कांग्रेस और भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं. यूनाइटेड गोवन्स डेमोक्रेटिक पार्टी, सेव गोवा फ्रंट और गोवा विकास पार्टी आपस में गठबंधन कर सकते हैं. इसके अलावा एक और क्षेत्रीय दल इस चुनाव में कूद रहा है, गोवा सुराज पार्टी. कांग्रेस जहां एनसीपी के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी, वहीं भाजपा महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के साथ गठबंधन करने की कोशिश में है. बहरहाल, बनते-बिगड़ते सियासी समीकरण के बीच कांग्रेस अपनी सत्ता बचाने की जुगत में है तो भाजपा सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है.

मणिपुर के लोगों को आतंकवाद और तीन माह तक चली आर्थिक नाकेबंदी के दौरान लोगों को पेट्रोल, रसोई गैस और दवा जैसी आवश्यक वस्तुओं का घोर अभाव झेलना पड़ा था. यहां के चुनाव से जुड़ा एक और दिलचस्प पहलू राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को लेकर है. प्रदेश की राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी न के बराबर है. पिछले इलेक्शन में महज एक महिला लांधोनी देवी, जो मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह पत्नी है, वही चुनाव जीत सकी थी. इस बार कांग्रेस ने 60 सीटों में महज तीन टिकट ही महिलाओं को दिया है, जिसमें एक बार फिर इबोबी सिंह की पत्नी हैं. वहीं एमपीपी(मणिपुर पीपुल्स पार्टी) ने एक भी महिला को टिकट नहीं दिया है. भाजपा ने सिर्फ एक टिकट पर महिला उम्मीदवार को खड़ा किया है. सियासत में महिलाओं केलिए आरक्षण की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी का चरित्र भी खुलकर सामने आ गया है. बहरहाल मणिपुर में गठबंधन की जो तस्वीर सामने आई है, उसमें जनता दल यूनाइटेड एमपीपी के साथ चुनावी मैदान में है. ख़ास बात यह है कि इसमें एनसीपी और सीपीएम भी शामिल हैं. वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का भी एमपीपी के साथ गठबंधन में शामिल होने से यह चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है. मणिपुर में कांग्रेस सरकार के ख़िलाफ़ बनी ग़ैर कांग्रेसी गठबंधन निश्चित तौर से कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है. वैसे मणिपुर के पिछले चुनाव नतीजों पर नज़र डालें तो यहां भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी. हालांकि, इस बार भाजपा नेताओं को उम्मीद है कि उन्हें इस बार कई सीटों पर कामयाबी मिलेगी. वैसे देखा जाए तो मणिपुर केतराई क्षेत्र में वैष्णव संप्रदाय केमैतई बहुल इलाकेमें भाजपा केहिंदुत्व का असर ज्यादा है. वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी मैतई समुदाय के पांच जातियों को दलित जातियों का दर्जा देकर उन्हें लुभाने की कोशिश की है. इस बीच उग्रपंथियों ने पहाड़ी इलाकेमें कांग्रेस उम्मीदवार को न घुसने देने और प्रचार न करने देने का ऐलान किया है. इससे कांग्रेस नेताओं में खौफ पैदा हो गया है. वहीं विपक्ष इसका फायदा उठाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती.

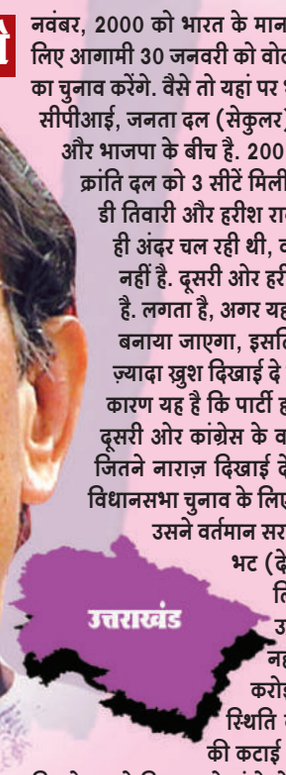

नौ नवंबर, 2000 को भारत के मानचित्र पर 27वें राज्य के रूप में उभरने वाले उत्तराखंड में विधानसभा की 70 सीटों के लिए आगामी 30 जनवरी को वोट डाले जाएंगे, जिसमें राज्य के 58 लाख 87 हज़ार 765 मतदाता अपने सातवें मुख्यमंत्री का चुनाव करेंगे. वैसे तो यहां पर भाजपा, कांग्रेस, बसपा एवं उत्तराखंड क्रांति दल के अलावा समाजवादी पार्टी, सीपीएम, सीपीआई, जनता दल (सेकुलर), लोक जनशक्ति पार्टी जैसी दर्जनों पार्टियां मैदान में हैं, लेकिन सीधा मुक़ाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच है. 2007 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 34, कांग्रेस को 21, बसपा को 8 और उत्तराखंड क्रांति दल को 3 सीटें मिली थीं, शेष पार्टियां अपना खाता खोलने में नाकाम रही थीं. कांग्रेस के दो बड़े नेताओं एन डी तिवारी और हरीश रावत के बीच पार्टी में अपना वर्चस्व क़ायम करने को लेकर जो लड़ाई काफ़ी दिनों से अंदर ही अंदर चल रही थी, वह अब सामने आने लगी है. आजकल पार्टी में एन डी तिवारी की बात सुनने वाला कोई नहीं है. दूसरी ओर हरीश रावत को हर टीवी चैनल पर कांग्रेस की ओर से बोलते हुए देखा जा सकता है. लगता है, अगर यहां कांग्रेस जीतकर आई तो शायद हरीश रावत को ही राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इसलिए प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होने के बाद हरीश रावत सबसे ज़्यादा ख़ुश दिखाई दे रहे हैं, जबकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष यशपाल आर्य मुरझाए हुए हैं. कारण यह है कि पार्टी हाईकमान ने सूची में रावत के चहेतों को प्राथमिकता दी है. दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एन डी तिवारी पहले जितने नाराज़ दिखाई दे रहे थे, अब उतने नाराज़ नहीं हैं. भाजपा ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए अपने 68 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है. दो सीटें उसने वर्तमान सरकार में शामिल उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं दिवाकर भट (देव प्रयाग) और ओम गोपाल रावत (नरेंद्र नगर) के लिए छोड़ दी हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उक्रांद के दोनों प्रत्याशी अपनी पार्टी के निशान पर नहीं, बल्कि भाजपा के निशान पर चुनाव लड़ेंगे. एक करोड़ से अधिक आबादी वाले उत्तराखंड की वर्तमान स्थिति बताती है कि यहां पर सबसे बड़ी समस्या वनों की कटाई और तेज़ी से हाइड्रो इलेक्ट्रो डैमों का निर्माण है, जिसके चलते हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं और उन्हें निचले क्षेत्रों में पलायन के लिए विवश किया जा रहा है.

यहां मतदाताओं की संख्या 1.74 करोड़ है, जिनमें 30 प्रतिशत दलित हैं. यहां 117 सीटों के लिए आगामी 30 जनवरी से चुनाव होने जा रहे हैं. नामांकन पत्र दाख़िल करने की आख़िरी तारीख़ 12 जनवरी है और नाम वापस लेने की आख़िरी तारीख़ 16 जनवरी. यहां 19,724 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. चुनाव में हिस्सा लेने वाली पार्टियों में कांग्रेस, भाजपा, बसपा, सीपीआई, सीपीआई (एम), शिरोमणि अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल (लोंगोवाल) और पीपुल्स पार्टी ऑफ पंजाब आदि प्रमुख हैं. यहां मुख्य मुक़ाबला अकाली दल-भाजपा गठबंधन और कांग्रेस के बीच है. पिछले चुनाव में अकाली दल ने 49 सीटें हासिल की थीं, जबकि उसकी सहयोगी पार्टी भाजपा को 19 सीटें मिली थीं. कांग्रेस को 44 और आज़ाद उम्मीदवारों को 5 सीटें मिली थीं. पंजाब में किसानों की संख्या सर्वाधिक है. इसलिए हर पार्टी उन्हें लुभाने की कोशिश करती है. पिछले चुनाव में अकाली दल ने पॉवर टू फार्मर का नारा दिया था, लेकिन उसकी तरफ़ सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया. यहां आलू की पैदावार बड़ी तादाद में होती है, लेकिन सरकार की ग़लत नीतियों की वजह से अक्सर आलू की फ़सल बर्बाद हो जाती है. पंजाब में तक़रीबन 8 लाख रिटायर्ड फौजी हैं, लेकिन कोई भी सरकार उनके लिए कुछ नहीं करती है. इसलिए फौजियों की नुमाइंदगी करने वाले 16 संगठनों ने फ़ैसला किया है कि वे चुनाव का बहिष्कार करेंगे.

कमर तबरेज/अभिषेक रंजन सिंह
feedback@chauthiduniya.com

मेरी दुनिया.... असली क़ाबिलियत

एक्सट्रीम अरेस्ट प्रोसिजर और गन डिसइंगेजमेंट हर पुलिसवाले को आनी चाहिए, ताकि एक लाठी के साथ या निहत्था भी पुलिस वाला अपराधी को अरेस्ट कर सके.

देश का पहला शाउलिन वॉरियर कनिष्क शर्मा

अपनी रक्षा अपने हाथ

मिलिट्री ट्रेनिंग

रीतिका सोनाली

भारत के इतिहास में 26/11 का दर्दनाक हादसा काले अक्षरों में दर्ज है. पूरा देश इस आतंकवादी हमले का साक्षी रहा है. हमले की शुरुआत से लेकर वीरों को गंवाने तक देशवासियों, सेना, पुलिस और सरकार ने केवल अफ़सोस ही जताया है. हादसे ने कई मांओं के कलेजे के टुकड़ों को छीना, कई पिताओं की आंख के तारे तोड़ दिए, कई पत्नियों की मांग सूनी कर दी. उन हमलावरों को सबक़ सिखाने के लिए हमने क्या किया? आधुनिक हथियारों से लैस कसाब जैसे आतंकवादी को पकड़ने के लिए फ़ौजियों की टीम को लाठियों के साथ घटनास्थल पर भेजा गया. परिणाम सामने है, तुकाराम जैसे वीर देशभक्त हमारे बीच नहीं हैं. आतंकवादी हमलों की धमकियों से देश अब भी थर्रा उठता है. हमने तुकाराम और उन जैसे दूसरे देशभक्त सिपाहियों को खोया न होता, अगर उनकी ट्रेनिंग में कमी न होती. यह कहना है देश के पहले शाउलिन वॉरियर कनिष्क शर्मा का. दरअसल, हम सबमें ख़ुद को किसी भी स्थिति में बचा पाने की ताक़त होती है. महत्वपूर्ण है उसकी जानकारी और उसका इस्तेमाल. शाउलिन एक मार्शल आर्ट है, जिसका मूलमंत्र है सरवाइवल यानी किसी भी स्थिति में अपनी सुरक्षा और बचाव. सिल्क रूट का हिस्सा शाउलिन चीन के कई प्राचीन मठों में एक कुंग फू मठ है, जिसे छठी शताब्दी में हिंदुस्तानी बौद्ध धर्मगुरु बातुनी ने शुरू किया था. छठी शताब्दी के अंत में एक और बौद्ध धर्मगुरु बौद्धिधर्मा भारत से शाउलिन मठ गए और उन्होंने शाउलिन मार्शल आर्ट बनाकर कुछ शिष्यों को सिखाया. जब चीन के राजा टैंग को तेरह शाउलिन शिष्यों ने लाठी के सहारे बचाया, तबसे शाउलिन शिष्यों को वॉरियर कहा जाने लगा. इस ऐतिहासिक कहानी को प्रस्तुत करते हुए जेटली की एक बहुत प्रसिद्ध फिल्म आई थी शाउलिन टेंपल द थर्टिन मंक सेव द टैंग एम्पेरर. एक और फिल्म आई 36 चेंबर्स ऑफ शाउलिन टेंपल, जिसे देखकर कनिष्क को बचपन में ही शाउलिन सीखने की इच्छा हुई और शाउलिन सीखने का सपना देखते हुए उन्होंने बचपन से ही भारत में उपलब्ध मार्शल आर्ट जैसे ताइक्वांडो, कुंग फू तुआ, कराटे इत्यादि सीखा और 2000 में एमबीए करने के बाद रिलायंस कंपनी की नौकरी छोड़कर चीन के शाउलिन मठ चले गए. छह साल की तपस्या के बाद कनिष्क 31वें जेनरेशन शाउलिन वॉरियर बनकर भारत वापस आए. बचपन से शर्मीले कनिष्क नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और उत्साह के साथ वतन लौटे और शाउलिन में रुचि रखने वाले लोगों को ट्रेनिंग देने लगे.

कमांडोज और मिलिट्री के पास वक़्त की कमी का ध्यान रखते हुए उन्हें पीकिडी टरसिया काली का क्लोज्ड क्वार्टर कॉमबैट सिस्टम सिखाया जाता है. इसमें फास्ट स्टंट करते हैं, जिससे दुश्मन को पता भी नहीं चलता कि कब उस पर वार हो जाता है और व्यक्ति किसी भी वार से बच जाता है. कॉमबैट मतलब काउंटर ऑन मोशन बिफोर अटैक टाइम यानी दुश्मन की तरफ़ से होने वाले प्रथम वार से पहले ही उसे गिरा देना. पीकिडी अन्य मार्शल आर्ट्स से अलग है, क्योंकि इसमें ऐसे तरीक़े सिखाए जाते हैं, जिससे ख़ुद को बचाने में अपनी क्षति नहीं होती, जबकि अन्य मार्शल आर्ट्स में ख़ुद को चोट पहुंच सकती है. ऐसी ही चीज़ों का एक सेगमेंट बनाकर कनिष्क ने मिक्स ऑफ नाइफ बनाया है, जिसमें वह अन्य मार्शल आर्ट में चाकूऔर दूसरे हथियारों से लड़ने के लिए सिखाए गए तरीक़ों में ख़ामियां बताते हैं. इसकी जगह वह पीकिडी टरसिया का नाइफ ट्रैपिंग ड्रिल सिखाते हैं. इसमें सामने वाले के चाकू के मूवमेंट का ध्यान रखते हुए उसे रोकते हुए ख़ुद को बचाना होता है. कमांडो को सिखाने वाले पीकिडी टरसिया में एक फिटनेस रेजीम कनिष्क ने ख़ुद जोड़ा है, जो जिम्नास्टिक से जुड़ा है. इसमें फुर्तीले तरीक़े से चक्कर खाते हुए दुश्मन के किसी भी वार से बचने की ट्रेनिंग दी जाती है. एक और सेगमेंट ग्रेनियन फुटवर्क स्ट्रेटजी है, जिससे दुश्मन के किसी भी वार से सिर्फ़ शारीरिक मूवमेंट के ज़रिये बचा जा सकता है. मिलिट्री फोर्सेस को दुश्मन को मार गिराने की पूरी आज़ादी होती है, इसलिए इसमें हथियार का इस्तेमाल जायज़ है. पीकिडी में इस्तेमाल होने वाले हथियार भी ख़ास हैं, जैसे गिनंगटिंग, यह तलवारनुमा हथियार फिलीपींस में फोर्स रेकॉन मरीन अलक़ायदा के ख़िलाफ़ लड़ने में इस्तेमाल करते हैं. आजकल की लड़ाई साइकलॉजिकल है, इसमें जान लेने से ज़्यादा डर फैलाया जाता है, जिससे ख़तरा ज़्यादा महसूस होता है. इसलिए इसके हथियार भी बेहद ख़तरनाक दिखने वाले हैं. वीपन ट्रांसफर टेकनोलॉजी सिस्टम भी केवल पीकिडी में है, जिसकी ख़ास बात यह है कि ख़ुद को बचाने वाले जो भी स्टंट बंदूक़ के साथ करते हैं, वहीं चाकू या किसी अन्य हथियार के साथ भी कर सकते हैं. अक्सर दुश्मन लड़ते हुए गिरा देता है, ऐसे में उसके हाथ-पैर लॉक कर सकते हैं. इसे ग्राउंड फाइटिंग कहते हैं. नर्व ब्रेकिंग सिस्टम में केवल हाथ से ही लड़ते हुए गर्दन और दूसरी जगहों की हड्डियों-पसलियों को तोड़ सकते हैं या अंधा कर सकते हैं. काउंटर री काउंटर ही पीकिडी का मुख्य अंश है. इससे आप कम वक़्त में एक से ज़्यादा व्यक्तियों से लड़ने में सक्षम होते हैं. मिलिट्री में अरेस्ट प्रोसिजर भी सिखाते हैं.

पीकिडी टरसीया काली

कनिष्क ने शाउलिन के साथ फिलीपींस का पीकिडीटरसीया काली भी सीखा है. यह मार्शल आर्ट फिलीपींस का सिस्टम है, जो फोर्थ रेकॉन मरीन और फिलिपिनो नेशनल कमांडो फॉलो करते हैं. पीकिडी यानी बंद, टरसिया मतलब क्वार्टर और काली मतलब तीन सेकेंड में व्यक्ति को जान से मार डालना. इसमें शरीर में मौजूद नसों के ज़रिये जान ली जाती है. इसमें क्लोज क्वार्टर और एक्ट्रीम क्लोज क्वार्टर स्टंट का इस्तेमाल होता है. पिछले तीस सालों से साठ देशों में अलग-अलग काउंटर टेरेरिस्ट फोर्स द्वारा इसे फॉलो किया जा रहा है. यह वह सिस्टम है, जिसने इतिहास में अकेले तीन-तीन लड़ाइयां जीती हैं. फिलीपींस को स्पेन, जापान और अमेरिका ने रूल किया और फिलीपींस ने इन सबसे ख़ुद को आज़ाद कराया, पीकिडी टरसीया काली सिस्टम का इस्तेमाल करके. भारत में कनिष्क इस फिलीपींस मार्शल आर्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो अलग-अलग काउंटर टेरेरिस्ट फोर्सेस को 2008 से ट्रेनिंग दे रहे हैं. कनिष्क मार्शल आर्ट के ज़रिये पुलिस और सैन्यबलों के अलावा दूसरे सभी सुरक्षाबलों को मज़बूत करने का लक्ष्य रखते हैं. कम से कम पचास ऐसे तरीक़े हैं, जिनसे आप निहत्थे भी ख़ुद को बचाते हुए सामने वाले को मार गिरा सकते हैं. वह सैन्य-सुरक्षाबलों, आम नागरिकों और पुलिस को अलग-अलग तरह की ट्रेनिंग देते हैं.

वुमेन सेल्फ डिफेंस

एक्जीक्यूटिव्स की तरह महिलाओं को एलीमेंट ऑफ एस्केप और सराउंडिंग अवेयरनेस सिखाया जाता है. इसमें विपन ऑफ अपॉरचुनिटी के तहत कंघी, हेयरपिन, क्लिप, नाख़ून, सैंडिल जैसी चीज़ें आम महिलाओं और पेनड्राइव, मोबाइल फोन, सन ग्लासेस, क्रेडिट कार्ड, लैपटॉप इत्यादि महिला प्रोफेशनल्स के हथियार होते हैं. यह भी कॉमबैट सरवाइवल प्रोग्राम है, जिसमें कुछ ख़ास फास्ट मूवमेंट स्टंट हैं. यह टेकनीक ईजी, एफेक्टिव और इकोनॉमिकल सिद्धांतों पर आधारित है. इसमें शाउलिन मार्शल आर्ट से एडॉप्ट कर मेडिटेशन और अपने अंदर की सोई हुई ऊर्जा जागृत करने का तरीक़ा सिखाया जाता है.

पुलिस कुंग फू

जनता के बीच जाने वाले पुलिसकर्मियों को कनिष्क पुलिस कुंग फू मार्शल आर्ट सिखाते हैं, जिसे वह क्रैडलिंग कहते हैं. क्रेडल सिस्टम मतलब कि आदमी को चोट पहुंचाए बिना और बग़ैर हथकड़ी के अरेस्ट करना. इस सिस्टम में यह करने के पचास से भी अधिक तरीक़े हैं. इस सिस्टम में शाउलिन से चीन ना यानी छीनने की कला और काली से डिफेंग द स्नेक सिस्टम लिया गया है. इसके अलावा व्हीकल एक्सट्रैक्शन सिस्टम भी सिखाया जाता है. व्हीकल एक्सट्रैक्शन का एक ख़ास तरीक़ा है, जिसमें सामने वाले के ख़तरनाक हथियार के वार से बचते हुए उसे अरेस्ट किया जा सकता है. कनिष्क कहते हैं कि अगर कसाब को पकड़ने गई टीम को इस तकनीक की जानकारी होती तो शायद आज वे हमारे बीच होते. इस तकनीक को बिना जाने किसी को भी ऐसी ख़तरनाक सिचुएशन में नहीं आना चाहिए. विपेन ऑफ अपॉरचुनिटी भी एक तरीक़ा है, जिसमें आपके पास हथियार न हो और दुश्मन के पास कितना भी ख़तरनाक हथियार हो, तो ऐसे में उसके हथियार को अपने पाले में लिया जा सकता है. ऐसे दस हज़ार तरीक़े हैं, जिनमें निहत्थे होकर भी ख़ुद को बचाया जा सकता है. यह सिस्टम किसी भी बैरियर को काटना सिखाता है. पुलिस में लॉकिंग सिस्टम और पुलिस डिफेंसिव टैक्टिक्स होते हैं, जिसमें अपराधी को ढूंढकर उसे अरेस्ट करना सिखाया जाता है और तीसरा सिस्टम है रायट कंट्रोल, जिसमें बिना किसी तरह की चोट पहुंचाए भीड़ को तितर-बितर कर स्थिति कंट्रोल में की जा सकती है. शरीर के किसी भी प्रेशर प्वाइंट को दबाकर दंगे में सक्रिय या धरने पर बैठे व्यक्ति पर क़ाबू पाया जा सकता है. पुलिस को वह पैरिंग भी सिखाते हैं, जिसमें निहत्थे रहकर भी बलपूर्वक सामने वाले को धराशायी कर अरेस्ट करते हैं. सिर्फ़ हथियार के वार से ख़ुद को बचाते हुए अपराधी को अरेस्ट कर और हथियार को अपने पाले में ले लेना इसका उद्देश्य है. एक्सट्रीम अरेस्ट प्रोसिजर और गन डिसइंगेजमेंट हर पुलिसवाले को आनी चाहिए, ताकि एक लाठी के साथ या निहत्था भी पुलिस वाला अपराधी को अरेस्ट कर सके. एडवांस नाइफ टेकनीक्स में डिगासो टरसिया का इस्तेमाल भी करते हैं, जिसमें किसी भी चीज़ का इस्तेमाल हथियार के तौर पर किया जा सकता है, मसलन पेन, लाठी, टॉर्च इत्यादि. कमांडो और पुलिस के अलावा कनिष्क प्रोफेशनल एक्जीक्यूटिव्स, महिलाओं, बच्चों और बॉलीवुड की चर्चित हस्तियों को भी ट्रेनिंग देते हैं.

बॉलीवुड कनेक्शन

आपने फिल्म डॉन में प्रियंका चोपड़ा को स्टंट परफॉर्म करते हुए चेन से शाहरुख़ ख़ान को औंधे मुंह गिराते हुए देखा होगा. प्रियंका की ये कातिल अदाएं कनिष्क शर्मा की ट्रेनिंग का नतीजा थीं. सिर्फ प्रियंका ही नहीं, शाहरुख़ ख़ान, बोमन ईरानी और अर्जुन रामपाल को भी ख़तरनाक स्टंट करते देख आप हैरान हुए होंगे. कनिष्क शर्मा ने ही इन्हें शाउलिन जैसी ख़ास मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी थी. इसके अलावा फिल्म गेम में अभिषेक बच्चन के स्टंट भी कनिष्क ने ही कोरियोग्राफ किए हैं. फिल्म गोल में हवा में उड़कर छल्ले की तरह घूमते हुए गोलपोस्ट पर आख़िरी गोल करके जॉन अब्राहम की टीम को जिताने वाले कनिष्क ही थे. कई हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों की स्टंट कोरियोग्राफी कनिष्क के नाम है. आगे भी कई फिल्मों की स्टंट कोरियाग्राफी के ऑफर हैं.

एक्जीक्यूटिव रिस्क कंट्रोल स्ट्रेटजी

कंप्यूटर इंजीनियर माइकल रास्ते से गुज़रते हुए पीछा कर रहे व्यक्ति पर भी ध्यान दे रहे थे. माइकल अपनी कार तक पहुंचते, इससे पहले ही गुंडे ने उन पर हमला कर दिया. हाथ में पड़े मैग्जीन रोल को घुमाते हुए उन्होंने काउंटर किया तो गुंडा औंधे मुंह सड़क पर गिर पड़ा और माइकल भाग निकले. दरअसल सतर्कता ही इस प्रोग्राम की ख़ासियत है. इस प्रोग्राम की ट्रेनिंग लेकर सड़क पर होने वाले किसी भी ख़तरे से बचा जा सकता है. उन चीज़ों की मदद से, जो एक एक्जीक्यूटिव अपने साथ रखता है, जैसे पेनड्राइव, मोबाइल फोन, सन ग्लासेस, क्रेडिट कार्ड, लैपटॉप इत्यादि. उन्हें ही व्यक्ति हथियार के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकता है. इसे विपन ऑफ अपॉरचुनिटी कहते हैं. यह कॉमबैट सरवाइवल प्रोग्राम है, जिसमें कुछ ख़ास फास्ट मूवमेंट स्टंट हैं. इसके लिए शरीर को ज़्यादा ताक़तवर बनाने के बजाय दिमाग़ को हालात से लड़ने के लिए तैयार करने की ज़रूरत है. इसमें अपने सराउंडिंग्स को लेकर अवेयर रहना एक एटीट्यूट बन जाता है. जिम में 4 से 5 घंटे पसीना बहाकर व्यक्ति सड़क पर सरवाइव करना नहीं सीख सकता. आप दुनिया के बेस्ट फाइटर हो सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास एलीमेंट ऑफ एस्केप यानी बच निकलने का मूलमंत्र न हो तो आप बच नहीं सकते. इस प्रोग्राम में कनिष्क ने अपने 26 सालों की मेहनत का निचोड़ दिया है, जिसमें बताया जाता है कि 3 सेकेंड में व्यक्ति ख़ुद को कैसे बचा सकता है. इस प्रोग्राम को सीखने में 25-30 दिन लगते हैं.

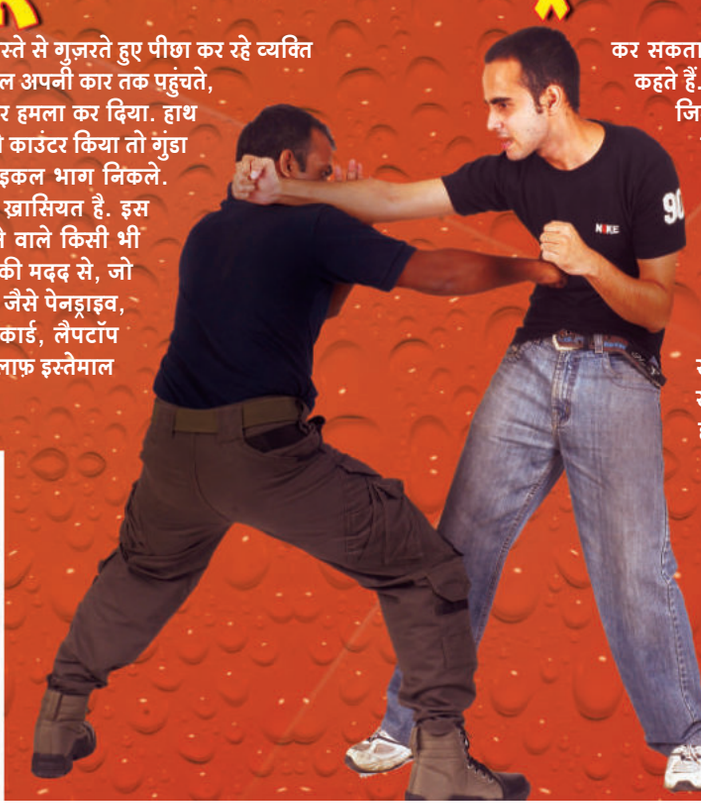

ritika@chauthiduniya.com

सौभाग्यवश भारत के गांवों में अभी तक पूंजीवादी प्रथा का ज़हर इतना नहीं फैला है. अभी भी गांव का बढ़ई, लोहार या मोची अपने-अपने पेशे के संपूर्ण काम ख़ुद कर लेते हैं या अपने परिवार द्वारा ही करवाते हैं.

महावीर प्रसाद आर मोरारका

मनुष्य का यंत्रीकरण

पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ने आदमी को एक तरह से मशीन बना दिया है. उदाहरण के लिए घर में काम आने वाली सुइयां या कीलें आज से 200 वर्ष पहले ग्राम का कोई लोहार बनाता था. उसके बनाने में जो साजो-सामान लगता था, उसको प्राप्त करने से लेकर तैयार सुई या कील घर- घर जाकर बेचकर पैसा इकट्ठा करने तक का सारा काम वह स्वयं या उसका परिवार कर लेता था. अगर सूक्ष्म दृष्टि से अध्ययन किया जाए, तो पता लगेगा कि कच्चा सामान प्राप्त करने से लेकर सुई या कील बेचने तक के काम में लगभग 18 विधियां काम में लाई जाती हैं. सुई या कील बनाने, उस पर पालिश आदि करने में ही एक दर्जन से ज़्यादा विधियां करनी पड़ती हैं. उस वक़्त ये तमाम विधियां वह एक व्यक्ति ही करता था. बाद में उत्पादन बढ़ाने के हेतु को लक्ष्य में रखकर काम का बंटवारा इस ढंग से हो गया कि वे 18 विधियां 1 आदमी न करके प्रत्येक विधि को 1-1 आदमी करे. इस तरह से कुल 18 आदमी सारे काम को करें. निश्चित ही है, जब एक आदमी एक ही काम करता रहेगा तो उसका हाथ उस काम पर रवां हो जाएगा और उस काम का उत्पादन बहुत जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा. परिणामस्वरूप सुइयों और कीलों का उत्पादन तो दस गुने से भी ज़्यादा बढ़ गया, पर हर एक व्यक्ति को प्रत्येक काम की जानकारी न रही, वे सिर्फ़ एकांगी ज्ञाता ही रहे.

इन्हीं सब अलग स्तरों पर काम करने वालों को व्यवस्थित करने वाला पूंजीवादी अपने मुनाफ़े का ध्यान रखकर यह खयाल रखता है कि सब अपना-अपना एकांगी काम ज़्यादा से ज़्यादा दक्षता से करें. कालांतर में हाड़-मांस की मशीन यानी मानव के बदले स्वचालित बिजली की मशीनें काम करने लग गईं. अत: सिर्फ़ एक-दो आदमियों से ही सुइयों और कीलों का उत्पादन होने लगा. यही बात सूती या ऊनी कपड़ा बुनने में भी लागू समझिए. एक जमाना था, जब जुलाहों के परिवार भेड़ से ऊन कतरने से लगाकर कपड़ा, कंबल इत्यादि बनाकर बेचने तक का काम करते थे. आज के युग में यह सब काम एक व्यक्ति या एक परिवार कर ही नहीं सकता. परिणाम यह हुआ कि मानव की ज्ञान राशियों में धीरे-धीरे कमी हुई और संपत्ति धीरे-धीरे उत्पादन बढ़ने से, बढ़ी. यही खास अवगुण पूंजीवादी व्यवस्था में है. मानव को मशीन बना दिया गया है. उसकी ज्ञान राशियों को संकुचित बना दिया गया है.

धनिकों या समृद्धों की असहाय अवस्था और भी अधिक दयनीय है. अगर आज उन्हें नौकर नहीं मिले तो वे नहीं जानते कि कैसे क्या होगा? वे अपने कपड़े तक नहीं पहन सकते, जब तक सारा साजो-सामान सामने न रख दिया जाए, अपने हाथ-मुंह स्वयं धोने में भी वे हिचकते हैं. आदतें ही उनकी ऐसी पड़ी हुई हैं कि प्रत्येक काम के लिए वे सेवकों पर ही निर्भर रहते हैं. इस अर्थव्यवस्था ने उन्हें इतना अधिक पराधीन बना दिया है कि वे एकदम असहाय-पंगु हो गए हैं.

पराश्रय (पराधीनता)

पूंजीवादी दलील यह है कि अगर मानव एक काम ही करता है तो उसे दिन में थोड़े घंटे काम करने के बाद बाक़ी का समय फ़ुर्सत का मिल जाता है. उस वक़्त वह अपना मनोरंजन कर सकता है. अगर सारे काम का अथ से इति तक उत्तरदायित्व उसी का रहेगा तो उसे कभी भी अवकाश नहीं मिल पाएगा. इसलिए वह मनोरंजन नहीं कर पाएगा. लोगों को मनोरंजन आदि के लिए अवकाश या फ़ुर्सत मिले, इसमें किसी को जरा भी ऐतराज नहीं. शायद हर व्यक्ति के लिए अवकाश या मनोरंजन उतना ही आवश्यक है, जितना काम. शिकायत सिर्फ़ इतनी ही है कि काम का ढर्रा जिस ढंग का पूंजीवादी व्यवस्था में बन गया है, उससे व्यक्ति एक-दूसरे पर इतना ज़्यादा आश्रित हो गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप में कोई काम करने योग्य ही नहीं रह पाता. एक कसब का पूरा जानकार कोई व्यक्ति शायद ही मिले.

सौभाग्यवश भारत के गांवों में अभी तक पूंजीवादी प्रथा का ज़हर इतना नहीं फैला है. अभी भी गांव का बढ़ई, लोहार या मोची अपने-अपने पेशे के संपूर्ण काम ख़ुद कर लेते हैं या अपने परिवार द्वारा ही करवाते हैं. शहरों में यह स्थिति बिल्कुल ही नहीं रही. शहर का बढ़ई या मोची बिल्कुल पराधीन है. जब तक आरे से चीरी हुई लकड़ी नहीं मिलेगी या टेनरी से कमाया हुआ चमड़ा नहीं आएगा, तब तक उनके पास कोई काम नहीं होगा और बाद में भी जिस काम को करने के लिए वे नियत हैं, उससे आगे या पीछे क्या करना होगा, इसकी जरा भी जानकारी उन्हें नहीं है. यह पराधीनता ग़रीबों या श्रमिकों तक ही सीमित हो, ऐसी बात नहीं. घरेलू कामकाज में भी यही हाल है. अगर रसोइया न आया तो या तो होटल का द्वार देखा जाता है या फाके-मस्ती की नौबत आ जाती है.

धनिकों या समृद्धों की असहाय अवस्था और भी अधिक दयनीय है. अगर आज उन्हें नौकर नहीं मिले तो वे नहीं जानते कि कैसे क्या होगा? वे अपने कपड़े तक नहीं पहन सकते, जब तक सारा साजो-सामान सामने न रख दिया जाए, अपने हाथ-मुंह स्वयं धोने में भी वे हिचकते हैं. आदतें ही उनकी ऐसी पड़ी हुई हैं कि प्रत्येक काम के लिए वे सेवकों पर ही निर्भर रहते हैं. इस अर्थव्यवस्था ने उन्हें इतना अधिक पराधीन बना दिया है कि वे एकदम असहाय-पंगु हो गए हैं. घरेलू कामकाज करने वाले एक नौकर या रसोइए को कोई काम न मिले तो भूखों मरने की नौबत आ जाएगी. उसे दूसरे किसी धंधे या रोज़गार का तो ज्ञान है नहीं. जिस काम का वह जानकार है, वह उसे मिलता नहीं है तो स्थिति दूभर ही होगी. पर उससे भी बुरी दशा उन मालिकों की होगी, जिन्हें कोई सेवक नहीं मिलता. वे अपना व्यक्तिगत कार्य भी कर नहीं सकते. हमेशा दूसरों से ही काम करवाने के वे आदी हैं.

कहने का तात्पर्य यही है कि इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक फल यह भी होता है कि आदमी अपने आप एक-दूसरे का दास हो जाता है, असहाय और पराधीन हो जाता है. इस पराधीनता की बेड़ी को तोड़ने में उसका जी घबराता है. चाहे वह मालिक वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे नौकर वर्ग का, समान वित्त वितरण चाहते हुए भी, जो चली आ रही अर्थव्यवस्था है, उसे बदलने में सभी घबड़ाहट अनुभव करते हैं. कारण है परवशता. नतीजा यह है कि एक तरफ़ तो पूंजीपति, जिनके पास ज़मीन जायदाद और पूंजी है, अपने आप कुछ नहीं कर सकते, पराधीन हैं. दूसरी ओर सेवक, नौकर, मज़दूर या किसान अपने आप कुछ नहीं कर सकते, वे भी पराधीन हैं, मजबूर हैं.

feedback@chauthiduniya.com

महावीर प्रसाद आर मोरारका का जन्म 12 अगस्त, 1919 को नवलगढ़ (झुंझनू) राजस्थान में हुआ था. उद्योगपति, स्वप्नदृष्टा और लेखक से कहीं अधिक वह उदात्त मानवीय मूल्यों के संवाहक थे. उनकी गणना भारत के प्रमुख उद्योगपतियों में की जाती है.

कमल मोरारका का ब्लॉग

www.kamalmorarka.com

राजनीति में नैतिकता बहुत ज़रूरी

पिछले साल देश भ्रष्टाचार और विदेश में रखे काले धन की चर्चा में व्यस्त रहा. कुछ मंत्री जेल गए और अन्ना हज़ारे ने भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आंदोलन शुरू किया. हालांकि भ्रष्टाचार एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है, देश में रोज़गार के अवसरों का अभाव. 1991 के आर्थिक सुधारों से पहले हमारी प्राथमिकता ग़रीबों को सस्ते दामों में अनाज उपलब्ध कराना, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से रोज़गार के अवसर बढ़ाना और कृषि क्षेत्र को सब्सिडी देना, ताकि अनाजों की कमी को दूर किया जा सके, आदि रही थी. देश का विकास बहुत तीव्र नहीं था, लेकिन धीमा और स्थायी ज़रूर था. 1991 के बाद आर्थिक विकास बहुत सालों तक बढ़ता रहा और इस साल सात फीसदी आर्थिक विकास दर को कम माना जा रहा है, क्योंकि उम्मीद 9-10 फीसदी की थी. हालांकि सात फीसदी विकास दर को हास्यास्पद नहीं कहा जा सकता, क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों की आर्थिक विकास दर अभी भी 3-4 फीसदी के बीच है.

भारत जिस समस्या का सामना कर रहा है, वह है सात फीसदी विकास दर. रोज़गार के अवसर पैदा नहीं किए जा रहे हैं. किसानों को बेदखल करके सरकार ने जो भूमि अधिग्रहण किया है, वह भी रोज़गार पैदा करने में असफल रहा है. व्यवसायी वर्ग इस बात के लिए शोर मचा रहा है कि रिटेल सेक्टर एवं अन्य क्षेत्रों में एफडीआई पर सरकार फ़ैसला ले. सरकार न केवल कॉरपोरेट सेक्टर, बल्कि पूरे देश के प्रति जिम्मेदार है. सरकार का काम केवल नफ़ा-नुकसान के बारे में सोचना नहीं हो सकता है, जबकि हमारे देश में छोटे दुकानदारों की संख्या अत्यधिक है. पश्चिमी देशों के लिए भारत का मतलब एक बड़ा बाज़ार है, जहां के बाज़ारों का दोहन करके मुनाफ़ा कमाया जा सकता है. लेकिन सरकार का काम तो हर तबके की समस्या को देखना है, न कि किसी एक तबके की समस्या का ध्यान रखना. सरकार के लिए तो भारत एक अरब से अधिक लोगों का भारत है.

आज के समय में सबसे प्रमुख संकट नैतिकता का है. स्वतंत्रता संग्राम के समय लोगों की आमदनी कम थी और वे महात्मा गांधी का साथ देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ देते थे. इससे उनका व्यक्तिगत नुकसान होता था. सभी लोगों में एक तरह का जोश होता था. आज शायद ही कोई अपने सफल व्यवसाय या नौकरी को छोड़कर राजनीति में जाएगा या जनहित के काम करने के लिए आगे बढ़ेगा. इसी का नतीजा है कि आज राजनीति में सक्रिय लोगों का मुख्य व्यवसाय राजनीति ही है, दूसरा कुछ नहीं. लोकपाल बनाकर भी अन्ना हज़ारे सफल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वास्तविक ताकत और अधिकार तो यहां राजनेताओं के पास है, जिन्हें लोगों का प्रतिनिधि कहा जाता है. जब तक राजनेताओं के नैतिक स्तर में बढ़ोत्तरी नहीं होगी, तब तक हमारे पास दोयम दर्जे की ही सरकार होगी.

पश्चिमी देशों में भी भ्रष्टाचार है, लेकिन वहां का आम आदमी उससे ज़्यादा प्रभावित नहीं होता. वहां पुलिस लोगों से पैसे नहीं वसूलती, वहां लोगों को अस्पताल, अदालत आदि में अपना काम कराने के लिए पैसे नहीं देने पड़ते. वहां भ्रष्टाचार ऊपर के स्तर पर है, लेकिन भारत में स्थिति अलग तरह की है. यहां भ्रष्टाचार चरम पर है, जिसका लाभ राजनेता एवं व्यवसायी दोनों को होता है. भ्रष्टाचार के भुक्तभोगी यहां रहने वाले आम लोग हैं, जिनसे पैसा वसूला जाता है. अगर कोई व्यक्ति सही काम भी करता है तो उसे उसके लिए रिश्वत देनी पड़ती है. मनमोहन सिंह व्यक्तिगत जीवन में बहुत ईमानदार आदमी हैं. इस समय वह निश्चित तौर पर भ्रष्ट मंत्रियों, भटके हुए कॉरपोरेट सेक्टर के ख़िलाफ़ कड़ा रुख़ अपनाए हुए हैं. उन्हें अधिकारियों के प्रति भी यही रुख अपनाना चाहिए, ताकि आम लोगों को कुछ राहत मिल सके.

feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

सर्वश्रेष्ठ पत्र

एक अनुरोध

बक्सर 20 गांवों वाला एक अविकसित इलाक़ा है. 50 हज़ार से अधिक आबादी वाले इस इलाक़े में स्वास्थ्य एवं परिवहन जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी है. तीन बरसाती नदियों से घिरा यह क्षेत्र प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार है. यहां की सिर्फ़ दो प्रतिशत लड़कियां ही मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त कर पाई हैं. यहां जन सहयोग से एक स्कूल खोला गया, लेकिन वह भी अफ़सरशाही का शिकार बन गया. मैं एक अवकाशप्राप्त शिक्षक हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि इस इलाक़े की समस्याओं को अपने अख़बार के माध्यम से उठाएं, ताकि एक सार्थक बदलाव आ सके.

-सुदर्शन पाठक, बक्सर, बिहार.

सत्यता से ओतप्रोत लेख

चौथी दुनिया में प्रकाशित आलेख-मिड डे मील की कछुआ चाल और सरकारी स्कूलों से लें हिसाब पढ़े. उक्त दोनों आलेख वास्तविकता से ओतप्रोत हैं. मैं राज्य के शिक्षा विभाग से प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त हुआ हूं. अपने अनुभवों के आधार पर कह सकता हूं कि इन दोनों आलेखों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया. मिड डे मील के बारे में जो कहा गया, वह बिल्कुल सही है. चौथी दुनिया के आलेखों को पढ़कर ऐसा लग रहा है कि इस अख़बार की शक्ति अपार होगी, सभी से श्रेष्ठ होगी.

-के एल पटेल, *भोपाल, मध्य प्रदेश.*

संबंध सुधारने की अच्छी पहल

चौथी दुनिया में प्रकाशित आलेख-बेहतर संबंध बनाने की क़वायद काफी अच्छा लगा. संबंधों को बेहतर बनाने के प्रयास की तारीफ़ अच्छी है, लेकिन बेहतर क्या होगा, इस पर राजनेताओं को मिलकर गहन विचार करने की ज़रूरत है. पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देते हुए भी अमेरिका से सहायता पाता रहा. चीन ने हमारे पड़ोसी देश तिब्बत पर, जिससे हमारा गहरा नाता था, क़ब्ज़ा कर लिया और हम कुछ नहीं कर सके. चीन से मुक़ाबला करने और पाकिस्तान के आतंकवाद से छुटकारा पाने के लिए उच्च कोटि की राजनीति और घरेलू तैयारी की ज़रूरत है. छोटे और कमज़ोर पड़ोसियों को भी मदद देकर संबंध सुधारने की क़वायद अच्छी है.

-ए के शर्मा, *हुगली, पश्चिम बंगाल.*

बिहार में सुशासन नहीं है

चौथी दुनिया में प्रकाशित आलेख-नीतीश जी, सुशासन कहां है ने राज्य की सच्चाई प्रस्तुत की है. नीतीश कुमार ने बिहार में कुछ पुलों एवं सड़कों का निर्माण कराकर, छात्राओं को साइकिलें देकर और कुछ विकास योजनाएं शुरू करके समझ लिया कि यही सुशासन है, जनता ख़ुशहाल है. जबकि सच तो यह है कि जनता की मूलभूत समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं. कुछ अपवादों को छोड़कर आज भी सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, वहां बिना रिश्वत दिए काम नहीं होता. बिजली, पानी एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, बेरोज़गारी और आपराधिक घटनाओं से जनता परेशान है. तो फिर सुशासन है कहां?

-रंजन कुमार सिंह, *पटना, बिहार.*

कल्याण की बातें

हम मानव मात्र के कल्याण की बातें करते हैं,
सरहद पर नफ़रत ही सही, इंसाफ़ की बातें करते हैं.
मरते हैं सैनिक सरहद पर, पर प्यार की बातें करते हैं,
गांधी, नानक और गौतम के संदेश की बातें करते हैं.
भूखा सोता है बचपन, पर उपदेश की बातें करते हैं,
हम मानव मात्र के कल्याण की बातें करते हैं.

-प्रहलाद सिंह चड्ढा, कोटा, राजस्थान.

मुलायम परिवारवाद में फंसे

इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मुलायम सिंह यादव परिवारवाद की राजनीति में फंस गए हैं. वह पहले भी फंसे थे, लेकिन अब बेटे और बहू को लेकर फंसे हैं. कांग्रेस को छोड़कर आज तक किसी भी दल ने परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा नहीं दिया. मुलायम सिंह यादव शायद आज भी उसे अपना आदर्श मानते हैं. परिवारवाद व्यक्ति को अकेला कर देता है. जरूरत इस बात की है कि मुलायम सिंह को समय रहते यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए, वरना एक दिन वह भी अकेले रह जाएंगे.

-नेम सिंह, *ई-मेल से.*

राजकमल प्रकाशन समूह

चौथी दुनिया में प्रकाशित सप्ताह के सर्वश्रेष्ठ पत्र को राजकमल प्रकाशन की ओर से 700 रुपए की किताबें दी जाएंगी.

राजकमल प्रकाशन की किसी भी पुस्तक की समीक्षा चौथी दुनिया को भेजें. हर महीने की सर्वश्रेष्ठ समीक्षा को 1100 रुपए की पुस्तकें दी जाएंगी.

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :

चौथी दुनिया

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301

ई मेल : feedback@chauthiduniya.com

ब्रिटिश संसद से इतर भारतीय संसद मतदान के मुद्दे पर भी कमज़ोर है. हाउस ऑफ लार्ड्स में कोई भी सदस्य सभापति को इस बात के लिए चुनौती दे सकता है कि ध्वनि मत से वह संतुष्ट नहीं है.

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

जनरल वी के सिंह के साथ न्याय होना चाहिए

भारतीय थल सेनाध्यक्ष के साथ एक तरफ़ सरकार मज़ाक कर रही है और दूसरी तरफ मीडिया. सरकार बार-बार एक ग़लत बात को सही साबित करने की कोशिश कर रही है. उसे चाहिए कि वह सुप्रीम कोर्ट जाए और वहां कहे कि हिंदुस्तान में किसी भी डेट ऑफ बर्थ के सवाल को हाईस्कूल के सर्टिफिकेट से हल नहीं किया जाएगा, बल्कि उस विभाग का प्रमुख जो डेट ऑफ बर्थ तय करे, उससे हल किया जाएगा. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह फ़ैसला कई मामलों में दिया है कि जब भी जन्मतिथि पर कोई सवाल खड़ा हो, उस समय हाईस्कूल का सर्टिफिकेट ही अंतिम प्रमाण माना जाएगा, न कि हॉरोस्कोप, जन्मपत्री या किसी रिटायर्ड हेड मास्टर द्वारा दिया हुआ सर्टिफिकेट. ये शब्द सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसलों में लिखे हैं, लेकिन जनरल वी के सिंह की जन्मतिथि के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के उक्त फ़ैसले नहीं माने जा रहे हैं.

क़ानून मंत्रालय की एक सलाह में लिखा गया है कि किसी क्लर्क ने एनडीए का फॉर्म भरते समय ग़लती से 51 की जगह 50 लिख दिया, लेकिन हाईस्कूल के सर्टिफिकेट में यह 1951 है, इसलिए इस डेट ऑफ बर्थ को 1951 ही माना जाए, लेकिन सरकार इसे नहीं मान रही है, क्योंकि सरकार चलाने वाले लोगों का इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है. उस वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से उनके सामने न सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का कोई मतलब है और न किसी अन्य संवैधानिक संस्था का. भारत के क़ानून मंत्री ने इसी तरह एक वक्तव्य दिया है कि चुनाव आयोग चूंकि स्वतंत्र है, किसी के नियंत्रण में नहीं है, इसलिए वह फ़ैसले ऐसे करता है, जिनकी वजह से परेशानी होती है. इसका मतलब यह है कि जो स्वतंत्र और संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या चुनाव आयोग, उन्हें नियंत्रण में लाना चाहिए. ये नियंत्रण में किसके आएं? ज़ाहिर है, संविधान के नियंत्रण में न आएं, ये सरकार के नियंत्रण में आएं. यह ख़तरनाक बात नए सिरे से हिंदुस्तान में स्थापित की जा रही है.

मीडिया का वह हिस्सा, जो डिफेंस मिनिस्ट्री कवर करता है, मैं उसके बारे में एक बात साफ़ कर दूं. नब्बे प्रतिशत से ज़्यादा डिफेंस जर्नलिस्ट ऐसे हैं, जिनका रिश्ता किसी न किसी हथियार लॉबी से है. अख़बार में उनका लेख पढ़कर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसके पीछे कौन सी हथियार लॉबी काम कर रही है. इसलिए ऐसे सारे जर्नलिस्ट, जो हथियार लॉबी से जुड़े हुए हैं, उन्होंने इस सवाल पर सरकार की तरफ से जनरल वी के सिंह पर हमला बोल दिया. इन पत्रकारों ने कहा कि चूंकि उन्होंने संगठन के हित में एक बार स्वीकार किया है कि मेरी जन्मतिथि 1950 है और इसी वाक्य को मानते हुए इन पत्रकारों ने कह दिया कि उनकी डेट ऑफ बर्थ 1950 ही है. ऐसे सारे मीडिया के दोस्तों ने मीडिया का अपमान किया है, मीडिया के सिद्धांतों का अपमान किया है. हर एक को पता है और अगर नहीं पता है तो वह महामूर्ख पत्रकार है. सेना के नियमों के अनुसार, अगर सेनाध्यक्ष कोई जुबानी आदेश देता है, उसे भी न मानना सेना के अनुशासन का उल्लंघन माना जाता है और आदेश न मानने वाला व्यक्ति कोर्ट मार्शल का सामना करने के लिए विवश हो जाता है. सेना के इस मूलभूत सिद्धांत के तहत जब जनरल दीपक कपूर ने, जो उस समय सेनाध्यक्ष थे, जनरल वी के सिंह (जो उस समय लेफ्टिनेंट जनरल थे) से कहा कि आप संगठन के हित में लिखकर दीजिए कि मैं अपनी जन्मतिथि 1950 मानता हूं तो उसे सेना का आदेश मानकर जनरल वी के सिंह ने लिखा, जैसा आपने मुझे निर्देशित किया...इसका मतलब दूसरे अर्थों में उनके गले पर बंदूक रखकर उनसे ऐसा लिखवाया गया. कंडीशनल लिखा हुआ और हाईस्कूल के सर्टिफिकेट में जो तारीख़ लिखी हुई है, क्या उन दोनों के बीच में सच्चाई नहीं खोजी जा सकती है. सच्चाई बिल्कुल साफ़ है और वह यह है कि जनरल वी के सिंह की जन्मतिथि 1951 है.

इसीलिए जब जनरल वी के सिंह ने अपने इस सवाल को उठाया और कहा कि यह मेरे आत्मसम्मान का मसला है तो हिंदुस्तान के हर न्यायप्रिय नागरिक ने उनकी भावना के साथ अपने को जोड़ा. इसके बावजूद अभी कुछ पत्रिकाएं, अख़बार और सरकार में हथियार माफ़ियाओं या ज़मीन माफ़ियाओं से सहानुभूति रखने वाले लोगों ने जनरल वी के सिंह पर हमला करना नहीं छोड़ा है. उनकी पुरज़ोर ख्वाहिश है कि जनरल वी के सिंह की जन्मतिथि 1950 ही मानी जाए और वह इस साल मई में रिटायर हो जाएं. लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट क्यों हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, यह हमारे लिए एक चिंता की बात है. सुप्रीम कोर्ट छोटी-छोटी चीजों में अपने आप संज्ञान ले लेता है, उन पर सुनवाई करता है और फ़ैसले देता है. कोई एक खत लिख दे, उस खत को भी पीआईएल मानकर सुनवाई शुरू हो जाती है, लेकिन एक ऐसे मसले में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, जिसमें देश के सबसे बड़े संगठन, ऐसा संगठन नहीं जो समाज सेवा का काम करता है, बल्कि जो देश की रक्षा करता है यानी भारतीय थलसेना के अध्यक्ष का मसला. जिस मसले को लेकर अख़बारों में लेख लिखवाए जा रहे हैं, उन पर हमले हो रहे हैं और जनरल वी के सिंह खुद पर लगाए गए आरोपों का एक भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि अगर वह जवाब देंगे तो माना जाएगा कि वह पत्रकारों के बीच अपने मामले को ले जा रहे हैं. उनकी मजबूरी है कि वह अपने पक्ष में सिर्फ़ और सिर्फ़ गोपनीय खत सरकार को लिखें. सरकार उन खतों को नहीं, बल्कि उन खतों को लेकर सामने आती है, जो उसके पक्ष में हैं. सच्चाई दोनों के बीच में कहीं है. उस सच्चाई को सरकार सामने नहीं लाती और जनरल वी के सिंह की इस विवशता का कि वह जनता के बीच अपनी बात नहीं ले जा सकते, फ़ायदा उठा रही है. ज़रूरत इस बात की है कि सर्वोच्च न्यायालय इसका संज्ञान ले और अपनी तरफ़ से सुनवाई शुरू करे. यह हमारा सर्वोच्च न्यायालय से विनम्र अनुरोध है कि आप देश में पहली बार पैदा किए गए एक नकली विवाद पर राय दें और हमारा आग्रह अगर आप मानें तो आपको यह करना चाहिए. अगर आप यह नहीं करेंगे तो आप भी कहीं न कहीं सरकार के साथ इस पूरी साज़िश का हिस्सा मान लिए जाएंगे. लोगों के जेहन में आपकी तस्वीर भी सरकार से मिलजुल कर काम करने वाले सुप्रीम कोर्ट की हो जाएगी. ऐसा ख़तरा हमें लगता है.

सेना के नियमों के अनुसार, अगर सेनाध्यक्ष कोई ज़ुबानी आदेश देता है, उसे भी न मानना सेना के अनुशासन का उल्लंघन माना जाता है और आदेश न मानने वाला व्यक्ति कोर्ट मार्शल का सामना करने के लिए विवश हो जाता है. सेना के इस मूलभूत सिद्धांत के तहत जब जनरल दीपक कपूर ने, जो उस समय सेनाध्यक्ष थे, जनरल वी के सिंह (जो उस समय लेफ्टिनेंट जनरल थे) से कहा कि आप संगठन के हित में लिखकर दीजिए कि मैं अपनी जन्मतिथि 1950 मानता हूं तो उसे सेना का आदेश मानकर जनरल वी के सिंह ने लिखा, जैसा आपने मुझे निर्देशित किया...इसका मतलब दूसरे अर्थों में उनके गले पर बंदूक रखकर उनसे ऐसा लिखवाया गया. कंडीशनल लिखा हुआ और हाईस्कूल के सर्टिफिकेट में जो तारीख़ लिखी हुई है, क्या उन दोनों के बीच में सच्चाई नहीं खोजी जा सकती है.

पाकिस्तान में सरकार, सेना और न्यायपालिका लगभग तीनों ही गड्डमड्ड हैं. हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है. हमारे देश में पाकिस्तान जैसी हालत नहीं है. हमारे पास स्वतंत्र न्यायपालिका और स्वतंत्र चुनाव आयोग है. यह स्वतंत्रता हमारे संविधान की सबसे ख़ूबसूरत महक है. देश में जब सभी जगह से लोग हार जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं. हम भी सुप्रीम कोर्ट से यही कहना चाहते हैं कि देश में पैदा हुए इस विवाद पर वह क्यों फ़ैसला नहीं ले रहा, क्यों इसकी सुनवाई नहीं कर रहा और लोगों के दिमाग में क्यों यह संदेह पनपने दे रहा है कि वह लोगों की बात नहीं सुनता. जनरल वी के सिंह का यह कहना कि यह जन्मतिथि का विवाद पूरी तरह उनके मान-सम्मान से जुड़ा है, हम इससे पूरी तरह से सहमत हैं. जनरल वी के सिंह एक व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि भारतीय सेना का नेतृत्व करने वाले सर्वोच्च सिपाही हैं. जनरल वी के सिंह के ख़िलाफ़ अगर उनके पूरे करियर में एक भी दाग़ होता तो अब तक सरकार या वे ताक़तें, जो जनरल वी के सिंह को हटाना चाहती हैं, हर हालत में उन दागों को लेकर अब तक देश में शोर मचा चुकी होतीं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि वी के सिंह की ज़िंदगी में और उनकी वर्दी पर एक भी दाग नहीं है. इसीलिए हम जनरल वी के सिंह के सम्मान की लड़ाई में उनके साथ खड़े हैं. हम इसलिए भी खड़े हैं, क्योंकि यह भारतीय सेना के सम्मान का मसला है. बहत सारे वरिष्ठ पत्रकारों ने सेना के अफ़सरों से बातचीत की. सारे अफसरों का यह कहना है कि जनरल वी के सिंह एक बेदाग़ और एक बेहतरीन नेतृत्व क्षमता वाले इंसान हैं. इसलिए पूरी सेना उनके साथ चट्टान की तरह खड़ी है.

अफ़सोस इस बात का है कि सेना को सवालिया घेरे में लाने का काम सरकार में वे लोग कर रहे हैं, जिनकी लोकतंत्र के प्रति वचनबद्धता अब संदेह के घेरे में आ गई है और विपक्ष के लोग इस सवाल पर ख़ामोश हैं. विपक्ष वैसे भी सरकार द्वारा उठाए गए किसी सवाल पर तब तक नहीं बोलता, जब तक उसे राजनीतिक फ़ायदा न मिलता हो. सेना पर विपक्ष ख़ामोश है. सरकार मनमाना फ़ैसला करना चाहती है. ऐसा लगता है कि देश में न्यायप्रियता या न्याय में आस्था रखने वालों की आशाओं के ख़त्म होने का वक़्त आने वाला है. मुझसे एक सेनाधिकारी की पत्नी ने कहा कि अगर मेरी अपने पति से शादी न हुई होती तो मैं उनसे कहती कि तुम्हें अगर मुझसे शादी करनी है तो तुम सेना में मत जाना. उन्होंने मुझसे कहा कि यह दुर्भाग्य की बात है कि मेरे पति भी बहुत ईमानदार हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सेना में अब ईमानदार अधिकारियों की क़द्र नहीं होने वाली है. सेना में काम करने वाले अफ़सर की इस पत्नी का दर्द शायद सेना में काम करने वाले लाखों लोगों की पत्नी का दर्द होगा, मुझे नहीं मालूम, पर उस महिला की इन मार्मिक बातों ने इतना तो सोचने पर विवश कर ही दिया है कि क्या हम ईमानदार लोगों के साथ, बेदाग़ लोगों के साथ खड़े होने की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाएंगे. यह सवाल देश के सामने भी है, राजनीति के सामने भी और सुप्रीम कोर्ट के सामने भी है.

संपादक
editor@chauthiduniya.com

मेघनाद देसाई

संसद और भारतीय राजनीति की शिथिलता

यूपीए-2 सरकार ने आर्थिक उदारीकरण की दिशा में एक और क़दम उठाया है. विदेशी निवेशकों को भारतीय कंपनी में शेयर ख़रीदने के लिए सरकार से अनुमति लेने की बाध्यता समाप्त कर दी गई है. इसी तरह का निर्णय खुदरा बाज़ार में एफडीआई के लिए लिया जा सकता था, लेकिन किसी ने इसके लिए साहस नहीं दिखाया. प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद हंगामा हो गया और सरकार ने इसे वापस ले लिया. प्रणब मुखर्जी ने कहा कि वह जानते हैं कि इसे लोकसभा में पारित कराने के लिए उनके पास बहुमत नहीं था और वह मध्यावधि चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं हैं. अगर वह अपनी बात पर अड़े रहते तो सरकार के लिए मुसीबत हो जाती. गठबंधन सरकार में बहुत सारे फ़ैसले इसलिए नहीं लिए गए, क्योंकि कांग्रेस न तो तृणमूल कांग्रेस को अपने पक्ष में कर पाई और न राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को. दूसरी ओर कनिमोझी के कारण डीएमके कांग्रेस का साथ नहीं दे रही थी. यूपीए-1 की सरकार में वामदल बाहर से समर्थन दे रहे थे और वे उचित तरीक़े से अपनी मांग रखते थे, लेकिन ममता बनर्जी ऐसा नहीं कर रही हैं, उनका तरीक़ा सही नहीं कहा जा सकता. मैंने सिंगुर मामले के समय ही चेतावनी दी थी कि कांग्रेस सीपीएम से छुटकारा पाने के लिए जिस तरीक़े से तृणमूल कांग्रेस का साथ दे रही है, वह उसके लिए आग से खेलने जैसा है. आज कांग्रेस को यह बात समझ में आ रही है. देखा जाए तो खुदरा बाज़ार में एफडीआई हो या पेंशन संबंधी नीति या फिर खाद्य सुरक्षा और भूमि अधिग्रहण विधेयक, सभी को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, क्योंकि ममता बनर्जी ने इस पर वीटो कर दिया था. आगे भी इस बात की संभावना कम है कि ममता बनर्जी नरम रुख़ अख्तियार कर लें. इसकी वजह यह है कि उन्हें कांग्रेस की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कांग्रेस को उनकी ज़रूरत है. शरद पवार के साथ भी ऐसा ही है. वह भी ख़ुद निर्णय लेते हैं कि कब और कितनी ढील कांग्रेस को देनी है. कांग्रेस के साथ यह बहुत बड़ी समस्या है. कांग्रेस के कुछ लोग यह आस लगाए बैठे हैं कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों में उनकी स्थिति अच्छी रहेगी. कांग्रेस को इन चुनावों में सफलता मिलेगी और अच्छी-खासी सीटें उसकी झोली में आ जाएंगी. इसके बाद उसे राज्यसभा में बहुमत मिल जाएगा और किसी भी विधेयक को राज्यसभा में पारित कराने के लिए उसे जुगाड़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ होने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है.

राहुल गांधी का जादू भी कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में पचास से अधिक सीटें नहीं दिला सकता है. आरएलडी के साथ मिलकर भी वह 75 सीटों से अधिक का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी. बसपा को सबसे अधिक सीटें मिल सकती हैं और सबसे बड़ी पार्टी की नेता मायावती होंगी, मुलायम सिंह यादव नहीं. अभी जिस तरह से कांग्रेस मायावती को परेशान करने में लगी है, उससे तो यही कहा जा सकता है कि मायावती चुनाव के बाद कांग्रेस के साथ नहीं, बल्कि भाजपा के साथ गठबंधन करना पसंद करेंगी.

राहुल गांधी का जादू भी कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में पचास से अधिक सीटें नहीं दिला सकता है. आरएलडी के साथ मिलकर भी वह 75 सीटों से अधिक का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी. बसपा को सबसे अधिक सीटें मिल सकती हैं और सबसे बड़ी पार्टी की नेता मायावती होंगी, मुलायम सिंह यादव नहीं. अभी जिस तरह से कांग्रेस मायावती को परेशान करने में लगी है, उससे तो यही कहा जा सकता है कि मायावती चुनाव के बाद कांग्रेस के साथ नहीं, बल्कि भाजपा के साथ गठबंधन करना पसंद करेंगी. कांग्रेस का समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का सपना साकार होना मुश्किल लग रहा है. ऐसी स्थिति में इन चुनावों द्वारा राज्यसभा में बहुमत लाना कांग्रेस के लिए मुश्किल होगा. वर्तमान समय में कांग्रेस और भाजपा की जैसी स्थिति है, उससे तो यही लगता है कि आगे भी फ़ैसला लेने में ऐसी ही कठिनाइयां आने वाली हैं. लोकसभा में बीते 27 दिसंबर को जो कुछ हुआ, उससे कांग्रेस की पोल खुल गई है. कांग्रेस अपने ही सांसदों को मैनेज करने में नाकाम रही, वह अपने सांसदों को सदन में उपस्थित रहने के लिए बाध्य नहीं कर सकी. हालांकि इससे भी उसे दो तिहाई बहुमत नहीं प्राप्त होता, लेकिन इसे पार्टी की कमज़ोरी तो कहा ही जा सकता है. राज्यसभा में मोहम्मद हामिद अंसारी ने कांग्रेस को मुश्किल घड़ी से निकाल लिया. ब्रिटेन के हाउस ऑफ कामंस में स्पीकर स्वयं या फिर सत्ता पक्ष एवं विपक्ष से मिलकर यह निर्णय ले सकता है कि संसद की अवधि बढ़ाई जाए या नहीं. हाउस ऑफ लार्ड्स में भी कुछ इसी तरह की व्यवस्था है, लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं है. सभापति को इसके लिए कैबिनेट की अनुमति चाहिए या फिर राष्ट्रपति की, जो कि कैबिनेट की सलाह पर काम करते हैं.

इस प्रकार देखा जाए तो भारतीय संसद ने अपना अधिकार सरकार को दे दिया है. ब्रिटिश संसद से इतर भारतीय संसद मतदान के मुद्दे पर भी कमज़ोर है. हाउस ऑफ लार्ड्स में कोई भी सदस्य सभापति को इस बात के लिए चुनौती दे सकता है कि ध्वनि मत से वह संतुष्ट नहीं है और इस पर मतदान कराया जाना चाहिए. ऐसी स्थिति में मतदान कराया जाता है और इस बात की जानकारी होती है कि कौन किसके पक्ष में मत दे रहा है. लोकसभा में लोकपाल बिल ध्वनि मत से पारित किया गया, जिसके कारण अन्ना हजारे को इस बात की जानकारी नहीं हो पाई कि किसने लोकपाल बिल के पक्ष में मत दिया और किसने विरोध में. अगर सरकार संसदीय नियमों को नहीं बदल सकती है तो बेहतर यही होगा कि वह अपना व्यवहार बदले. अगर भारतीय संसद में सब ठीक चल रहा है तो इसका मतलब है कि भाजपा और कांग्रेस में पहले ही बातचीत हो चुकी है, जैसा कि लोकपाल बिल के मुद्दे पर सेंस ऑफ हाउस रिजोल्यूशन पारित होने के समय दिखा था. उस समय संसद सबसे मज़बूत स्थिति में थी और पिछले दिनों वह सबसे कमज़ोर स्थिति में थी. प्रश्न यह नहीं है कि ग़लती किसकी थी, बल्कि प्रश्न यह है कि क्या भारतीय राजनीति का विकास हो पाएगा?

feedback@chauthiduniya.com

ये हड्डियां शाकाहारी डायनासोर अलामोसोउरस सांजुआनेनसिस की हैं, जो क़रीब 6.9 करोड़ वर्ष पूर्व अमेरिका और मैक्सिको में पाया जाता था.

चौथी दुनिया
दिल्ली, 23 जनवरी–29 जनवरी 2012

आरटीआई ईमानदार अधिकारियों के लिए वरदान है

आरटीआई को लेकर एक आशंका ज़ाहिर की जाती है कि फाइल नोटिंग के सार्वजनिक होने की वजह से अधिकारी ईमानदार सलाह देने से डरेंगे, लेकिन यह आशंका ग़लत है. इसके विपरीत, हर अधिकारी को अब यह पता होगा कि वह जो कुछ भी लिखता है, वह जन समीक्षा का विषय हो सकता है. यह उस पर जनहित में लिखने का दबाव बनाएगा. आरटीआई ईमानदार अधिकारियों पर राजनीतिक एवं अन्य दबाव कम करने में बहुत प्रभावी रहा है. अब अधिकारी सीधे तौर स्वीकार करते हैं कि यदि उन्होंने कुछ ग़लत किया तो उनका पर्दाफाश हो जाएगा. इसलिए अधिकारियों ने इस बात पर जोर देना शुरू कर दिया है कि वरिष्ठ अधिकारी भी उन्हें लिखित में निर्देश दें.

एक दूसरी बात यह कही जाती है कि लोग बहुत लंबी-चौड़ी सूचना मांगने वाले आवेदन देते हैं और उन्हें ख़ारिज किया जाना चाहिए, लेकिन सवाल है कि ऐसा क्यों किया जाना चाहिए? यदि कोई आवेदक ऐसी जानकारी चाहता है, जो एक लाख पृष्ठों की हो तो वह ऐसा तभी करेगा, जब सचमुच उसे इसकी ज़रूरत होगी, क्योंकि उसके लिए दो लाख रुपये का भुगतान करना होगा. यदि अर्ज़ी इस आधार पर रद्द कर दी गई तो प्रार्थी प्रत्येक अर्ज़ी में 100 पृष्ठ मांगते हुए 1000 अर्जियां बना लेगा, जिससे किसी को भी लाभ नहीं होगा. इसलिए इस वजह से अर्जियां रद्द नहीं होनी चाहिए कि लोग ऐसे मुद्दों से जुड़ी सूचना मांग रहे हैं, जो सीधे-सीधे उनसे जुड़ी हुई नहीं हैं. उन्हें सरकार के अन्य मामलों के बारे में प्रश्न पूछने की छूट नहीं दी जानी चाहिए, यह पूर्णत: ग़लत है. आरटीआई अधिनियम का अनुच्छेद 6 (2) स्पष्ट तौर पर कहता है कि प्रार्थी से यह नहीं पूछा जा सकता कि वह क्यों कोई जानकारी मांग रहा है. किसी भी मामले में आरटीआई इस तथ्य से उद्धृत होता है कि लोग टैक्स/कर देते हैं, यह उनका पैसा है और इसीलिए उन्हें यह जानने का अधिकार है कि उनका पैसा कैसे ख़र्च हो रहा है और कैसे उनकी सरकार चल रही है. इसलिए लोगों को सरकार के प्रत्येक कार्य की प्रत्येक बात जानने का अधिकार है. भले ही वे उस मामले से सीधे तौर पर जुड़ें हों या नहीं. इसलिए दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति ऐसी कोई भी सूचना मांग सकता है, जो तमिलनाडु से संबंधित हो. एक और बात है, अभी तक सरकारी रेकॉर्ड्स सही रूप में व्यवस्थित नहीं हैं. आरटीआई क़ानून की वजह से इन रिकॉर्ड्स को व्यवस्थित करने की ज़िम्मेदारी भी अधिकारियों पर आएगी, ताकि इस क़ानून का सफल क्रियान्वयन हो सके. इस बार हम एक आरटीआई आवेदन जो मनरेगा से संबंधित है, प्रकाशित कर रहे हैं. यह आवेदन मनरेगा में हो रही (अगर ऐसा है तो) धांधली सामने लाने या जॉब कार्ड बनवाने में मददगार साबित हो सकता है. हम अपने सुधी पाठकों से अपेक्षा करते हैं कि वे गांव-देहात में रहने वाले लोगों को भी इस स्तंभ के बारे में बताएंगे और इसमें दिए गए आरटीआई आवेदन के प्रारूप को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन -201301
ई-मेल : rti@chauthiduniya.com

आवेदन पत्र का प्रारूप

(मनरेगा के तहत जॉब कार्ड)

सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन

महोदय,
मैं.....ग्राम का निवासी हूं. मैंने दिनांक.....को मनरेगा के तहत जॉब कार्ड के लिए आवेदन किया था. कृपया इस संबंध में निम्न विवरण प्रदान करें:-

1. मेरे आवेदन पर की गई प्रतिदिन की कार्रवाई अर्थात दैनिक प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराएं. मेरा आवेदन किन-किन अधिकारियों के पास गया और किस अधिकारी के पास कितने दिनों तक रहा और इस दौरान उन अधिकारियों ने उस पर क्या कार्रवाई की? पूरा विवरण उपलब्ध कराएं.
2. मनरेगा के तहत जॉब कार्ड के लिए आवेदन करने के कितने दिनों के अंदर जॉब कार्ड बन जाना चाहिए? इससे संबंधित नियमों या नागरिक चार्टर या किसी अन्य आदेशों/दिशानिर्देशों की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराएं.
3. कृपया उन अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम एवं पद बताएं, जिन्हें मेरे आवेदन पर कार्रवाई करनी थी, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की.
4. अपना काम ठीक से न करने और जनता को परेशान करने वाले उन अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी और यह कार्रवाई कब तक की जाएगी?
5. अब मेरा जॉब कार्ड कब तक मिल जाएगा?
6. मनरेगा के तहत जॉब कार्ड बनाने के लिए मेरे गांव से अब तक कितने आवेदन प्राप्त हुए? उनकी सूची निम्नलिखित विवरणों के साथ उपलब्ध कराएं:-

क. आवेदक का नाम व पता.
ख. आवेदन संख्या.
ग. आवेदन की तारीख.
घ. आवेदन पर की गई कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण (जॉब कार्ड बना/नहीं बना/विचाराधीन).
ड. यदि जॉब कार्ड नहीं बना तो उसका कारण बताएं.
च. यदि बना तो किस तारीख को?

मैं आवेदन शुल्क के रूप में 10 रुपये अलग से जमा कर रहा/रही हूं.
या
मैं बीपीएल कार्डधारक हूं, इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूं. मेरा बीपीएल कार्ड नंबर.....है.
यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित न हो तो सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों की समयावधि के अंतर्गत हस्तांतरित करें. साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम एवं पता अवश्य बताएं.
भवदीय
नाम.....
पता.....
फोन नं.....
संलग्नक.....

ज़रा हट के

डायनासोर के राज

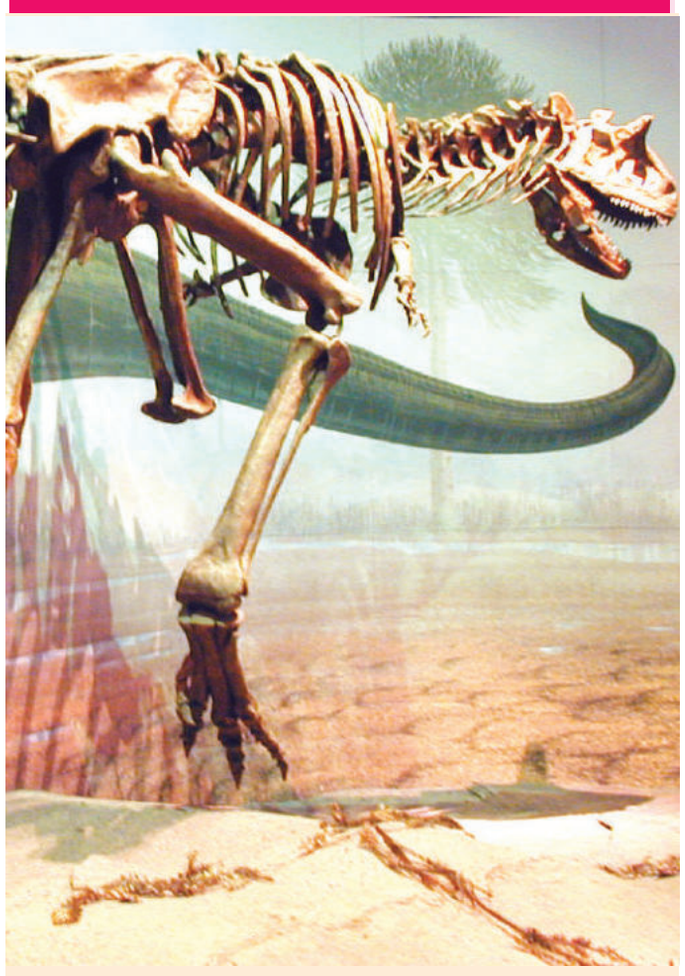

जीवाश्म विज्ञानियों के मुताबिक़ उन्होंने अमेरिका में सबसे बड़े डायनासोर की हड्डियां खोज ली हैं. ख़बर के मुताबिक़, मोंटाना स्टेट के म्यूज़ियम ऑफ राकिज और पेनसिलेवानिया के स्टेट म्यूज़ियम के दलों ने अपने शोध में दो विशालकाय हड्डियों, एक रीढ़ की और दूसरी जांघ की हड्डी के बारे में बताया है. इन हड्डियों को उन्होंने वर्ष 2003 से 2006 के बीच न्यू मैक्सिको से एकत्र किया था. ये हड्डियां शाकाहारी डायनासोर अलामोसोउरस सांजुआनेनसिस की हैं, जो करीब 6.9 करोड़ वर्ष पूर्व अमेरिका और मैक्सिको में पाया जाता था. जीवाश्म वैज्ञानिक यह भी खोज कर रहे हैं कि डायनासोर का वजूद पृथ्वी से क्यों और कैसे मिटा. मध्य प्रदेश के खोजकर्ता समूह का दावा है कि नर्मदा घाटी में ही इन सवालों का राज छिपा हुआ है. धार जिले में खोज अभियान के दौरान मिले सुरागों से पता चलता है कि डायनासोर बेमौत मारे गए थे. उनका ऐसा अंदेशा है कि तापमान में अधिक वृद्धि के कारण ही डायनासोरों की लगातार मौत हो रही थी और वे अपनी जान बचाने के लिए ठंडी जगह की तलाश कर रहे थे.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

बड़े काम का बंदर

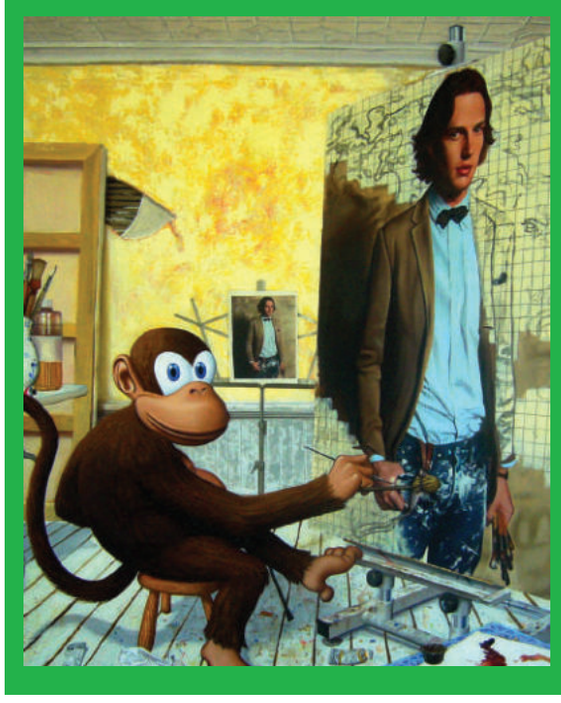

कैपुचिन प्रजाति का एक बंदर नामी कलाकार बन गया है और उसके बनाए चित्र यूरोप और इजरायल में काफी महंगे बिके हैं. सफेद टोपी पहनने वाले इस कनाडाई कैपुचिन बंदर को पाकेटस वरहोल नाम दिया गया है. यह बंदर अपनी पूंछ, हाथ, पैर और एक ब्रश की मदद से पेंटिंग बनाता है. इसे कनाडा के एक निजी अभयारण्य स्टोरी बुक फार्म में रखा गया है. यह बंदर अपने मालिकों के लिए पैसा कमाने की मशीन बन गया है. इसकी बनाई पेंटिंग्स 250 पौंड तक में बिकी हैं. यह बंदर दूसरे कलाकारों की तरह स्वच्छ छवियां नहीं उकेरता, बल्कि इसकी कलाकृतियां गूढ़ और प्रायोगिक होती हैं. पिछले साल स्टोरी फार्म की स्वयंसेवक चारमैन क्वीन ने इस बंदर के हाथ में बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले गैर हानिकारक रंग थमा दिए थे, तबसे इसने प्रायोगिक कलाकृतियां उकेरनी शुरू कर दीं. क्वीन ने कहा, पाकेटस को इसमें मजा आता है, लेकिन वह दूसरे कलाकारों की तरह हमेशा शांत नहीं रहता. कई बार वह रंग खाने भी लगता है. अभयारण्य के मालिकों ने बताया कि पाकेटस की कमाई से जुटाए गए पैसों से एक नया बाड़ा खरीदा जाएगा. ऑस्ट्रेलिया के एडीलेड स्ट्रीट में पाकेटस द्वारा बनाए गए चित्रों की एक प्रदर्शनी लगाई गई है, जो दो महीनों के लिए है.

कलम का कमाल

एक ख़बर के मुताबिक़, एक महिला के पेट में 25 वर्षों तक रहने के बावजूद एक कलम अभी भी काम कर रही है. यह 76 वर्षीय महिला लगातार कम हो रहे वजन और डायरिया से परेशान होकर डॉक्टर के पास पहुंची. डाक्टरों ने जांच में पाया कि उसकी बड़ी आंत के एक हिस्से में जलन जैसी स्थिति पैदा हो रही है, जिसकी वजह से उसे पेट में दर्द हो रहा है. रॉयल डेवोन एंड एक्सेटर हॉस्पिटल फाउंडेशन ट्रस्ट के डॉक्टरों ने जब महिला के पेट का सीटी स्कैन किया तो उन्होंने उसके पेट में कलम की तरह दिखने वाली एक चीज देखी. पूछे जाने पर महिला ने बताया कि क़रीब 25 साल पहले उसने ग़लती से कलम निगल ली थी. डॉक्टरों ने वह कलम उसके पेट से बाहर निकाली और पाया कि उससे अभी भी लिखा जा सकता था. ऐसी-ऐसी अजीबोग़रीब घटनाएं घटित होती रहती हैं, जिनके बारे में पढ़-सुनकर सहज विश्वास नहीं होता.

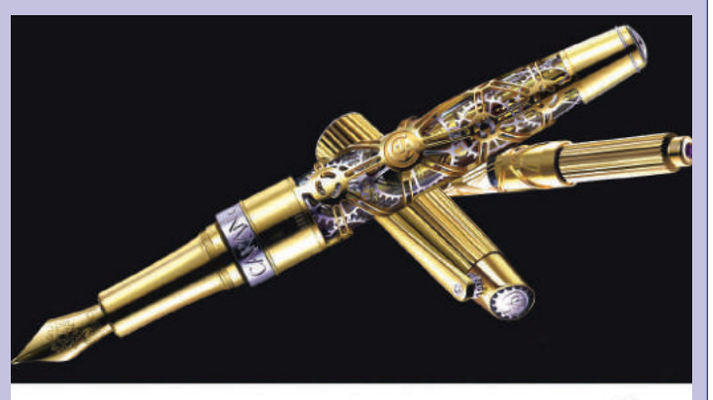

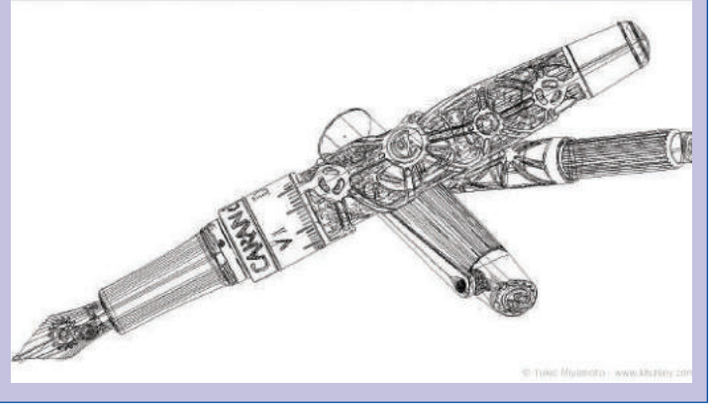

राशिफल

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)
इस सप्ताह किसी अति आवश्यक अथवा पूर्व नियोजित कार्य में आपका शामिल होना बहुत ज़रूरी है. यदि आप सच्ची लगन से कोई काम करेंगे तो उसमें सफलता निश्चित है. कोई ऐसा समाचार-संदेश भी मिल सकता है, जिससे तत्काल हर्षोल्लास का वातावरण बनेगा.

वृष (21 अप्रैल से 20 मई)
किसी के आगे ज़रूरत के मुताबिक़ ही मांग रखें, अन्यथा पछतावा हाथ लगेगा. सप्ताह मध्य में घर से निकलते ही किसी दुर्घटना का शिकार होना पड़ सकता है. बेहतर यही होगा कि आप प्रत्येक कार्य सावधानी से करें. किसी को धन देना ठीक नहीं है, लंबे समय तक उसकी वापसी नहीं हो पाएगी.

मिथुन (21 मई से 20 जून)
ख़र्च अधिक होने का मलाल रहेगा. सामान्य व्यवहार से ही आप अपनी निराशा और अकेलापन दूर कर सकते हैं. यदि नौकरी की तलाश में हैं तो उत्साहजनक परिणाम मिल सकते हैं. इंटरव्यू में जाने से पहले परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का आशीर्वाद अवश्य लें.

कर्क (21 जून से 20 जुलाई)
धीरे-धीरे लाभ मार्ग प्रशस्त होगा और नवीन योजनाएं फलीभूत होंगी. यात्रा के दौरान किसी अजनबी से घनिष्ठता नहीं करनी चाहिए. जब तक ज़रूरी न हो, अपनी कोई भी बात दूसरों से बढ़ा-चढ़ाकर कहने में हानि होगी. घर और बाहर आपकी व्यस्तता बढ़ सकती है.

सिंह (21 जुलाई से 20 अगस्त)
किसी जटिल कार्य की सिद्धि के लिए अधिक साहस को विडंबना समझें. पराक्रम दिखाने के लिए लंबे समय की ज़रूरत नहीं होती. व्यापार में जो दौर चल रहा है, वह आपके प्रतिकूल नहीं है. सप्ताह मध्य में शत्रुओं और विरोधियों पर अंकुश रख सकते हैं.

कन्या (21 अगस्त से 20 सितंबर)
अस्थायी उपक्रम से लाभ के अवसर पैदा होंगे. अपने पुरुषार्थ और कर्म पर भरोसा करें. आपके उत्साह एवं प्रेरणा से कई लोगों को आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है. महिलाओं एवं युवाओं को कार्यक्षेत्र में सजग रहना होगा.

तुला (21 सितंबर से 20 अक्टूबर)
कोई बेहतरीन काम करने से सामाजिक सुयश में वृद्धि होगी. यात्रा का कार्यक्रम बनेगा. शुभचिंतकों एवं सहकर्मियों से तालमेल बैठाने में दिक्कत आएगी, क्योंकि कार्यक्षेत्र में कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो मेहनत न करके दूसरे के कामों में दखलंदाज़ी करते हैं.

वृश्चिक (21 अक्टूबर से 20 नवंबर)
व्यर्थ के झंझटों के कारण लाभकारी प्रयास मंद पड़ सकते हैं. जो कुछ मिल जाए, उसी में संतोष कर लें. किसी नए कारोबार या कार्यक्षेत्र में समय देने के लिए तैयार रहें. हो सकता है, उससे आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाए.

धनु (21 नवंबर से 20 दिसंबर)
बौद्धिक क्षमता के बावजूद आप अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं. उचित अवसर की प्रतीक्षा करें. परिवारीजन इस समय आपके विरुद्ध चल सकते हैं, लेकिन सबको साथ लेकर चलना भी आपकी मजबूरी है.

मकर (21 दिसंबर से 20 जनवरी)
शत्रुओं के गुप्त षड्यंत्र विफल होंगे. स्वास्थ्य की दृष्टि से सप्ताह का आरंभ कुछ हैक्टिक रहेगा. उन्नति के कार्यों में बाधा आ रही है. लोग आपके व्यक्तित्व पर उंगली उठा सकते हैं. कोई ऐसा काम बन सकता है, जिससे आपकी आर्थिक समस्या हल होती नज़र आएगी.

कुंभ (21 जनवरी से 20 फरवरी)
महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाएंगे. स्वास्थ्य में सुधार होगा. किसी शुभ कार्य में आपका शामिल होना ज़रूरी होगा. जो भी महत्वपूर्ण कार्य आप करना चाहेंगे, उन्हें बनने में देर नहीं लगेगी.

मीन (21 फरवरी से 20 मार्च)
कोई महत्वपूर्ण काम न बनने से आपको मायूस होना पड़ सकता है. धन लाभ की प्रबल संभावना ज़रूर रहेगी, लेकिन धनागमन कुछ समय के लिए टल भी सकता है. यदि आप जनसंपर्क से लाभ उठाना चाहें तो सप्ताहांत आपके लिए सकारात्मक और योग्यता को संवारने वाला साबित हो सकता है.

पंडित सुदर्शन
feedback@chauthiduniya.com

इब्राहिम का कहना है, खुदा का शुक्र है कि न्याय की जीत हुई और मैं निर्दोष ठहराया गया. सच तो यह है कि मैं थोड़ा हैरान हूं.

मलेशिया

इब्राहिम आरोपमुक्त नजीब को कड़ी चुनौती

राजीव कुमार

मलेशिया के पूर्व उप प्रधानमंत्री एवं प्रमुख विपक्षी नेता अनवर इब्राहिम को अपने पुरुष सहायक के साथ यौन संबंध बनाने के आरोप से मुक्त कर दिया गया है. कुआलालंपुर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जबिदीन मोहम्मद दियाह ने कहा, हालांकि न्यायालय को इस बात का शत-प्रतिशत भरोसा नहीं है कि मामले से संबंधित डीएनए रिपोर्ट के साथ कोई छेड़छाड़ की गई है, लेकिन इब्राहिम को इस मामले में दोषी नहीं ठहराया जा सकता. न्यायालय का कहना था कि यह एक यौन अपराध का मामला है और ऐसे मामलों में अप्रमाणित साक्ष्यों के आधार पर सजा नहीं सुनाई जा सकती. ग़ौरतलब है कि इब्राहिम पर अपने पूर्व सहायक मोहम्मद सैफुल बुखारी अजलान के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का आरोप था. मलेशियाई क़ानून के अनुसार, ऐसे अप्राकृतिक यौन संबंध साबित होने बीस साल तक की सज़ा हो सकती है. न्यायालय इतनी कड़ी सज़ा अप्रमाणित साक्ष्यों के आधार पर नहीं दे सकता. मलेशिया में इस तरह के अपराध के लिए बहुत कम लोगों को सज़ा हो पाती है, क्योंकि पुख्ता प्रमाण जुटाना थोड़ा मुश्किल होता है. इब्राहिम पर पहली बार इस प्रकार का आरोप नहीं लगा है.

इससे पहले भी उन पर अप्राकृतिक यौन संबंध का आरोप लगा था. उस समय उनका जुर्म पहली बार में साबित हो गया था और उन्हें 9 वर्ष की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में उन पर लगे आरोप की समीक्षा की गई और फिर उन्हें 2004 में रिहा कर दिया गया.

इस बार न्यायालय उस तरह की ग़लती दोहराना नहीं चाहता था, इसलिए उसने साक्ष्यों की प्रामाणिकता की अच्छी तरह जांच की और जब उसे लगा कि यह काफी नहीं है तो इब्राहिम को रिहा कर दिया गया. इब्राहिम पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे थे, जिसके लिए उन्हें 6 वर्ष की सज़ा सुनाई गई थी. चूंकि अनवर इब्राहिम एक राजनीतिक व्यक्ति हैं और मलेशिया के प्रमुख विपक्षी नेता भी, इसलिए इस मुक़दमे के फ़ैसले पर सबकी नज़र टिकी हुई थी. पक्ष और विपक्ष दोनों पर फ़ैसले का प्रभाव पड़ना लाज़िमी था. अगर इब्राहिम का जुर्म साबित हो जाता तो उन्हें बीस साल तक की सज़ा हो सकती थी. ऐसा होने पर उनके राजनीतिक जीवन का अंत हो जाता. इससे सत्ता पक्ष को भी नुक़सान होता. अनवर एवं उनकी पार्टी के लोग शुरू से कहते आ रहे थे कि यह आरोप राजनीति से प्रेरित है. अगर फ़ैसला अनवर के विरुद्ध आता तो विपक्षियों का आरोप कुछ-कुछ साबित होता दिखता और 2013 में होने वाले चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नजीब रज़ाक को इस बारे में सफाई देनी पड़ती. उम्मीद इस बात की भी है कि मलेशिया में चुनाव इसी साल हो सकते हैं.

> इब्राहिम का कहना है, खुदा का शुक्र है कि न्याय की जीत हुई और मैं निर्दोष ठहराया गया. सच तो यह है कि मैं थोड़ा हैरान हूं. इस फ़ैसले ने यह साबित कर दिया है कि मलेशिया की न्यायपालिका अभी सही तरीक़ से काम कर रही है. सत्ता पक्ष भी इस अवसर को खोना नहीं चाहता. सूचना मंत्री रायेस यतिम ने कहा कि यह फ़ैसला

साबित करता है कि देशमें न्यायाधीशों को निष्पक्ष तरीक़े से काम करने का अधिकार है और सरकार न्यायपालिका के कामों में कोई हस्तक्षेप नहीं करती है. पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने कहा कि हालांकि फ़ैसले से आश्चर्य हुआ, लेकिन इससे यह साबित होता है कि इब्राहिम पर लगाया गया आरोप राजनीति से प्रेरित नहीं था और न सरकार उनके विरुद्ध कोई षड्यंत्र कर रही है. फ़ैसले से सत्ता पक्ष को बचाव का मौक़ा तो मिल गया, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि सरकार इब्राहिम के ख़िलाफ़ किसी भी प्रकार का कोई षड्यंत्र नहीं कर रही है. यह आरोप इब्राहिम के सहायक द्वारा लगाया गया था. कहा जा सकता है कि ऐसा करने के लिए उसे कोई प्रलोभन दिया गया हो. अगर मलेशिया सरकार को अपनी निष्पक्षता साबित करनी है तो उसे इस बात की जांच करानी चाहिए कि आख़िर इब्राहिम के विरुद्ध यह षड्यंत्र किसने किया है यानी इसके पीछे किसका हाथ है. न्यायालय के फ़ैसले को आधार बनाकर सरकार यह साबित नहीं कर सकती कि इस मामले में उसकी कोई भूमिका नहीं है.

ग़ौरतलब है कि अनवर इब्राहिम मलेशिया के प्रमुख विपक्षी नेता हैं और अगले चुनाव में उनकी जीत की उम्मीद जताई जा रही है. वह महातिर मोहम्मद के कार्यकाल में उप प्रधानमंत्री थे, लेकिन बाद में वह उनकी सरकार के सबसे बड़े आलोचक बन गए. इब्राहिम छात्र जीवन से ही राजनीति से जुड़े हैं. वह मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष रहे और उन्होंने 1974 में भूख और ग़रीबी के ख़िलाफ़ प्रदर्शन किया था, जिसके चलते उन्हें जेल भी जाना पड़ा. जब वह महातिर मुहम्मद के नेतृत्व वाली पार्टी यूनाइटेड मलइज नेशनल ऑर्गेनाइजेशन (यूएमएनओ) में शामिल हो गए तो उनके समर्थकों को काफी निराशा हुई. महातिर की सरकार में वह कई विभागों में मंत्री रहे. बाद में वह मलेशिया के उप प्रधानमंत्री भी बने और उन्हें महातिर मोहम्मद के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाने लगा, लेकिन जब इब्राहिम ने सरकार की आर्थिक नीति का विरोध किया और शासन में सुधार की बात उठाई, तो उनका विरोध होने लगा. वह पार्टी में भाई-भतीजावाद के विरोधी थे. महातिर मोहम्मद से अनबन होने के बाद उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, जो साबित हुआ और उन्हें 6 साल की सज़ा हुई. बाद में उन पर अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का आरोप लगा और 9 साल की सज़ा हुई, लेकिन समीक्षा के बाद उन्हें 2004 में रिहा कर दिया गया. जब चुनाव के लिए अयोग्य क़रार दिए जाने की समय सीमा समाप्त हो गई तो वह फिर राजनीति में आ गए और 2008 के उपचुनाव में उन्होंने जीत हासिल की. इसी दौरान उनके सहायक ने उन पर अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का आरोप लगा दिया, जिस पर 2010 से सुनवाई चल रही थी.

पचास सालों से शासन कर रही यूएमएनओ के ख़िलाफ़ उनका अभियान जारी है और वह लगातार प्रधानमंत्री नजीब पर हमला कर रहे हैं. हालांकि नजीब भी शासन में कई सुधार करके जनता को अपनी ओर करने की कोशिश कर रहे हैं. नजीब ने आपातकालीन आदेशों, जिसके अनुसार किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था, को रद्द कर दिया. साथ ही उन्होंने जनता को कई और सुधारों का भरोसा दिलाया है. इब्राहिम समर्थकों की संख्या भी कम नहीं है. रिहाई के वक़्त उनके तीन-चार हज़ार समर्थक अदालत के बाहर मौजूद थे. उसी समय एक विस्फोट भी हुआ, जिसका लाभ इब्राहिम को मिल सकता है. आगामी चुनाव में प्रधानमंत्री नजीब रज़्ज़ाक का सीधा मुक़ाबला इब्राहिम से है. अगर इब्राहिम ने समय का सही उपयोग किया और भ्रष्टाचार एवं भाई-भतीजावाद आदि को मुद्दा बना लिया तो उन्हें सफलता मिल सकती है. मलेशिया में आगामी सरकार किसकी होगी, यह तो दोनों दलों की रणनीति पर निर्भर करता है. सरकार विरोधी भावनाओं को इब्राहिम उभार पाते हैं या नजीब सुधारों का भरोसा दिलाकर जनता को अपने पक्ष में करने में सफल होंगे, यह तो समय बताएगा, लेकिन इतना तय है कि इस बार टक्कर कांटे की होगी.

feedback@chauthiduniya.com

देश का पहला इंटरनेट टीवी

हर दिन 50,000 से ज़्यादा दर्शक

- दो टूक-संतोष भारतीय के साथ
- ब्लैक एंड व्हाइट रोज़ाना 1 बजे
- पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया
- स्पेशल रिपोर्ट
- नायाब हैं हम-उर्दू के मशहूर शायरों, गीतकारों के साथ मुलाक़ात
- साई की महिमा

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301 www.chauthiduniya.tv

पैसे के लालच ने धरती पर भगवान का रूप कहे जाने वाले डॉक्टरों को अपने कर्तव्य से इस क़दर विमुख कर दिया है कि अब उन्हें अपने पेशे से भी नाइंसाफ़ी करने में कोई शर्म महसूस नहीं होती.

दिल्ली, 23 जनवरी-29 जनवरी 2012
चौथी दुनिया

भिक्षावृत्ति की आवश्यकता

संभव है, कुछ लोगों के मन में संदेह उत्पन्न हो कि जब बाबा इतने श्रेष्ठ पुरुष थे तो फिर उन्होंने आजीवन भिक्षावृत्ति पर ही क्यों निर्वाह किया. यह प्रश्न दो दृष्टिकोण सामने रखकर हल किया जा सकता है. पहला दृष्टिकोण यह कि भिक्षावृत्ति पर निर्वाह करने का कौन अधिकारी है. शास्त्रानुसार वे व्यक्ति, जिन्होंने तीन मुख्य आसक्तियों, कामिनी, कांचन और कीर्ति का त्याग करके आसक्ति मुक्त होकर संन्यास ग्रहण कर लिया हो, भिक्षावृत्ति के उपयुक्त अधिकारी हैं, क्योंकि वे अपने गृह में भोजन तैयार कराने का प्रबंध नहीं कर सकते. अत: उन्हें भोजन कराने का भार गृहस्थों पर ही है. श्री साई बाबा न तो गृहस्थ थे और न वानप्रस्थी. वह तो बाल ब्रह्मचारी थे. उनकी यह दृढ़ भावना थी कि विश्व ही मेरा गृह है. वह तो स्वयं ही भगवान वासुदेव, विश्वपालनकर्ता एवं पारब्रह्म थे. अत: वह भिक्षा उपार्जन के पूर्ण अधिकारी थे. दूसरा दृष्टिकोण यह कि पंचसूना यानी पांच पाप और उनका प्रायश्चित. सबको ज्ञात है कि भोजन सामग्री या रसोई बनाने के लिए गृहस्थाश्रमियों को पांच प्रकार की क्रियाएं करनी पड़ती हैं, कंडणी (पीसना), पेषणी (दलना), उदकुंभी (बर्तन मलना), मार्जनी (मांजना और धोना) और चूली (चूल्हा सुलगाना). इन क्रियाओं के परिणाम स्वरूप अनेक कीटाणुओं एवं जीवों का नाश होता है और इस प्रकार गृहस्थाश्रमियों को पाप लगता है. उन पापों के प्रायश्चित स्वरूप शास्त्रों ने पांच प्रकार केयाग (यज्ञ) करने की आज्ञा दी है:-

1. ब्रह्मयज्ञ यानी वेदाध्ययन: ब्रह्म को अर्पण करना या वेद का अध्ययन करना.
2. पितृयज्ञ: पूर्वजों को दान.
3. देवयज्ञ: देवताओं को बलि.
4. भूतयज्ञ: प्राणियों को दान.
5. मनुष्य (अतिथि) यज्ञ: मनुष्यों (अतिथियों) को दान.

यदि ये कर्म विधिपूर्वक शास्त्रानुसार किए जाएं तो चित्त शुद्ध होकर ज्ञान और आत्मानुभूति की प्राप्ति सुलभ हो जाती है. बाबा द्वार-द्वार जाकर गृहस्थाश्रमियों को इस पवित्र कर्तव्य की स्मृति दिलाते रहते थे और वे लोग अत्यंत भाग्यशाली थे, जिन्हें घर बैठे ही बाबा से शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिल जाता था. तर्खड कुटुंब (पिता और पुत्र) श्री रामचंद्र आत्माराम उपनाम बाबा साहेब तर्खड पहले प्रार्थना समाजी थे, तथापि वह बाबा के परम भक्त थे. उनकी स्त्री और पुत्र तो बाबा के एकनिष्ठ भक्त थे. एक बार उन्होंने निश्चय किया कि पुत्र एवं उसकी मां ग्रीष्मकालीन छुट्टियां शिरडी में ही व्यतीत करें, परंतु पुत्र बांद्रा छोड़ने को सहमत न हुआ. उसे भय था कि बाबा का पूजन घर में विधिपूर्वक न हो सकेगा, क्योंकि पिता जी प्रार्थना समाजी हैं और संभव है कि वह श्री साई बाबा के पूजनादि का उचित ध्यान न रख सकें, परंतु पिता द्वारा यह आश्वासन देने पर कि पूजन यथाविधि ही होता रहेगा, मां और पुत्र ने एक शुक्रवार की रात्रि में शिरडी को प्रस्थान कर दिया.

दूसरे दिन शनिवार को श्रीमान तर्खड ब्रह्म मुहूर्त में उठे और स्नानादि करके पूजन प्रारंभ करने के पूर्व बाबा के समक्ष साष्टांग दंडवत करकेबोले, हे बाबा, मैं ठीक वैसे ही आपका पूजन करता रहूंगा, जैसे मेरा पुत्र करता रहा है, परंतु कृपा करके इसे शारीरिक परिश्रम तक ही सीमित न रखना. ऐसा कहकर उन्होंने पूजन आरंभ किया और मिश्री का नैवेद्य अर्पित किया, जो दोपहर के भोजन के समय प्रसाद के रूप में वितरित कर दिया गया. उस दिन की संध्या एवं अगला दिन इतवार भी निर्विघ्न व्यतीत हो गया. सोमवार को उन्हें ऑफिस जाना था, परंतु वह दिन भी निर्विघ्न निकल गया. श्री तर्खड ने अपने जीवन में इस प्रकार कभी पूजा नहीं की थी. उनके हृदय में अति संतोष हुआ कि पुत्र को दिए गए वचनानुसार पूजा यथाक्रम संतोषपूर्वक चल रही है. अगले दिन मंगलवार को सदैव की भांति उन्होंने पूजा की और ऑफिस चले गए. दोपहर को घर लौटने पर जब वह भोजन को बैठे तो थाली में प्रसाद न देखकर उन्होंने अपने रसोइए से इस संबंध में प्रश्न किया. उसने बताया कि आज विस्मृतिवश वह नैवेद्य अर्पण करना भूल गए हैं. यह सुनकर वह तुरंत अपने आसन से उठे और बाबा को दंडवत करके क्षमा याचना करने लगे तथा उनसे उचित पथ प्रदर्शन न करने व पूजन को केवल शारीरिक परिश्रम तक ही सीमित रखने के लिए उलाहना देने लगे. उन्होंने संपूर्ण घटना का विवरण अपने पुत्र को पत्र द्वारा सूचित किया और उससे प्रार्थना की कि वह पत्र बाबा के श्रीचरणों पर रखकर उनसे कहे कि वह इस अपराध के लिए क्षमा प्रार्थी हैं. यह घटना बांद्रा में लगभग दोपहर को हुई थी और उसी समय शिरडी में जब दोपहर की आरती प्रारंभ होने ही वाली थी कि बाबा ने श्रीमती तर्खड से कहा, मां, मैं कुछ भोजन पाने के विचार से तुम्हारे घर बांद्रा गया था. द्वार पर ताला लगा देखकर भी मैंने किसी प्रकार गृह में प्रवेश किया, परंतु वहां देखा कि भाऊ (श्री तर्खड) मेरे लिए कुछ भी खाने को नहीं रख गए हैं. अत: आज मैं भूखा ही लौट आया हूं. किसी को भी बाबा के वचनों का अभिप्राय समझ में नहीं आया, परंतु श्री तर्खड का पुत्र, जो समीप ही खड़ा था, सब कुछ समझ गया कि बांद्रा में पूजन में कुछ तो त्रुटि हो गई है, इसलिए वह बाबा से लौटने की अनुमति मांगने लगा, परंतु बाबा ने आज्ञा न दी और वहीं पूजन करने का आदेश दिया. तर्खड के पुत्र ने शिरडी में जो कुछ हुआ, उसे पत्र में लिखकर पिता को भेजा और भविष्य में पूजन में सावधानी बरतने के लिए विनती की. दोनों पत्र डाक द्वारा दूसरे दिन दोनों पक्षों को मिले. क्या यह घटना आश्चर्यपूर्ण नहीं है?

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चिकित्सा अब समाजसेवा नहीं

कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले के भोगनवाला गांव निवासी शमशाद (25) को उसके परिवारीजन इलाज के लिए ज़िला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसके फेफड़ों में पानी होने की बात कहते हुए भर्ती करने से इंकार कर दिया. मरीज के परिवारीजन डॉक्टरों से घंटों मिन्नतें करते रहे, मगर अस्पताल प्रशासन अपने रवैये पर अड़ा रहा. किसी तरह मामले की भनक मीडिया को लगी और जब वहां मीडिया का जमावड़ा होने लगा तो बदनामी के डर से अस्पताल ने शमशाद को भर्ती कर लिया. इस घटना को आप क्या कहेंगे, मरीज के प्रति डॉक्टरों का प्रेम या फिर मीडिया का डर? राजस्थान में भी डॉक्टरों की हड़ताल और मरीज़ों को उससे हुई परेशानी किसी से छुपी नहीं है. राज्य सरकार द्वारा हड़ताली डॉक्टरों से बार-बार अपील के बावजूद उनका हड़ताल पर डटे रहना मरीजों के प्रति उनके गैर ज़िम्मेदाराना रवैये को दर्शाता है. क़रीब 60 मरीज़ों की मौत भी उनकी नाराजगी खत्म नहीं कर पाई.

पैसे के लालच ने धरती पर भगवान का रूप कहे जाने वाले डॉक्टरों को अपने कर्तव्य से इस क़दर विमुख कर दिया है कि अब उन्हें अपने पेशे से भी नाइंसाफ़ी करने में कोई शर्म महसूस नहीं होती. जब उनकी इस हरकत पर सरकार भी अपनी आंखें मूंद लेती है तो फिर कोलकाता के एएमआरआई अस्पताल जैसी दुर्घटना सामने आती है. ज्ञात हो कि शुरुआती जांच से यह बात सामने आई है कि अस्पताल में सभी दिशानिर्देशों को ताक पर रखते हुए कामकाज चलाया जा रहा था. अस्पताल की निचली मंजिल, जिसे बनाया तो पार्किंग के लिए गया था, परंतु उसका इस्तेमाल गोदाम के रूप में किया जा रहा था. वहां से आग शुरू हुई और देखते ही देखते उसने समूची इमारत को अपनी चपेट में ले लिया. आग से सुरक्षा के उपाय भी बहुत कमज़ोर थे और जब तक आग ने अपना विकराल रूप नहीं दिखाया, तब तक अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को सूचित करना आवश्यक नहीं समझा. अस्पताल में ऐसा कोई आपातकालीन द्वार भी नहीं था, जहां से मरीजों को बाहर निकाला जा सके. इस हादसे में क़रीब 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई. सवाल यह उठता है कि इतनी बड़ी दुर्घटना का ज़िम्मेदार कौन है? जब अस्पताल ज़रूरी दिशानिर्देशों को पूरा नहीं कर रहा था तो उसे चलाने की अनुमति क्यों दी गई? क्या किसी दुर्घटना के बाद मुआवजा देना ही समस्या का समाधान है?

सरकारी अस्पतालों की हालत किसी से छुपी नहीं है. साफ़-सफ़ाई के बजाय यहां इतनी गंदगी होती है कि मामूली बुखार का इलाज कराने आए मरीज को भी डेंगू और मलेरिया जैसी ख़तरनाक बीमारी हो जाए. अब तो यहां ग़रीब मरीज भी इलाज कराने से कतराता है. डॉक्टरों का समय पर न आना और मरीज देखने के समय निजी अस्पतालों में अपनी सेवाएं देना आम बात है. यदि इससे भी दिल नहीं भरता है तो कोई भी बहाना लेकर वे हड़ताल पर चले जाते हैं. लैब में अक्सर आपको अस्पताल का सफ़ाई कर्मचारी ख़ून टेस्ट करता मिल जाएगा. सबसे ज़्यादा समस्या उन मरीजों को होती है, जिनका इलाज ईएसआई के माध्यम से होता है. सरकार हर महीने एक निर्धारित राशि उनकी आय से काटती है. पहले यह योजना उन कर्मचारियों पर लागू थी, जिनकी मासिक आय दस हज़ार रुपये से भी कम थी, अब यह सीमा पंद्रह हजार रुपये कर दी गई है. इसके पीछे यह तर्क दिया जाता है कि सरकार इसके माध्यम से उन्हें स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करती है, परंतु ध्यान देने योग्य बात यह है कि सरकार ने ईएसआई का दायरा तो बढ़ा दिया, लेकिन अस्पतालों की संख्या नहीं बढ़ाई. परिणामस्वरूप इन अस्पतालों में मरीजों की लंबी कतारें लगी रहती हैं. कार्य निपटान को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा सभी अस्पतालों की व्यवस्था कंप्यूटरीकृत कर दी गई, परंतु कंप्यूटर प्रशिक्षण का कोई इंतजाम नहीं किया गया, जिसके चलते काम जल्दी होने के बजाय और अधिक देर से होते हैं. एक छोटा सा टेस्ट कराने और फिर उसकी रिपोर्ट पाने के लिए मरीजों को कई सप्ताह इंतजार करना पड़ता है. निजी लैब वालों से साठगांठ करके अधिकतर टेस्ट किसी न किसी बहाने से उनके पास भेज दिए जाते हैं. और तो और, अस्पतालों का अदना कर्मचारी भी अक्सर मरीजों से दुर्व्यवहार कर बैठता है. तंग आकर जब मरीज निजी अस्पताल का रुख़ करता है तो वहां इलाज की फीस सुनकर वह स्वयं को ग़रीब अथवा अल्प मध्यमवर्गीय होने के लिए कोसने लगता है. (चरखा)

सरकारी अस्पतालों की हालत किसी से छुपी नहीं है. साफ़-सफ़ाई के बजाय यहां इतनी गंदगी होती है कि मामूली बुखार का इलाज कराने आए मरीज़ को भी डेंगू और मलेरिया जैसी ख़तरनाक बीमारी हो जाए. अब तो यहां ग़रीब मरीज़ भी इलाज कराने से कतराता है. डॉक्टरों का समय पर न आना और मरीज़ देखने के समय निजी अस्पतालों में अपनी सेवाएं देना आम बात है.

अबु बुशरा कासमी
feedback@chauthiduniya.com

साधना अग्रवाल ने पहला नाम मेवाराम के उपन्यास सुल्तान रजिया का दिया है. हो सकता है कि मेवाराम का यह उपन्यास बेहतर हो.

अनंत विजय

2011: उल्लेखनीय कृति का रहा इंतज़ार

वर्ष 2011 ख़त्म हो गया. देश के विभिन्न समाचारपत्र–पत्रिकाओं में पिछले वर्ष प्रकाशित किताबों का लेखा–जोखा छपा. पत्र–पत्रिकाओं में जिस तरह के सर्वे छपे, उससे हिंदी प्रकाशन की बेहद संजीदा तस्वीर सामने आई. एक अनुमान के मुताबिक़, तक़रीबन डेढ़ से दो हज़ार किताबों का प्रकाशन पिछले साल भर में हुआ. लेखा–जोखा करने वाले लेखकों ने हर विधा में कई पुस्तकों को उल्लेखनीय तो कई पुस्तकों को साहित्यिक जगत की अहम घटना करार दिया. कुछ समीक्षकों ने तो चुनिंदा कृतियों को महान कृतियों की श्रेणी में भी रख दिया. मैं उन समीक्षकों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन अगर हम वस्तुनिष्ठता के साथ पिछले वर्ष के हिंदी साहित्य पर नज़र डालें तो पाते हैं कि बीता वर्ष रचनात्मकता के लिहाज़ से उतना उर्वर नहीं रहा, जितना साहित्यिक सर्वे में हमें दिखा. मैंने पिछले वर्ष जितना पढ़ा या फिर यह कह सकता हूं कि जिन कृतियों के बारे में पढ़ा, उसके आधार पर जो एक तस्वीर उभर कर सामने आती है, वह बहुत निराशाजनक है. अगर हम हर विधा के हिसाब से बात करें तो भी हिंदी साहित्य में कोई आउटस्टैंडिंग कृति के आने का दावा नहीं कर सकते.

अगर हम हिंदी साहित्य में उपन्यास के परिदृश्य को देखें तो पिछले साल साहित्य की इस विधा में दर्जनों किताबें प्रकाशित हुईं, कईयों की चर्चा भी हुई, लेकिन कोई भी किताब साहित्य जगत में धूम मचा दे, यह हो नहीं सका. कुछ दिनों पहले एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर समीक्षक साधना अग्रवाल ने पिछले वर्ष प्रकाशित दस किताबों की सूची जारी की. साधना अग्रवाल ने उन्हीं किताबों के आधार पर तहलका में लेख भी लिखा. फेसबुक पर मेरा और साधना जी का संवाद भी हुआ. वहां भी मैंने यह संकेत करने की कोशिश की थी कि इस वर्ष कुछ भी उल्लेखनीय नहीं छपा. यहां मैं अगर उल्लेखनीय कह रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि वर्ष भर उस कृति की चर्चा हो और उसके बहाने साहित्य में विमर्श भी हो. इसके अलावा साहित्यिक पत्रिका हंस और पाखी में भी साल भर की किताबों पर विस्तार से लेख छपे. हंस में अशोक मिश्र ने उपन्यासों की पूरी सूची दी. अशोक मिश्र के मुताबिक़, हरिसुमन बिष्ट का उपन्यास बसेरा साल का सबसे अच्छा उपन्यास है. उन्होंने श्रमपूर्वक उपन्यासों की एक पूरी सूची गिनाई है, लेकिन बिष्ट के उपन्यास को सबसे अच्छा क्यों माना, इसकी वजह नहीं बताई. हो सकता है कि अशोक मिश्र की राय में दम हो, लेकिन हिंदी जगत में बिष्ट का यह उपन्यास अननोटिस्ड रह गया.

हंस के सर्वेक्षण में आलोचना विधा में पहला नाम निर्मला जैन की किताब कथा समय में तीन हमसफर का है. पता नहीं, अशोक मिश्र को निर्मला जैन की किताब आलोचना की किताब कैसे लगी, ज़्यादा से ज़्यादा उस किताब को संस्मरणात्मक समीक्षा कह सकते हैं. निर्मला जैन की उक्त किताब में उनकी तीन सहेलियों के घर–परिवार से लेकर नाते– रिश्तेदार सभी मौजूद हैं. उस किताब को पढ़ने के बाद मेरी जो राय बनी, वह यह है कि निर्मला जैन का लेखन बेहद कंफ्यूज्ड है और वह क्या लिखना चाहती थीं, यह साफ ही नहीं हो पाया. आलोचना में जिन नामों को उन्होंने प्रमुख किताबें माना है, उनमें से

हंस के सर्वेक्षण में आलोचना विधा में पहला नाम निर्मला जैन की किताब कथा समय में तीन हमसफर का है. पता नहीं, अशोक मिश्र को निर्मला जैन की किताब आलोचना की किताब कैसे लगी, ज़्यादा से ज़्यादा उस किताब को संस्मरणात्मक समीक्षा कह सकते हैं. निर्मला जैन की उक्त किताब में उनकी तीन सहेलियों के घर-परिवार से लेकर नाते- रिश्तेदार सभी मौजूद हैं.

ज़्यादातर लेखों के संग्रह हैं या फिर कुछ संपादित किताबें. पाखी में भारत भारद्वाज के लेख पर टिप्पणी करने से मैं अपने आपको रेस्कयू कर रहा हूं. तहलका में साधना अग्रवाल ने अपने चयन को सीमित किया है और सिर्फ़ दस किताबों पर बात की है. इसका एक फ़ायदा यह हुआ कि दस किताबों के बारे में संक्षिप्त ही सही, जानकारी तो मिली.

साधना अग्रवाल ने पहला नाम मेवाराम के उपन्यास सुल्तान रजिया का दिया है. हो सकता है कि मेवाराम का यह उपन्यास बेहतर हो, लेकिन अगर यह इतना अच्छा था तो हिंदी जगत में इस पर चर्चा होनी चाहिए थी, जो सर्वेक्षणों के अलावा ज़्यादा दिखी नहीं. सूची में और नाम हैं– मंजूर एहतेशाम का मदरसा, प्रदीप सौरभ का उपन्यास तीसरी ताली, ओम थानवी का यात्रा संस्मरण मुअनजोदड़ो. तीसरी ताली मैंने पढ़ी है और मुझे लगता है कि इस उपन्यास का न तो विषय नया है और न कहने का अंदाज़. इस विषय पर अंग्रेजी में कई किताबें लिखी जा चुकी हैं. प्रदीप सौरभ के उपन्यास तीसरी ताली और पूर्व में प्रकाशित रेवती के उपन्यास अ ट्रूथ अबाउट में संयोगवश कई समानताएं देखी जा सकती हैं. अब अगर जनसत्ता के संपादक ओम थानवी के यात्रा संस्मरण मुअनजोदड़ो पर बात करें तो हम देखते हैं कि इस किताब की समीक्षा हिंदी की लगभग सभी पत्र–पत्रिकाओं में छपी. एक अनुमान के मुताबिक़, इस किताब की तक़रीबन दो से तीन दर्जन समीक्षाएं तो मेरी ही नज़र से गुजरी होंगी. ओम थानवी यशस्वी संपादक हैं, देश–विदेश में घूमते रहते हैं. उनका यह यात्रा संस्मरण अच्छा है, लेकिन हिंदी में यात्रा संस्मरणों की जो समृद्ध परंपरा रही है, उसमें मुअनजोदड़ो ने थोड़ा ही जोड़ा है. इसके अलावा साधना अग्रवाल की सूची में जो अहम नाम है, वह है विश्वनाथ त्रिपाठी की किताब व्योमकेश दरवेश. इस किताब की भी ख़ूब समीक्षाएं छपीं, लेकिन हिंदी के आलोचकों में इसको लेकर दो मत हैं. कुछ लोगों को यह कृति कालजयी लग रही है तो कई नामवर आलोचकों ने इस कृति को साधारण क़रार दिया, जिसमें तथ्यात्मक भूलों के अलावा बहुत ज़्यादा दोहराव है. मैंने दो सर्वेक्षणों का जिक्र इसलिए किया, ताकि एक अंदाज़ा लग सके कि हिंदी में पिछले वर्ष किन रचनाओं को लेकर सर्वेक्षणकर्ताओं ने उत्साह दिखाया. मैं जो एक बड़ा सवाल खड़ा करना चाहता हूं, वह यह कि हिंदी में पिछले वर्ष जो रचनाएं छपीं, उन्हें लेकर हिंदी साहित्य में कोई खासा उत्साह देखने को नहीं मिला. मैं यह बात पाठकों के पाले में डालता हूं कि वे यह तय करें और विचार करें कि क्या पिछले वर्ष गालिब छूटी शराब, मुझे चांद चाहिए, चाक, आंवा, कितने पाकिस्तान जैसी कोई कृति छपी. मैं सर्वेक्षणकर्ताओं और हिंदी के आलोचकों के सामने भी यह सवाल खड़ा करता हूं कि वे इस बात पर ग़ौर करें कि बीते वर्षों में कोई अहम कृति सामने क्यों नहीं आ पा रही है, क्या हिंदी लेखकों के सामने रचनात्मकता का संकट है या फिर जो स्थापित लेखक हैं, वे चुकने लगे हैं और नए लेखकों के लेखन में वह कलेवर नहीं है या फिर कहें कि उनकी लेखनी पर अभी सान नहीं चढ़ पाई है कि वे हिंदी साहित्य जगत को झकझोर सकें.

पिछले दिनों सामयिक प्रकाशन के सर्वेसर्वा और मित्र महेश भारद्वाज से बात हो रही थी तो मैंने यूं ही उनसे पूछ लिया कि पिछले कई सालों से आंवा जैसी कृति क्यों नहीं छाप रहे हैं. महेश जी ने जो बात कही, उसने मुझे झकझोर दिया. महेश भारद्वाज के मुताबिक़, आज का हिंदी का लेखक डूबकर लेखन नहीं कर रहा है, पाठकों के बदलते मिज़ाज को समझ भी नहीं पा रहा है और लेखकों से पाठकों की नब्ज़ छूटती हुई सी प्रतीत होती है. आज हिंदी के लेखकों का ज़्यादा ध्यान लेखन के बजाय पुरस्कार–सम्मान पाने की तिकड़मों में लगा है. अगर हिंदी का लेखक इन तिकड़मों के बजाय अपने विषय पर ध्यान केंद्रित करे और विषय में डूबकर लिखे तो हिंदी जगत को पिछले एक दशक से जिस मुझे चांद चाहिए, आंवा और चाक जैसी कृतियों का इंतज़ार है, वह ख़त्म हो सकता है. बातों–बातों में महेश भारद्वाज ने बहुत बड़ी बात कह दी है, जिस पर हिंदी के लेखकों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्रकाशक होने की वजह से वह पाठकों के बदलते मन–मिज़ाज से तो वाक़िफ़ हैं ही.

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)
anant.ibn@gmail.com

महेंद्र अवधेश

जहां चाह, वहां राह

एक अच्छी कोशिश हमेशा प्रशंसनीय होती है, लेकिन जब ऐसी कोई कोशिश नए और संसाधनों का अभाव झेलने वाले लोग करते हैं तो वे दो–चार अच्छे शब्दों और शाबाशी के हक़दार ख़ुद–बख़ुद हो जाते हैं. त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिका समसामयिक सृजन इसकी मिसाल है. इसका सितंबर–दिसंबर 2011 अंक कविता विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ है. यह पत्रिका दिल्ली विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा पूरी करके निकले दो युवा, महेंद्र प्रजापति एवं साक्षी अपने सुयोग्य एवं साहित्यप्रेमी शिक्षकों डॉ. प्रभात कुमार एवं डॉ. रमा के मार्गदर्शन में निकाल रहे हैं.

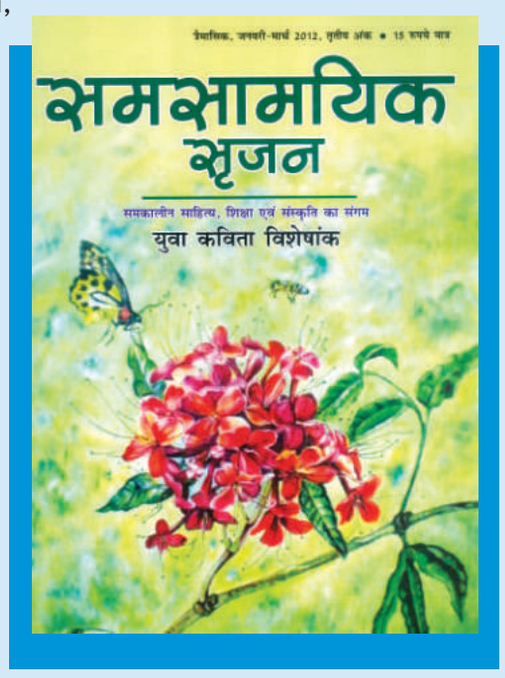

कई वरिष्ठ लेखकों–कवियों के सारगर्भित लेखों और युवा कवियों, खासकर नए कवियों की रचनाओं से सज़ा यह विशेषांक बताता है कि अगर मन में चाह हो तो कोई भी अभाव आपके रास्ते में बाधा नहीं बन सकता. युवा कविता: सारे दृश्य बदल रहे हैं, आज का युवा कवि और युवा काव्य दृष्टि की सूक्ष्मता: युगीन यथार्थ का प्रतिरूप आदि गंभीर आलेखों के ज़रिए वरिष्ठ साहित्यकार नीलाभ, डॉ. सत्यकेतु सांकृत एवं अशोक गुप्ता ने विशेषांक को मज़बूती प्रदान की है. इसके अलावा डॉ. सीमा शर्मा, दीविक रमेश, आर सी पांडेय एवं अभिषेक सचान के आलेख भी उल्लेखनीय हैं. इस कविता विशेषांक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें युवा, खासकर नए कवियों की रचनाओं को उनका सम्मानजनक स्थान हासिल हुआ है. छात्र एवं रंगकर्मी राजकमल की रचना अधूरापन काफी प्रभावित करती है. जीवन की भाग–दौड़, रोजी–रोटी की जद्दोजहद हर संवेदनशील शख्स को अक्सर इस दर्द से दो–चार करती है कि वह कहीं न कहीं अधूरा रहा जाता है, ख़ुद से दूर हुआ जाता है, अपने प्रियजनों से छूटा जाता है और इसी छटपटाहट में जन्म लेती हैं ये पंक्तियां:–

मैं वापस लौटना चाहता हूं/अपने घर
अपने संपूर्ण रूप में/लेकिन कुछ न कुछ
बाहर ही रह जाता है मेरा.

संस्कारों का जीवन में काफी महत्व है. बिना संस्कार जीवन निरर्थक है. संस्कार जन्मजात नहीं होते, बल्कि संस्कार रोपे जाते हैं घर में, समाज में और तब तैयार होता है एक संस्कारवान व्यक्तित्व. प्रेरणा दुबे ने अपनी कविता–अच्छी लड़की में इसी सत्य की ओर इशारा किया है:–

पैदा नहीं होती वरन्/बनाई जाती है अच्छी लड़की
बोकर अच्छे संस्कार जन्म से/उगाई जाती है अच्छी लड़की.

युवा हस्ताक्षर अभिषेक अंशु ने अपनी कविता में तंग बस्तियों यानी महानगरों में यत्र–तत्र बसी झोपड़पट्टियों, मलिन बस्तियों का दर्द बयान किया है कि ऐसी बस्तियां होकर भी नहीं होतीं. वे अस्तित्व में हैं, लेकिन व्यवस्था की नज़र में उनका कोई महत्व नहीं है:–

हर शहर के आखिरी छोर पर/होती हैं तंग बस्तियां
योजनाओं की सूची में/जिनका क्रम भी
अक्सर आखिरी ही होता है/ रेल की पटरियां
ठीक बीच से चीरती हैं/इन बस्तियों को
शहर भर की गंदगी/इन्हीं के आसपास होकर
गुजरती है/इनके नामों में
गांधी और अंबेडकर की घुसपैठ रहती है.

प्रज्ञा गुप्ता ने अपनी रचना में राखी जैसे पावन पर्व पर एक बहन द्वारा अपने भाई की प्रतीक्षा का वर्णन किया है कि उन पलों में उसकी मनोदशा क्या होती है, उसकी हर गतिविधि में किस तरह शामिल रहता है अपने भाई का इंतज़ार:–

आने वाला है त्योहार/राखी बंधन का
ससुराल में बहन/सरियाती है रोज
घर–आंगन–द्वार/तुलसी चौरा के पास
निहोरा करती है आंगन में/दिन में कई बार
दरवाजे के पार पदचाप सुन/चिंहुक उठती है.

कवि अजय मेहताब ने एक रचनाकार के शिकारीपन पर बड़ी बेबाकी से कलम चलाई है:–

सड़क पर/कलम और डायरी थामे
शिकारी सा एक रचनाकार/अक्सर ढूंढता कोई शिकार
गिद्ध सी नज़रों से/ताड़ता कई दृश्य
किसी का झगड़ना/इंतज़ार किसी पागल का.

इनके अलावा शोभा मिश्रा, विभा नायक, सरिता सलिल, नितिन सारंग, प्रियोबती निङथौजा, सुमन सिंह, विजय कुमार सिंह, आशीष कुमार अंशु एवं बृजराज सिंह आदि रचनाकार भी अपनी कविताओं के ज़रिए काफी प्रभावित करते हैं.

m_awdhesh@chauthiduniya.com

किताब मिली

पुस्तक का नाम
कंप्यूटर क्या है

लेखक
गुणाकर मुळे

प्रकाशक
राजकमल प्रकाशन

मूल्य
250 रुपये

इस किताब में कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण और विस्तृत जानकारी है.

लेखक और प्रकाशक इस कॉलम के लिए अपनी किताबें हमें भेज सकते हैं.
चौथी दुनिया एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301
ई मेल : feedback@chauthiduniya.com

कंपनी ग्राहकों की उम्मीदों एवं ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए नई श्रेणी के वाहन पेश करेगी.

देशी सुपर कार अवंती

जहां एक तरफ़ जॉन अब्राहम ने यामहा के स्टॉल की रौनक़ बढ़ाई, वहीं बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन मशहूर कार डिज़ाइनर दिलीप छाबड़िया की सुपर कार अवंती के स्टॉल पर जलवा बिखेरते नज़र आए. अमिताभ को भी कारों का बहुत शौक़ है और शायद यही कारण है कि उनके पास ख़ुद की एक से बढ़कर एक शानदार कारें हैं, जिनमें रॉल्स रायस प्रमुख है. अमिताभ बच्चन ने देश की पहली सुपर कार अवंती का अनावरण किया और इस शानदार कार की जमकर तारीफ़ भी की. आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन को हाल में देश की जानी-मानी वाहन निर्माता कंपनी फोर्स ने अपने एसयूवी फोर्स वन को पेश करने के दौरान ब्रांड अम्बेस्डर भी बनाया था. देश की पहली सुपर कार अवंती फेरारी और लेम्बोर्गिनी को टक्कर देगी.

भारतीय बाज़ार में सुपर कारों की मांग में ज़बरदस्त तेज़ी देखनें को मिल रही है. हाल में भारतीय बाज़ार में दुनिया भर में एक से बढ़कर एक शानदार कारों को पेश करने वाली जानी-मानी कार निर्माता कंपनी फेरारी ने अपनी शानदार स्पोर्ट्स कार एफएफ को पेश किया था. उसके बाद लेम्बोर्गिनी ने अपनी सुपर कार अवेंटाडोर को पेश किया, लेकिन आपको बता दें कि इन सभी कारों को टक्कर देने के लिए दिलीप छाबड़िया की शानदार सुपर कार अवंती आ गई है. दिलीप छाबड़िया दुनिया भर में अपने शानदार डिज़ाइन के लिए मशहूर हैं. उन्होंने इस बार ऑटो एक्सपो में अपनी इस शानदार कार अवंती को पेश किया. आपको बता दें कि इस कार को पुणे स्थित संयंत्र में तैयार किया गया है. इस कार को पेश करने के दौरान दिलीप छाबड़िया ने बताया कि मेरी यह सुपर कार एक बेहतरीन लुक के साथ-साथ अच्छी गुणवत्ता का अहसास कराती है. उन्होंने दावा किया है कि उनकी यह नई सुपर कार फेरारी और लेम्बोर्गिनी को भी मात दे देगी. दिलीप ने बताया कि देखने और राइडिंग में यह कार बिलकुल फेरारी और लेम्बोर्गिनी की सुपर कारों की ही तरह है, बस इंजन की शक्ति क्षमता उन कारों से थोड़ी सी कम है. फ़िलहाल इस कार को पेश किया गया है. अभी दिलीप छाबड़िया अपने इस कार को उत्पादन स्तर तक ले जाने में प्रयासरत हैं.

दिलीप छाबड़िया ने अवंती में फोर्ड के 2 लीटर का इंजन प्रयोग किया है. इसके अलावा इस कार में शानदार 6-स्पीड की मैनुअल गियर बॉक्स का भी शानदार प्रयोग किया गया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह कार भारतीय बाज़ार में अगले वर्ष 2013 तक बिक्री के लिए पेश कर दी जाएगी. फ़िलहाल दिलीप अपनी इस कार के 300 मॉडल का उत्पादन करने की योजना बना रहे हैं.

डूकाटी मॉन्सटर-795

दुनिया भर में एक से बढ़कर एक शानदार बाइकों को पेश करने वाली इतालवी वाहन निर्माता कंपनी डूकाटी ने ग्यारहवें ऑटो एक्सपो में अपनी शानदार बाइक मॉन्सटर 795 को पेश किया. आपको बता दें कि बेहद ही शानदार इंजन क्षमता और आकर्षक लुक वाली इस बाइक की क़ीमत भारतीय बाज़ार में कुल 6.99 लाख रुपये तय की गई है. ग़ौरतलब हो कि भारतीय ऑटोमोबाइल बाज़ार को इस शानदार बाइक का बहुत दिनों से इंतज़ार था. दिल्ली ऑटो एक्सपो में इस बाइक को पेश करने के दौरान डूकाटी इंडिया के सीईओ आशीष कोर्डिया ने बताया कि हमने इस बाइक को भारतीय बाज़ार में वाजिब क़ीमत में पेश किया है. कोर्डिया ने बताया कि इस बाइक को विशेषकर एशियन बाज़ार को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इस बाइक 6-स्पीड गियर बॉक्स और 800 सीसी की क्षमता का दमदार एल-ट्वीन एअर कूल्ड इंजन का प्रयोग किया गया है. यह इंजन बाइक को 87 पीएस की शक्ति प्रदान करता है. इस बाइक की दमदार 78 एनएम टॉर्क 6250 आरपीएम के साथ फर्राटा भरने में सक्षम है. भारतीय बाज़ार में डूकाटी के डीलर्स की संख्या केवल तीन ही है, लेकिन कंपनी अब अपने डीलर्स की संख्या को बढ़ाकर लगभग 13 करने की सोच रही है. ग़ौरतलब हो कि भारतीय ग्राहकों के बीच भी हैवी सीसी की इंजन क्षमता की शानदार बाइकों का क्रेज़ बढ़ता जा रहा है.

नई डूकाटी मॉन्सटर का कुल वज़न 167 किलोग्राम है. मॉन्सटर में कंपनी ने बेहतरीन आधुनिक तकनीकी का प्रयोग किया है. इस बाइक में बेहतरीन एपीटीसी वेट मल्टीप्लेट हाइड्रीक्यूलिक क्लच का इस्तेमाल किया गया है. शानदार सीटिंग अरेंजमेंट और बेहतरीन स्पोर्टी लुक किसी को भी अपना दीवाना बनाने में सक्षम है.

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

कैटरीना का जलवा

कैटरीना ने इस बार ऑटो एक्सपो में लग्जरी सिडान कार ऑडी क्यू3 2.0 क्वार्टो को पेश किया.

करोड़ों दिलों की धड़कन और बार्बी गर्ल कैटरीना कैफ इस बार ऑटो एक्सपो में दुनिया भर में एक से बढ़कर एक लग्ज़री कारों को पेश करने वाली जर्मनी की कार निर्माता कंपनी ऑडी के स्टॉल पर जलवा बिखेरती नज़र आईं. कैटरीना ने इस बार ऑटो एक्सपो में लग्ज़री सिडान कार ऑडी क्यू3 2.0 क्वार्टो को पेश किया. कैटरीना कैफ इस समय बॉलीवुड में अपने लटकों-झटकों से हर दिल की चहेती बनी हुई हैं. इसी का फ़ायदा उठाने के लिए ऑडी ने अपनी ब्यूटीफुल कार को इस शानदार ब्यूटी के हाथों पेश कराया. कार को पेश करने के दौरान ऑडी के स्टॉल पर कैटरीना के फैंस की भारी भीड़ मौजूद थी.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

शेवरले ने पेश की शानदार कार ईएन-वी

दुनिया की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी जनरल मोटर्स की ब्रांड शेवरले ने ग्यारहवें ऑटो एक्सपो में अपने कई वाहनों के बीच एक बेहद ही अद्भुत कार को पेश किया. देखने में यह आपको अजीब ज़रूर लग रही हो, लेकिन शेवरले की यह भविष्य की इलेक्ट्रिक कार ईएन-वी है. इस कार को देखने के लिए शेवरले के स्टॉल पर लोगों की भारी भीड़ जमा थी. लोगों के दिमाग़ में यह सवाल बरबस ही उठ रहा था कि आख़िर कैसे चलेगी यह कार. आइए हम आपको बताते हैं इस कार के बारे में. आपको बता दें कि शेवरले ने इस ईएन-वी को हाल में टोक्यो मोटर शो में भी पेश किया था, जहां इस शानदार कार ने ख़ूब वाहवाही लूटी थी. शेवरले की इस छोटी कार में कुल दो सीटें हैं और कंपनी ने इस कार को विशेषकर शहरी क्षेत्र के भारी यातायात को ध्यान में रखकर तैयार किया है. भारी यातायात के बीच ईंधन की खपत ज़्यादा होने के कारण यह इलेक्ट्रिक कार एक बेहतर विकल्प बनकर उभरेगी. नई शेवरले ईएन-वी में ईंधन का प्रयोग न होने के कारण इससे प्रदूषण भी कम होगा. ईएन-वी के पूरे नाम पर ग़ौर करें तो यह इलेक्ट्रिक नेटवर्क व्हीकल के नाम पर रखा गया है. कंपनी फ़िलहाल अपने इस कांसेप्ट मॉडल पर काम कर रही है. फ़िलहाल कंपनी ने इस कार के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी है.

टीवीएस का इलेक्ट्रिक स्कूटर क्यूब

देश की जानी-मानी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी टीवीएस ने दिल्ली ऑटो एक्सपो में अपने शानदार इलेक्ट्रिक पॉवर स्कूटर को पेश किया है. फ़िलहाल कंपनी ने इसका कांसेप्ट वर्जन ही पेश किया है. बेहद ही आकर्षक लुक और शानदार इंजन क्षमता से लबरेज़ यह स्कूटर जल्द ही भारतीय बाज़ार में बिक्री केलिए पेश किया जाएगा. आपको बता दें कि भारतीय बाज़ार में ईंधन की क़ीमतों में आए उछाल के कारण वाहन निर्माता हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ़ तेज़ी से रुख़ कर रहे हैं. ग़ौरतलब हो कि फ़िलहाल कंपनी ने क्यूब का केवल डिज़ाइन मात्र ही पेश किया है और अभी कंपनी अपने इस प्रोजक्ट पर काम रही है. हालांकि कंपनी की तरफ़ से इस वाहन को बाज़ार में उतारे जाने की तारीख़ आदि के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है.जानकारों का मानना है कि टीवीएस अपने इस हाइब्रिड स्कूटर क्यूब को आगामी दो वर्ष के बीच बाज़ार में पेश कर सकती है. कंपनी ने इस पॉवर स्कूटर को एक शानदार लुक देने के साथ-साथ बेहतरीन फीचर्स के साथ पेश किया है. टीवीएस क्यूब में बेहतरीन सीटिंग अरेंजमेंट और एलसीडी डिस्पले का प्रयोग किया गया है. क्यूब के सामने वाइजर पर ही एक्जॉस्ट सिस्टम का प्रयोग किया गया है, जो वाहन के इंजन के गर्म होने पर उसे ठंडा रखेगा. टीवीएस क्यूब पूरी तरह से एक हाइब्रिड स्कूटर है, जो भारतीय बाज़ार में शानदार प्रदर्शन करेगी.

रॉयल इन्फील्ड की थंडरबर्ड-500

दुनिया भर में एक से बढ़कर एक शानदार बुलेट बाइकों को पेश करने वाली देश की वाहन निर्माता कंपनी रॉयल इंफिल्ड ने दिल्ली ऑटो एक्सपो में अपनी उपस्थिती दर्ज कराते हुए शानदार बाइक थंडरबर्ड 500 को पेश किया. प्राप्त जानकारी के अनुसार, भारतीय बाज़ार में जल्द ही इस बाइक को बिक्री के लिए पेश किया जाएगा. इस बाइक को पेश करने के दौरान आयशर मोटर्स के प्रबंध निदेशक सिद्धार्थ लाल ने बताया कि हमने इस बाइक को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को ध्यान में रखकर तैयार किया है. यह बाइक उन लोगों के लिए बेहद शानदार साबित होगी, जो लंबी दूरी तय करते हैं. बेहद शानदार लुक और बेहतरीन इंजन क्षमता के साथ रॉयल इंफिल्ड ने इस बाइक को पेश किया है. कंपनी ने बाइक का ब्रेकिंग सिस्टम बेहतर बनाया है. दोनों ही पहियो में डिस्क ब्रेक बख़ूबी इस्तेमाल किया गया है, जो तेज़ से तेज़ रफ्तार में भी आपको बेहतरीन संतुलन प्रदान करता है. इसके अलावा नई थंडरबर्ड 500 का सीटिंग अरेंजमेंट भी काफ़ी बेहतर है. बाइक की सीट को कंपनी ने इस तरह से तैयार किया है, जो चालक को लंबी दूरी पर भी आरामदेह सफ़र प्रदान करता है. हालांकि कंपनी ने अपनी इस नई बाइक की क़ीमत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है.

मारुति की एसयूवी एक्स-ए अल्फा

देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने 11वें ऑटो एक्सपो में अपने वाहनों को पेश किया है. दिल्ली ऑटो एक्सपो में मारुति सुजुकी ने एसयूवी एक्सए अल्फा पेश करते हुए नए खंड में उतरने की घोषणा की. मारुति की इस एसयूवी एक्सए अल्फा को मारुति सुजुकी के प्रबंध निदेशक शिंजो नाकानिशि ने दुनिया के सामने पेश किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग तथा सरकारी समर्थन के बल पर भारत दुनिया में शीर्ष ऑटोमोबाइल अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने जा रहा है. उन्होंने कहा कि कंपनी ग्राहकों की उम्मीदों एवं ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए नई श्रेणी के वाहन पेश करेगी. उन्होंने कहा कि कंपनी के-सीरिज इंजन रेंज का विस्तार करेगी और डीजल वाहन पेश करना जारी रखेगी. बेहद ही शानदार लुक और बेहतरीन स्पेस वाली इस एसयूवी को कंपनी जल्द से जल्द भारतीय बाज़ार में पेश करने की सोच रही है. इसके अलावा उसकी नए उत्पाद पेश करने की भी योजना है. उन्होंने बताया कि प्रस्तावित एक्सए अल्फा को सुजुकी मोटर कोर्प तथा मारुति सुजुकी इंडिया के अभियंताओं ने मिलकर लगभग दस माह में विकसित किया है. दुनिया की प्रमुख वाहन प्रदर्शनियों में से एक इस ऑटो एक्सपो में लगभग 50 अंतरराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पादों को पेश करेंगी. इसमें घरेलू कंपनियां 24 तथा विदेशी कंपनियां आठ नई कारें पेश करेंगी. इसके अलावा मोटरसाइकिल के आठ नए मॉडल भी आने हैं. कंपनी का दावा है कि भारतीय बाज़ार में इस कार को किफ़ायती क़ीमत के साथ पेश किया जाएगा.

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

तनिष्ठा के पास बुद्धदेव दासगुप्ता जैसे निर्माता की भी एक फिल्म का ऑफर है. इसके अलावा वह श्याम बेनेगल, मधुर भंडारकर एवं शिमित अमीन जैसे निर्देशकों के साथ काम करना चाहती हैं.

समानांतर सिनेमा की महारानी

ग्लोबलाइज़ेशन का दौर है, पूरी दुनिया सिमट गई है. जहां भी अच्छा काम मिलेगा, मैं करती रहूंगी. फिर मैं तो भारतीय हूं, ऐसे में बॉलीवुड से दूरी बनाकर कैसे रह सकती हूं, यह कहना है तनिष्ठा चटर्जी का. उन्होंने अब तक ज़्यादातर रियलिस्टिक फिल्में की हैं. उनकी आने वाली फिल्में भी कमोबेश ऐसी हैं. उनकी रुचि ऐसी फिल्मों में इसलिए है, क्योंकि ये न केवल आम लोगों से जुड़ी होती हैं, बल्कि इनके दर्शक बुद्धिजीवी होते हैं. ऐसी फिल्मों और इनके किरदारों से उनका जुड़ाव जल्दी हो जाता है. तनिष्ठा बॉलीवुड में दोबारा सक्रिय ज़रूर हो गई हैं, लेकिन यहां भी वह सार्थक और अच्छी फिल्में ही करना चाहती हैं. उन्होंने शौकिया तौर पर एक्टिंग में क़दम रखा है, इसलिए चालू या फॉर्मूला फिल्में करने का उनका कोई इरादा नहीं है. वह जिन फिल्मकारों के साथ काम कर रही हैं, वे सभी ख़ास किस्म की फिल्मों के मास्टर हैं. इसीलिए उनकी फिल्में निर्माण के समय से ही चर्चा में आ जाती हैं. तनिष्ठा के पास बुद्धदेव दासगुप्ता जैसे निर्माता की भी एक फिल्म का ऑफर है. इसके अलावा वह श्याम बेनेगल, मधुर भंडारकर एवं शिमित अमीन जैसे निर्देशकों के साथ काम करना चाहती हैं. इरफान खान, नसीरूद्दीन शाह, विजयराज, सतीश कौशिक एवं नीना गुप्ता आदि के साथ काम कर चुकीं तनिष्ठा बॉलीवुड की कई अच्छी फिल्में कर रही हैं. राजा मेनन की बारह आना, एनएफडीसी की व्हाइट एलीफैंट, सुधीर मिश्रा की साइलेंस फिल्म द सनराइज के अलावा वह देव बेनेगल की भी एक फिल्म कर रही हैं. अनवर जमाल की नेशनल अवॉर्ड विजेता फिल्म स्वराज में बेहतर अभिनय के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट किया गया था. बाद में उन्होंने अपना रुख़ इंटरनेशनल फिल्मों की ओर कर लिया. फिर तो वह कई देशी-विदेशी फिल्मकारों की नज़रों में रातोंरात चढ़ गई. स्वराज के बाद उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म बस यूं ही में काम किया. उसी दौरान उन्हें फ्रेंच फिल्म ब्रिक लेन का ऑफर मिला और अनुभव पाने के लिए उन्होंने हामी भर दी. इस फिल्म को काफी सराहना मिली तो कई अन्य फिल्में भी मिलीं. जर्मन फिल्म शैडोज ऑफ लव में उनके साथ इरफान खान भी थे. इसकी अधिकांश शूटिंग कोलकाता में हुई थी. इसी बीच उन्होंने बांग्ला फिल्म बीबोर में भी काम किया. इसके लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवॉर्ड मिला. न्यूयॉर्क बेस्ड डायरेक्टर जोसेफ मैथ्यू की हिंगलिश फिल्म बॉम्बे समर में उनका रोचक किरदार है. चाहे बॉलीवुड को इसकी ख़बर न हो, लेकिन तनिष्ठा पिछले कुछ सालों से काफी व्यस्त हैं. फ़िलहाल उन्हें समानांतर सिनेमा की महारानी कहा जाने लगा है. 32 वर्षीय तनिष्ठा फिल्मकार जॉन राइट की अगली फिल्म में अंग्रेजी दां कलाकारों के साथ नज़र आएंगी. राइट लियो टालस्टाय के क्लासिक उपन्यास अन्ना कारेनिना पर फिल्म बना रहे हैं. तनिष्ठा उसमें एक जिप्सी महिला मासा का किरदार निभाएंगी. वह पहले भारतीय फिल्म रोड मूवी और विदेशी फिल्म ब्रिक लेन में अभिनय कर चुकी हैं, लेकिन यह उनके लिए सबसे बड़ा इंटरनेशनल ब्रेक है. राइट मशहूर सितार वादक अनुष्का शंकर के पति हैं और जाने-माने ब्रिटिश फिल्म निर्देशक. इसके पहले वह प्राइड एंड प्रेज्यूडिस और एटोनमेंट जैसे उपन्यासों पर आधारित फिल्में बना चुके हैं. इंजीनियर पिता और दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीतिशास्त्र की प्राध्यापक मां की पुत्री तनिष्ठा अच्छी गायिका भी हैं. वह टिप्स म्यूज़िक के साथ अपना एलबम भी ला चुकी हैं. उन्होंने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक की तालीम ली है.

रणबीर बने लुटेरे

अपनी पहली फिल्म बैंड बाजा बारात की सफलता के बाद रणबीर सिंह के पास फिल्मों की लाइन लग गई, लेकिन उन्होंने ख़ुद को संयमित रखते हुए फिल्मों का चयन प्रभावित नहीं होने दिया. हाल में आई उनकी फिल्म लेडीज वर्सेस रिकी बहल पर्दे पर आई, जिसमें वह दिलों के साथ-साथ हसीनाओं के पैसे भी लूटकर ले जाते हैं. फिल्मी हीरो की तरह रणबीर रीयल लाइफ में भी फ्लर्ट हैं, ऐसा वह ख़ुद कहते हैं. बकौल रणबीर, लड़कियों को ख़ुश करना एक कला है, जो उनके भीतर प्राकृतिक रूप से है. बैंड बाजा बारात के बाद के दिनों को याद करते हुए रणवीर कहते हैं कि वह वक़्त बहुत अजीब था, उन्हें बहुत सारे ऑफर मिल रहे थे. अगर वह चाहते तो आने वाले छह वर्षों के लिए फिल्में साइन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने तय किया कि वह रुकेंगे और एक बार में एक ही क़दम चलेंगे. उन्हें लगता है कि अपनी पहली फिल्म की सफलता के बहाव में न बहने के कारण ही आज वह बेहतर स्थिति में हैं. रणबीर ने फ़िलहाल उड़ान के निर्देशक विक्रमादित्य मोटवानी के साथ भी एक फिल्म साइन की है. फ़िलहाल उनकी आने वाली फिल्म का नाम है लुटेरा, जिसमें वह दबंग की अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा के साथ दिखाई देंगे. उन्होंने बताया कि मुझे याद है, जब मैंने अपने सेल फोन का इनबॉक्स देखा तो वहां कई ऐसे नाम थे कि यक़ीन करना मुश्किल हो गया कि मैं अपना ही फोन देख रहा हूं. वह अपनी आगामी फिल्म को लेकर बहुत उत्साहित हैं. यह 1950 के दशक के बंगाल की पृष्ठभूमि में एक प्रेम कहानी पर आधारित है. अपनी को-स्टार अनुष्का शर्मा के बारे में रणबीर का कहना है, अनुष्का के साथ काम करने से मुझमें सहजता आ गई है. वह मेरी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाती हैं, हमारी केमेस्ट्री ज़बरदस्त है.

हॉलीवुड से

ख़ुशी के साथ समझौता नहीं

कमनीय काया के लिए चर्चित मॉडल से अभिनेत्री बनी केली ब्रूक का मानना है कि सुंदर महिलाओं की प्रशंसा की जानी चाहिए. हाल में अपने ब्वॉयफ्रेंड डैनी सिप्रियानी से संबंध तोड़ने वाली इस तीस वर्षीय ब्रिटिश सुंदरी का कहना है कि कमनीय औरत से ज़्यादा सशक्त कुछ भी नहीं है और वह व्यक्तिगत रूप से राकेल वेल्च की प्रशंसा करती हैं. उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि स्क्रीन पर सुंदर महिला से ज़्यादा कुछ सशक्त है. केली ब्रूक का मानना है कि किसी भी रिश्ते में ख़ुशी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, इसलिए जिन रिश्तों में उन्हें ख़ुशी नहीं मिलती है, वह उनमें कभी नहीं रहेंगी. फ़िलहाल पूर्व रग्बी खिलाड़ी थॉम इवांस के साथ डेटिंग कर रही 32 वर्षीय ब्रूक ने कहा कि ख़ुशी के मुद्दे पर वह किसी के साथ समझौता करके नहीं रह सकतीं, इसके बजाय वह अकेली रहना पसंद करेंगी. ब्रूक ने कहा कि मैंने कई रिश्ते तोड़ दिए और ये निर्णय काफी मुश्किल थे. मैं ख़ुशी को महत्व देती हूं और अपने दिल की सुनती हूं. हाल में ब्रूक ने एक फ्रेंच पत्रिका के लिए न्यूड पोज दिया था. इसके पहले प्लेब्वॉय के लिए न्यूड फोटो सेशन के बदले उन्हें ढाई लाख पौंड की रकम मिली थी.

अग्निपथ में संजय दत्त

चालाकी भरी मुस्कान और सफाचट सिर के साथ संजय दत्त फिल्म अग्निपथ में एक बिल्कुल नए रूप में दिखाई देंगे. उनका कहना है कि खलनायक फिल्मों में हमेशा शक्तिशाली होता है, जिसके पीछे एक कारण होता है. फिल्म में संजय ने कांचा की भूमिका निभाई है. यह वही पात्र है जिसकी भूमिका 1990 के दशक में आई अमिताभ बच्चन अभिनीत अग्निपथ में डैनी डैनजोंगपा ने निभाई थी. फिल्म में संजय काले वस्त्रों, कान में बाली और बांहों पर गोदना गुदवाए हैं. अग्निपथ के बाद संजय रेस के सिक्वल में नज़र आएंगे. अगर आपको अब्बास मस्तान की फिल्म रेस पसंद आई थी तो आपके लिए रेस टू से जुड़ी एक ख़बर है, वह यह कि रेस टू में एक साथ 8 सितारे नज़र आएंगे. अब्बास मस्तान ने अपनी फिल्म में दीपिका पादुकोण, जैकलीन फर्नांडीज, अमीषा पटेल, बिपाशा बसु, अनिल कपूर, सैफ़ अली ख़ान और जॉन अब्राहम जैसे स्टार्स को साइन किया है. इतना ही नहीं उन्होंने अपनी फिल्म में संजय दत्त को कास्ट करने के लिए रेस टू की कहानी में नया ट्विस्ट भी दिया है. अब्बास अपनी फिल्म में संजू बाबा को लेना चाहते थे, जिसके चलते फिल्म के प्रोड्यूसर्स को भी मनाया गया और उन्हें विश्वास में लिया गया कि वे अपनी फिल्म में संजय दत्त को भी साइन करें. रेस टू एक थ्रिलर फिल्म है. ऐसे में संजय दत्त की इंट्री भी एक ट्विस्ट के साथ होगी. सुनने में आ रहा है कि संजय का रोल बहुत ख़ास है.

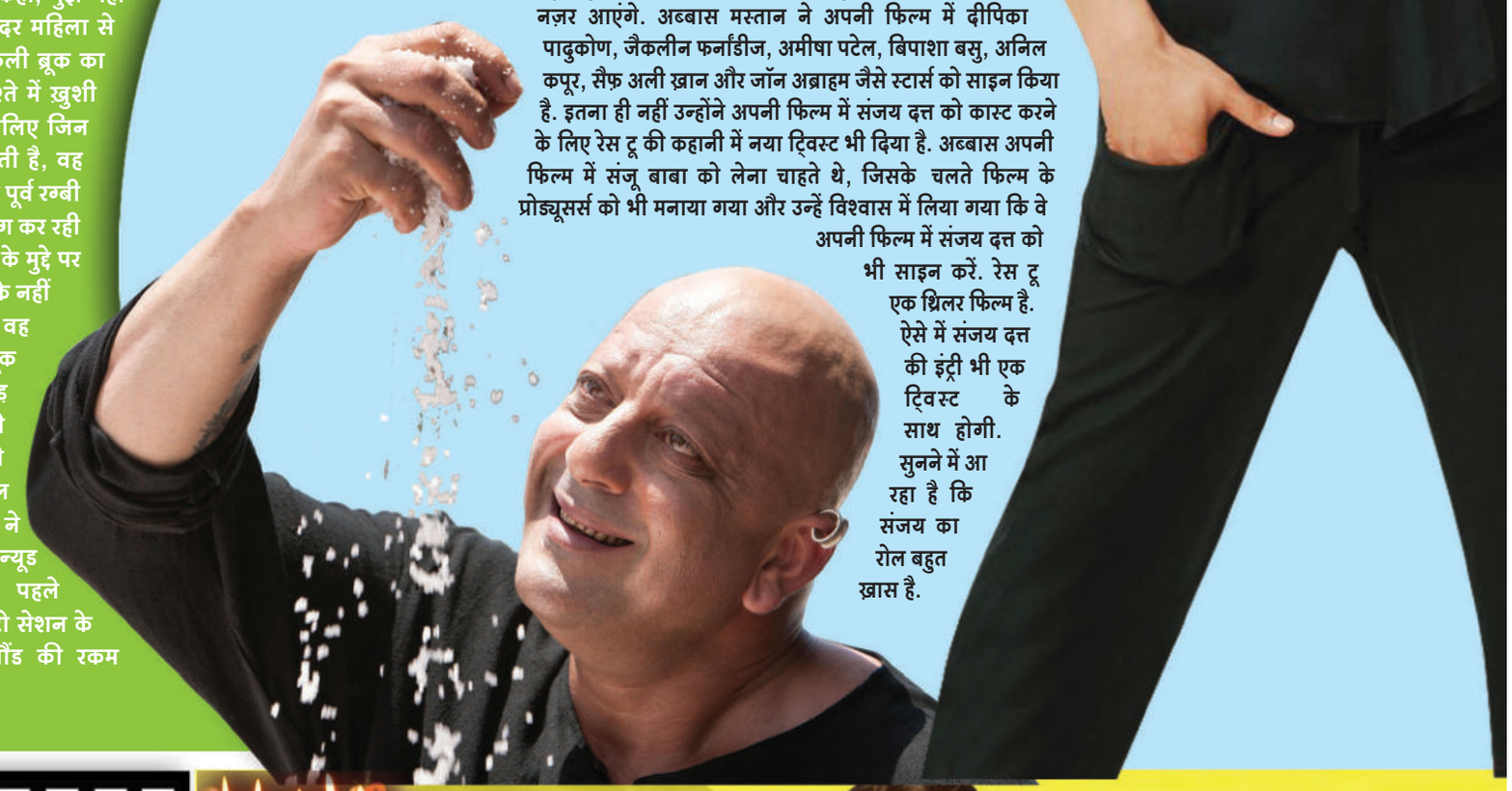

फिल्म प्रीव्यू

अग्निपथ

अगर आप 1990 में आई अमिताभ बच्चन की फिल्म अग्निपथ के प्रशंसक हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन ख़बर है. जल्द ही आपको इस फिल्म का नया संस्करण देखने को मिलेगा. अमिताभ बच्चन अभिनीत अग्निपथ के निर्माता यश जौहर थे और अब उस फिल्म का नया संस्करण उनके पुत्र करण जौहर बना रहे हैं. पिता की बनाई अग्निपथ बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं दिखा सकी थी. वैसे अमिताभ बच्चन को उसमें अभिनय के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था. उन्होंने विजय दीना नाथ चौहान का किरदार निभाया था. निर्माता करण जौहर की फिल्म में ऋतिक रोशन, संजय दत्त, ऋषि कपूर एवं प्रियंका चोपड़ा मुख्य भूमिका में हैं. संजय दत्त और ऋषि कपूर का किरदार निगेटिव है. ऋतिक रोशन एक बार फिर एक्शन और रोमांस करते नज़र आएंगे, वहीं संजय दत्त की परफेक्ट बॉडी देखकर आपको जिम की याद आएगी. फिल्म में ऋषि कपूर कुर्ता, पायजामा, कराकुल टोपी पहने और आंखों में काजल लगाए नज़र आएंगे.

अमिताभ ने बोलने के अंदाज़ और आवाज़ में बदलाव लाकर संवाद बोले थे, जिसके कारण दर्शकों को ज़्यादातर संवाद समझ में नहीं आए थे और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन बाद में लोगों ने इस फिल्म को वीडियो एवं टीवी पर देखा और सराहा. यह फिल्म यश जौहर के दिल के बेहद क़रीब थी. इसी बात को ध्यान में रखते हुए करण जौहर लगभग 22 वर्षों के बाद इसका रीमेक लेकर आए हैं, जिसमें थोड़े-बहुत बदलाव किए गए हैं. मांडवा नामक छोटे से गांव में रहने वाले विजय दीना नाथ चौहान (ऋतिक रोशन) को उसके पिता ने आदर्शों, सिद्धांतों और ईमानदारी की शिक्षा दी. विजय की ज़िंदगी में भूचाल तब आ जाता है, जब ड्रग डीलर कांचा (संजय दत्त) उसके पिता को मौत के घाट उतार देता है. अपनी मां के साथ विजय मुंबई पहुंच जाता है. उसकी ज़िंदगी का एक ही उद्देश्य है कि मांडवा लौटकर अपने पिता के नाम पर लगे धब्बे को साफ करना, जो कांचा ने लगाया है. मुंबई में 12 वर्षीय विजय की ज़िंदगी संवारने का ज़िम्मा रऊफ लाला (ऋषि कपूर) लेता है. कांचा तक पहुंचने के लिए विजय कई नियम-क़ानून तोड़ता है. उसके कई रिश्ते बनते और बिगड़ते हैं. विजय को हर क़दम और मोड़ पर उसकी दोस्त काली (प्रियंका चोपड़ा) का समर्थन मिलता है. पंद्रह साल बाद कांचा के प्रति नफरत विजय को मांडवा ले जाती है, जहां दोनों आमने-सामने होते हैं.

तुम जियो हज़ारों साल

नम्रता शिरोडकर परिवार ही सब कुछ

जब-जब भी निजी ज़िंदगी में व्यस्त किसी अभिनेत्री के पास पर्दे पर वापसी का प्रस्ताव गया, ज़्यादातर ने इंकार नहीं किया. ताजातरीन उदाहरण हैं माधुरी दीक्षित नेने, लेकिन एक अभिनेत्री ऐसी भी है, जो प्रशंसकों के दिल में अपनी मुस्कराहट बसाने और उनकी नज़रों की कशिश बनने के बजाय बेटे को अपनी आंखें और पति को अपनी मुस्कान बताती है. फिल्म वास्तव में दमदार अभिनय से सुर्ख़ियों में आईं नम्रता शिरोडकर ने हाल में एक फिल्म में अभिनय करने से इसलिए मना कर दिया, क्योंकि वह अपने बेटे को अधिक वक़्त देना चाहती हैं. नम्रता के दोस्त एवं को-स्टार संजय दत्त ने जब राकेश नाथ के ज़रिए उन्हें एक फिल्म का प्रस्ताव भेजा तो वह काफी ख़ुश हुईं, लेकिन जब अपने बेटे की ओर देखा तो उन्होंने निर्णय बदल लिया. नम्रता अपने बेटे को प्राथमिकता देती हैं और उन्हें उसके साथ समय बिताकर सबसे अधिक ख़ुशी होती है. नम्रता ने 2005 में तेलुगु फिल्मों के सुपर स्टार महेश बाबू से शादी की थी और 2006 में उन्हें एक बेटा हुआ. नम्रता कहती हैं, मेरा बेटा मेरी आंखें और महेश मेरी मुस्कान हैं. ख़बर यह है कि अब जल्द ही नम्रता दोबारा मां बनने वाली हैं, हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन याद करें, अपने रिश्ते और शादी की बात भी नम्रता ने काफी बाद में स्वीकार की थी. बाद में उन्होंने इसकी वजह यह बताई थी कि उनके पति महेश बाबू को ओपननेस पसंद नहीं है. नम्रता फिल्म वास्तव की अच्छी वाइफ से रीयल लाइफ की अच्छी वाइफ बनने का सफर तय कर चुकी हैं, लेकिन आश्चर्य यह है कि उन्हें अपने करियर को लेकर कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि वह अपने पति के बढ़ते करियर ग्राफ में महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं. पति की स्क्रिप्ट्स तय करना, उनकी ड्रेस, फिल्म में उनकी अतिरिक्त ज़रूरतों और उनकी सेहत का ख्याल नम्रता ख़ुद करती हैं. पति के एक हिट से वह उतनी ही ख़ुश होती हैं, जितनी अपनी फिल्म हिट होने पर. पति की फिल्मों में कुछ बेहतर करने के लिए वह बॉलीवुड के दोस्तों से भी मदद और राय-मशविरा लेती हैं. इस तरह उनकी बॉलीवुड के लोगों से दोस्ती भी बरक़रार है. अच्छी बात यह है कि ग्लैमर वर्ल्ड, जहां एक फिल्म हिट या फ्लॉप होने के बाद पति-पत्नी के रिश्ते में बदलाव दिखने लगते हैं, से ताल्लुक होने के बावजूद नम्रता अपनी जड़ों को नहीं भूलीं और उन्होंने पति और परिवार में ही ख़ुशियां तलाशने की कोशिश की. निस्संदेह नम्रता आधुनिक महिलाओं के लिए प्रेरणास्रोत हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

दिल्ली, 23 जनवरी-29 जनवरी 2012

www.chauthiduniya.com

बाग़ी बिगाड़ेंगे खेल

गठबंधन पर संशय बरक़रार

भाजपा की सत्ता वाली नागपुर महानगर पालिका पर नज़र डालें तो यह नितिन गडकरी का गृहनगर है और आगामी लोकसभा चुनाव में भी उनके यहीं से उतरने की संभावना है. इसलिए इस मनपा पर पूरे देश की नज़र लगी हुई है. यहां भाजपा की जो हालत है उससे यही लगता है कि शायद ही वह सत्ता में वापसी कर सके. यहां भाजपा पर कारटेल घोटाला, स्टार बस घोटाला सहित कई आरोप लगे हैं. पानी का निजीकरण किए जाने और संपत्ति कर में वृद्धि किए जाने से भी जनता नाराज़ है. इसे लेकर विपक्षी दल कांग्रेस-राकांपा ने भी भाजपा पर हमले तेज़ कर दिए हैं. महापौर अर्चना डेहनकर और स्थायी समिति के अध्यक्ष संदीप जोशी अपनी पार्टी के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों के दम पर चाहे जीत का जितना भी दावा करें, लेकिन प्रभाग पद्धति से चुनाव होने के कारण उनकी भी हालत डांवाडोल है.

युधिष्ठिर जोशी

राज्य में महानगर पालिका चुनाव ने नेताओं की व्यस्तता बढ़ा दी है. सत्तारूढ़ व विपक्षी गठबंधनों में सीट बंटवारे का अंतिम दौर चल रहा है. सभी दलों के लिए इस बार का चुनाव मिनी विधानसभा चुनाव लग रहा है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनीतिक दलों का शीर्ष नेतृत्व जहां गठबंधन कर चुका है, वहीं महत्वाकांक्षी कार्यकर्ता बग़ावती तेवर अपनाए हुए हैं और उन्होंने चुनाव मैदान में उतरने के लिए कमर कस ली है. दूसरी ओर सहयोगी दलों के नेताओं द्वारा विश्वासघात किए जाने की आशंकाएं भी सभी दल के नेताओं को सता रही हैं. इन सबके बीच कांग्रेस-राष्ट्रवादी कांग्रेस की आघाड़ी व शिवसेना-भाजपा-रिपब्लिकन की महायुति के रणनीतिकार अपनी-अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटे हैं. उन्हें राज्य की 10 महानगर पालिकाओं के लिए अलग-अलग परिस्थितियां होने के कारण सभी के लिए अलग तरीक़े से रणनीति बनाने के लिए माथापच्ची करनी पड़ रही है. वहीं मनपा के चुनावी मैदान में उतरने वाले योद्धाओं द्वारा नामांकन भरा जा रहा है. इधर बाग़ियों को भी मनाने की कोशिश हो रही है. इन चुनावों में ख़ास बात यह है कि इसमें मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, शिवसेना प्रमुख बालासाहब ठाकरे और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है.

भाजपा की सत्ता वाली नागपुर महानगर पालिका पर नज़र डालें तो यह नितिन गडकरी का गृहनगर है और आगामी लोकसभा चुनाव में भी उनके यहीं से उतरने की संभावना है. इसलिए इस मनपा पर पूरे देश की नज़र लगी हुई है. यहां भाजपा की जो हालत है उससे यही लगता है कि शायद ही वह सत्ता में वापसी कर सके. यहां भाजपा पर कारटेल घोटाला, स्टार बस घोटाला सहित कई आरोप लगे हैं. पानी का निजीकरण किए जाने और संपत्ति कर में वृद्धि किए जाने से भी जनता नाराज़ है. इसे लेकर विपक्षी दल कांग्रेस-राकांपा ने भी भाजपा पर हमले तेज़ कर दिए हैं. महापौर अर्चना डेहनकर और स्थायी समिति के अध्यक्ष संदीप जोशी अपनी पार्टी के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों के दम पर चाहे जीत का जितना भी दावा करें, लेकिन प्रभाग पद्धति से चुनाव होने के कारण उनकी भी हालत डांवाडोल है. ऐसे में सवाल यह उठता है कि भाजपा की नैया पार कौन लगाएगा? ऐसी सूरत में अब सारा दारोमदार नितिन गडकरी और विधायक देवेंद्र फड़णवीस पर टिका है. यदि ये दोनों नेता चाहें तो भाजपा की नैया पार लगा सकते हैं. समस्या यह है कि गडकरी पार्टी की राष्ट्रीय समस्याओं में उलझे हुए हैं. उनके लिए नागपुर मनपा से अधिक पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में पार्टी की नैया पार लगाने की बड़ी ज़िम्मेदारी है. बचे विधायक फड़णवीस तो उनके लिए गडकरी के समर्थक ही परेशानी खड़ी कर रहे हैं. पार्टी शहराध्यक्ष अनिल सोले गडकरी गुट के हैं. यहां यही कहा जा सकता है कि यदि भाजपा ने समय रहते एकजुटता से अपने सहयोगियों के साथ तालमेल नहीं बिठाया तो उसके हाथ से मनपा की सत्ता निकल सकती है. ग़ौरतलब है कि कांग्रेस-राकांपा इस चुनाव में उसे सत्ता से बाहर करने के लिए मिलकर चुनाव लड़ रही हैं. इसके साथ ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अपना विस्तार करने के लिए तेज़ी से प्रयासरत है, जो भाजपा-शिवसेना का खेल बिगाड़ सकती है.

अमरावती मनपा में फ़िलहाल कांग्रेस-राकांपा की सत्ता है. यहां कांग्रेस के जितने नेता हैं उतने ही गुट हैं. हर नगरसेवक अपने को नेता से कम नहीं समझता है. राकांपा में जबसे राज्य स्तर पर उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने कमान संभाली है तब से उसके नेता-कार्यकर्ता एकजुट हैं. यहां कांग्रेस-राकांपा पर भी बड़े पैमाने पर हुए ज़मीन घोटाले का आरोप लग रहे हैं. जिन अधिकारियों ने मनपा के कार्यों में धांधली की है, उन्हें कांग्रेस नेताओं का संरक्षण मिले होने की बात कही जा रही है. मनपा की आर्थिक हालत ऐसी है कि कर्मचारियों को समय पर वेतन देने तक को पैसे नहीं रहते हैं, जिसके चलते कर्मचारियों को वेतन के लिए आंदोलन भी करना पड़ा है. यहां कांग्रेस के समक्ष शिवसेना-भाजपा-रिपा महायुति के अलावा पूर्व राज्यमंत्री डॉ. सनील देशमुख और बडनेरा के विधायक रवि राणा की आघाड़ियां भी चुनौती दे रही हैं. राकांपा के स्थानीय नेता भी कांग्रेस से गठबंधन करने के ख़िलाफ़ थे. इन हालात में यहां कांग्रेस-राकांपा का अपने दम पर सत्ता पर लौटना आसान नहीं होगा.

विदर्भ की तीसरी महानगर पालिका अकोला है. यहां पर कांग्रेस-राकांपा की सत्ता थी, लेकिन इस बार उनका सत्ता में आना आसान नही, बल्कि असंभव लग रहा है. कांग्रेस-राकांपा शासनकाल में भारी आर्थिक कदाचार से अकोला मनपा दिवालियापन की हालत में पहुंच गई थी. अंततः मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण को विवश होकर उसे बर्ख़ास्त करना पड़ा. वर्तमान में वहां का कामकाज प्रशासक के हवाले है. यहां विपक्षी शिवसेना-भाजपा की राह आसान है, यदि महायुति ने सटीक रणनीति बनाकर चुनावी पारी खेली तो कांग्रेस-राकांपा के पास गठबंधन के अलावा कोई राह नहीं है.

नासिक महानगर पालिका क्षेत्र सार्वजनिक लोक निर्माण मंत्री छगन भुजबल का क्षेत्र है. यहां उनका दबदबा भी है. इसके बावजूद यहां की मनपा पर सत्ता शिवसेना-भाजपा की है. इस बार शिवसेना-भाजपा के साथ रामदास अठावले के जुड़ने से विपक्षी गठबंधन मज़बूत हुआ है. हालांकि, महायुति के घटक दलों में कई मुद्दों पर गहरे मतभेद हैं. वहीं यहां कांग्रेस-राकांपा के हाथ मिलाने से सत्तारूढ़ शिवसेना-भाजपा को कड़ी चुनौती मिल रही है, क्योंकि भुजबल और कांग्रेस विधायक जयप्रकाश छाजेड़ दोनों मिलकर उन्हें सत्ता से बाहर करने के लिए एड़ी-चोटी एक कर रहे हैं. मनसे भी यहां अपने उम्मीदवार उतार कर अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है.

सोलापुर मनपा में सत्ता कांग्रेस-राकांपा की है. दोनों के स्थानीय नेताओं में गहरे मतभेद हैं और वे गठबंधन का विरोध भी कर रहे हैं. कांग्रेस के नेता जहां राकांपा से गठजोड़ के ख़िलाफ़ हैं, वहीं राकांपा में गुटबाज़ी सड़कों तक व्याप्त है, जिसका फटका दोनों को झेलना पड़ सकता है. यहां शिवसेना-भाजपा-रिपा की महायुति के लिए अच्छे अवसर हैं. शिवसेना-भाजपा की ठाणे महानगर पालिका में सत्ता ज़रूर है, लेकिन यहां मनसे के बढ़ते दख़ल से शिवसेना के नेताओं की चिंता बढ़ गई है. भाजपा-शिवसेना की सत्ता के दौरान जो भी भ्रष्टाचार हुआ है उसे लेकर यहां के राकांपा के नेताओं का मानना है कि यदि कांग्रेस से गठबंधन हो जाता है तो आघाड़ी को ठाणे मनपा की सत्ता मिलना आसान हो जाएगा, लेकिन उनके सामने समस्या यह है कि कांग्रेस के स्थानीय नेता गठबंधन करने के ख़िलाफ़ हैं. वहीं उल्हासनगर मनपा में शिवसेना-भाजपा ने लोकभारती के साथ मिलकर पिछली बार सत्ता हासिल की थी. इस बार युति में रामदास अठावले के शामिल होने से बनी महायुति पुनः चमत्कार दिखा सकती है. पिछले चुनाव में भाजपा-शिवसेना की युति के सामने पप्पू कालानी को हार का सामना करना पड़ा था. इस बार पप्पू कालानी आघाड़ी के राकांपा के साथ जाने के आसार है. यहां कांग्रेस-राकांपा साथ होकर भी स्थानीय नेता अपनी-अपनी राह चल रहे हैं.

राकांपा के वर्चस्व वाली पुणे व पिंपरी चिंचवड़ में गठबंधन को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है. हालांकि पिछले चुनाव में पुणे मनपा में कांग्रेस-राकांपा की सत्ता बनी है. वहीं पिंपरी-चिंचवड में भी राकांपा की अपनी सत्ता है. यहां उपमुख्यमंत्री अजीत पवार का ख़ासा प्रभाव है. वे यहां कांग्रेस से गठबंधन करने की बजाय अकेले दम पर राकांपा के चुनाव मैदान रहने के पक्ष में हैं. उनका यह पक्का विश्वास है कि यहां राकांपा अपने दम पर पुनः सत्ता में आ सकती है, लेकिन उनका यह अति आत्मविश्वास घातक भी साबित हो सकता है, जैसा कि खड़कवासला विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के सामने उनके उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा था. वहीं कांग्रेस यहां राकांपा से गठबंधन करना चाहती है. शिवसेना-भाजपा-रिपा की महायुति कितनी कारगर रणनीति अपना पाती है, उस पर ही उसकी सफलता निर्भर करती है. मनसे भी ज़ोर आज़माइश के लिए तैयार है.

इन सभी मनपा में एक चीज कॉमन दिख रही है, मसलन यहां सभी दलों के चुनावी समीकरण पर बाग़ी ग्रहण लगा रहे हैं.

मुंबई पर किसका राज

मुंबई महानगरपालिका का चुनाव 16 फरवरी को होगा. इस महामाया नगरी में आख़िर किसकी सत्ता होगी? इस प्रश्न का जवाब चुनावी नतीजे से ही तय होगा. पिछले 15 वर्षों से देश की आर्थिक राजधानी मानी जाने वाली मुंबई महानगरी पर शिवसेना की ही सत्ता रही है. सभी राजनीतिक पार्टियां, उनके कार्यकर्ता और नेताओं को पैसे कमाए बग़ैर चैन नहीं मिलता. बाहर जैसे भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ बोलना उनकी रणनीति है, ठीक वैसे ही भ्रष्टाचार करना और पैसे जमा कर उसी पैसे से चुनाव जीतना भी उनका छुपा हुआ एजेंडा है. क़ानून की पकड़ में आए बग़ैर अपना हित कैसे पूरा किया जाए, इसका ज्ञान सभी को है, लेकिन राजनेता इसमें माहिर हैं. शिवसेना ने जात-पात छोड़कर सामान्य आदमी को सत्ता दी, यह सही है. फुटपाथ पर फ़लां की जय और एड़ियां घिसने तक संघर्ष करने वाले सत्ताधीश बने, यह भी सौ फ़ीसदी सही है. शिवसेना के सैनिक वंश परंपरा से राजनीति में नहीं आए. चाल में रहने वाले युवक बालासाहब ठाकरे के साथ आवाज़ से आवाज़ मिलाकर सड़क पर अस्तित्व की लड़ाई लड़ते थे. इन शिव सैनिकों ने आगे चलकर हम नगरसेवक बनेंगे, महापौर, विधायक या फिर मंत्री बनेंगे, ये सपने में भी नहीं सोचा था. पूर्व के शिवसैनिक छगन भुजबल, नारायण राणे से यदि पूछा जाए तो यही सच सामने आएगा. मनोहर जोशी तो नगरसेवक, महापौर, विधायक, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष पद तक पहुंचे. उनसे 1970 के पहले के दिनों के बारे में पूछा जाए तो वे भी यही बताएंगे. शुरुआत में मुंबई महानगरपालिका, फिर ठाणे, कल्याण और फिर पूरे राज्य में शिवसेना ने अपने उम्मीदवार खड़े किए. साधारणतः 1970 के दशक में शिवसेना ने महानगरपालिका पर क़ब्ज़ा जमाया.

इस दौरान 15 वर्ष पूर्व केवल एक बार (पांच वर्ष के लिए) कांग्रेस पार्टी के पास महानगरपालिका की सत्ता आई. मुंबई महानगरपालिका का वार्षिक बजट 21 हज़ार करोड़ रुपये का है. गोवा और केरल राज्य की अपेक्षा यह बजट काफ़ी बड़ा है. इसलिए इस महानगरपालिका पर सत्ता हासिल करने के लिए सभी पार्टियां उत्सुक रहती हैं. 1970 के दशक में शिवसेना के हाथ मुंबई महानगरपालिका की सत्ता आने के बाद सेना के नगरसेवक और उनके नज़दीकी कार्यकर्ताओं के जीवन में बदलाव आया है. शिवसेना, उसके कार्यकर्ता, नगरसेवक और नेताओं की लाइफ स्टाइल बदल गई है. क़ीमती चौपहिया गाड़ियां, सर्व सुविधायुक्त नेताओं के संपर्क कार्यालय और भी बहुत कुछ तामझाम बढ़ गया है. 1970 के पूर्व का

शेष पृष्ठ संख्या- 18 पर

फोटो-*प्रभात पाण्डेय*

feedback@chauthiduniya.com

बनावटी कागज़ातों के जरिये एनडीए में प्रवेश पाने वाले 18 वर्षीय कश्मीरी युवक ने अपना नाम अनमोल विजय बनोत्रा उर्फ शर्मा बताया है, लेकिन उसका अकादमी में प्रवेश लेने का मक़सद क्या था, यह नहीं बताया गया है.

बड़ा व्यस्त हूं. महानगर पालिका और ज़िला परिषद चुनाव न हुए सिर दर्द हो गया है. कहीं सीटों के बंटवारे को लेकर विवाद है, तो कहीं प्रत्याशी को लेकर विवाद है.

महाराष्ट्र हलचल

स्वर्गीय मांसाहब मीनाताई ठाकरे की जयंती के मौके पर शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे व रश्मि ठाकरे शिवाजी पार्क स्थित उनकी प्रतिमा को पुष्पहार अर्पित करते हुए.

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी नवनिर्वाचित नगरपालिका सदस्यों की बैठक आयोजित बैठक को संबोधित करते राकांपा अध्यक्ष व केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार. उनके साथ हैं उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, प्रदेशाध्यक्ष मधुकरराव पिचड़, केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल और मंत्री छगन भुजबल.

अकोला के के.एम. असगर हुसैन शिक्षण महाविद्यालय में आयोजित क्रीडा सत्र के दौरान गोला फेंक स्पर्धा में हिस्सा लेती छात्राएं.

दादर स्थित भाजपा की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी, प्रदेशाध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार और सांसद गोपीनाथ मुंडे का स्वागत करते पार्टी के पदाधिकारी.

नागपुर रेलवे स्टेशन पर पुलिस द्वारा बरामद की गई विस्फोटक सामग्री.

अमरावती स्थित नेहरू मैदान में आयोजित ग्रंथोत्सव का उद्घाटन व समारोह को संबोधित करते प्रसिद्ध साहित्यकार व पक्षी विशेषज्ञ मारुति चितमपल्ली व मंचासीन अतिथिगण.

राष्ट्रसंत तुकड़ी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित चंद्रपुर स्थित सरदार पटेल महाविद्यालय में ज़िला स्तरीय अविष्कार कार्यक्रम में विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरित करते मुख्य अतिथि.

मुंबई पर किसका राज

पृष्ठ 17 का शेष

फुटपाथ का आदमी अब महल में रहने चला गया है. धन-दौलत की चमक उनके चेहरे पर साफ दिखाई देती है. राज्य पर कांग्रेस की सत्ता, लेकिन मुंबई पर शिवसेना का कब्ज़ा और उसके हाथ में 21 हज़ार करोड़ रुपये का बजट. कांग्रेसी नेताओं को यह काफी चुभती है. यही वजह है कि 12 वर्ष पूर्व कांग्रेस-राकांपा आघाड़ी की सरकार आते ही तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख ने ढांचागत सुविधा निर्माण करने की ज़िम्मेदारी महानगरपालिका के हाथ से छीन ली. इसके लिए मुंबई महानगर प्राधिकरण स्थापित किया गया. इस प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं. कार्यकारी संचालक आई.ए.एस. अधिकारी होता है. इस प्राधिकरण का काफी बड़ा बज़ट होता है. पिछले 12 वर्षों से इस प्राधिकरण ने करोड़ों रुपये के फ्लाईओवर्स, स्कायवॉक्स, मोनो रेल, रास्ते का चौड़ाईकरण, निर्माण आदि सैकड़ों काम किए हैं. इसे देखते हुए प्राधिकरण निर्माण करने के दौरान शिवसेना ने इसका विरोध किया था. प्राधिकरण ने जो 12 वर्षों में काम किया है, उसकी व्यापकता को देखकर कहा जा सकता है कि मनपा को इसे संभालना मुश्किल हो गया होता. पिछले 12 वर्षों में प्राधिकरण (एमएमआरडी) ने मुंबई में ढांचागत सुविधाओं का मज़बूत जाल बिछाया है.

इस तरह करोड़ों रुपये के काम मनपा से प्राधिकरण की ओर जाने से शिवसेना का परेशान होना समझा जा सकता है. उसका तकलीफ़ सिर्फ राजनीतिक पार्टियां और नेता ही समझ सकता है. आम आदमी करोड़ों रुपये का हिसाब कभी नहीं करता. उम्र के कारण शिवसेना प्रमुख बाला-साहब ठाकरे का राजनीतिक जीवन काफी मर्यादित हो गया है. इसके कारण उन्होंने पार्टी के कार्याध्यक्ष पद की ज़िम्मेदारी अपने बेटे उद्धव ठाकरे के कंधों पर सौंपी. मुंबई मनपा का पिछला चुनाव उद्धव ठाकरे की पहली राजनीतिक परीक्षा थी, जिसमें वे सफल हुए. शिवसेना-भाजपा युति सत्ता में आई. मुंबई मनपा में शिवसेना, भाजपा और निर्दलीय मिलाकर 150 नगरसेवक हैं. इनमें शिवसेना के 82, भाजपा 28 और निर्दलीय 4 नगरसेवक हैं. वहीं विपक्षी पार्टियों में कांग्रेस के 76, राकांपा 14, मनसे 7 और समाजवादी पार्टी के 7 नगरसेवक हैं. मुंबई मनपा में कुल सदस्य संख्या 227 है. इसे देखते हुए साफ है कि शिवसेना-भाजपा को अपनी संख्या बढ़ानी होगी. राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने काफी ताकत इकट्ठा कर ली है. मुंबईकर युवा मतदाताओं में मनसे के प्रति काफी सहानुभूति है.

माना जा रहा है कि मनसे फैक्टर मुंबई मनपा चुनाव में काफी प्रभावी रहेगा, जिसका सीधा नुकसान शिवसेना को होगा. इसे देखते हुए भाजपा सतर्क हो गई है. चुनाव के बाद यदि मनसे 35 सीटें भी जीत पायी तो उसके साथ गठबंधन करने में कोई परेशानी न हो, इसलिए 15 दिनों पूर्व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी ने राज ठाकरे से मुलाकात की. साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत और राज ठाकरे के बीच भी चर्चा हुई. उधर, उद्धव ठाकरे पर अपने पारिवारिक मतभेद को राजनीति से दूर रख, मनसे के अस्तित्व और उसकी ताकत की वास्तविकता को स्वीकार कर व्यावहारिक राजनीति करने का दबाव शिवसेना और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने शुरू कर दिया है. वहीं शिवसेना और मनसे के बीच का विवाद चलता रहे, ऐसा प्रयास कांग्रेस और राकांपा की ओर से शुरू है. यह चुनाव पृथ्वीराज चव्हाण के लिए सबसे बड़ी परीक्षा है.

ग़ौर करने वाली बात यह है कि पिछले 15 वर्षों से मुंबई मनपा में शिवसेना की सत्ता है और पिछले लोकसभा चुनाव में मुंबई शहर के 6 में से 5 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस और एक में राकांपा के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की. शिवसेना और भाजपा के हाथ में कुछ नहीं लगा. कांग्रेस हाईकमान का कहना है कि अब मुंबई मनपा में कांग्रेस की सत्ता होनी चाहिए. इसके कारण मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण का परेशान होना और उनकी ज़िम्मेदारी बढ़ना स्वाभाविक है. पिछले 5 वर्षों में राकांपा के मंत्रियों ने मुंबई में काम समाधानकारक है. इसके कारण राकांपा के उम्मीदवारों की संख्या मनपा में बढ़ सकती है. राकांपा का कांग्रेस से गठबंधन होने के बाद भी कांग्रेस, राकांपा पर अधिक से अधिक निर्भर रहे इसके लिए उसके उम्मीदवारों को गिराने का खेल शरद पवार इस बार भी ज़रूर खेलेंगे, इसकी पूरी संभावना है. अब सवाल यह है कि धारावी के ग़रीबों को नि:शुल्क घर देने की योजना इतने आनन-फानन में क्यों घोषित करनी पड़ी. यह योजना 2-3 महीने पूर्व घोषित की होती तो उसका लाभ कांग्रेस पार्टी को निश्चित मिलता. मुख्यमंत्री ने योजना की घोषणा करने में क्यों देरी की? इसके पीछे राकांपा की तो कुछ रणनीति नहीं होगी? वहीं चुनाव में रिपाइ के रामदास आठवले और मनसे के उम्मीदवारों की संख्या बढ़ी, तो ये दोनों पार्टियां सत्ता में निर्णायक भूमिका निभाएंगी. नया महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिति का अध्यक्ष कौन होगा? इसका निर्णय रामदास आठवले या राज ठाकरे की राजनीतिक इच्छाशक्ति पर निर्भर रहेगा.

पैकेज की वसूली शुरू

विदर्भ की राशि में होगी कटौती

नागपुर में हुए शीतकालीन अधिवेशन को ख़त्म हुए अभी एक महीना भी नहीं हुआ कि राज्य सरकार ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है. विदर्भ के कपास, धान और सोयाबीन उत्पादकों को मदद देने के लिए राज्य सरकार ने दिसंबर में नागपुर अधिवेशन में 2 हज़ार करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की थी. तब भी विपक्ष ने सवाल उठाया था कि लाखों करोड़ रुपये के क़र्ज़ में घिरी सरकार आख़िर 2 हज़ार करोड़ रुपये लाएगी कहां से? अधिवेशन ख़त्म होने के महीने भर में ही यह साफ़ हो गया है कि सरकार विदर्भ के किसानों को कोई अतिरिक्त राशि नहीं देने वाली, बल्कि यहां की विकास योजनाओं का पैसा काटकर उसे पैकेज के तौर पर देने की तैयारी राज्य सरकार बजट में कर रही है. ऐसे में साफ़ है कि विदर्भवासियों के हाथ कुछ नहीं लगेगा.

विदर्भ के नागपुर विभाग के नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरोली, वर्धा और अमरावती विभाग के अमरावती, अकोला, यवतमाल, बुलढाना, वाशिम ज़िलों के लिए चालू बजट में ज़िला विकास निधि तय करने हेतु जनवरी के पहले सप्ताह में अमरावती और नागपुर के विभागीय कार्यालयों में उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने मंत्रियों और अधिकारियों की बैठकें लीं. हालांकि मनपा, ज़िला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव की आचार संहिता लागू होने के कारण उन्होंने बैठक में तय हुए मुद्दों की जानकारी देने से मना कर दिया, लेकिन बैठक में शामिल विश्वसनीय लोगों ने बताया कि किसान पैकेज के लिए आगामी बजट में राज्य सरकार विदर्भ की विकास योजनाओं की राशि में कटौती करने का मन बना चुकी है. उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण और उपमुख्यमंत्री पवार ने अधिवेशन में ही इसके संकेत दे दिए थे.

विदर्भ का पैसा विदर्भ को

अब यह तय हो चुका है कि राज्य सरकार किसानों की मदद के लिए अतिरिक्त 2 हज़ार करोड़ रुपये नहीं दे रही. विदर्भ की ही विकास योजनाओं में से राशि काटकर वह यह पैकेज पूरा करने जा रही है. इससे विदर्भ को कोई लाभ होना तो दूर उल्टा नुक़सान अधिक है. पैकेज की शर्तों पर ग़ौर करें तो काफी कम किसानों के हाथ में केवल 500 से एक हज़ार रुपये आएंगे. इससे आगामी फ़सल के लिए बीज और खाद के पैकेट भी किसान नहीं ख़रीद पाएगा. अभी मनपा, ज़िला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव है. सभी अधिकारी-कर्मचारी इसमें व्यस्त हैं. आचार संहिता लागू हैं. ऐसे में यह तय है कि पैकेज पर अमल चुनाव के बाद ही हो पाएगा. इसके बाद भी पैकेज की राशि किसानों के हाथ कब तक पहुंचती है और इसके लिए उन्हें कितनी परेशानी झेलनी पड़ेगी, यह तो आने वाला समय ही बताएगा. सरकार ने अपनी परेशानी कम करने की पूरी तैयारी कर ली है. चुनाव के बहाने वह ज़िला विकास निधि घोषित नहीं कर रही, जिससे मतदान पर होने वाले अच्छे-बुरे परिणामों से कांग्रेस-राकांपा दूर रहेगी. दूसरा चुनाव के बाद निधि घोषित करने पर यदि विरोध भी हुआ तो भी सरकार पर इसका कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा.

अधिकारियों पर बरसे पवार

यह सही है कि राज्य सरकार किसी एक क्षेत्र के प्रति पूरी तौर पर समर्पित नहीं रह सकती, लेकिन फिर भी आख़िर क्या वजह है कि पश्चिम महाराष्ट्र और कोंकण अपने पाले में अधिक राशि लेकर चले जाते हैं. साफ़ है कि यहां जनप्रतिनिधि और अधिकारी राज्य सरकार पर दबाव नहीं बना पाते. कई मौक़ों पर विदर्भ के विधायकों, सांसदों और मंत्रियों तक को होमवर्क में कच्चा पाया गया है. चर्चा के दौरान काफ़ी कम जनप्रतिनिधि पुख़्ता और जानकारीपूर्ण मुद्दों को सामने रख पाते हैं. जानकारों के अनुसार ज़िला विकास निधि (डीपीसी) के नियोजन को लेकर नागपुर के विभागीय कार्यालय में हुई बैठक में यहां के अधिकारी सही तरह से जानकारी नहीं रख पाए. इससे गुस्साए उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने उनकी जमकर ख़बर ली. यह पहली बार नहीं है जब पवार ने अधिकारियों को आड़े हाथों लिया है. ऐसे में साफ़ है कि विदर्भ के जनप्रतिनिधि और अधिकारियों की कमी का फ़ायदा आसानी से पश्चिम महाराष्ट्र और कोंकण के नेता ले लेते हैं और विदर्भवासी हाथ मलते रह जाते हैं.

नहीं मिली 40 फ़ीसदी निधि

ज़िला वार्षिक नियोजन (डीपीसी) के तहत हर वर्ष राज्य सरकार ज़िले के विकास के लिए राशि देती है. वर्ष 2011-12 में राज्य सरकार ने नागपुर ज़िले के विकास के लिए 160 करोड़ रुपये मंज़ूर किए थे. यह राशि पुणे, अहमदनगर, ठाणे, नासिक, सोलापुर, जलगांव, सातारा, जालना, कोल्हापुर ज़िलों को दी गई नागपुर विभाग को दी गई राशि सबसे कम थी. इसके बाद भी नागपुर ज़िले की राशि से 25 करोड़ रुपये की कटौती कर दी. बताया जाता है कि बाकी बची 135 करोड़ में से 40 फ़ीसदी राशि अब तक ज़िला प्रशासन को नहीं मिली है. ज़िलाधिकारी कार्यालय के एक अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि राज्य सरकार बजट वर्ष के आख़िरी महीने में राशि आवंटित करती है. ऐसे में उसे ख़र्च करना असंभव है, जिससे अधिकतर राशि वापस चली जाती है. उन्होंने बताया कि इसके लिए जितनी राज्य सरकार ज़िम्मेदार है, उतने ही यहां के अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी. दोनों राज्य सरकार पर दबाव नहीं बनाते, इसलिए मंज़ूर निधि भी क्षेत्र को नहीं मिलती. नियम के अनुसार भौगोलिक क्षेत्र, ग्रामीण जनसंख्या, कुल जनसंख्या और मानव निर्देशांक के आधार पर ज़िला वार्षिक निधि तय की जाती है. वर्तमान में नागपुर शहर की ही जनसंख्या 25 लाख के ऊपर पहुंच चुकी है. इसके बाद भी पिछले वर्ष नागपुर ज़िले को सबसे कम निधि मिली. इसके विपरीत 2011-12 के बजट वर्ष में पुणे ज़िले को 285 करोड़ रुपये, अहमदनगर 210 करोड़ रुपये, ठाणे 201 करोड़ रुपये, नासिक 200 करोड़ रुपये, सोलापुर 200 करोड़ रुपये, जलगांव 179 करोड़ रुपये, सातारा 175 करोड़ रुपये, जालना 175 करोड़ रुपये और कोल्हापुर ज़िले को 165 करोड़ रुपये मंज़ूर किए गए थे. इनमें अधिकतर ज़िले नागपुर ज़िले से छोटे हैं. इसके बाद भी यहां के जनप्रतिनिधियों ने कोई आवाज़ नहीं उठाई. हालांकि 2010-11 में मिले 117.5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर इसे वर्ष 2011-12 में 135 करोड़ रुपये किया गया, लेकिन फिर भी नागपुर ज़िले के विकास की उपेक्षा की गई. इस वर्ष फिर पैकेज के नाम पर विदर्भ के ज़िलों की विकास निधि में कटौती करने की बात कही जा रही है.

महाराष्ट्र ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

कश्मीरी युवक की करतूत

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में घुसपैठ

आलोक मिश्रा

देश में साल-दर-साल आतंकवादी हमले होते आ रहे हैं और हमेशा हमले होने की आशंका बनी रहती है. हाल ही में ख़ुफिया एजेंसियों की सूचना पर केंद्र सरकार ने समुद्र के तटवर्तीय इलाकों में हाईअलर्ट करने के दिशा निर्देश भी दिए है ताकि 26/11 को दोहराया न जा सके, लेकिन देश के रक्षा संस्थानों की सुरक्षा क्या पूरी तरह चाकचौबंद है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है, क्योंकि जिस राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) में जवानों को प्रशिक्षण मिलता है, वे ही पूरी तरह सुरक्षित नहीं है. इस बात का खुलासा हाल ही में पुणे स्थित रक्षा अकादमी में जाली दस्तावेज़ों के जरिये एक कश्मीरी युवक द्वारा प्रवेश पा लेने के बाद हुआ है. यह अलग बात हे कि पांच दिन में ही वह पकड़ा गया. इसी के साथ रक्षा अकादमी की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो गए हैं.

यह सर्वविदित है कि देश की सुरक्षा की दृष्टि से पुणे स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) को अतिसंवेदनशील माना जाता है. इतने सुरक्षित रक्षा संस्थान में जाली दस्तावेज़ों के साथ उसमें एक कश्मीरी युवक का प्रवेश पा जाना और वहां पांच दिन रहना, अकादमी की सुरक्षा पर कई सवाल खड़े हो जाते हैं. एनडीए को इसलिए अतिसंवेदनशील माना जाता है, क्योंकि यहां देश की रक्षा करने वाले जवानों को हर तरह की तकनीकी व ग़ैर तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता है. ऐसे संस्थान में किसी व्यक्ति द्वारा जाली दस्तावेज़ों के जरिये प्रवेश पाने का प्रयास करना चिंता में डालने वाली बात है. बनावटी कागज़ातों के जरिये एनडीए में प्रवेश पाने वाले 18 वर्षीय कश्मीरी युवक ने अपना नाम अनमोल विजय बनोत्रा उर्फ शर्मा बताया है, लेकिन उसका अकादमी में प्रवेश लेने का मक़सद क्या था, यह नहीं बताया गया है. सबसे अहम बात यह है कि वह जो भी अपने विषय में जानकारियां दे रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है? इसकी वजह यह है कि वह यदि सही व्यक्ति होता और उसके नेक इरादे रहते तो उसे जाली दस्तावेज़ों के सहारे एनडीए में प्रवेश लेने की क्या जरूरत पड़ती. उसने यह ज़रूर बताया है कि वह कश्मीर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है तो क्या वह वास्तव में अनमोल है या अनमोल का नाम उपयोग करने वाला कोई और व्यक्ति है. इन सब विषयों पर गंभीरता से जांच करने की ज़रूरत है. कोई भी साधारण युवक जो इंजीनियरिंग जैसे विषय की पढ़ाई कर रहा हो जाली दस्तावेज़ों के आधार पर सुरक्षा की दृष्टि से अतिसंवेदनशील माने जाने किसी भी रक्षा संस्थान में प्रवेश करके अपने उज्ज्वल भविष्य को अंधकारमय नहीं बनाना चाहेगा. इसलिए उस युवक ने अब तक जो जानकारियां दी हैं उन पर शंकाएं उठना लाज़िमी है.

अकादमी के अधिकारियों के अनुसार एनडीए की पासिंग परेड पिछले वर्ष नवंबर में हुई थी. उसके बाद पहले के कैडेट्स वहां से जा चुके थे. उसके बाद नए कैडेट्स की भर्ती की शुरुआत हुई. यहां केंद्रीय लोकसेवा आयोग की परीक्षा पास कैडेट्स को ही प्रशिक्षण के लिए चुना जाता है. एक समय में 300 कैडेट्स को ही प्रवेश दिया जाता है. 30 दिसंबर 2011 को एनडीए में प्रवेश लेने वाले कैडेट्स की भीड थी. इसी का लाभ उठाते हुए उक्त युवक ने जाली दस्तावेज़ों के बल पर एनडीए में प्रवेश पाने में कामयाब हो गया, लेकिन इस गफलत का पता तब चला जब एनडीए में प्रवेश पाए कैडेट्स की सूची बनाई गई और उनकी गणना हुई. गणना के दौरान एक कैडेट अधिक होने की बात सामने आयी. इस पर संबंधित अधिकारियों ने सभी कैडेट्स से संबंधित दस्तावेज़ों की गंभीरतापूर्वक जांच की तो पता चला कि कश्मीर से अनमोल नामक युवा ने अवांछित तरीके से एनडीए में प्रवेश पा लिया है.

इस खुलासे से एनडीए में हड़कंप मच गया. उसके बाद अनमोल को पकड़ कर एनडीए के अधिकारियों ने उससे पूछताछ की, लेकिन उसके गोलमोल जवाबों से वे संतुष्ट नहीं हुए. विशेष बात यह थी कि उसे जाली दस्तावेज़ों के जरिए अकादमी में प्रवेश करने का दोषी मानते हुए एनडीए प्रशिक्षक जशनदीप सिंह, अवतार सिंह ने उसे पुणे के वारजे पुलिस थाने के सुपुर्द कर दिया और उसके ख़िलाफ़ धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज कराया. इस बात की तस्दीक वारजे थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सुनील दरेकर ने भी की है. पुलिस ने आरोपी कश्मीरी युवक को अदालत में पेश किया और पुलिस हिरासत में भेज दिया.

अब इस मामले की जांच का सारा दारोमदार पुणे पुलिस पर है. राहत की बात यह है कि उक्त कश्मीरी युवक 5 दिन एनडीए में था पर उसने कोई गड़बड़ी नहीं की. हालांकि, इन पांच दिनों में वह कहां-कहां गया, इस पर ग़ौर किया जाना चाहिए. अभी तक उसने यह नहीं बताया है कि उसका एनडीए में प्रवेश लेने का उद्देश्य क्या था? उसने अपने आवेदन में वायुसेना में प्रशिक्षण पाने का अनुरोध किया है. अब शंका यह उठती है कि यदि वह युवक किसी आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ है तो उसके इरादे बहुत ही ख़तरनाक थे. यदि वह एनडीए में प्रशिक्षण पाने में कामयाब हो जाता तो उसका आतंकी संगठन किस तरीके से उपयोग करते, यह कहना मुश्किल है. उसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है. इसका उदाहरण है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर किया गया हवाई हमला. इसके अलावा एनडीए में रहते हुए वायुसेना के विषय में वह जो भी जानकारी एकत्र करता उसका उपयोग वायुसेना की रक्षा पंक्तियों को तहस-नहस करने के लिए आतंकवादियों के साथ-साथ पाकिस्तानी सेना भी कर सकती थी. इसलिए यह पता लगाना अति आवश्यक है कि वह आतंकवादी संगठन या दुश्मन देश का जासूस तो नहीं है, क्योंकि दोनों ही रूप में वह भारत को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचा सकता था. बहरहाल इस मामले की जांच पुलिस और ख़ुफिया एजेंसियां करेंगी, लेकिन हमें और सतर्क रहने की ज़रूरत है.

feedback@chauthiduniya.com

ये क्या हो रहा है...

वोट दे दो बाबा

राज्य में ये क्या हो रहा है? आजकल मुंबई से लेकर मनसर तक का नेता बड़ा व्यस्त है. किसी के पास फालतू समय नहीं है. वक्त जाया होना कोई बड़ी बात नहीं है और वह अपने प्रवाह पर बह रहा है, लेकिन आजकल उल्टी गंगा बह रही है. एक आम आदमी अपनी शिकायत लेकर मंत्री के पास गया, पर मंत्री स्वयं परेशान नज़र आ रहे थे. उसने सहज बुद्धिवश मंत्री से पूछा माजरा क्या है? आप इतने हैरान-परेशान क्यों? मंत्री महोदय ने कहा- बड़ा व्यस्त हूं. महानगर पालिका और ज़िला परिषद चुनाव न हुए सिर दर्द हो गया है. कहीं सीटों के बंटवारे को लेकर विवाद है, तो कहीं प्रत्याशी को लेकर विवाद है. कुछ जगहों में चुनावी फंड को लेकर हो हल्ला हो रहा है. तू बता किस लिए आया है. आम आदमी ने कहा- हुजूर मेरा छोटा-सा काम था. इस पर मंत्री महोदय ने नाराज़गी भरे स्वर में कहा अरे अभी तेरी बात सुनने का वक्त नहीं है, बाद में आना. कभी भी शिकायत का पुलिंदा लिए चले आते हो. वक्त की नज़ाकत को समझा करो. बेचारा आम आदमी निराश हो कर मंत्री के दरबार से रुख़सत होने लगा. तभी मंत्री ने पीछे से आवाज लगाई अरे सुनो, अच्छा अपनी शिकायत लिखकर मुझे दे दो. और सुनो भइया वोट हमारे ही आदमी को देना. वह आदमी जो शिकायत लिख कर लाया था उसे मंत्री को दे दिया और मंत्री ने अपने चंगु-मंगु को पकड़ा दिया. चंगु-मंगु ने तिरस्कार भरी नज़रों से उस आम आदमी को देखा और कागज़ों को एक ओर डाल दिया, लेकिन उस आदमी को तब आश्चर्य हुआ जब मंत्री के पीछे घूमने वाला स्थानीय नेता उसके मोहल्ले में हाथ जोड़े लोगों का अभिवादन करता दिखाई दिया. उसकी समझ में कुछ नहीं आया, क्योंकि अपने काम के लिए उसने इस नेता के कई चक्कर लगाए थे, उसने कभी उसकी बात सुनने का उसके पास समय नहीं रहा. कभी मीटिंग में जाना रहता या कभी कही के दौरे पर गया रहता था. आश्चर्य की बात यह है कि अब वह गली-गली हाथ जोड़ कर घूम रहा है. इतना सुखद परिवर्तन. वह अभी इन्हीं विचारों में खोया था कि वह नेता उसके सामने पहुंचा और हाथ जोड़े बोला- बाबा मेरा ख्याल रखना. चुनाव में मुझे ही वोट देना. उस आम आदमी के समझ में कुछ नहीं आया. वह सोच में पड़ गया कि जिस नेता के पास कल तक मेरी बात सुनने का वक्त नहीं था, वह आज मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा है. कोई भ्रम तो नहीं है, लेकिन नेता के आगे बढ़ते ही उसके आगे से गुजर रहे उसके परिचित व्यक्ति ने उसे सोच की दुनिया से बाहर निकाला. उसने कहा बाबा, नेता आगे चला गया तुम किस दुनिया में खो गए. आजकल राज्य में चुनावी मौसम है. नेता वोट मांग रहे है- दे.... बाबा वोट....दे....दो. चुनाव जीतने के बाद तो उनके पास पांच साल तक जनता की बात सुनने का वक्त नहीं रहता है. अपनी-अपनी कोठियों, बंगलों में दुबक जाते हैं. बस अपने पिछलग्गुओं का दरबार लगा कर बैठे रहते हैं. हर जनहित के काम से कमीशन का जुगाड़ करने की सोचते रहते हैं. जब चुनाव का मौसम होता है तो वोट की भीख मांगने चले आते हैं हाथ जोड़कर. ये नेता पांच साल तक राजा बने रहते है और पांच बाद एक माह के लिए भिखारी बन दे...दे...वोट...दे....दे, की टेर लगाते गांव-गांव, गली-गली घूमते नज़र आते हैं. आख़िर आम ने परेशान होकर बोला नहीं देना हमको वोट.

महाराष्ट्र ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

महाराष्ट्र हलचल

चंद्रपुर में आयोजित मराठी साहित्य सम्मेलन स्थल का भूमिपूजन करते गोंडवाना विश्वविद्यालय के कुलगुरू डॉ. विजय आईंचवार, राजीव गांधी अभियांत्रिकी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. कीर्तिवर्धन दीक्षित.

यवतमाल के गजानन महाराज मंदिर में आयोजित चित्रकला स्पर्धा में भाग लेते बच्चे.

वर्धा स्थित स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल में पांच दिवसीय रोबोटिक्स वर्कशॉप में रोबोटिक्स प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थियों के साथ प्राचार्य अपूर्वा पाडे.

भंडारा ज़िला परिषद की ओर से देव्हाड़ी में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते जिप के लोकनिर्माण सभापति चरण वाघमारे. इस मौके पर जिप उपाध्यक्ष दीपक गजभिये, पूर्व विधायक मधुकर कुकड़े और नारायणराव तितिरमारे भी मौजूद रहे.

गढ़चिरोली ज़िले के भामरागड़ में सीआरपीएफ की ओर से सिविक एक्शन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों को साइकिल व शैक्षणिक सामग्री और महिलाओं को स्वरोजगार के लिए सिलाई मशीन, ज़रूरतमंदों को सोलर लैंप आदि वितरण किया गया, इस मौके पर उपविभागीय पुलिस अधिकारी विजयकांत सागर, नायब तहसीलदार मेश्राम, सीआरपीएफ के पुलिस निरीक्षक ओमवीर सिंह, पुलिस उपनिरीक्षक इंगवले मौजूद रहे.

राज्य के कृषि आयुक्त ने गोंदिया ज़िले का दौरा किया. इस अवसर पर पूर्व जिप सदस्य संजय टेंभरे की अगुआई में किसानों ने उन्हें एक ज्ञापन भी सौंपा.

बुलढाना ज़िले स्थित खामगांव नगर परिषद मैदान में आयोजित भागवत कथा में प्रवचन करते पं. कमलकिशोर महाराज और उपस्थित श्रद्धालु.

यहां कांग्रेस और राकांपा में अंदरूनी विवाद है. पिछले नपा चुनाव में अनिल देशमुख को ज़बरदस्त हार का सामना करना पड़ा.

Postal Regn. No. RNP/NP/CITY/383/2011-13, RNI No. DELHIN/2009/30467

ज़िला परिषद चुनाव

मित्रों में खिंची तलवार

मयूर रंगारी

नागपुर ज़िला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव फिर एक परिवर्तन लेकर आए हैं. राजनीति में कोई अछूत नहीं होता बरसों पुरानी कहावत आज फिर नागपुर ज़िले में जनता साकार होती देख रही है. सांसद विलास मुत्तेमवार और पूर्व मंत्री सतीश चतुर्वेदी के बीच की दुश्मनी जग ज़ाहिर है, लेकिन नागपुर मनपा के चुनाव ने इन्हें सच्चे बैरी से सच्चा मित्र बना दिया है. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी और भाजपा के प्रदेश महासचिव व विधायक देवेंद्र फड़णवीस के बीच का मनमुटाव आज नज़र नहीं आ रहा. वहीं कभी गडकरी के सबसे क़रीबियों में से एक पूर्व विधायक मोहन मते आज उनके ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं. कई वर्षों तक कांग्रेस के दोस्त और भाजपा–शिवसेना को जातिवादी कहने वाले पूर्व सांसद रामदास अठावले आज कांग्रेस से दूर भाजपा–शिवसेना के मंच को साझा करते दिख रहे हैं. शिवसेना के टिकट पर विधायक और फिर मंत्री रहे सुबोध मोहिते, भाजपा की टिकट पर ज़िला परिषद सदस्य और फिर जिप अध्यक्ष बने सुरेश भोयर, दोनों आज कांग्रेस में है. पहले एक ही पार्टी में रहे भाजपा विधायक चंद्रशेखर बावनकुले और जिप अध्यक्ष भोयर के बीच आज नहीं जमती. साफ़ है कि सत्ता की चमक ने पुराने रिश्तों, अनुभवों को अंधकार में धकेल दिया है. अब नागपुर नए रिश्तों के साथ चुनावों का सामना करने के लिए तैयार है.

नागपुर में प्रतिष्ठा दांव पर

नागपुर ज़िला परिषद की स्थिति बिल्कुल विपरीत है. यहां पार्टी के लिए नहीं, बल्कि नेता अपनी प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए चुनावी रण में कूद गए हैं. इनमें कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष रणजीत देशमुख, राज्यमंत्री राजेंद्र मुलक, राकांपा के मंत्री अनिल देशमुख, कांग्रेस के ही सुनील केदार, नाना गावंडे, सुबोध मोहिते, सुरेश भोयर, राकांपा के रमेश बंग, नितिन राठी, शिवसेना के आशीष जैस्वाल, भाजपा के चंद्रशेखर बावनकुले, रिपाइं की सुरेखा कुंभारे प्रमुख हैं. काटोल, कलमेश्वर, नरखेड़ में कांग्रेस के रणजीत देशमुख और सुनील केदार, वहीं राकांपा के अनिल देशमुख और रमेश बंग के बीच विवाद है. वहीं रिश्ते में भाई होने के बाद भी रणजीत देशमुख और अनिल देशमुख एक–दूसरे का प्रभाव कम करने में लगे रहते हैं. यहां कांग्रेस और राकांपा में अंदरूनी विवाद है. पिछले नपा चुनाव में अनिल देशमुख को ज़बरदस्त हार का सामना करना पड़ा. कहा जाता है कि इसके लिए रणजीत देशमुख ज़िम्मेदार थे. सुनील केदार का अपना प्रभाव है. पिछले विधानसभा चुनाव में पराजित हुए रमेश बंग इस बार अपनी स्थिति को मज़बूत करने में लगे हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि इनके बीच की लड़ाई का फ़ायदा शिवसेना–भाजपा को हो सकता है. इसके साथ ही यहां लोधी समाज गठबंधन ने 8 नपा सीटें जीतकर अपना प्रभाव छोड़ा है. ज़ाहिर है इसका असर ज़िला परिषद की सीटों पर भी पड़ेगा. रामटेक में सीधे तौर पर शिवसेना और कांग्रेस के बीच की लड़ाई है. शिवसेना विधायक आशीष जैस्वाल अभी अच्छी स्थिति में है. वहीं कुछ वर्ष पूर्व शिवसेना से कांग्रेस में आए सुबोध मोहिते भी काफ़ी दिनों से परिसर में अपना दबदबा वापस हासिल करने के लिए छटपटा रहे हैं. उन्हें केंद्रीय मंत्री मुकुल वासनिक, पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख का क़रीबी माना जाता है. कामठी में भी भाजपा वर्सेस कांग्रेस की स्थिति है. ज़िला परिषद के अध्यक्ष सुरेश भोयर पहले भाजपा में थे. बाद में अध्यक्ष का दामन थाम कर अध्यक्ष बने. पिछले नपा चुनाव में उन्होंने भाजपा विधायक चंद्रशेखर बावनकुले को काफ़ी कड़ी टक्कर दी थी. जिप चुनाव में दोनों में वर्चस्व की लड़ाई जारी है. वहीं रिपाई की पूर्व राज्यमंत्री सुरेखा कुंभारे भी अपनी स्थिति मज़बूत करने के लिए पूरा ज़ोर लगाए हुए हैं. नागपुर ज़िला परिषद में सत्ता किसी भी पार्टी की बने, यहां प्रस्थापित नेता अपना क़द बनाए रखने के लिए पार्टी को कम महत्व दे रहे हैं. नपा चुनाव से यह साबित हो गया है.

चंद्रपुर में बदले हालात

चंद्रपुर ज़िले में वैसे कांग्रेस का वर्चस्व रहा है, लेकिन पिछले ज़िला परिषद चुनाव के बाद पांच वर्षों में यहां परिस्थितियां बदल गई हैं. वर्तमान में यहां कांग्रेस–भाजपा सत्ता में है. पिछले चुनाव में कांग्रेस के विधायक संजय देवतले मंत्री नहीं थे, लेकिन आज वे कैबिनेट मंत्री हैं. उनका विजय वटेट्टीवार और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नरेश पुगलिया के बीच का विवाद सर्वविदित है. पुगलिया को कामगारों का नेता माना जाता है. सीमेंट कारख़ानों में उनकी समर्थित लेबर यूनियनों का अच्छा दबदबा है. पूर्व विधायक निमकर, पुगलिया के काफ़ी क़रीबी माने जाते थे, लेकिन आज वे राकांपा में हैं. ऐसे में पुगलिया का दबदबा थोड़ा कम हो गया है. भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार के कारण ही यहां कांग्रेस–भाजपा में गठबंधन हुआ है. वैसे यहां कांग्रेस के 25, भाजपा के 18, राकांपा के 5, बसपा के 2, शेतकरी संगठन के 2 और शिवसेना के पास 1 ज़िला परिषद की सीट है. राकांपा के बालासाहब वासाडे और पूर्व विधायक निमकर राकांपा को सत्ता में लाने के लिए काफ़ी ज़ोर लगा रहे हैं. वैसे देखा जाए, तो यहां सीधा मुक़ाबला कांग्रेस–भाजपा में ही है.

गढ़चिरोली में उभरा युवा शक्ति पैनल

गढ़चिरोली ज़िला परिषद में राकांपा 22 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है. वहीं कांग्रेस 9 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर है. भाजपा और शिवसेना के पास 5–5 सीटें हैं. गढ़चिरोली में विजय वडेट्टीवार गुट का अच्छा वर्चस्व है. वहीं राकांपा के धर्मरावबाबा आत्राम अच्छी स्थिति में है. लेकिन पिछले नपा चुनाव में जिस तरह युवा शक्ति पैनल ने सीटें जीती हैं, उससे यहां सत्ता के सभी समीकरण उसके इर्द–गिर्द घूमने लगे हैं. जानकारों की मानें, तो चुनाव के बाद सत्ता हासिल करने में पैनल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा.

बुलढाना में कांग्रेस-राकांपा में बढ़ी तक़रार

पिछले नगरपालिका चुनाव में गृहमंत्री व राकांपा के नेता आर.आर. पाटिल ने कांग्रेस को छोटी पार्टी कह दिया था. इसका सीधा असर बुलढाना में कांग्रेस–राकांपा के रिश्तों पर पड़ा है. बुलढाना नपा में कांग्रेस ने शिवसेना से हाथ मिलाकर सत्ता हासिल की और राकांपा को किनारे कर दिया. नपा में सबसे अधिक 11 सीटें जीतने के बाद भी राकांपा विपक्ष में बैठी है और महज़ 5 सीटें जीतकर कांग्रेस सत्ता में है. अब दोनों ही पार्टियों के नेता एक–दूसरे को फूटी आंख नहीं भा रहे हैं. बुलढाना ज़िले की 7 विधानसभा सीटों में से शिवसेना, भाजपा और कांग्रेस के पास 2–2 विधायक हैं, जबकि राकांपा के खाते में 1 विधायक है. भाजपा के संजय कुटे, चैनसुख संचेती, शिवसेना के विजयराज शिंदे, डॉ. संजय रायमुलकर, कांग्रेस के राहुल बोंद्रे, दिलीप कुमार सानंदा और राकांपा के डॉ. राजेंद्र शिंगणे में वर्चस्व क़ायम करने के लिए जद्दोजहद शुरू हो गई है.

यवतमाल में ठाकरे या राठौड़

यवतमाल ज़िले में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे की प्रतिष्ठा दांव पर है. यहां उनके बेटे राहुल ठाकरे ज़िला परिषद के अध्यक्ष हैं. वहीं कांग्रेस के ही मानकर उपाध्यक्ष हैं. 30 सीटों के साथ यहां कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त है, लेकिन कांग्रेस के नेता उत्तमराव पाटिल के पिछले दिनों राकांपा में शामिल होने से सत्ता के समीकरण पूरी तरह बदल गए हैं. वहीं शिवसेना के दारव्हा से विधायक संजय राठौड़ कांग्रेस को कड़ी चुनौती दे रहे हैं. ग़ौरतलब है कि राठौड़ इससे पूर्व ठाकरे को विधानसभा चुनाव में हरा चुके हैं. जिप में भाजपा–शिवसेना की 11 सीटें हैं. वहीं राकांपा 17 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर है. हालांकि यहां कांग्रेस की स्थिति मज़बूत है, लेकिन पाटिल के राकांपा में जाने और शिवसेना के राठौड़ द्वारा ज़बरदस्त ज़ोर मारने से परिणाम पर अनिश्चितता के बादल छाए हुए हैं.

अमरावती में भी संशय बरक़रार

अमरावती ज़िला परिषद में वैसे तो अभी कांग्रेस–राकांपा की सत्ता है, लेकिन इससे पहले ढाई वर्ष तक यहां राकांपा, शिवसेना, भाजपा ने निर्दलियों को साथ लेकर सत्ता का सुख भोगा है. बाद में ढाई वर्ष कांग्रेस–राकांपा गठबंधन सत्ता में आया. यहां राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल के बेटे रावसाहब शेखावत भी अपनी स्थिति मज़बूत करने में लगे हैं. कांग्रेस के बबलू देशमुख अध्यक्ष और राकांपा के संतोष महात्मे ढाई वर्ष तक उपाध्यक्ष रहे. वर्तमान में कांग्रेस के पास 22 और राकांपा की 8 सीटें हैं. वहीं शिवसेना 9 और भाजपा के खाते में 8 सीटें हैं. ज़ाहिर है आंकड़ों से कांग्रेस की स्थिति थोड़ी मज़बूत है, लेकिन पिछले चुनाव के बाद जिस तरह तेज़ी से यहां सत्ता के समीकरण बदले हैं, हाल में पूर्व मंत्री डॉ. सुनील देशमुख और उनके सहयोगियों ने जन विकास कांग्रेस के नाम से नई पार्टी बनाई है और दूसरी ओर भाजपा से निष्कासित विधायक जगदीश गुप्ता ने जनकल्याण कांग्रेस के नाम पर नई पार्टी का गठन किया है. इसके साथ ही डॉ. देशमुख, जगदीश गुप्ता और विधायक रवि राणा ने हाथ मिलाकर महायुति बनाकर नई चुनौती खड़ी कर दी है. इसे देखते हुए इस बार भी अनिश्चितता बनी हुई है.

वर्धा में मेघे फैक्टर

जब तक सांसद दत्ता मेघे राकांपा में थे, तब तक यहां राकांपा अच्छी स्थिति में थी, लेकिन मेघे के कांग्रेस में जाते ही यहां राकांपा कमज़ोर हुई है. हालांकि कांग्रेस में भी मेघे और कुछ नेताओं के बीच नहीं जमती, लेकिन फिर भी कार्यकर्ताओं में मेघे काफ़ी लोकप्रिय हैं. वर्तमान में यहां कांग्रेस–राकांपा की सत्ता है. कांग्रेस के विजय जैस्वाल अध्यक्ष और राकांपा के सुनील राऊत उपाध्यक्ष हैं. कांग्रेस के पास 19, राकांपा 10, भाजपा 7 और शिवसेना के पास 4 सीटें हैं. कांग्रेस–राकांपा में गठबंधन नहीं होने के कारण इस बार राकांपा अपने दम पर जिप की सत्ता हासिल करने हेतु ज़ोर लगा रही है. दोनों के बीच रस्सी खेंच जमकर जारी है. वहीं भाजपा और शिवसेना भी अपनी सीटें बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़ोर लगा रही हैं.

feedback@chauthiduniya.com

वर्चस्व की लड़ाई चरम पर

महाराष्ट्र की राजनीति जिसे समझ में आ गई, उसने न सिर्फ़ राज्य में, बल्कि देश में भी अपना दबदबा बनाया. इसी दबदबे और रुतबे की लड़ाई फिर शुरू हो गई है या कहिए चरम पर पहुंच गई है. राज्य की राजनीति में महानगरपालिका चुनाव में जहां पार्टियों का बैनर मायने रखता है, वहीं ज़िला परिषद चुनाव में व्यक्ति विशेष का महत्व काफ़ी अधिक होता है, यानी यहां पार्टी नहीं, बल्कि वे लोग मायने रखते हैं, जो यहां माने जाते हैं. अलग-अलग जगहों पर उन्हें अलग-अलग नामों से पहचाना जाता है, जैसे दिग्गज, बाहुबली या फिर नेता. इन्हीं दिग्गजों का रुतबा नागपुर और विदर्भ सहित पूरे राज्य में ज़िला परिषद चुनाव के बहाने दांव पर लगा है. कई महीने पहले ही बिछ चुकी इस बिसात में सभी तेज़ी से चालें चल कर एक-दूसरे को मात देने में लगे हैं. जैसे-जैसे मतदान की तिथि नज़दीक आ रही है, वैसे-वैसे अब यह लड़ाई चरम पर पहुंचती जा रही है. राज्य की 27 ज़िला परिषदों के लिए 7 फरवरी को मतदान होना है. संभवतः उसी दिन या उसके अगले दिन चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे, यानी आने वाले 15 दिनों में महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्र की राजनीति आख़िर किस करवट बैठती है, यह सामने आ जाएगा. इन 27 ज़िला परिषदों में से केवल 4 पर भाजपा-शिवसेना और शेतकरी कामगार पार्टी की सत्ता है, जबकि बाक़ी बची 23 ज़िला परिषदों पर कांग्रेस-राकांपा सत्ता में है. ग़ौर करने वाली बात यह है कि दोनों ही पार्टियों ने पिछला चुनाव भी अलग-अलग लड़ा था. इस बार भी दोनों ने ज़िला परिषद चुनाव में गठबंधन नहीं करने का निर्णय लिया है. राज्य की 27 ज़िला परिषदों में विदर्भ की 7 ज़िला परिषदें शामिल हैं. इनमें नागपुर, चंद्रपुर, अमरावती, गढ़चिरोली, यवतमाल, वर्धा और बुलढाना ज़िला परिषदों का समावेश है. चंद्रपुर को छोड़ दिया जाए, तो बाक़ी सभी 6 ज़िला परिषदों पर कांग्रेस-राकांपा की सत्ता है. चंद्रपुर में धुर विरोधी कांग्रेस-भाजपा की युति सत्ता पर है. उल्लेखनीय है कि भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार इसी ज़िले से हैं.

महिलाओं की ताक़त बढ़ेगी

स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं के लिए 50 फ़ीसदी आरक्षण घोषित होने से यहां महिला राज होगा. ज़िला परिषद में हालांकि पहले सही महिला उम्मीदवार ढूंढने में हर पार्टी को मेहनत करनी पड़ी थी. काफ़ी माथापच्ची के बाद अब पार्टियों का पूरा ध्यान प्रचार पर लगा है. महिला उम्मीदवार अपनी कार्यकर्ताओं के साथ घर के खाने की चिंता छोड़ गांव-गांव घूम रही हैं. मंचों पर सिर पर पल्लू लेकर बेधड़क भाषण दे रही हैं. वादे कर रही हैं और उसे निभाने का दम भर रही हैं. निश्चित ही इस चुनावी माहौल ने घर से लेकर सभागृह तक की राजनीति को बदलकर रख दिया है.

चौथी दुनिया

बिहार झारखंड

दिल्ली, 23 जनवरी–29 जनवरी 2012

www.chauthiduniya.com

संजीवनी का है ऐलान, झारखण्ड–बिहार में हो सबका मकान

SANJEEVANI BUILDCON

3rd & 4th floor, GEL Church Complex, Main Road, Ranchi, Customer Care No. - 0651-2331429

Sanjeevani Dynasty-I
PLOT-13 LAC, DUPLEX-25 LAC
Near Ranchi College

Sanjeevani Dynasty-II
PLOT-10 LAC, DUPLEX-22 LAC
Booty More

Future City (BIT)
PLOT-4 LAC,
BUNGLOW-10 LAC

Future City (Namkom)
PLOT-4 LAC,
BUNGLOW-10 LAC

Future City (Pithoria)
PLOT-4 LAC,
BUNGLOW-10 LAC

Sanjeevani Mega Township
PLOT-3.5 LAC, BUNGLOW-09 LAC
Hazaribagh

हाशिए पर पासवान बिरादरी

ज़िम्मेदार कौन

पासवान बिरादरी के नेताओं को अपनी बिरादरी से अधिक अपने हितों की चिंता रहती है, यही वजह है कि बिहार में एक बड़ी राजनीतिक ताक़त होने के बावजूद पासवान समाज आज हाशिए पर चला गया है.

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

सरोज सिंह

बिहार में नीतीश कुमार समेकित विकास की नई परिभाषा गढ़ने का दावा करते हैं. लेकिन राज्य सरकार द्वारा नवपरिभाषित प्रदेश की एकमात्र दलित जाति पासवान समुदाय के बीच इस दावे पर सवाल उठने लगे हैं. लाजिमी भी है. दशकों बाद राज्य मंत्रिमंडल में इस बिरादरी का कोई सदस्य नहीं है. विगत छह वर्षों में सत्ताधारी एनडीए ने किसी पासवान समुदाय के नेता को राज्यसभा और विधान परिषद में जगह देना भी मुनासिब नहीं समझा गया. वहीं सिर्फ़ पासवान जाति ही अधिकारिक तौर पर दलित कहलाने का हक़दार रह गई. बाकी सब महादलित क़रार दे दिए गए. इस कुर्सी जनित राजनीति का विद्रुप चेहरा तब उजागर हुआ, जब पासवान समुदाय को भी संतुष्ट करने की नीयत से भविष्य में उन्हें भी महादलित का दर्जा प्रदान करने का मुलम्मा दिया गया. इससे पूर्व बिहार की अनुसूचित जातियों में से मोची, पासवान, धोबी एवं पासी बिरादरी के अलावा अन्य जातियों को महादलित घोषित कर दिया गया था. दलित समुदाय का यह पृथक्करण राजनीतिक स्वार्थ सिद्धी में बाधक साबित होता दिखा. लिहाज़ा, महादलित आयोग की तथाकथित सिफ़ारिशों के आधार पर धोबी एवं पासी बिरादरी को भी दलित से महादलित का चोला ओढ़ा दिया गया. इसके बाद भी मन में कुछ फांस रह गयी थी. तदोपरांत पुन: मोची समुदाय को भी दलित से महादलित के तौर पर रूपांतरित कर दिया गया. लेकिन पासवान बिरादरी को कोई भला नहीं हो पाया. ज़मीनी सच्चाई तो यह है कि इस सरकार के साथ–साथ इस बिरादरी की राजनीति करने वाले नेता भी इसके लिए कम ज़िम्मेदार नहीं हैं.

लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस कहते हैं कि नीतीश कुमार घोर जातिवादी हैं. उन्हें लगता है कि पासवान समुदाय के लोग उन्हें वोट नहीं देते हैं. इसलिये उन्हें नीचा दिखाने के लिए इस समुदाय के किसी व्यक्ति को मंत्री नहीं बनाया. उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में किसी पासवान की भलाई नहीं की है. पासवान समुदाय के राजनीतिक कार्यकर्ता को विधान परिषद और राज्यसभा में मेम्बरी दिलवाना भी इन्हें गंवारा नहीं हुआ. लोजपा के प्रधान महासचिव राघवेंद्र कुशवाहा कहते हैं दरअसल यह सारा कुछ पासवान जाति को सामाजिक व राजनीतिक हाशिए पर लाने की कवायद है. पासवानों की राजनीतिक ताक़त से यह सरकार घबराती है.

इन आरोपों से बाहर निकलें तो ज़मीनी सच्चाई यह भी है कि पासवान बिरादरी की इस दुर्दशा के ज़िम्मेदार इस समुदाय के अग्रणी नेतागण भी हैं. सर्वविदित है कि जाति से संबंधित राजनीतिक जलसे आयोजित कर जातिगत राजनीति के सूरमा निज स्वार्थ की पूर्ति करते हैं. पासवान बिरादरी के नेताओं का स्वाभिमान भी ऐसे ही अवसरों पर जागता है. और, हर छोटा बड़ा नेता अपनी हैसियत के मुताबिक़ इस सुअवसर को भुनाने में जुट जाता है. ऐसे अवसर पर वक्तागण समाज के वास्तविक मुद्दों की चर्चा के बजाए व्यक्तिगत सियासी मसले के प्रति अधिक प्रतिबद्ध नज़र आते हैं. कोई ख़ुशामदी, चापलूसी की हद तोड़ता दिखता है. वहीं कुछ बागी होने का दम भर रहा होते हैं. लेकिन किसी को समाज की फिक्र नहीं होती है. ऐसे ही राजनेताओं की करतूत के कारण पासवान समुदाय राजनीतिक रूप से हाशिये पर धकेल दिया गया है. फ़िलवक़्त राज्य मंत्रिमंडल में इस समुदाय का एक भी मंत्री नहीं है. बिहार विधानसभा में इनकी राजनीतिक हैसियत न्यूनतम हो गयी है. इसके ज़िम्मेदार वही नेता हैं जो जाति के नाम पर सियासी फसल तो काटते रहे, सत्ता का सुख भोग करते रहे, लेकिन समाज में ऐसा राजनीतिक व्यक्तित्व विकसित करने पर ज़ोर नहीं दिया, जिसकी बिरादरी के इतर भी काफी स्वीकार्यता हो. यही वजह है कि पासवान समुदाय से काफी कम आबादी वाली कुर्मी बिरादरी से आने वाले नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन गये. वहीं पासवान समुदाय का कोई नेता दूर–दूर तक इसके आस–पास नज़र नहीं आता. हालांकि, लोजपा नेता रामविलास पासवान देश के बड़े राजनेता माने जाते हैं. लेकिन कुछ ग़लत राजनीतिक फैसलों ने इन्हें पीछे धकेल दिया है. भाजपा नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय पासवान दावा करते हैं कि पासवान समुदाय रामविलास पासवान के भ्रमजाल से मुक्त हो रहा है. यही कारण है कि सबसे अधिक भाजपा के टिकट पर इस समुदाय के विधायक चुनाव जीत कर आए हैं. लेकिन राज्य मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दिये जाने के मुद्दे पर सीधे तौर पर कुछ नहीं कह पाते हैं. हालांकि, विधानसभा में सत्ताधारी दल में पासवान समुदाय के विधायकों की तादाद बढ़ने और योगेंद्र पासवान को अनुसूचित जाति आयोग का उपाध्यक्ष बनाने को राजग सरकार की उपलब्धि बताते अघाते नहीं हैं. वैसे इन्हें भरोसा है कि इस बार राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव में इस समुदाय का ख्याल रखा जायेगा. क़ाबिलेग़ौर है कि पिछला विधानसभा चुनाव भी पासवान उम्मीदवारों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण साबित हुआ था. राजनगर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के रामप्रीत पासवान राजद के रामलखन राम रमण से मात खा गए. लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस को अलौली विधानसभा क्षेत्र में रामचंद्र सदा ने तकरीबन दो दशक बाद पटखनी दे दी. बखरी में भाकपा के दिग्गज पूर्व विधायक रामविनोद पासवान लोजपा के टिकट पर भाजपा उम्मीदवार रामानंद राम ने चारों खाने चित कर दिया. इसके अलावा ज़्यादातर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्रों में पासवान समुदाय के ही उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे थे. इसके अलावा भी इस समुदाय की बदनसीबी की दास्तान है. पासवान समुदाय के कुछ निवर्तमान विधायकों का टिकट काट जदयू नेतृत्व ने ग़ैर पासवान बिरादरी के दलित नेताओं को उम्मीदवार बना दिया. कुटुम्बा में रेणु देवी का टिकट काट ललन भुइयां, चेनारी में ललन पासवान के बदले श्यामबिहारी राम और राजपुर में श्यामपरी देवी के निधन के बाद संतोष निराला को उम्मीदवार बनाया गया था. हालांकि, कुछ पासवान नेताओं ने अन्य दलित विधायकों को पटखनी देकर तीन नए क्षेत्रों पर कब्जा जमाया. कोढ़ा में भाजपा के महेश पासवान ने कांग्रेस की नेत्री सुनीता देवी को चारों खाने चित कर दिया. वहीं कुशेश्वरस्थान में भाजपा के शशिभूषण हजारी ने कांग्रेस के विधायक दल के नेता रहे डॉ. अशोक कुमार को मात दी. एक और नया चेहरा भाजपा के अमन पासवान नवसृजित पीरपैंती सुरक्षित सीट से विधायक बने हैं. दिलचस्प है कि जदयू में भी इस जाति के कई विधायक हैं, सिकंदरा से पूर्व मंत्री रामेश्वर पासवान, मोहनियां से पूर्व मंत्री छेदी पासवान तथा कल्याणपुर से पूर्व मंत्री रामसेवक हजारी. वहीं भाजपा में पासवान समुदाय के विधायकों की संख्या सर्वाधिक है, महेश पासवान, अमन पासवान, शशिभूषण हजारी के अलावा रोसड़ा से मंजू हजारी, हरिसिद्धी से कृष्णनंदन पासवान और बोधगया से श्यामदेव पासवान. क़ाबिलेग़ौर है कि पासवान के स्वघोषित नेता रामविलास पासवान की पार्टी लोजापा से एक भी पासवान उम्मीदवार विधानसभा का मुंह नहीं देख सका. तमाम विपक्षी दलों के टिकट पर कोई पासवान बिरादरी का उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाया. हालांकि, इसका अहसास लोकसभा चुनाव के समय ही हो गया था. उस समय रामविलास पासवान और इनके भाई रामचंद्र पासवान दोनों क्रमश: हाजीपुर और समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से मुंह की खा बैठे थे. सिर्फ़ जदयू के टिकट पर रिश्ते में इनके ममेरे भाई महेश्वर हजारी रामचंद्र पासवान को समस्तीपुर में चित कर लोकसभा का रास्ता तय कर पाए. इनके अलावा तमाम पक्ष–विपक्ष के दिग्गज पासवान नेता चुनाव में खेत रहे थे.

पासवान समुदाय के कुछ नेता मतलब सिद्ध होने के लिए चमचई की हद तोड़ देते हैं. अगर स्वार्थ की पूर्ति नहीं हुई तो बेवजह आग उगलने में भी देर नहीं करते हैं. इसके ताजा उदाहरण हैं छेदी पासवान. गत चुनाव के बाद इन्हें मंत्रिपरिषद में जगह नहीं दी गई तो वह आगबबूला हो उठे. सरकार को आड़े हाथों लेने लगे हैं. गत वर्ष पूर्व राजधानी पटना में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री नहीं बनाए जाने और हाशिए पर धकेल दिए जाने से नाराज़ छेदी पासवान ने अपने ही पार्टी के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए. मतलब पासवान बिरादरी की चिंता से कहीं ज़्यादा ये नेता अपने हित साधने में लगे रहे. यही वजह है कि राजनीतिक रूप से एक बड़ी राजनीतिक ताक़त होने के बावजूद पासवान बिरादरी बिहार में हाशिए पर चली गई है.

छेदी पासवान | पशुपति कुमार पारस | ललन पासवान | रामचंद्र पासवान | संजय पासवान | महेश्वर हजारी

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

सरकार द्वारा किसानों को कृषि यांत्रिकरण योजना के तहत पचास प्रतिशत अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने की योजना है.

लोगों ने भी आशा लगा रखी थी कि मुख्यमंत्री फुर्सत के कुछ पल देते और कार्यकर्ताओं का मान–सम्मान बढ़ाते.

चौथी दुनिया

अफ़सर ही नेताओं को भ्रष्ट बनाते हैं

सरकारी नौकरी में रहकर दिल की बात जुबां पर लाने का साहस कम ही अफसर जुटा पाते हैं. ख़ासकर तब, जब बात उनकी अपनी ही बिरादरी की हो. आईजी (कमज़ोर वर्ग) सीआईडी बिहार अरविंद पांडेय बिहार के लिए ऐसा नाम है जो अपने काम को पूरी ईमानदारी से अंजाम देते हैं और दूसरों के लिए उदाहरण पेश करते हैं. नौकरी के अलावा धार्मिक व साहित्यिक कार्यों में भी विशेष रुचि रखते हैं. फेसबुक उनके विचार दुनिया और जीवन को समझने का अच्छा ज़रिया है. इसीलिए फेसबुक की दुनिया में उनको पसंद करने वालों की संख्या काफ़ी है. पांडेय ने नौकरशाही के सामने आने वाली मुश्किलें, भ्रष्टाचार, नक्सलवाद और इससे निपटने के उपायों पर विस्तार से कई बातें कहीं. प्रस्तुत है ख़ास अंश.

बिहार में अधिकारियों को काम करने की कितनी आज़ादी है.

मेरा अनुभव रहा है कि बिहार में सरकारी सेवकों को अपने कर्तव्यों के पालन में सर्वाधिक हस्तक्षेप–मुक्त परिवेश उपलब्ध रहा है और इस अवसर का उपयोग अधिकांश अधिकारी करते भी हैं. सिद्धांतनिष्ठ पक्षधरता और नियमों के पालन हेतु यहां के अधिकारी अपने पक्ष को सशक्त रूप में प्रस्तुत करते हैं और इसे अन्य सम्बंधित पक्षों द्वारा स्वीकार भी किया जाता है. यहां अनुचित राजनीतिक हस्क्षेप भारत के अन्य सभी राज्यों की तुलना में सदा ही कम रहा है. सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा विचरित एवं भारत के संविधान द्वारा उपबंधित भारत की अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों से यह अपेक्षा की गई थी कि वे लोक–सेवा का कार्य, शत–प्रतिशत नियमों का पालन करते–कराते हुए संपन्न करेंगे और बिहार में यह सर्वाधिक स्पष्ट और उज्जवल रूप में होता रहा है. यहां यदि कोई अधिकारी नियमों से विचलित होता है तो लोक–सचेष्टता और प्रशासनिक सतर्कता के कारण ऐसे अधिकारी पर यथोचित कारवाई भी अपरिहार्य हो जाती है. यहां के लोग एवं सम्पूर्ण प्रशासनिक–प्रणाली सदा ही सुचारू, सतर्क एवं स्वाभवत: सचेष्ट रही है.

इस क्षेत्र में लगभग दो दशक से हैं, भ्रष्टाचार के प्रति आपका क्या अनुभव रहा है?

वर्ष 1996 में मैंने पुलिस अधीक्षक साहिबगंज (जो इस समय झारखंड का ज़िला है) में जाली मास्टर रोल बनाकर मज़दूरों को दी जाने वाली मज़दूरी की राशि के गबन का मामला दर्ज कराया था. इस मामले को साहिबगंज के एक कार्यपालक अभियंता के लिखित परिवाद के आधार पर मामला दर्ज कराया गया था. बाद में इस मामले को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में सीबीआई अन्वेषण हेतु दिया गया और इसमें सीबीआई ने अनेक अधिकारियों सहित अन्य अभियुक्तों को आरोप पत्रित किया.

अरविंद पांडेय

इसी तरह वर्ष 2000 में मोतिहारी ज़िले के चिरैया प्रखंड में कारित हुडको इंदिरा आवास घोटाला में तत्कालीन भवन निर्माण राज्यमंत्री के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के हेतु सख्त कारवाई करने के साथ अन्य अनुवर्ती कारवाई भी सुनिश्चित कराई. राज्य में कुछ सरकारी सेवकों के अपराधिक षडयंत्र के कारण व्यापक रूप से किये जा रहे वाणिज्य कर अपवंचना के मामले में अन्वेषणा करते हुए अनके सरकरी सेवकों और अन्य लोगों के विरुद्ध क़ानूनी कार्रवाई कराई गई, जिससे सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व का लाभ हुआ और करवंचना रुक गयी. वर्ष 1998 में जांच में दौरान मैंने 200 करोड़ रुपये के ग़रीबी रेखा से नीचे रहने वाले नागरिकों के लिए संकल्पित साड़ी–धोती घोटाला में एक प्रमुख राजनीतिज्ञ के विरुद्ध प्राप्त साक्ष्यों को लिपिबद्ध करते हुए कारवाई की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया. ऐसेअनेक उदाहरण हैं. इन सारे कर्तव्य–र्निवहन की स्वतंत्रता सदा से रही है जो वा य दबाव की बात और राजनीतिक हस्तक्षेप की बात करते हैं वे कमज़ोर लोग हैं.

पुलिस पब्लिक की दोस्त है, यह बात केवल नारों में ही क्यों रह जाती है?

पुलिस की प्रकृति, प्रयास और प्रक्रिया के शुद्धिकरण के बाद ही आम नागरिक इसे मित्र मानेगा अन्यथा पारंपरिक पुलिसिया अगर होती रहेगी तो आम लोग पुलिस से दूर ही रहेंगे. मैंने इस हेतु अनेक प्रयोग किये, जिन्हें मेरे फेसबुक पेज Arvind Pandey: Litigation Free Society में देखा जा सकता है. इसमें जहांगीरी घंटी का प्रयोग उल्लेखनीय है. मेरा मानना है कि क्षेत्रों में पुलिस अधीक्षक क्षेत्रीय उप महानिरीक्षक और प्रक्षेत्रीय महानिरीक्षक के रूप में पदस्थापित अधिकारी 24 घंटे आम लोगों की सेवा के लिए उपलब्ध रहें तभी वे संतोषजनक सेवा दे पाएंगे. पुलिस को सेवा–प्रदाता के रूप में कार्य करना चहिए.

आपको लगता है कि नेता लोग अफसरों को भ्रष्ट बनाते हैं?

मेरा मानना है कि सरकारी सेवक ही राजनीतिज्ञों को भ्रष्ट बनने का प्रशिक्षण देते हैं. आप किसी केस के इतिहास और उसके घटित होने की प्रक्रिया और विभिन्न चरणों का अध्ययन करेंगे तो पायेंगे कि सारे घोटालों की पृष्ठभूमि उस विभाग के किसी अधिकारी ने ही तैयारी की होगी. निर्णय के विभिन्न चरणों में नींव और अंतिम सीढ़ी के पहले तक सिर्फ़ अधिकारी ही होते हैं. अंतिम सीढ़ी पर कार्यकारी शक्ति प्राप्त कोई अधिकारी होता है. अत: आपके इस प्रश्न का यार्थिथ सत्य आम धारणा के विपरीत है.

आजकल नौकरशाहों का राजनीति में आने का सिलसिला बढ़ा है. इसे आप किस नज़रिए से देखते हैं?

भारत का संविधान राजनीतिक प्रणाली के माध्यम से ही संवधिान की उद्देशिका में लिए गये संकल्पों और सपनों को साकार करने की एक व्यवस्था हम भारत के लोगों को देता है. इसलिए राजनीति में किसी वर्ग समुदाय के लोगों का आना संविधान–सम्मत है. अधिकारियों के लिए सेवा में रहते हुए कु आचार–नियम है, जिनका पालन करना होता है, किन्तु यदि कोई अधिकारी सेवा त्याग कर किसी अन्य माध्यम से समाज और देश की सेवा करना चाहता है तो उसके इस भाव का सम्मान होना चाहिए.

नक्सल की बढ़ती समस्या और इसके निराकरण पर आप क्या कहेंगे.

बिहार में इस समय सरकार की सकारात्मक विकास–नीतियों के कारण नक्सलवाद की घटनाओं की संख्या और गंभीरता दोनों ही दृष्टियों से कमी आई है. बिहार में विकास की यही गति बनी रहेगी. हम नक्सलमुक्त बिहार शीघ्र देखेंगे. 2005 के पहले एक समय था जब यहां पुलिस बल, उसके पिकेट और थानों पर अक्सर हमले होते थे और वहां से रायफल और गोलियां लूट ली जाती थीं. लेकिन अब लूटी हुई रायफलें बरामद होती हैं. अत: इस समय बिहार अपने पूर्व महिमामय रूप को प्राप्त करने के लिए संकल्पबद्ध है और ऐसा शीघ्र होकर रहेगा.

सरोज सिंह
feedback@chauthiduniya.com

जदयू–भाजपा के दिल नहीं मिले

पूर्णिया

नीरज कुमार सिंह

राजनीति में उठा–पटक के साथ दांव–पेंच का दौर हमेशा चलता रहता है, लेकिन ऐसे में सत्तारूढ़ घटक दलों के आपसी तालमेल में सामंजस्यता के अभाव के साथ एक दूसरे को नीचा दिखाने का खेल खेला जाए तो इससे सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि और अंदर ही अंदर कुछ राजनीतिक खिचड़ी अवश्य पक रही है. मालूम हो कि पूर्णिया प्रमंडलीय मुख्यालय में मुख्यमंत्री की सेवा यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें बैनर पोस्टर से पूरे पूर्णिया शहर को पाट दिया गया. हालांकि मुख्यमंत्री की सेवा यात्रा सरकारी दौरे का कार्यक्रम था, लेकिन बैनर–पोस्टर देखने के बाद लगता है कि सेवा यात्रा सरकारी दौरा ना होकर किसी एक विशेष दल की यात्रा बनकर रह गई है. पूर्णिया भाजपा की तरफ से उदय सिंह ...

feedback@chauthiduniya.com

मरीज़ों का इलाज व सेवा ही धर्म है

कोसी प्रमंडल में सर्जरी के मामले काफ़ी बढ़ गए हैं. इस बारे में चिकित्सक से लेकर ...

सर्जरी कब और क्यों ज़रूरी है और इससे कैसे बचा जा सकता है?

सर्जरी करने के दौरान इस इलाके में आपको क्या क्या परेशानी उठानी पड़ती है?

इतने कम समय में सूर्या हॉस्पिटल अपनी साख और लोगों का विश्वास कैसे हासिल कर पाया और भविष्य में क्या देने जा रहे हैं आप यहां के लोगों को.

प्रस्तुति मनोज ठाकुर
feedback@chauthiduniya.com

कृषि योजनाओं में लूट मची है

सारण ज़िले के किसानों के विकास हेतु चलाई जा रही सरकारी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही हैं. हाल ही में संयुक्त कृषि निदेशक अरुण कुमार तथा कृषि उप निदेशक शिवदत्त सिन्हा को विभाग द्वारा निलंबित किया जा चुका है. इसके पहले यहां पदस्थापित संयुक्त कृषि निदेशक ...

अनिल कुमार सिंह | सत्येंद्र यादव | शिवनाथ सिंह

... करने के प्रयास में जुट गए. ज़िले में वर्ष 2010–11 में कृषक पाठशाला का आयोजन नहीं हुआ और कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी अजय कुमार वर्मा ने लाखों की निकासी फर्ज़ी ढंग से कर ली.

शहर के ब्रह्मपुरपुल निवासी नागेश्वर राय ने कृषक पाठशाला के बारे में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी मांगी ...

शुभम रानी चौहान
feedback@chauthiduniya.com

सारण एक नज़र

गर्म कपड़ों का वितरण

सुरेश का नागरिक अभिनन्दन

इंडिया अगेंस्ट करप्शन व पतंजलि योग की बैठक

सबको साथ लेकर चलेंगे– भारद्वाज

कामगारों को प्रोत्साहन

चंदन ने फिर नाम रोशन किया

विभूशंकर ने गौरवान्वित किया

सांप्रदायिक एवं लक्षित हिंसा कानून जन विरोधी

सीवान में जदयू की बैठक

सशक्त लोकपाल बिल चाहिए

कुचायकोट विधायक ने कंबल दिए

खाद उपलब्ध कराए सरकार

प्रस्तुति– शुभम रानी चौहान, मनीष कुमार कश्यप

एक नज़र

शिक्षक बच्चों के सामने आदर्श रखें

माताएं बच्चों की पहली शिक्षिका होती हैं. माता–पिता के आचरण और चरित्र बच्चों पर पहला और स्थायी प्रभाव डालता है. जिसे संस्कार भी कहा जा सकता है. शिक्षक इनके भीतर की छिपी प्रतिभा को निखार कर इनके भविष्य का निर्माण करते हैं. इस प्रकार माता–पिता और शिक्षक ही योग्य मानव संसाधन के आधार और कारण तथा कारक है. इन्हें बच्चों के सामने अपने आचरण और व्यवहार से एक रोल मॉडल की तरह आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए. उपरोक्त बातें एसएसपी स्कूल के 14 वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में अपना विचार व्यक्त करते हुए बिहार प्रदेश कांग्रेस कमिटि के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉ. अनिल सुलभ ने कहीं. डॉ. सुलभ ने कहा कि आज चरित्र निर्माण की सारी कार्यशालाएं बंद होती जा रही हैं प्रतिभावान मानव संसाधन तो निकल रहे हैं किन्तु इनमें चारित्रिक सदगुणों का अभाव मिलता है.

शक्तिपीठों में बखोरापुरवाली मंदिर

देश के प्रमुख शक्तिपीठों में एक नाम आरा में उत्तर बड़हरा रोड स्थित मां काली बखोरापुर वाली मंदिर का भी होगा. सभी के सहयोग से इसका निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है. मंदिर में खास यह है कि इसमें मां बखोरापुर वाली की मूर्ति एशिया में दूसरी व भारत में पहली सबसे ऊंची होगी. निर्माणाधीन मूर्ति को 150 फुट लम्बा बनाया जा रहा है. देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी यहां ...

लोहे के बंधन तोड़े नहीं काटे जाते हैं

जमुई में जांच शिविर

सास–बहू के क़ब्ज़े में आंगनबाड़ी केंद्र

बीपीएल कार्ड बनाने का कार्य प्रारंभ

गर्म वस्त्र संग्रह सहवितरण शिविर सम्पन्न

एमएस एजूकेशन कंसलटेंसी की सलाह

फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट में अपार रोज़गार

जनता हर हाल में यहीं केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कराने के लिए संघर्षशील है. विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए तीन स्थानों से भूमि का प्रस्ताव ज़िलाधिकारी के माध्यम से भेजा गया है.

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

कोरे वादों से काम नहीं चलेगा

समस्तीपुर की बंद पड़ी चीनी मिल

अशोक कुमार, मुन्ना

महेश्वर हजारी

मंजू हजारी

राणा गंगेश्वर प्रसाद सिंह

विजय कुमार चौधरी

नये वर्ष में कार्यकर्ताओं के खाली हाथ मुठ्ठी बनकर राजग गठबंधन सरकार को ज़िले के चहुमुखी विकास के लिए बाध्य करेंगे. नीतीश सरकार के प्रथम और द्वितीय पाली मिलाकर कुल छह वर्ष ज़िलावासी विकासात्मक कार्य की बाट जोहते रह गये. लुभावने वायदे–इरादे सबकुछ अब लोगों को भाजपा का भुलावा और जदयू का छलावा के रूप में नज़र आ रहा है. ज़िले की 28 लाख की आबादी 20 प्रखंडों एवं 381 पंचायतों में समाहित है.

विकास कुमार

समस्तीपुर

बिहार में राजग गठबंधन सरकार के छह वर्ष बीतने के बाद भी समस्तीपुर ज़िले को अब तक कुछ ख़ास हासिल नहीं होने से जनमानस में गोलबंदी की आम धारणा बनने लगी है. समस्तीपुर ज़िला स्थापना काल से ही विधायक और सांसद प्रतिनिधि के लिए लालायित भारतीय जनता पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में रोसड़ा और मोहउद्दीनगर विधानसभा सीट पर पहली बार जीत हासिल कर ज़िले में पहली बार दो–दो कमल खिलाए. नीतीश कुमार सरकार की दूसरी पाली की पहली वर्षगांठ भी मनाई गई और वर्ष 2011 अलविदा कहने को आतुर हैं लेकिन भाजपा के राणा गंगेश्वर सिंह और मंजू हजारी अपने–अपने विधानसभा क्षेत्रों में कमल की खुशबू फैलाने में नाकाम साबित हुए हैं. भाजपा के पूर्व ज़िलाध्यक्ष प्रो. विजय कुमार शर्मा के बदले सुशील चौधरी को एक मात्र वोट से ज़िलाध्यक्ष पद की बागडोर सौंपकर कार्यकर्ता काफी उत्साहित हुए थे लेकिन सत्ता की चकाचौंध में भाजपा की पहचान बल्लीपुर एवं रोसड़ा में सिमटकर रह गई है. इसी प्रकार जदयू भी ज़िले के शिवाजीनगर प्रखंड में सिमटकर आम जनता की नजर में कटघरे में खड़ी है. समस्तीपुर का रोसड़ा अनुमंडल लालू राबड़ी शासनकाल के बाद नीतीश कुमार की सरकार में भी जिला का दर्जा नहीं पा सका लेकिन सत्ताधारी दल जदयू एवं भाजपा दोनों के ज़िलाध्यक्ष की ज़िम्मेवारी शिवाजीनगर प्रखंड के ही सुशील चौधरी (बल्लीपुर गांव) और अशोक कुमार, मुन्ना (कटघारा गांव) निभा रहे हैं. सत्ताधारी दल के दोनों ज़िलाध्यक्ष रोसड़ावासियों को ज़िला का दर्जा दिलाने हेतु लम्बे अर्से से उत्साहित करते आ रहे हैं. रोसड़ा संसदीय क्षेत्र (अब समस्तीपुर) के सांसद एवं सभी विधायकों का चुनावी वादा आज भी लोगों को याद है, जिसमें जदयू एवं भाजपा के कद्दावर नेताओं ने मतदाताओं से आह्वान किया था कि लोग हमें जितायें हम इन्हें रोसड़ा जिला देंगे. सारे अरमान धूल में मिलने की स्थिति में सत्ताधारी दल जदयू एवं भाजपा के लिए नया साल 2012 चुनौतीपूर्ण होगा क्योंकि नये साल की शुरुआत से ही रोसड़ा के लोग अपनी अलग पहचान के लिए कमर कस चुके दिखाई दे रहे हैं.

वर्ष 2011 ज़िलावासियों के लिए खाली चला गया लेकिन नये वर्ष में कार्यकर्ताओं के खाली हाथ मुठ्ठी बनकर राजग गठबंधन सरकार को ज़िले के चहुमुखी विकास के लिए बाध्य करेंगे. नीतीश सरकार के प्रथम और द्वितीय पाली मिलाकर कुल छह वर्ष ज़िलावासी विकासात्मक कार्य की बाट जोहते रह गये. लुभावने वायदे–इरादे सबकुछ अब लोगों को भाजपा का भुलावा और जदयू का छलावा के रूप में नज़र आ रहा है. ज़िले की 28 लाख की आबादी 20 प्रखंडों एवं 381 पंचायतों में समाहित है. आपदा, विपदा, बाढ़–सुखाड़ एवं अतिवृष्टि जैसे समस्याओं से जूझ रही जनता का दिल बाग–बाग हुआ था कि जंगल राज से मुक्ति मिली है तो मंगलराज कायम होगा, लेकिन ज़िले में बाढ़ की समस्या का स्थाई निदान से लेकर बिजली, शुद्ध पेयजल एवं रोजी–रोजगार की समस्या कांग्रेस एवं राजद शासनकाल की तरह ही बरकरार है. ज़िले की औद्योगिक स्थिति में तब्दीली करने के लिए सत्ताधारी दल के नेता कार्यकर्ताओं ने चुनाव के मौके पर समस्तीपुर की बंद चीनी मिल के स्थान पर नई चीनी मिल खोलने का लुभावना वादा कर वोट बटोर लिये लेकिन नीतीश कुमार सरकार के छह वर्षों के कार्यकाल में सड़क एवं स्कूल की मरम्मत के सिवा कोई ख़ास उपलब्धि हासिल नहीं हो सकी है. नए उद्योग के नाम पर भी कोई सुगबुगाहट देखने को नहीं मिल रही है. ज़िले के किसानों की आर्थिक स्थिति गन्ने की फसल से सुदृढ़ होती थी लेकिन समस्तीपुर स्थित निगम की चीनी मिल एवं ठाकुर पेपर मिल के बंद हो जाने से गन्ने की खेती सीमित होकर रह गई है और ज़िले के हसनपुर में बिड़ला ग्रुप की चीनी मिल को किसान प्रबंधन की शर्त पर गन्ना दे रहे हैं. ज़िला गठन के 40 वर्षों के सफर में विकास के नाम पर कोई खास उपलब्धि नहीं हासिल हो सकी है लेकिन लोग आज भी ज़िले के सर्वांगीण विकास के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं ज़िले के जनप्रतिनिधियों की ओर टकटकी लगाए हुए हैं.

feedback@chauthiduniya.com

Nutan Construction Wishes A Very Happy & Prosperous-2012
WE MAKE YOUR DREAMS COME TRUE

Nutan Plaza (Corporate Business Hub)
L.G., (U.G., Ist & 2nd Floor - High end Retail Shops)
3rd to 7th Floor - Corporate Office
at Bander Bagicha, Near Maurya Lok, Patna

Shiv Raj Apartment(Residential)
Opp. Punchmukhi Hanuman Mandir
West Boring Canal Road, Patna

Divya Kanti Mansion (Residential)
Vivekanand Marg, Boring Road, Patna

Brij Nandan Complex (Residential)
Rajapur Pul, Patna

Royal Regency(Residential) K. Bagh
Nr. Nutan Tower (Krish Hyundai) Patna

R.K. Sadan
Nr. Pharmacy College , Dhanaut Bailey Rd, Patna

Hari Sewa Complex (Res-cum-Comm.)
Bigrahpur Opp. Bus Stand, Patna

LUXURY AND PRIMUM RESIDENCES, SHOPS & OFFICES
For Booking Pls. Contact:
Architech : Kapoor & Associates
9431022671
NUTAN CONSTRUCTION
Hariom Apartment, G- Floor, Block-B, Exhibition Road, Patna:-1
website : www.nutanconstruction.com, e-mail : info@nutanconstruction.com
Contact:- 0612-2500308, 9334152344, 7488394726,9334322237, 9334159884, 7488934726,

केंद्रीय विश्व विद्यालय की स्थापना कब होगी

चंपारण

पूर्वी चम्पारण ज़िले में प्रस्तावित महात्मा गांधी केंद्रीय विश्व विद्यालय की स्थापना को लेकर राजनीति गर्म है. सत्ता व ग़ैर सत्ता के लोग विश्व विद्यालय की स्थापना को लेकर आर–पार की लड़ाई लड़ रहे हैं और हर हाल में मोतिहारी में ही केंद्रीय विश्व विद्यालय की स्थापना हो, इसके लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं. दूसरी तरफ़ कांग्रेस की ख़ामोशी ने सभी को परेशानी में डाल दिया है. पूर्वी चम्पारण ज़िला महात्मा गांधी की कर्मभूमि है और यहीं से उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी और 18 अप्रैल 1917 को तत्कालीन अंग्रेज एसडीओ जॉर्ज चंडर की अदालत में अपना बयान दर्ज कराया था, इसलिए यहां की जनता हर हाल में यहीं केंद्रीय विश्व विद्यालय की स्थापना हेतु संघर्षशील है. विश्व विद्यालय की स्थापना के लिए तीन स्थानों से भूमि का प्रस्ताव ज़िलाधिकारी के माध्यम से भेजा गया है. इनमें पटपरिया, फुर्सतपुर व चैलाहा का नाम शामिल है. गौरतलब है कि 20 नवम्बर 2008 को अभियंत्रण महाविद्यालय के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी के नाम से पूर्वी चंपारण में केंद्रीय विश्व विद्यालय खोलने की घोषणा की थी और वहां उपस्थित अधिकारियों से ज़मीन उपलब्ध कराने को कहा था. तब से लेकर आज तक यह मामला चला आ रहा है और लड़ाई जारी है. स्थानीय सांसद व भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राधा मोहन सिंह समेत ज़िले के सभी विधायक व बुद्धिजीवी आपस में मिलकर हर हाल में मोतिहारी में ही उक्त विश्व विद्यालय की स्थापना के लिए केंद्र सरकार पर अपना दबाव बना रहे हैं. हालांकि केंद्र की यूपीए सरकार व मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल की नीयत साफ़ न होने के कारण बेवजह देरी हो रही है. संसाधनों के लिहाज़ में 36,680 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र में फैले पूर्वी चम्पारण की आबादी 50.82 लाख है. 1827 प्राथमिक, 1356 माध्यमिक एवं 147 उच्च विद्यालय संचालित हैं. 17 मान्यता प्राप्त महाविद्यालय और सीबीएसई से संबद्धता प्राप्त 6 बड़े विद्यालय हैं. पूर्वी चम्पारण ज़िले में केंद्रीय विश्व विद्यालय की स्थापना का सीधा शैक्षणिक प्रभाव पश्चिमी चम्पारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, शिवहर ज़िलों के अलावा पड़ोसी देश नेपाल के सीमाई क्षेत्र पर पड़ेगा और अंतरराष्ट्रीय संबंधों को मज़बूती मिलेगी. आबादी के अनुसार 2 करोड़ लोग केंद्रीय विश्व विद्यालय के प्रभाव क्षेत्र में आएंगे. तुलनात्मक दृष्टिकोण से जिन राज्यों में केंद्रीय विश्व विद्यालय की स्थापना हुई है उनमें से सात राज्यों मणिपुर 27.21 लाख, त्रिपुरा 36.71 लाख, नागालैंड 19.80 लाख, पुडुचेरी 12.40, मिजोरम 40.91, मेघालय 29.64 लाख एवं सिक्किम 6.7 लाख की आबादी पूर्वी चंपारण ज़िला की कुल आबादी 50.82 लाख से काफ़ी कम है. इन राज्यों में मेघालय की साक्षरता दर 75.48 प्रतिशत है जो सबसे कम है. पूर्वी चम्पारण की साक्षरता दर 58 प्रतिशत है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 94 वर्ष पूर्व शिक्षा की ज्योति यहीं से जलाई थी. बिहार विधान सभा एवं विधान परिषद ने भी मोतिहारी में ही केंद्रीय विश्व विद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है. उधर स्थानीय विधायक प्रमोद कुमार ने कहा कि कपिल सिब्बल महात्मा गांधी व चंपारण के इतिहास को भूल गये हैं और चम्पारणवासियों की भावना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि जब तक पूर्वी चम्पारण में केंद्रीय विश्व विद्यालय की स्थापना नहीं होती तब तक लड़ाई जारी रहेगी और इसके लिए चंपारणवासियों की ओर से जो कुर्बानी देनी पड़ेगी, वे देने को तैयार रहेंगे. यहां बता दे कि कपिल सिब्बल ने अपने बयान में कहा था कि पूर्वी चंपारण ज़िला में अनेक सुविधाओं की कमी है. इस कारण किसी भी कीमत पर यहां विश्व विद्यालय की स्थापना नहीं हो सकती है. दूसरी तरफ उक्त विश्व विद्यालय की स्थापना के लिए गठित महात्मा गांधी केंद्रीय विश्व विद्यालय संघर्ष मोर्चा के महासचिव अब्दुल हमीद कैप्टन, प्रधान महासचिव राय सुन्दर देव शर्मा ने भी कपिल सिब्बल को घेरा और कहा कि केंद्रीय विश्व विद्यालय की स्थापना समय की मांग है और हर हाल में पूर्वी चंपारण में ही इसकी स्थापना होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि संघर्ष मोर्चा के लोग राजनीति तेज करने के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं और चरणबद्ध तरीके से लड़ाई लड़ेंगे. कुल मिलाकर चंपारण में उक्त विश्व विद्यालय की स्थापना का मामला अभी अधर में लटका हुआ है और केंद्र की यूपीए सरकार आख़िर पूर्वी चंपारण में इसे स्थापित करने से क्यो परहेज कर रही है और इसके पीछे दूसरी और कौन सी राजनीति है, यह समझ से परे है.

प्रमोद कुमार

अब्दुल हामिद

राधा मोहन सिंह

इन्तेजारूल हक
feedback@chauthiduniya.com

इंडियन इंस्टीच्युट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एण्ड रिसर्च
हेल्थ इंस्टीच्युट रोड, बेउर, पटना–२
(बिहार सरकार, भारतीय पुनर्वास परिषद, भारत सरकार तथा आइ.ए.पी.से मान्यता प्राप्त)
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया से संबंधन प्राप्त

We Impart:-
POST GRADUAGE COURSES:
MPT Master of Physiotherapy
MOT Master of Occupational Therapy
MPO Master of Prosthetic & Orthotic
MASLP Master of audiology speech & Language Pathology
BPT Bachelor of Physiotherapy
BOT Bachelor of Occupational Therapy
BPO Bachelor of Prosthetic & Orthotic
BASLP Bachelor of Audiology Speech & Language Pathology
BMRT Bachelor of Radio Imaging Technology
BMLT Bachelor of Medical Laboratory Technology
B.Ed. (Special Education)
B.Ophth. Bachelor of Ophthalmology

मेधावी छात्र–छात्राओं के लिये निःशुल्क शिक्षा
बिहार प्रदेश के मेधावी छात्र–छात्राओं को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से संस्थान प्रबंधन ने अपने शैक्षणिक सत्र–२०१२–१३ में, सभी डिग्री पाठ्यक्रमों के तीन–तीन स्थानों के लिए (कुल २१) तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में पाँच–पाँच स्थानों कुल ३० पर निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस हेतु आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तारीख ३१ जनवरी २०१२ तथा मेधा परीक्षा की तिथि १२ फरवरी निर्धारित की गई है।
फॉर्म भरने की अंतिम तिथि ३१ जनवरी २०१२
मेधा परीक्षा १२ फरवरी २०१२
1 Yr. ABRIDGED DEGREE For DPT & DOT

DIPLOMA COURSES:
DPT Diploma in Physiotherapy
DPO Diploma in Prosthetic & Orthotic
DMLT Diploma in Medical Lab.
D-X-Ray Diploma in x-ray Technology.
DHM Diploma in Hospital Management
DOTA Diploma in Operation Theather Assistant
DECG Diploma in E.C.G.
certificate courses:
CMD Certificate in Medical Dressing
Foundation Course for Teachers in Disability

Form & Prospectus:- Available at the institute counter against payment of Rs. 300/-and DD of Rs. 350/-only for postal delivery, in favour of Indian Institute of Health Education & Research, Patna-2
Eligibility:- For Post Graduate Courses- Degree in the same, 10+2 with science for under Grtaduate & diploma Courses For B.Ed. Degree in any Subjecty.

डा.अनिल सुलभ निदेशक–प्रमुख

Registration for Admission into Academic session 2012-2013 going on.
फोन न. : 0612-2253290, 2252999, फैक्स: 0612-2253290,email.iiher_beur@gmail.com, www.iiher.org

चौथी दुनिया

उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड

दिल्ली, 23 जनवरी-29 जनवरी 2012

www.chauthiduniya.com

मीडिया को नचा रही हैं मायावती

अजय कुमार

मुख्यमंत्री मायावती को अपने अलावा किसी की आवाज़ अच्छी नहीं लगती है, न संगठन के अंदर और न ही बाहर. पार्टी में प्रवक्ता नहीं है. यह काम सूचना विभाग करता है. बसपा नेताओं को मीडिया या अन्य किसी मंच पर मुंह खोलने की मनाही है. नैतिकता के नाते भी बसपा का कोई नेता विपक्षी दलों के नेताओं से बात नहीं कर सकता है. यहां तक कि बसपा नेता अपनी बहनजी के सामने भी तभी जा पाते हैं, जब उनकी क्लास ली जाती है. मीडिया की अहमियत मायावती के लिए सिर्फ़ इतनी भर है कि जब उन्हें अपनी कोई बात मीडिया के माध्यम से जनता से कहनी होती है तो वह उसे बुलाकर अपनी बात रख देती हैं. कोई मीडिया कर्मी उनसे सवाल नहीं करता. सवाल पूछने वाले को बुरी तरह बेइज़्ज़त करके ही छोड़ा जाता है. मायावती का हमेशा से मानना रहा है कि उनका वोटर न अख़बार पढ़ता है न टेलीविजन में न्यूज देखता है. इसलिए वह मीडिया से क्यों ख़ौफ़ खाएं. पिछले तीन कार्यकालों में भी मायावती का यही रंग-ढंग मीडिया के प्रति था और पूर्ण बहुमत ने उनको और भी अहंकारी बना दिया.

मायावती सरकार की लालफ़ीताशाही ने लोकतंत्र का चौथा खंभा कहे जाने वाले मीडिया का गला घोंटने का काम किया है. छोटे अख़बारों को विज्ञापन न देकर जहां उनकी उपेक्षा की, वहीं बड़े अख़बारों तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मुंह करोड़ों रुपये के विज्ञापन से बंद कर दिया. शासन में ही बैठे कुछ अधिकारी नाम न छापने की शर्त पर कहते हैं कि आज के ज़माने में राजनेताओं के लिए मीडिया को धमकाना और अपना हित साधना कोई मुश्किल काम नहीं है. अब पत्रकारिता को पैशन मानने वाले लोग तो रहे नहीं. आज के दौर में पत्रकारों के कंधों पर थैलों की जगह लैपटॉप, हाथों में महंगे मोबाइल रहते हैं. साइकिल की जगह मोटरसाइकिल और कार ने ले ली है. एक-एक अख़बार के कई-कई संस्करण निकल रहे हैं. पत्रकारिता व्यवसाय बन गई है. कोई ज़मीन का धंधा कर रहा है, तो किसी का स्कूल खुला हुआ है. ऐसे मीडिया समूह भी हैं जो बैंकिंग, रियल स्टेट में अपना अरबों रुपया खपा रह हैं. सरकारी ज़मीनों को आधे-पौने दाम पर क़ब्ज़ाना आम बात हो गई है. उनके हित सरकार से सधते हैं, तो सरकार अपने हित उनसे साध रही है. एक हाथ लेना और एक हाथ देना के फॉर्मूले पर काम हो रहा है. किस अधिकारी की पोस्टिंग कहां कराने से फ़ायदा हो सकता है और किसके हटने से नुक़सान, इस बात की चिंता ने मीडिया कर्मियों को तबादले-पोस्टिंग के काम में भी उतार दिया है. अक्सर बड़े मीडिया घरानों को किसी विशेष अधिकारी के पक्ष में लॉबिंग करते देखा जा सकता है. अब कौन सी ख़बर जानी है और कोई सी नहीं. इस बात का फ़ैसला संपादक नहीं अख़बार का मालिक और विज्ञापन विभाग करता है. कई बड़े अख़बारों में तो मालिक ही संपादक बन बैठे हैं. यह और बात है कि पत्रकारिता का कखग...भी इन्हें नहीं आता. पत्रकारों को अक्सर ख़बर लिखने की गाइड लाइन संपादक से नहीं, बल्कि विज्ञापन विभाग और अख़बार मालिक से मिलती है. मायावती सरकार के सामने पूरी तरह नतमस्तक मीडिया के किसी पत्रकार ने कभी मुंह खोलने की हिम्मत दिखाई तो उसे मुंह की खानी पड़ी. मायावती के सत्ता में आने के बाद मीडिया कर्मियों के उत्पीड़न की बात की जाए तो कई उदाहरण मिल जाएंगे, जब पत्रकारों के ऊपर सरकार का डंडा चला. मायावती ने जब सत्ता ग्रहण की तो रायटर के संवाददाता और वरिष्ठ पत्रकार शरत प्रधान की मुख्यमंत्री से चलते-फिरते बातचीत हुई. इस बातचीत के आधार पर शरत ने एक साक्षात्कार तैयार किया, जिसका सार था कि मायावती देश का प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति तो एक पड़ाव मात्र है. यह साक्षात्कार कई जगह छपा. इसी बीच मायावती के क़रीबियों ने उन्हें समझा दिया कि इस साक्षात्कार का ग़लत असर पड़ सकता है. बस, बहनजी को गुस्सा आ गया. उन्होंने खंडन जारी कर दिया. शरत प्रधान से बात होने तक से इंकार कर दिया. इसके बाद से शरत प्रधान को मुख्यमंत्री की प्रेस कांफ्रेस में बुलाना भी बंद कर दिया गया. यह दौर काफ़ी लंबा चला. इसी प्रकार की एक और ख़बर अंग्रेजी समाचार पत्र के लखनऊ संस्करण में छपी. ख़बर में तथ्यों सहित कहा गया था कि मायावती प्रदेश में किसी विपक्षी दलित नेता को उभरने का मौक़ा नहीं देती हैं. दक्षिण भारत से आए संपादक जी ने इस ख़बर को क़ायदे से हाईलाइट किया था. यह ख़बर बहनजी को इतनी नागवार गुज़री कि अगले ही दिन संपादक जी को बोरिया-बिस्तर बांध कर बैरंग वापस जाना पड़ गया. मीडिया पर उत्पीड़न का सिलसिला यहीं नहीं थमा. जब बहनजी ने अपने ख़िलाफ़ लिखने वालों को आड़े हाथों लिया तो उनके नौकरशाहों ने भी अपनी आक़ा की राह पकड़ ली. कैबिनेट सचिव शशांक शेखर के ख़िलाफ़ मध्य प्रदेश के अलावा लखनऊ से प्रकाशित एक प्रतिष्ठित साप्ताहिक समाचार पत्र के संवाददाता अरविंद शुक्ल ने लिखना शुरू किया तो पहले तो पत्रकार की मान्यता रद्द कर दी गई. इसके बाद पत्रकार प्रेस काउंसिल से अपनी मान्यता बहाल करा लाए तो इस वर्ष उनकी मान्यता रोक दी गई. मायावती पत्रकारों के प्रति कितनी कठोर हैं, इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अबकी बार उन्होंने पत्रकारों की पेंशन (पत्रकारों की पेंशन के लिए चलने वाली जीवन बीमा निगम की पॉलिसी की आधी रक़म जिसका वहन सरकार करती है) के लिए दिए जाने वाले 20 लाख रुपये के अनुदान पर ही रोक लगा दी. मायावती के चहेते सूचना निदेशक बादल चटर्जी के अड़ंगे के कारण ऐसा हुआ, जबकि बजट में इसका प्रावधान है. बादल की तरह ही पूर्व में प्रमुख सचिव सूचना रहे विजय शंकर पांडेय भी अपने पूरे कार्यकाल में पत्रकारों के हितों की कटौती में लगे रहे, उन्होंने उन पत्रकारों को अवश्य फ़ायदा पहुंचाया जो उनके क़रीबी थे. बादल और विजय शंकर के बीच की एक और कड़ी हैं आईएएस दिवाकर त्रिपाठी. वह भी कुछ समय के लिए सूचना निदेशक रहे. उनके कार्यकाल में पत्रकारों के साथ सरकार का रवैया कुछ सुधरता दिखा, लेकिन वह ज़्यादा समय तक इस कुर्सी पर टिक नहीं पाए. त्रिपाठी की छवि पत्रकारों के बीच अच्छी थी, इसका फ़ायदा भी मायावती सरकार ने भरपूर उठाया. उनके माध्यम से कई सरकार विरोधी ख़बरों का प्रकाशन रोका गया. दिवाकर रिटायर्ड हो गए तो उन्हें मायावती ने ओएसडी (प्रेस) बना दिया. वह कुछ समय तक तो इस कुर्सी पर काम करते रहे, लेकिन चुनाव नज़दीक आते ही समय की नाज़ुकता भांप उन्होंने इस पद से छुट्टी ले ली. हद तो तब हो गई जब बिजनौर से प्रकाशित होने वाले एक समाचार पत्र के लखनऊ संवाददाता सुधीर लहरी की असामयिक मौत के बाद उन्हें सरकारी मदद का आश्वासन तो दिया गया, लेकिन एक पैसा भी मदद के लिए परिवार को नहीं मिल पाया. सुधरी लहरी को इस बात का सदमा लगा था कि उनके काफ़ी प्रयास के बाद भी उन्हें सरकारी आवास आवंटित नहीं हुआ था. लहरी का परिवार अब गंभीर आर्थिक संकट से गुज़र रहा है.

कुछ माह पूर्व मीडिया से बदसलूकी को लेकर इस समय हो हल्ला मचा, जब आईबीएन-7 के पत्रकार से पुलिस कार पार्किंग को लेकर कहासुनी हो गई, जिसे लेकर इलेक्ट्रॉनिक चैनलों ने दबाव बनाया. नतीजतन, मुख्यमंत्री के सचिव नवनीत सहगल के हस्तक्षेप के बाद संबंधित अपर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी को निलंबित कर दिया गया. चूंकि बात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की थी, इसलिए दबाव काम आ गया, जबकि गाज़ीपुर ज़िले के एक थाने में भड़ास मीडिया पोर्टल के संपादक यशवंत सिंह की माता को अपमानित किए जाने के मामले में पत्रकारों के काफ़ी हाय-तौबा मचाने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है. राजधानी लखनऊ के एक-दो मामलों को तो प्रशासन-पुलिस ने संज्ञान में ले भी लिया, लेकिन मायावती राज में पूरे राज्य में पत्रकारों के उत्पीड़न की सैकड़ों वारदातों में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है. बहरहाल, मीडिया घरानों की नकेल कसने के बाद मायावती के लिए पत्रकारों की नकेल कसना काफ़ी आसान हो गया है. उनके कैबिनेट सचिव शशांक शेखर का काम मीडिया घरानों के मालिकों को साधने का है तो मुख्यमंत्री के सचिव नवनीत सहगल पत्रकारों के लिए अघोषित रूप से गाइड लाइन जारी करते हैं. यही वजह है कि कई ख़बरें समाचार पत्रों के डेस्क या फिर पत्रकारों की जेब में ही दम तोड़ देती हैं. मालिक ख़बरें छपने ही नहीं देते हैं. सरकार की तरफ़ से संरक्षण नहीं मिलने के कारण भी पत्रकार ऐसी ख़बरों को लिखने से कतराने लगे हैं, जिससे उनकी नौकरी को ख़तरा हो सकता है.

फोटो-*प्रभात पाण्डेय*

क्र. सं	समाचार पत्र	विज्ञापन भुगतान राशि 1 अप्रैल से 30 नवंबर 2011 तक
1.	अमर उजाला	6,24,20,745-00
2.	द टाइम्स आफ इंडिया	1,51,93,900-00
3.	दैनिक जागरण	89873022-00
4.	राष्ट्रीय सहारा	7421799-00
5.	दैनिक हिंदुस्तान	30358104-00
6.	हिंदुस्तान टाइम्स	12832539-00
	न्यूज चैनल	
7.	सहारा समय उत्तर प्रदेश	47,83,793-00
8.	जीन्यूज	87,13,686-00
9.	आईबीएन-7	1,02,95,293-00
10.	स्टार न्यूज	1,48,33,812-00
11.	इंडिया न्यूज	5,15,119-00
12.	एनडीटीवी	1,48,32,560-00
13.	आज तक	2,45,48,606-00
14.	ईटीवी उत्तर प्रदेश	89,57,807-00
15.	इंडिया टीवी	1,91,04,468-00
16.	सीएनएनआईबीएन	11,74,180-00
17.	सीएनबीसी	9,31,360-00
18.	टाइम्स नाऊ	4,85,560-00
19.	साधना न्यूज	11,08,500-00
	योग	332384853-00

विज्ञापन के गुणा-भाग की बात की जाए तो इस खेल में बड़े अख़बार और इलेक्ट्रॉनिक चैनल लगातार छोटे और मझोले अख़बारों का हक़ मारते रहे हैं. सूचना और जनसंपर्क विभाग जिसके कंधों पर पत्रकारों के हितों की ज़िम्मेदारी है, वह सरकार के हितों को साधने में लगा है. मायावती सरकार अपनी उपलब्धियों का प्रचार करने में कभी पीछे नहीं रही. लखनऊ में तो हर बिजली के खंभे पर मायावती के चित्र वाली छोटी होर्डिंग लगाई गई हैं. ऑटो रिफ्लेक्शन वाली इस क्यास की क़ीमत 7,650 रुपये थी. लखनऊ में ऐसे दो हज़ार से अधिक क्यास एयर पोर्ट से लेकर वीआईपी मार्ग और गोमती नगर तक में लगाई गई थीं, जबकि सभी प्रमुख स्थानों पर दस हज़ार से तीस हज़ार तक की क़ीमत वाली सैकड़ों होर्डिंग्स साढ़े चार साल तक लगे रहे. राजधानी लखनऊ के अतिरिक्त गाज़ियाबाद, नोएडा सहित सभी मंडल मुख्यालयों और ज़िला मुख्यालयों पर भी सूचना विभाग द्वारा ऐसे होर्डिंग लगवाए गए थे. इन होर्डिंग के निर्माण और संबंधित विज्ञापन एजेंसियों को किराये के रूप में पूरे कार्यकाल में 415 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान सरकारी और ग़ैर-सरकारी स्तर से किया गया. इनमें कई होर्डिंग का किराया तो पांच लाख रुपये वार्षिक तक था. जिन विज्ञापन एजेंसियों को यह होर्डिंग लगाने का कार्य सौंपा गया, उनमें मुख्य रूप से दीक्षा, आर्यावर्त, हिंदुस्तान एडवरटाइजिंग, भारत, कंस्ट्रक्शन तथा नोएडा की ओरिजिंस एजेंसी शामिल हैं.

जहां तक राज्य के प्रमुख छह समाचार पत्रों और एक दर्जन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को चालू वित्तीय वर्ष के आठ माह (1 अप्रैल से 30 नवंबर, 2011 तक) में विज्ञापन राशि के भुगतान का प्रश्न है तो यह राशि 33 करोड़ रुपये से अधिक है. इसमें सबसे अधिक दैनिक जागरण को 8.98 करोड़ रुपये, अमर उजाला को 6.24 करोड़ रुपये, टाइम्स ऑफ इंडिया को 1.51 करोड़ रुपये, दैनिक हिंदुस्तान को 3.03 करोड़ रुपये, हिंदुस्तान टाइम्स को 1.28 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय सहारा को 74 लाख रुपये का भुगतान किया गया. इनमें वह राशि शमिल नहीं है जिसके बिल भुगतान के लिए सूचना विभाग में अभी लंबित हैं. इसी तरह इस अवधि में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के न्यूज चैनल आज तक को 2.45 करोड़ रुपये, एनडी टीवी और स्टार न्यूज को डेढ़-डेढ़ करोड़ रुपये, इंडिया टीवी को 1.91 करोड़ रुपये तथा ईटीवी उत्तर प्रदेश को 89 लाख रुपये और इंडिया न्यूज को 45 लाख रुपये एवं टाइम्स नाउ को सबसे कम 4.85 लाख रुपये का भुगतान किया गया. इसमें भी कई चैनलों के बिल भुगतान के लिए अभी लंबित हैं.

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

राहुल गांधी पूर्वांचल दौरे की तैयारी में लगे हुए हैं. अन्य छोटे बड़े दल अपना अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं. राहुल के साथ ही प्रियंका गांधी भी चुनाव प्रचारक के रूप में उतरने वाली है.

चुनावी हलचल

समाजवादी पार्टी असमंजस में

कानपुर नगर और देहात की सभी 14 विधानसभाओं के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा अधिसूचना जारी होने से पहले कर दी थी. लेकिन चुनावी घोषणा होते ही सपा ने कानपुर में जीत के समीकरण पर फिर से विचार शुरू कर दिया और एक के बाद एक चार प्रत्याशियों को बदल दिया. कानपुर छावनी से पूर्व नगर महासचिव मोहम्मद हसन रूमी की जगह पर परवेज अंसारी के नाम की घोषणा हुई. इसके बाद भोगनीपुर से पूर्व घोषित प्रत्याशी दिलीप सिंह को हटाकर पूर्व एमएलसी योगेंद्र पाल के नाम की घोषणा की गई. महाराजपुर सीट से सुरेश यादव को हटाकर विधायक अरूणा तोमर पर फिर से विश्वास जताया गया है. अप्रत्याशित रूप से उम्मीदवारों को बदले जाने से कानपुर के राजनीतिक हल्कों में मानों भूचाल सा आ गया. पार्टी के जो प्रत्याशी अपना नाम घोषित होने के बाद चुनाव प्रचार में जी जान से जुटे हुए थे, अपनी उम्मीदवारी हटने पर हताश हो गए. सपा के अप्रत्याशित फ़ैसलों से कानपुर में पार्टी में गुटबंदी काफ़ी बढ़ चुकी है. हटाए गए प्रत्याशियों वाली सीटों पर पार्टी में कलह पैदा हो गई है, पार्टी के कार्यकर्ताओं में दो फाड़ होने से हटाए गए प्रत्याशी के समर्थकों ने अपने ही दल के प्रत्याशी को हराने के लिए कमर कस ली है, इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा कांग्रेस और बसपा को मिलता दिख रहा है. बताया यह भी जा रहा है कि महाराष्ट्र के पार्टी अध्यक्ष अबू आजमी ने और एक पूर्व नगर अध्यक्ष ने छावनी के प्रत्याशी को हटाने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया था. चुनाव पूर्व पिछले 6 माह से लगातार उम्मीदवारों के बदलाव से मतदाताओं में ग़लत संदेश गया है तो दूसरी तरफ़ कई माह से प्रचार कर रहे प्रत्याशियों की मेहनत पर पानी फेर कर पार्टी ने स्वयं को ही नुक़सान पहुंचा दिया है. जबकि सपा आलाकमान का कहना है कि इस बार वह उत्तर प्रदेश की सत्ता को अपने हाथ से नहीं निकलने देना चाहते, इसलिए ठोंक बजाकर केवल जीतने वाले [illegible]

–[illegible]

चुनावी महासमर में लालू, शरद, पासवान और ममता

[illegible] लोक जनशक्ति पार्टी और शरद यादव की पार्टी जद (एकी) के अलग-अलग कालखंड में एक मात्र विधायक जौनपुर के धनंजय सिंह रहे हैं, जो पार्टी से ज़्यादा अपनी उपलब्धियों के चलते जीतते रहे हैं. इसलिए जद (एकी) और लोकजन शक्ति पार्टी को अपवाद मान लें तो बाक़ी दल पूरी तरह हवा में हैं. उनके सफ़ल होने की उम्मीद कम ही दिखती है. भाजपा प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा-जद(एकी) से इस बार सीटों के तालमेल पर बात नहीं बनी, इसलिए वह अलग से लड़ रहे है. वहीं राजद के प्रदेश अध्यक्ष अशोक सिंह कहते हैं यह सही है कि उत्तर प्रदेश की ज़मीनी राजनीति में हमारा असर बहुत कम है. यही वजह है कि इस बार यह विचार हो रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के ख़िलाफ़ कोई उम्मीदवार न उतारा जाए. यह भी सही है पार्टी का ठोस राजनीतिक काम कुछ वजहों से नहीं हो पाया. जैसी स्थिति हमारी है, वैसी ही ममता बनर्जी, पासवान और शरद पवार की पार्टी की हो सकती है. बहरहाल इन क्षेत्रीय पार्टियों के महत्वाकांक्षी मुखिया चुनाव के समय तो अपनी दम-खम दिखाते नज़र आ रहे हैं. पर जल्दबाज़ी में इन दलों को सुयोग्य प्रत्याशी का अकाल पड़ जाता है. वोट के लालच में इन दलों की कमजोरियों को परखकर बाहुबली और दबंग फ़ायदा उठाते हैं. यही कारण है ऐसे दलों के नेताओं को कभी कभार बाग़ी उम्मीदवार हाथ लग जाते हैं या किसी बाहुबली के सहारे अपनी नैया खेने लगते हैं. क़रीब डेढ़ सौ छोटे दल भी एक दूसरे से ताल ठोंकते नज़र आएंगे. ऐसे में ये दल बड़े दलों के ही वोट काटकर नुक़सानदायक साबित होंगे.

चुनाव में चलने लगे जाली नोट

उत्तर प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में लगभग पचास करोड़ रूपए पुलिस ने जब्त किए हैं, वहीं जाली नोट भी पकड़े हैं. हालांकि जाली नोटों की आमद नेपाल सीमा से होने की आशंका ख़ुफिया विभाग ने जताई थी. ख़ुफिया विभाग की स्थानीय अभिसूचना इकाइयों के साथ ज़िलों के विशेष पुलिस दस्तों को भी ऐसे तत्वों से आगाह रहने की हिदायत दी गई थी. नेपाल में रहकर नक़ली भारतीय करेंसी की छपाई से लेकर इसे प्रदेश व अन्य सूबों में खपाने की कोशिश होगी. सरकारी मशीनरी की सक्रियता निर्वाचन प्रक्रिया पर केंद्रित होगी, लिहाज़ा इस मौक़े पर नक़ली करेंसी की तस्करी में अधिक दिक्कत नहीं होगी. इसके लिए सशस्त्र सीमा बल के अधिकारियों से भी आग्रह किया गया है कि वे भी सीमा पर तैनात बल को इस दिशा में कार्यवाही के लिए सचेत करें. चुनाव के दौरान जहां प्रदेश में अब तक पचास करोड रूपये पुलिस बरामद कर चुकी है. वहीं जाली नोट का सौदागर भी पकड़ा गया है. कानपुर से जाली नोटों की खेप लेकर आया माफ़िया 8 जनवरी को पुलिस के हत्थे चढ़ गया. उसके पास से हज़ार रुपए के 97 नोट और पांच सौ रुपए के 17 नोट बरामद हुए. पुलिस जाली नोटों के चुनाव में इस्तेमाल होने की आशंका से इनकार नहीं कर रही है. अपर पुलिस अधीक्षक बलरामपुर के अनुसार एसओजी ने मुखबिर की सूचना पर रात में बलरामपुर बस स्टेशन के गेट पर संदिग्ध हालात में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया. तलाशी में उसके पास से 1 लाख 5 हज़ार 500 रुपए के जाली नोट बरामद हुए. जब पुलिस ने बैंककर्मियों को बुलाकर पड़ताल कराई तो जांच में नोट जाली पाए गए. जाली नोटों का सौदागर मंसूर पुत्र फकीर मोहम्मद निवासी पूरे तिवारी थाना कोतवाली देहात गोंडा का है. बरामद नोटों में 97 नोट एक हज़ार के और 17 नोट पांच सौ रुपये के हैं. मंसूर जाली नोटों को कानपुर से लाकर बलरामपुर के स्थानीय बाज़ारों में खपाने का काम करता था. वहीं पुलिस का यह भी मानना है कि कहीं यह नोट चुनाव के लिए तो नहीं लाए जा रहे थे. पुलिस इन नोटों के पीछे राजनीतिक हलकों की पड़ताल कर रही है.

भाजपा के सुपर स्टार दाग़ियों के क्षेत्र में नहीं जाएंगे

बाबू सिंह कुशवाहा के मुद्दे से मुंह की खाई भाजपा अब फुंक-फुंक कर क़दम रखने लगी है. फिलहाल कुशवाहा की सदस्यता स्थगित कर दी गई है. इसके अलावा भाजपा ने क़रीब 2 दर्जन दाग़ियों को टिकट बांटे हैं. इन दाग़ियों में छत्रपाल सिंह को संसदीय समिति ने राज्यसभा सदस्य रहते प्रश्न पूछने के लिए धन लेने का दोषी पाया था. इसी तरह बसपा से निकाले जाने पर भाजपा में शामिल किए गए बुंदेलखंड के बादशाह सिंह को उत्तर प्रदेश लोकायुक्त ने वित्तीय अनियमितताएं बरतने के लिए नोटिस दिया हैं. भाजपा में आए दद्दन मिश्र पर भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं. यौन उत्पीड़न मामलों में कुछ महीने जेल में रहे सच्चिदानंद हरि साक्षी महाराज भी प्रदेश के भानगांव से भाजपा के उम्मीदवार हैं. इसी तरह अन्य दाग़ियों के भी क्षेत्र हैं. सूत्रों के हवाले से भाजपा प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा कि सुपर स्टार आडवाणी और सुषमा स्वराज जैसे कद्दावर नेता दाग़ी क्षेत्रों से बचेंगे, वहीं स्टार प्रचारक सभी जगह प्रचार करेंगे.

हवा और पानी पर सबका अधिकार : मुलायम सिंह

सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने दवाई, शिक्षा व सिंचाई के पानी के साथ बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की सपा सरकार में वायदे के बाद, सर्द मौसम में भी ज़िले के सियासी पारे को गर्म कर दिया है. इस दौरान जुटी भारी भीड़ इस बात का गवाह बनी कि मौसम पर सपाइयों का उत्साह भारी पड़ रहा है. सभा में उमड़े जनसैलाब को देख धरती पुत्र भावुक होकर बोले. उन्होंने किसानों, महिलाओं तथा बेटियों की जमकर वकालत की. उन्होंने युवाओं को अपने पक्ष में करने के लिए बेरोजगारी भत्ते का ऐसा तीर चलाया कि बाराबंकी का मौरंग मैदान काफ़ी देर तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा. वह बोले हवा और पानी पर सबका बराबर का अधिकार है. तो इसका पैसा क्या लेना. वह आगे बोले, कि पानी नहर का हो या नलकूप का समाजवादी पार्टी सरकार में यह मुफ्त दिया जाएगा. मुलायम सिंह यादव को सुनने के लिए बाराबंकी जनपद की सभी विधानसभाओं के लोग उन्हें सुनने पहुंचे थे. - **दर्शन शर्मा,** *लखनऊ ब्यूरो*

रामवीर उपाध्याय ने माफ़ी मांगी

लोकायुक्त पर गरजने-बरसने के बाद राज्य के ऊर्जा मंत्री रामवीर उपाध्याय को आख़िरकार अपनी टिप्पणी के लिए ऊपरी मन से ही सही माफ़ी मांगनी ही पड़ गई. लोकायुक्त को भेजे गए लिखित बयान में मंत्रीजी ने कहा कि उन्हें लोकायुक्त संस्था में गहरा विश्वास है और वह इसका आदर करते हैं. एक तरफ़ उन्होंने माफ़ी मांगी तो दूसरी तरफ़ सफ़ाई देते हुए एक बार फिर दोहराया कि उन्होंने लोकायुक्त पद की गरिमा के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कहा. उनका कहना था कि अगर उनकी टिप्पणी से या ग़लत शब्दों के इस्तेमाल से लोकायुक्त पद की गरिमा को ठेस पहुंची है तो वह इसके लिए माफ़ी मांगते हैं. उपाध्याय ने मीडिया पर अपने बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश करने का आरोप भी मढ़ा. गौरतलब है कि ऊर्जा मंत्री ने कुछ दिनों पूर्व हाथरस में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर लोकायुक्त एनके मेहरोत्रा से उनके व्यक्तिगत संबंध नहीं होता तो वह उच्चतम न्यायालय में जाकर मेहरोत्रा को हटवा देते. इस विवादास्पद टिप्पणी से जुड़े मामले के तूल पकड़ने पर ज़िला प्रशासन ने इसकी रिपोर्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी उमेश सिन्हा को भेजी थी, जिसे चुनाव आयोग को प्रेशित किया गया था. कहा जा रहा है कि चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन से बचने के लिए उपाध्याय द्वारा उक्त क़दम उठाया गया है.

– **संजय सक्सेना,** *लखनऊ*

छोटे-छोटे दल पंचकोटि मुक़ाबले की वजह बनेंगे

सुरेंद्र अग्निहोत्री

मायावती का टूटता तिलस्म बहुजन समाज पार्टी के लिए ख़तरे की घंटी साबित हो सकता है. क्या यूपी में पराजय का कारण छोटे-छोटे दल बनेंगे? वर्ष 2012 में होने वाले विधानसभा चुनाव को फ़तह करने की रणनीति के तहत सपा, बसपा, कांग्रेस और भाजपा अपने दांव चलने की तैयारी में लगी हैं. वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में प्रमुख दलों के ख़िलाफ़ कई वोटकाटू छोटे दल खड़े हो गए हैं. इससे बड़े दलों की परेशानी बढ़ गई है. कई राष्ट्रीय और प्रांतीय दलों ने इन दलों को मनाने की कोशिश की, लेकिन इन दलों ने दो टूक जवाब दिया है कि वे किसी भी हालात में चुनाव मैदान से अपना दावा नहीं छोड़ेंगे. छोटे-छोटे दलों का गठबंधन चुनावी समर में सियासी पार्टियों के बहुमत के अंकगणित को बिगाड़ने के लिए किसी भी दल से हाथ मिलाने के लिए तैयार है. सत्ता के लिए लालायित दलों के लिए समर्थन का झुनझुना दिखाने की चाहत के तहत अंकों के गणित में त्रिभुज का तीसरा कोण कितना कामयाब होता है, यह तो वक़्त ही तय करेगा. लेकिन इतना तय है कि चींटी जिस तरह हाथी को धूल चटा देती है, वैसे ही बड़े-बड़े राजनीतिक दलों के समीकरणों को धूल धूसरित करने का दम भरते चुनावी मैदान में डटे छोटे-छोटे दलों के कारण 2007 के विधानसभा चुनाव में 91 विधानसभा क्षेत्रों में जीते प्रत्याशियों की जीत का अंतर तीन हज़ार से लेकर सौ मतों के बीच सिमट कर रह गया था. 25 से अधिक प्रत्याशी एक हज़ार से कम मत के अंतर से जीते थे तो जलेसर और झांसी में यह अंतर सौ के नीचे भी खिसक गया था. छोटे दलों में जनमोर्चा ने 118 प्रत्याशी खड़े किए थे और 1.99 प्रतिशत हासिल कर 1 सीट जीतने में कामयाबी मिली थी. इस पार्टी के संयोजक राज बब्बर अब कांग्रेस के लोकसभा सदस्य हैं. इसी तरह उमा भारती की भारतीय जनशक्ति पार्टी ने 66 सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए. 1.40 प्रतिशत मत हासिल करके 1 सीट जीतने में कामयाबी पाई, अब इस पार्टी की मुखिया भाजपा में हैं. यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के यूसुफ़ क़ुरैशी ने 54 सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए, 2.59 प्रतिशत मत हासिल कर 1 सीट जीतने में कामयाबी पाई. अब अध्यक्ष कांग्रेस में हैं. बाहुबली डीपी यादव के राष्ट्रीय परिवर्तन दल ने 14 सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए और 6.22 प्रतिशत मत हासिल करके सबसे अधिक दो सीटें जीतने में कामयाबी पाई, बाद में बसपा में पार्टी का विलय कर लिया. डॉ. मसूद ने नेशनल लोकतांत्रिक हिंद पार्टी से 76 प्रत्याशी खड़े किए, लेकिन एक भी सीट हासिल नहीं कर सके और सपा में शामिल हो गए. अखिल भारतीय श्याम सुंदर शर्मा भारतीय लोकतांत्रिक कांग्रेस ने दो सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए, 36.96 प्रतिशत मत हासिल कर, एक सीट जीतकर बसपा में शामिल हो गए. मुस्लिम धर्म गुरु सलमान नदवी की अगुवाई में छोटे दलों को एक मंच पर लाते हुए इत्तेहाद फ्रंट के गठन का ऐलान राजधानी लखनऊ में किया गया. इस फ्रंट के बन जाने से बिखरे हुए छोटे दल पूरी ताक़त के साथ विधानसभा चुनाव 2012 के मुक़ाबले के लिए तैयार हो गए हैं.

कुछ दिन पूर्व पीस पार्टी अपना दल और बुंदेलखंड कांग्रेस का गठबंधन बना था. पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अयूब, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर, क़ौमी एकता दल के संस्थापक अफ़ज़ाल अंसारी, अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल, इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौक़ीर रज़ा बरेलवी, बुंदेलखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजा बुंदेला, गौड़वाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र गौड़, इंडियन नेशनल लीग के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. सुलेमान अहमद, भारतीय युवा कल्याण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमए सिद्दीक़ी, भारतीय जनसेवा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य, इंडियन जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. उदित राज सोनकर, नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुहम्मद अरशद ख़ां और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के अध्यक्ष भगवान सिंह अपने साथियों सहित इत्तेहाद फ्रंट में शामिल हुए. इस फ्रंट में शामिल होने के संदर्भ में सभी नेताओं का कहना है कि प्रदेश की जनता बदलाव लाना चाहती है. इस गठबंधन के पूर्व छोटे-छोटे दलों को एक जुटकर रालोद मुखिया अजित सिंह के नेतृत्व में गठबंधन बना था, लेकिन चुनाव के पूर्व ही बिखर गया. रालोद के मुखिया ने कांग्रेस से गठबंधन कर लिया. ऐसे ही एक प्रयास छोटे दलों को ताक़त देने के लिए तृणमूल कांग्रेस के नेता एवं केंद्रीय मंत्री मुकुलराय और सुलतान अहमद की पहल पर राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बना था, जिसमें अवामी समता पार्टी के रामसमुझ वंचित जमात पार्टी के चतर सिंह कश्यप, राष्ट्रीय लेबल पार्टी के रणवीर पाल, क्षत्रिय महासभा के राघवेंद्र सिंह, भारतीय पार्टी के तौसीफ़ ख़ान राष्ट्रीय समानता दल के गोपाल कुशवाहा, पिछड़ा महासभा के धर्मपाल चौहान, राष्ट्रीय जनसेवक संघ के रमेश कुशवाहा, कोरी महासभा के हूबलाल कोरी से लेकर हुआ. यह गठबंधन अंजाम के पहले ही बिखर गया है. एक बार फिर से परिवर्तन मोर्चा के संस्थापक और क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर हरिवंश सिंह ने मोर्चा के कई घटकों के 52 उम्मीदवारों की घोषणा की. मोर्चा की पहली सूची में नेलोपा, वंचित जमात पार्टी, राष्ट्रीय महान गणतंत्र पार्टी, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं. मोर्चा के प्रवक्ता राघवेंद्र सिंह राजू, संयोजक लालजी सिंह, राष्ट्रीय समानता दल के अध्यक्ष मोती लाल शास्त्री, हरिशंकर सफरीवाला, अवामी समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामसमुझ पासी, राष्ट्रीय महान गणतंत्र पार्टी के अध्यक्ष पूर्व आ-इएएस आनंद निषाद, वंचित जमात पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चतर सिंह कश्यप, नेलोपा के अरशद पवार समेत कई दलों के नेताओं ने कहा कि हमारा गठबंधन क़ायम रहेगा. छोटे दलों की दावेदारी क्षेत्र विशेष तक सिमटकर दो हज़ार से पांच हज़ार तक रह जाती है. लेकिन वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में 50 से अधिक सीटों की जद्दोजहद की कोशिश इत्तेहाद फ्रंट करने की तैयारी में है. डॉ. अयूब का मानना है कि चुनाव में इस फ्रंट के 50 विधायकों का गठबंधन तीसरा कोण बनेगा. कुछ इसी तर्ज़ पर बुंदेलखंड कांग्रेस के नेता राजा बुंदेला बुंदेलखंड की 19 सीटों में से दस सीटों पर चुनावी जंग में उतर रहे हैं. उनका मानना है चोरों और लुटेरों से बचने के लिए एक मात्र रास्ता बुंदेलखंड वासियों को बुंदेलखंड कांग्रेस के अलावा और कहीं नहीं दिख रहा है.

कभी बनते कभी बिगड़ते छोटे-छोटे दलो का महागठबंधन 2012 के चुनावी समर में हर हालत में सियासी पार्टियों के बहुमत के अंकगणित को बिगाड़ने के लिए किसी से भी हाथ मिलाने के लिए तैयार है. दामन और दाग के राग के चक्कर से जब बड़े-बड़े दल बेरूखी कर रहें हों तब इन छोटे दलो से उपेक्षा करना कहा तक सही होगा. सत्ता के लिए लालायित दलों के लिए समर्थन का झुनझुना दिखाने की चाहत के तहत अंकों के गणित में त्रिभुज का तीसरा कोण कितना कामयाब होता हैं यह तो वक्त ही तय करेगा.

छोटे दलों की कोशिश है कि किसी तरह अति दलित और अति पिछड़ों के साथ सत्ता की मलाई से वंचित लोगों में भावना जगाकर सत्ता की चाबी झटक लें, ताकि बड़े बड़ों के समीकरण बिखर जाएं और छोटे दलों की पौ बारह हो जाए. इस मुक़ाम की दिशा में मायावती का दांव भी कारण बन गया है. छोटे राज्य की बात करके पूरे प्रदेश के के बंटवारे पर बहस चल रही है. जब छोटे राज्य ठीक है तो छोटे दलों को कैसे बुरा कह सकते हैं. निशाद समाज की एकजुटता व क्षत्रियों का सहयोग भ्रष्टाचार की व्यवस्था परिवर्तन में आगामी चुनाव नया इतिहास रचेगा. रेणुका आयोग ने निषादों के ऊपर हो रही सदियों से जुर्म और उनका गौरवशाली इतिहास मिटाने का पिछली सरकारों ने हमें आदिवासी आरक्षण न देकर हमारा आरक्षण अनुसूचित जातियों के कोटे में डालने का जो प्रयास किया है. हम बड़े राजनीतिक दल के रूप में अपना मुख्यमंत्री घोषित कर अपने लोगों का विधानसभा से क्षत्रियों, मुसलमानों और उपेक्षित समाज जिनके अब तक मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, उनके साथ मिलकर सत्ता की चाबी 2012 में प्राप्त कर अपने समाज का हक़ दिलाने में कामयाब होंगे. उत्तर प्रदेश में हमारी आबादी 25 प्रतिशत है. हमारा समाज नदियों, झीलों-तालाबों व जंगलों में रहते हुए अपना जीवन यापन कर रहा है. पिछली सरकारों ने हमारे समाज को रोज़ी-रोटी छीनी और उनको अशिक्षित उपेक्षित बनाकर रखा है. एक वार्ता में राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के साथ राष्ट्रीय महान गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद निशाद एवं राष्ट्रीय महासचिव डॉ. संजय कुमार निषाद ने कुंवर हरिवंश सिंह द्वारा गठित मोर्चा के साथ काफ़ी आक्रमक दिखे. कई दलों को एक मंच पर लाकर क्षत्रिय निषाद, पासी, कुशवाहा, मुस्लिम गठबंधन को एतिहासिक बनाया है. 15 दलों के साथ 403 सीटों पर सभी सहयोगी दलों के प्रत्याशियों का बैठक में हुआ है. अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा को संरक्षक बनाकर प्रदेश में भ्रष्ट व्यवस्था के परिवर्तन को लेकर कई सफल रैलियां हुई हैं. हमारे साथ सहयोगी वंचित जमात पार्टी, वंचित जमान इंसाफ़ पार्टी, राष्ट्रीय समानता दल, जनवादी पार्टी, समस्त भारत पार्टी, राष्ट्रीय लेबर पार्टी, अवामी समता पार्टी, इंसाफ़ सेना, सोशलिस्ट पार्टी व अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा आदि सहित परिवर्तन मोर्चा का विकल्प संस्थापक/संरक्षक हरिवंश सिंह के साथ है. दूसरे चरण के चुनाव में गोरखपुर में एक विराट परिवर्तन रैली, राष्ट्रीय महान गणतंत्र पार्टी एवं परिवर्तन मोर्चा के बैनर तले की जाएगी. डॉ. संजय कुमार ने छोटे दलों की रणनीति का ख़ुलासा करते हुए कहा कि अपने समाज को 13 प्रतिशत ठाकुर, 27 प्रतिशत मुस्लिम वोट, 25 प्रतिशत केवट, कश्यप बिंद, मल्लाह, 7 प्रतिशत पासी व सभी पिछड़ों को जोड़कर राजनीतिक बदलाव लाएंगे.

भारतीय जनता पार्टी के वोटों में सेंध लगाने के लिए इस बार जनता पार्टी, शिवसेना के साथ कल्याण सिंह की नेतृत्व जनक्रांति पार्टी भी मैदान में है. राष्ट्रीय समानता दल, नवभारत निर्माण पार्टी, रघु ठाकुर की लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी, अंबेडकर समाज पार्टी, उलेमा कौंसिल, हमारा दल संजय चौहान की जनवादी पार्टी, बुंदेलखंड एकीकरण पार्टी, अमर सिंह का लोकमंच, नैतिक पार्टी भारतीय जनसेवा पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, आरके चौधरी की राष्ट्रीय स्वाभिमान पार्टी, महान दल, उदय मंच, पारख महासंघ, प्रगति मानव समाज पार्टी जैसे छोटे-छोटे दल चुनाव मैदान में कूद गए हैं.

feedback@chauthiduniya.com

साढ़े चार सालों में जनता और नेताओं से दूर रहने वाले बसपा के क़रीबी नौकरशाहों की कार्यप्रणाली में काफ़ी बदलाव आ गया हैं.

चौथी दुनिया

नए आशियाने की तलाश में मायावती के प्यारे

अक्सर चर्चा होती है कि देश में कहीं भी चुनाव हो वहां की ब्यूरोक्रेसी (नौकशाही) नतीजे आने से पहले ही इस बात का अंदाज़ा लगा लेती हैं कि राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा. इसका अंदाज़ा नौकरशाहों को कैसे लग जाता है, यह अहम बात नहीं है. ब्यूरोक्रेसी सरकार और जनता के बीच की कड़ी होती है, उसे जनता की नाराज़गी और सरकार में बैठे मंत्रियों की ज़मीनी हक़ीक़त पता होता है. इसीलिए अक्सर नतीजों को लेकर नौकरशाही की सोच सच्चाई (चुनावी नतीजों) के आस-पास ही होती है. इस मामले में नौकशााहों की तुलना उन चूहों से की जाए तो ग़लत नहीं होगा जिन्हें इस बात का सबसे पहले अहसास हो जाता है कि जहाज डूबने वाला है. डूबते जहाज से भागने वालों में चूहें सबसे आगे रहते हैं, तो राजनीति के डूबते जहाज से सबसे पहले नौकशाह किनारा करते हैं. जैसा की आजकल उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है. मायावती के कई वफादार नौकरशाह आजकल बसपा सरकार के जाने की चिंता में अन्य दलों के दरवाजों पर दस्तक देने लगे हैं. इसमें वह नौकशाह तो सबसे आगे हैं जो मायावती के पंच प्यारे कहलाते थे. प्रमुख सचिव गृह फतेह बहादुर सिंह, कैबिनेट सचिव शशांक शेखर, सचिव मुख्यमंत्री और अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन नवनीत सहगल, अपर कैबिनेट सचिव रवींद्र सिंह और पुलिस महानिदेशक बृजलाल मायावती के पांच साल के कार्यकाल में उनके ख़ास रहे, लेकिन अब यही अधिकारी नई सरकार में सुरक्षित ठिकानों की तलाश में लग गए हैं. मायावती सरकार से किनारा करने वाले नौकरशाह चुनावी गणित लगाकर अपने-अपने सियासी आका चुनने की होड़ में दिख रहे हैं.

कोई पुराने घरौंदों पर जा रहा है तो किसी को नए की तलाश है. विधानसभा चुनाव ने नौकरशाही में आपाधापी का माहौल बना दिया हैं. बीते साढ़े चार सालों में जनता और नेताओं से दूर रहने वाले मायावती सरकार के क़रीबी नौकरशाहों की कार्यप्रणाली में काफ़ी बदलाव आ गया हैं. भविष्य की चिंता ने उन्हें कई राजनीतिक दलों से संबंध सुधारने पर मजबूर कर दिया हैं. जनता के हितों को भुलाकर मायावती के पंच प्यारे नौकरशाहों में कोई कांग्रेसी नेताओं की चौखट पर नाक रगड़ रहा है तो किसी को समाजवादी मुलायम सिंह यादव में ख़ूबियां ही ख़ूबियां नज़र आने लगी है. नौकरशाह भाजपा नेताओं से नज़दीकियां बढ़ाने में लगे हैं तो मायावती का एक प्यारा राष्ट्रीय लोकदल के चौधरी अजित सिंह में अपनी खुशियां तलाश रहा है. कुछ नौकरशाह वफादारी बदल रहे हैं तो ऐसे नौकरशाहों की भी कमी नहीं है जिनको मायावती ने पूरी तरह से किनारे कर रखा था, ऐसे नौकरशाहों को उम्मीद है कि प्रदेश में सरकार बदलेगी तो उनके भी दिन बदल जाएंगे. इसमें से कुछ के ऊपर सपा के प्रति वफ़ादारी का तो कइयों के ऊपर भाजपा के प्रति लचीला रहने का ठप्पा लगा है. अधिकांश नौकरशाह कांग्रेस के क़रीब आना चाहते हैं ताकि मौक़ा पड़ने पर वह प्रतिनियुक्ति पर केंद्र में जा सकें. इसमें फतेह बहादुर सिंह सबसे आगे हैं. मायावती सरकार में प्रमुख सचिव गृह फतेह बहादुर सिंह की गुपचुप तरीके से कांग्रेस ख़ेमे में जाने की बात कही जा रही है. कहा जा रहा है कि वह मध्य प्रदेश के एक पूर्व कांग्रेसी मुख्यमंत्री के माध्यम से कांग्रेस से रिश्ता जोड़ने की की कोशिश कर रहे हैं. अपर कैबिनेट सचिव रवींद्र सिंह भाजपा के एक मुख्यमंत्री सहित कई बीजेपी नेताओं से घुले-मिले हुए हैं. इसी प्रकार मायावती सरकार में चर्चित आईएएस अधिकारी नवनीत सहगल समाजवादी पार्टी के नेताओं से संबंध सुधारने में लगे हुए हैं. कहते हैं कि बसपा की खराब हालत को देखते ही सहगल ने दूसरी बड़ी पार्टियों के बड़े नेताओं से संपर्क साधना शुरू कर दिया है. चर्चा तो यहां तक है कि नवनीत सहगल ने सपा के उच्च नेताओं से मिलकर संबंध सुधारने का प्रयास किया है, वहीं भाजपा और कांग्रेस के बड़े नेताओं से भी वे मिलकर गुफ्तगू कर चुके हैं. इतना ही नहीं वे सपा सुप्रीमो के रिश्तेदारों से भी दुआ बंदगी कर अपनी हाज़िरी लगा चुके हैं. उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक बृजलाल ने भी मायावती सरकार में ख़ूब नाम कमाया, लेकिन अब बृजलाल को कांग्रेस में कई ख़ूबियां नज़र आने लगी हैं. बृजलाल के समाजवादी पार्टी से रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं, सपा सरकार आने पर उनकी कुर्सी पर सबसे पहले ख़तरा मंडराने की उम्मीद है. बात कैबिनेट सचिव शशांक शेखर की कि जाए तो वह अपनी सरकारी सेवा की पारी तो समाप्त कर ही चुके हैं, लेकिन किसी तरह सांसद बनने का सपना वह अपने मन में पाले हुए हैं, जिसको लेकर वह विदा नहीं होना चाहते हैं, वह इसे मूर्त रूप देने के लिए कुछ भी करने का आतुर लगते हैं. मायावती सरकार में कुछ नौकरशाह ऐसे भी रहे जिनकी योग्यता का कोई मोल बसपा सरकार ने नहीं लगाया. उनमें प्रमुख रूप से नौकरशाह अनीता सिंह, शंभू सिंह यादव, जगदेव सिंह, दीपक सिंघल, अनिल गुप्ता और आर एन श्रीवास्तव आदि हैं. इन नौकरशाहों को उम्मीद है कि अगर मुलायम सरकार बनेगी तो उनका सितारा चमक सकता है.

मायावती

ब्रजलाल

शशांक शेखर

कुंवर बहादुर

नवनीत सहगल

अजय कुमार
feedback@chauthiduniya.com

दलों का दंगल

उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर सभी दलों में घमासान चल रहा है. कांग्रेस के दिग्गज उत्तर प्रदेश के कोने कोने में जहां अपनी अलख जगा रहे हैं. वहीं युवराज राहुल पूरे प्रदेश में अपने नए तेवर में उतर आए हैं. अखिलेश यादव का रथ लगातार चल रहा है. उत्तर प्रदेश में साध्वी उमा भारती के दौरे जारी है. पार्टी नेता एक दूसरे के दामन पर लगे दागों की विस्तार से व्याख्या करते अघा नहीं रहे हैं. भाजपा जहां कांग्रेस को कोसती है. वहीं कांग्रेस भाजपा को कहीं पर छूट नहीं दे रही है. भाजपा के केंद्रीय नेताओं का जमावड़ा लगने लगा है. बड़े नेता एक दूसरे से दो-दो हाथ करने के मूड में है. वहीं बसपा नेत्री अपने स्टार प्रचारक तैयार करने में जुटी हुई है. बसपा ने आचार संहिता लागू होने के पहले ही कार्यकर्ताओं को अस्त्र-शस्त्र दे चुकी है. कैडर कैंपों में उन्हें बसपा की उपलब्धियों से भरा साहित्य दिया जा चुका है. मुस्लिम वोटों को प्रभावित करने के लिए उर्दू में पुस्तिका छपवाकर इसे वितरित किया जा चुका है. पार्टी ने प्रत्याशियों को पूरी तरह चुनाव में समर्पित करने की योजना के तहत ही प्रचार के ख़र्च का जिम्मा भी उनपर डाला रखा है. वितरित स्टेशनरी इस नज़रिए से तैयार की गई है कि जनता में सत्ताजनित विरोध कम किया जा सके. इसके अतिरिक्त पार्टी की ओर से तैयार कराए गए चुनाव प्रचार के लोकगीत बजने लगे हैं. प्रत्याशियों को अपने स्तर पर प्रचार के लिए किसी भी संचार माध्यम को अपनाने की पूरी छूट दी गई है. बस नतीजा बसपा के पक्ष में रहे. सुरक्षित सीटों पर बसपा की विशेष निगाह है, इसलिए वहां ब्राह्मण, मुस्लिम, वैश्य नेताओं की अलग-अलग सभाओं की योजना है ताकि वे वहां जातीय मतों को प्रभावित कर सकें. सपा के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव आठ जनवरी से दसवें चरण की क्रांतिरथ यात्रा की धुंआधार शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं. लखनऊ से श्रीगणेश करता हुआ उनका क्रांति रथ चार दिनी यात्रा के पहले दिन राजधानी से होता हुआ सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती और बहराइच ज़िलों में जनजागरण अभियान के तहत सभाओं को संबोधित करेंगे. कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी अब पूर्वांचल दौरे की तैयारी में लगे हुए हैं. अन्य छोटे बड़े दल अपना अपना चुनाव प्रचार कर रहे है. राहुल के साथ ही प्रियंका गांधी भी चुनाव प्रचारक के रूप में कांग्रेस में उतरने वाली है.

फरवरी में होने वाले चुनाव के मद्देनज़र कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलने का दावा करते हुए केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव के बाद बसपा और भाजपा पहले की तरह एक हो जाएंगे. दोनों दल भ्रष्ट नेताओं को पनाह देने में लगे हैं. बसपा के भ्रष्ट भाजपा में शामिल हो रहे है. केंद्र सरकार ने सर्वशिक्षा अभियान में 31 हज़ार करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश को दिए, लेकिन राज्य सरकार ने 13 हज़ार करोड़ रुपये ही ख़र्च किए. राज्य में 25 लाख बच्चे अभी भी स्कूल जाने से वंचित हैं. बसपा ने मनरेगा व एनआरएचम में लूट की है. वहीं कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने कहा, भाजपा बसपा तीन बार हाथ मिला चुके हैं. राज्य में हालात काफ़ी ख़राब है, लोग बदलाव चाह रहे हैं. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी ने ललितपुर के महरौनी दौरे में कहा कि प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती और केंद्र सरकार के बीच तालमेल है. मायावती कहती है कि तुम दिल्ली लूटो. मैं प्रदेश को लूटूंगी. प्रदेश की जनता ने गुंडाराज को ख़त्म कर बसपा को इस उद्देश्य से जिताया था कि यहां पर एक आदर्श शासन तंत्र स्थापित होगा, लेकिन इसके ठीक विपरीत यहां की जनता को जिस बेरहमी से ठगा गया है. इसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है. जैसे अपने मताधिकार का प्रयोग करके उनसे बहुत बड़ी चूक हो गई. भजापा शासित प्रदेशों में विकास की गंगा बह रही है और यहां उत्तर प्रदेश के लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं. विद्युत न होने पर उद्योग धंधों की स्थापना नहीं हो पा रही है. जिससे रोजगार के लाले पड़े हैं. किसानों की हिमायती कोई पार्टी है तो वह भाजपा ही है. स्वाधीनता के बाद से 63 वर्षों में से 50 साल तक कांग्रेस ने ही राज किया और उसके शासन काल के दौरान ग़रीबी ओर बेकारी बढ़ती ही गई. उनके भ्रष्टमंत्री एवं विधायक बड़े बड़े घोटलों में लिप्त हैं चाहे वह टूजी स्पेक्ट्रम घेटाला हो या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले. कन्नौज के सिकंदरपुर में आयोजित सभा में बोलते हुए साध्वी उमा भारती ने कहा कि बसपा सरकार ने 5 वर्ष दलितों, ब्राह्मणों का उत्पीड़न, किसानों की ज़मीनें छीनने का काम किया. वहीं अपराधियों को चुनाव लड़ने की नींव कांग्रेस ने डाली थी. प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व जनक्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कल्याण सिंह ने कहा है कि भाजपा ने कुशवाहा को कैसे शामिल किया, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए. अब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भाजपा बोलने लायक नहीं रही. आडवाणी के पास है कोई जवाब. इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना होगा. यह एक डील है. अगर भ्रष्टाचार के बाद पार्टियों में प्रत्याशियों की बात करें तो एडीआर के सर्वे के अनुसार भाजपा के 220 उम्मीदवारों में 26दाग़ी, कांग्रेस के 215 प्रत्याशियों में 26, सपा के 165 में 26 दाग़ी हैं. रालोद की 17 उम्मीदवारों में एक उम्मीदवार आपराधिक छवि वाला है. वैसे 403 विधायकों में से 143 पर आपराधिक मामले लंबित बताए गए हैं, 35 प्रतिशत विधायक आपराधिक प्रवृत्ति वाले हैं. जिसमें बसपा के 17, सपा के 16 विधायक आपराधिक मामले पुलिस में दर्ज हैं. इनमें से धीरेंद्र प्रताप सिंह पर 29, सुशील कुमार पर 14, राम प्रकाश यादव पर 11, जितेंद्र कुमार पर 12 और मुख्तार अंसारी पर 13 मामले लंबित चल रहे हैं. एडीआर (एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स) के मुताबिक यूपी के 127 विधायक करोड़पति जिसमें बसपा के 51, सपा के 38, भाजपा के 16 और बाक़ी अन्य पार्टियों के हैं. एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में यह भी दावा किया है. पिछले तीन वर्षों में भाजपा को 520.32 करोड़, बसपा को 231.19 करोड़, कांग्रेस को 168 और सपा को 61.61 करोड़ रुपए चंदा मिला है.

दर्शन शर्मा, लखनऊ ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया साप्ताहिक अख़बार को मथुरा में लॉन्च करते हुए चौथी दुनिया के प्रधान संपादक संतोष भारतीय, मथुरा के विधायक प्रदीप माथुर एवं अन्य.

चुनावी हलचल

सुबह सवेरे सौ-सौ ग्राम, भइया जीतेंगे संग्राम

चुनाव नजदीक आते ही माननीयों के यहां दारू मुर्गे का दौर चलने लगता है. चुनाव दफ्तरों के आसपास नशेड़ियों की ज़मात लगने लगती है. इन नशेड़ियों का नारा रहता है, सुबह सबेरे सौ-सौ ग्राम, भइया जीतेंगे संग्राम. मतदाताओं को रिझाने के लिए गांवों में मांस पकाने की भट्ठियां जल जाती हैं. जहां मतदाताओं को दावतें दी जाती है और छककर सोमपान कराया जाता है. ग़रीबों को शराब पीने का मौक़ा मिलता है, वहीं चुनाव भर दो टाइम का खाने का भी जुगाड़ हो जाता है. मतदाताओं के लिए कच्ची दारू अवैध रूप से बनने लगती है. जिसपर चुनाव आयोग नज़र भी रखता है. आचार संहिता के उल्लंघन का दंश भी प्रत्याशियों को झेलना पड़ता है. लेकिन वे इससे बाज़ नहीं आते. चुनाव जीत जाएं, बाक़ी देखा जाएगा. क्योंकि कच्ची दारू सस्ती होती है जिससे ख़र्च कम आता है. हालांकि अब कच्ची की जगह अंग्रेजी दारू मतदाताओं की पसंद बनने लगी है. आबकारी विभाग के आला अधिकारियों की मानें तो इस चुनावी मौसम में 30 से 50 फ़ीसदी तक की वृद्धि हो जाती है. पूरे प्रदेश में रोज बेची जा रही शराब का आंकड़ा जुटाने के लिए आबकारी विभाग ने मुख्यालय में कंट्रोल रूम बनाया है. दुकानों के बारे में रोज सूचना एकत्रित किए जा रहे हैं. मध्य प्रदेश, बिहार और नेपाल की सीमाओं पर विभाग की टीमों को लगाया गया है. हिदायत दिया गया है कि चार पहिया गाड़ी वाला कितना भी असरदार हो, बिना चेकिंग के निकलने न पाए. प्रत्याशी शराब पिलाकर वोट न झटक सकें, इसके लिए चुनाव आयोग ने पहली बार प्रदेश की सारी दुकानों को निगहबानी में रखने का निर्णय लिया है. *-चौथी दुनिया ब्यूरो*

चरण बदलने से बिगड़ा अर्थशास्त्र

भारतीय चुनाव आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण को आख़िर में करने से प्रत्याशियों के चेहरे मुरझा गए हैं. सबसे पहले मतदान की कतार में आ रहे मुरादाबाद मंडल के भीम नगर रामपुर, जेपीनगर और मुरादाबाद ज़िलों में अब मतदान का नंबर सबसे आख़िर में पड़ गया है. ईद मिलादुन्नबी को लेकर निर्वाचन आयोग ने चार फरवरी का चुनाव तीन मार्च को कराने का फ़ैसला लिया है. अब सवाल यह उठता है कि इतनी लंबी अवधि तक चुनावी माहौल को बनाए रखना प्रत्याशियों के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है. इतने अंतराल में वाहनों का ख़र्च और मतदाताओं को रोके रहने के ख़र्च ने उम्मीदवारों को सांसत में डाल दिया है. वहीं आचार संहिता का उल्लंघन का कोड़ा भी उन्हें सता रहा है. उन्हें सबसे बड़ी चिंता रुपए पैसे के ख़र्च को लेकर है. चुनाव आयोग के इस फ़ैसले ने उनके अर्थशास्त्र को बिगाड़कर रख दिया है. कुछ प्रत्याशियों का कहना है कि तारीख़ बढ़ने से उन्हें जनता तक पहुंचने का पर्याप्त समय मिल गया हैं. टिकट विलंब से मिलने के कारण अब समय बेहतर है. वहीं कुछ लोगों का कहना है कि आयोग ने चुनाव का खिलवाड़ बना दिया है. पूरी तैयारी के बाद नामांकन शुरू होने थे. चुनाव आगे बढ़ने से एक समस्या खड़ी हो गई है.

मायावती के वफ़ादारों पर चुनाव आयोग की गाज

बसपा सरकार के वफ़ादार अफसरों पर चुनाव आयोग की गाज गिरनी शुरू हो चुकी है. पहले तो चुनाव आयोग ने प्रमुख सचिव गृह पद से कुंवर फतेहबहादुर और डीजीपी बृजलाल को हटाया और अब मायावती के सबसे क़रीब रहे शशांक शेखर पर चुनाव आयोग की नज़र पड़ चुकी है. विपक्षी दलों से मिली शिकायत के आधार इन अफसरों को हटाया जा रहा है. हालांकि कुंवर फतेह बहादुर को 2009 के लोकसभा चुनाव में हटाया जा चुका हैं, तब उन्हें प्रमुख सचिव गृह के पद से हटाए जाने के बाद पंचम तल पर तैनाती दी गई थी. कहते हैं कि बृजलाल को तीन माह पहले ही डीजीपी बनाया गया था, उन्हें तीन लोगों को सुपर सीट करके डीजीपी बनाया गया था. मायावती का स्वजातीय होने के साथ उनकी निष्ठा एवं समर्पण भी बसपा के प्रति होने के कारण विपक्ष कई महीनों से आयोग से हटाने की गुहार लगा रहा था. इसी प्रकार प्रमुख सचिव गृह कुंवर फतेहबहादुर भी जिनके पास गृह गोपन और नियुक्ति जैसे महत्वपूर्ण विभाग थे. मायावती के स्वजातीय होने के कारण उनकी निष्ठा भी बसपा के प्रति ज़्यादा रही है. बसपा विधायकों पर किसी भी तरह के कार्रवाई के बारे में जवाब मुख्यमंत्री मायावती के बजाय वही देते थे. मायावती सरकार में उन्हें महत्वपूर्ण विभागों का दायित्व सौंपा गया था. हर बार चुनाव के दौरान उन्हें पद से हटाया गया. हालांकि विपक्षी पार्टियों ने इन दोनों अफसरों के साथ ही कैबिनेट सेक्रेटरी शशांक शेखर सिंह को भी हटाने की बाबत ज्ञापन दिए हैं. इन पर भी अधिकारी के बजाए सरकार के एजेंट के रूप में काम करने का आरोप है. प्रदेश में इस तरह की कार्रवाई पहली बार नहीं हो रही हैं वर्ष 2007 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव गृह, और डीजीपी को हटाया गया था. पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों की शिकायत पर डीजीपी पद से बुआसिंह, मुख्यसचिव पद से नवीन बाजपेई और प्रमुखसचिव गृह पद से सतीश अग्रवाल को हटाया गया था.

– **दर्शन शर्मा,** *लखनऊ ब्यूरो*

मेरे ख़िलाफ़ संघ का प्लान डी : दिग्गी राजा

बाबा रामदेव, अन्ना हजारे और श्रीश्री रविशंकर को भाजपा और संघ का प्लान ए-बी और सी बताने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के ख़िलाफ़ जब मुगलसराय स्टेशन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध-प्रदर्शन किया तो दिग्गी राजा ने इसे संघ-भाजपा के प्लान-डी का हिस्सा बता दिया. सिंह इससे पहले कालेधन और लोकपाल के मुद्दे पर बाबा रामदेव और अन्ना हजारे के आंदोलन को क्रमश: आरएसएस, भाजपा का प्लान ए और प्लान बी करार दिया था, जबकि श्री श्री रविशंकर को प्लान सी का हिस्सा बताया था. दिग्गी राजा के मुंह से प्लान डी की बात सुनकर लोगों को कहना था दिग्गी तो स्वयं संघ से जुड़े रहे हैं, उन्हें असलियत ज़्यादा पता होगी. इधर, भाजपा ने संघ पर दिग्गी के ताजा हमले को हास्यास्पद बताते हुए भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगातार निशाने साधने वाले दिग्विजय सिंह की कुछ समय पहले इस संगठन से काफ़ी घनिष्ठता थी. दिग्विजय संघ के हर कार्यक्रम और समारोहों में हिस्सा लेते थे. लेकिन वह कुछ महीनों से संघ से बेरुख़ी दिखा रहे हैं. उन्होंने कहा कि संघ के ख़िलाफ़ दिग्विजय का बयान इस बात का प्रमाण है कि उनके शरीर में ओसामाजी की आत्मा प्रवेश कर गई है. उनके लिए भाजपा का कांग्रेस को सुझाव है, उनकी झाड़ फुंक कराई जाए ताकि ओसामा की शैतानी आत्मा उनके शरीर से बाहर निकले और वह सामान्य व्यवहार कर सकें. *–चौथी दुनिया ब्यूरो*

गणतंत्र दिवस की बधाई
इन्डग्रो फूटस प्रा. लि.
औद्योगिक क्षेत्र, दही चौकी, उन्नाव

गणतंत्र दिवस की बधाई
संजय निगम
कांग्रेस पार्टी
उन्नाव

समाजवादी पार्टी, उन्नाव
गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं
शिशिर गुप्ता
नगर अध्यक्ष-उन्नाव
9415045592

कांग्रेस पार्टी जिन्दाबाद!
समस्त उन्नाव जनपदवासियों को
नव वर्ष एवं गणतंत्र दिवस
की हार्दिक शुभकामनाएं
अन्नू टण्डन, सांसद-उन्नाव

मुलायम नाराज मित्रों को मनाने में माहिर हैं. किसी को संसद में मनाया तो किसी को दावतों में तो किसी मीटिंग्स में मनाने का अवसर पाया.

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

दिग्विजय से मुसलमानों का विश्वास उठा

संजय सक्सेना

कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रभारी दिग्विजय सिंह उर्फ दिग्गी राजा का उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता में वापसी के लिए सोते–जागते राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस)को कोसना था. मुसलमानों को खुश करने के लिए दिग्गी लगातार संघ पर हमला करके वाहवाही लूट रहे हैं, लेकिन ऐसा करते समय वह अपना अतीत भूल गए या फिर उन्होंने समझ लिया था कि जनता की याददाश्त इतनी अच्छी नहीं है जो बीती बातों को लंबे समय तक याद रखे. कांग्रेस के महासचिव, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, एवं युवराज राहुल गांधी के पथ–प्रदर्शक और न जाने क्या–क्या पहचान है दिग्विजय सिंह उर्फ दिग्गी राजा की. संघ पर हमला करके यूपी से लेकर दिल्ली में खूब सुर्खियां बटोर रहे दिग्गी राजा को जब संघ का ही समाचार पत्र समझे जाने वाले एक साप्ताहिक समाचार पत्र ने पलटवार किया तो वह चूहे की तरह बिल में दुबकते नज़र आए. लोगों को दिग्गी राजा के बारे में हक़ीक़त पता लगने में जरा भी देरी नहीं लगी कि उनके रिश्ते संघ से हुआ करते थे, कहा तो यहां तक जाता है कि वह संघ की शाखाओं में भी जाते थे, लेकिन अपनी सहूलियत की राजनीति करने वाले दिग्गी राजा ने जब अपने ही पुराने संगठन को निशाने पर लिया तो संघ ही नहीं मुस्लिम जगत भी उनकी ठगी से तिलमिला गया. मुस्लिम जमात इस बात से नाराज़ हुआ कि धर्मनिरपेक्षता का चोला ओढ़कर दिग्गी राजा जैसे कुछ नेता भोली भाली जनता को बरगला रहे हैं,जबकि हकीकत में इनके तार संघ वालों से जुड़े हैं.

बात दिग्गी राजा के स्वभाव की कि जाए तो वह अनचाहे मेहमान की तरह वह कहीं भी आ धमकते हैं. सिवाय मध्य प्रदेश के. जहां से उन्होंने राजनीति का कखग...सीखा और जहां मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पर विराजमान रह चुके हैं. कहते हैं कि दिग्गी राजा की दाल मध्य प्रदेश में न मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान रहते उमा भारती ने गलने दी और न ही शिवराज सिंह चौहान गलने दे रहे हैं. अंदर खाने की खबर यह भी है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस भी दिग्गी के मध्य प्रदेश से दूर रहने से खुश है. यह और बात है कि कोई खुलकर यह बात कहने को तैयार नहीं है.

दिग्गी राजा की कांग्रेस में क्या हैसियत है और उनकी बात को कांग्रेसी कितनी गंभीरता से लेते हैं, यह बात एक नहीं कई बार मीडिया के सामने आ चुकी है, लेकिन इसके बाद भी वह गांधी परिवार के विश्वासपात्रों की लिस्ट में सबसे ऊपर हैं. विपक्ष तो यहां तक कहता है कि जो बात सोनिया और राहुल गांधी अपने मुंह से नहीं कह पाते हैं, वह बात वह दिग्गी राजा के मुंह में रखकर जनता के सामने परोस देते हैं. चाहे बाबा रामदेव पर हमला हो या फिर अन्ना हजारे अथवा श्रीश्री रविशंकर जी महाराज सभी की छवि को दिग्विजय सिंह ने धूमिल करने का काम किया. उनके रिश्ते संघ से बताए. जब खुद की पोल खुली तो कहने लगे कि जरा पता करें कि मैंने विराट हिंदू सम्मलेन में क्या बोला था. गांधी परिवार के विश्वासपात्र होने के अलावा दिग्गी राजा की एक और खूबी है. वह किसी मामले पर त्वरित टिप्पणी नहीं देते. कभी–कभी तो उनको टिप्पणी देने में महीनों लग जाता है जैसा कि बटाला हाउस कांड में देखा जा चुका है. बिहार में कांग्रेस की बहुमत वाली सरकार का दावा करने वाले दिग्गी राजा उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही भ्रम पाले हुए हैं. अपने जीते–जी राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनते देखने का एक मात्र सपना पाल दिग्गी राजा को सावन के अंधे की तरह सब तरफ हरा–हरा ही दिखता है. बिहार में वह राहुल का गुणगान करते नहीं थके थे, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नितीश कुमार विराजमान हो गए. राहुल का हश्र वैसा ही हुआ जैसे किसी को आसमान पर चढ़ाकर जमीन पर पटक दिया हो. कुछ दिनों तक तो दिग्गी राजा और उनके युवराज राहुल गांधी इस सदमें से ही नहीं उबर पाए.

बिहार में मुंह की खाने के बाद दिग्गी राजा ने उत्तर प्रदेश में भी बिहार जैसा राग अलापना शुरू कर दिया है. वह बिहार की तरह ही यूपी में भी कांग्रेस की सरकार बनने का सपना राहुल गांधी को दिखाने लगे हैं. जमीनी हकीकत को जाने–समझे बिना दावे और वायदे करने वाले दिग्गी राजा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कितना भला कर पाएंगे, इसका जबाव तीन–चार महीनों में मिल जाएगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि उन्होंने अपनी तरफ से कोई कोर–कसर नहीं छोड़ा हैं. एक वर्ग विशेष को खुश करने में लगे राजा साहब कुछ ज्यादा ही उतावले दिख रहे हैं. इस वर्ग को खुश करने के लिए वह पिछड़ों को आरक्षण का मुद्दा खूब हवा मे उछाल रहे हैं. हर बात के पीछे अन्ना, आरएसएस व भाजपा का हाथ बतना उनकी आदत है. बात दिग्गी के संघ कनेक्शन की कि जाए तो अब दिग्विजय सिंह इस बात से इंकार नहीं कर सकते हैं कि वह संघ से जुड़े रहे थे, जब उन्हें लगा कि संघ के साथ रहकर उनकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो पाएगी तो उन्होंने संघ से किनारा करके उसे गाली देने का काम शुरू कर दिया.

प्रसिद्ध शिया धर्म गुरु मौलाना कल्बे जब्बाद कहते हैं कि राजनीति का स्तर गिरता चला जा रहा है, नेताओं ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है, उनके मुंह में कुछ और पेट में कुछ और रहता है. इसी लिए दिग्गी जैसे नेता समय के अनुसार अपना चेहरा–मोहरा भी बदल लेते हैं. दिग्गी राजा के संघ से रिश्ते हैं तो उन्हें इस बात को छिपा कर नहीं रखना चाहिए था. धर्मगुरु खालिद रशीद फिरंगी महली कहते हैं भोली भाली मुस्लिम जनता को नेता छलने का काम वर्षों से कर रहे हैं. जब इन नेताओं को मुस्लिम वोटों की जरूरत होती है तो उन्हें कौम की याद आती है और फिर भूल जाना आदत बन गई है. दिग्गी राजा की संघ से नजदीकी की बात सामने आ रही है, यह बेहद दुखद है, वह धर्मनिरपेक्षता का चोला ओढ़कर अवाम को बरगला रहे थे. सुन्नी धर्म गुरु जहांगीर आलम कासमी कहते हैं कि कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह की सच्चाई देखकर लग रहा है कि किसपर विश्वास किया जाए और किसपर नहीं.

feedback@chauthiduniya.com

दिग्गी राजा की कांग्रेस में क्या हैसियत है और उनकी बात को कांग्रेसी कितनी गंभीरता से लेते हैं, यह बात एक नहीं कई बार मीडिया के सामने आ चुकी है, लेकिन इसके बाद भी वह गांधी परिवार के विश्वासपात्रों की लिस्ट में सबसे ऊपर हैं. विपक्ष तो यहां तक कहता है कि जो बात सोनिया और राहुल गांधी अपने मुंह से नहीं कह पाते हैं, वह बात वह दिग्गी राजा के मुंह में रखकर जनता के सामने परोस देते हैं.

अखिलेश मुसलमानों के रहनुमा बने

देश के राजनीतिक इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण वोट बैंक समझे जाने वाले मुसलमानों पर उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में कई पार्टियों का सियासी भविष्य टिका है. उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में क़रीब 19 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखने वाले मुसलमानों को रिझाने के लिए सभी पार्टियां जी–जान से जुटी हैं. इस होड़ में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सबसे आगे दिख रही हैं. जहां कांग्रेस ने मुसलमानों को लुभाने के लिए अल्पसंख्यकों को साढ़े चार प्रतिशत आरक्षण का पासा फेंका है वहीं समाजवादी पार्टी भी मुसलमानों को रिझाने के लिए आरक्षण के प्रतिशत में बढ़ोत्तरी करने का वादा कर रही है. अगर मुसलमानों का 30 प्रतिशत वोट भी किसी एक दल के पास पहुंच गया तो वह अहम हो सकता है. समाजवादी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव सत्ता में आने पर इस प्रतिशत में इजाफ़े का वादा कर रहे हैं.

अखिलेश ने कहा है कि मुस्लिमों को आबादी के आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए और समाजवादी पार्टी आवश्यकता होने पर इसके लिए संविधान में संशोधन के पक्ष में है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 4 प्रतिशत आरक्षण देने का दावा करके मुस्लिम समाज के साथ धोखा किया है. कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों को 4 प्रतिशत आरक्षण दिया है, जिसमें जैन, पारसी, सिख, बौद्ध, ईसाई सभी शामिल हैं. मुसलमानों को इससे क्या मिलने वाला है. अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी सच्चर कमेटी की सिफ़ारिशों को लागू करने के लिए संसद के अंदर और बाहर आवाज़ उठाती रही है. कांग्रेस सरकार मुसलमानों में भ्रम पैदा करने के लिए कमीशन बनाती है, लेकिन उनकी रिपोर्ट ठंडे बस्ते में डाल देती है. वह सिर्फ़ उनके वोट के लिए ये खेल करती है. इसके विपरीत समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार में मुस्लिमों को पुलिस में 15 प्रतिशत नौकरियां दी. उर्दू टीचर और अनुवादक रखे. बहुजन समाज पार्टी के राज में मुस्लिमों को 2 प्रतिशत नौकरियां भी नहीं मिलीं. अखिलेश यादव ने कहा कि महंगाई से ग़रीबी बढ़ती है और भ्रष्टाचार बढ़ता है. कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी की इसमें मिलीभगत है. आज आम आदमी ईंट, सीमेंट के महंगे होने से मकान नहीं बनवा सकता है. किसान खाद की क़िल्लत से परेशान हैं. ग़रीबों की जिस पैसे से मदद होती, वह पैसा उत्तर प्रदेश के पत्थर के हाथियों पर ख़र्च हो गया. कांग्रेस के नेता कहते हैं कि केंद्र का पैसा प्रदेश में हाथी खा गया. कोई उनसे पूछे कि हाथी को किसने तगड़ा होने दिया है. पैसा खाने से रोका क्यों नहीं. यह मौक़ा उसे किसने दिया? बसपा की सरकार लुटेरी है. अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने नौजवानों को आगे बढ़ाया है. उसके सबसे ज़्यादा प्रत्याशी नौजवान हैं. लड़ाई कठिन है, लेकिन समीकरण और सर्वेक्षण हमारे पक्ष में हैं. हम बहुजन समाज पार्टी को हटाना और समाजवादी पार्टी की बहुमत की सरकार बनाना चाहते हैं.

दर्शन शर्मा, लखनऊ ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com